खण्ड–525, अंक–06
गुरुवार, 19 माघ, शक संवत् 1945
(दिनांक 08 फरवरी, 2024 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2024)

(खण्ड 525 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	7-108
मा0 सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई		...	108
कृषि मंत्री द्वारा व्यस्तता के दृष्टिगत कार्य-स्थगन के रूप में आज प्राप्त नोटिस की ग्राह्यता पर अगले दिन सुने जाने का पीठ से अनुरोध		...	108-109
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	109-111
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत पार्क एवं स्मृति द्वार बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	111
जनपद हमीरपुर में अधूरी बेतवा यमुना बाईपास परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	112
जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानी में नाली के सी0 सी0 निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...		...	112
जनपद गोण्डा में सरयू-घाघरा नदी के विरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	113
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	113
मुरादाबाद ग्रामीण में खेल मैदान को सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग न किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	113-114
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के हिंदनगर वार्ड में सीवर लाइन की सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	...	...	114
जनपद आगरा के खेरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रावतपुर में पार्वती नदी के पास चेक डैम बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	114-115
उत्तर प्रदेश पुलिस के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	115

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में गौशाला के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	115
जनपद बुलन्दशहर में कृषि उपकरण की सब्सिडी में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद बांदा के कैनाल बांदा अबरी रोड के नहर की पटरी पर अवैध कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117-118
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	118
जनपद सीतापुर के बिसवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	118-119
जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में राप्ती नदी पर पैन्टून पुल बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	119
जनपद बहराइच के पयागपुर के ग्राम हुजूरपुर में पानी की टंकी बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद अलीगढ़ के गोण्डा ब्लॉक को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ के ग्राम में कतिपय मार्गों पर नालों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
जनपद सहारनपुर की मस्कारा नदी की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ में कतिपय पौराणिक स्थलों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	121

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद महोबा के चरखारी में राजकीय महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर में कतिपय स्थानों पर अल्पिका/माइनर बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121-122
जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर में ढमोला नदी की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	122
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कृषि भूमि आवंटित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	122-123
प्रदेश के समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में हड्डी रोग के उपचार हेतु निःशुल्क सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	123
जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123-124
विंध्याचल विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूमि को आवासीय घोषित किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	124
उत्तर प्रदेश के रेसलर कोच को सम्मान राशि दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट में आबादी हेतु भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125-126
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावाँ के ग्राम भैड़ा-भरतपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, ग्राम मलिकपुर से नगला जौहरी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
ओम साई मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	126-127
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	127
इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि के फ्री-होल्ड प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर अध्यक्ष के निदेश ...	127-128

विषय	पृष्ठ संख्या
बजट सत्र के उपवेशन की संख्या बढ़ाये जाने तथा विभागवार बजट लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	129-131
प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	131
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	131
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का अट्ठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	132
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)...	132
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	133-142
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 का अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	142-144
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (पारित) ...	144-156
लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन में वृद्धि के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	156-158
बजट चर्चा पर मा0 सदस्यों/मा0 मंत्रिगण हेतु समय का निर्धारण ...	158-160
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	160-274
श्री अध्यक्ष द्वारा टैब पर लॉग-इन कर उपस्थिति दर्ज करने सम्बन्धी निर्देश..	274-275
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अयोध्या धाम दर्शनार्थ जाने हेतु सदन को सूचना ...	275
बजट चर्चा पर मा0 सदस्यों हेतु पुनः समय का निर्धारण ...	275
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	276-280
याचिकाओं का उपस्थापन	281
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	281
इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	281

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	281
डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	281
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	281-282
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	282
श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	282
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	282
श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	282
श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	282
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	282-283
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	283
श्री जैकिशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	283
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	283
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	283
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	283
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	284

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	284
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	284
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	284
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	284
श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	284
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	285
श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	285
श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	285
श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भईया'', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	285
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	285
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	285
श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	286
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	286
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	286
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	287
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	287
श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	287
श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	288
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	288
श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	288
डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	288
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	289
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	289

विषय	पृष्ठ संख्या
डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	289-290
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्रीमती मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	290
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	290
श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	290
श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	290
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	291
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	291
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	291
डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	291
श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	291

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	291
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	292
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	292
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	292
श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	292
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	292
श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	292
श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	293
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	293
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	293
श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	293
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	293
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	293-294
श्री कमलाकान्त राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	294
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	294

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	294
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295
श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	295
डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	295
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	295
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	295
डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की प्रदेश में वित्त विहीन कालेजों में कार्यरत शिक्षकों से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	296
श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	296
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	296
श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	296
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	296
श्री ठा0 रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	296
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	297

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	297
श्री बाबू राम पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	297
श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	297
श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	297
श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	297
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	298
श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	298
श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	298
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	298
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	298
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	298
श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	299
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	299
श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	299
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	299

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	299
श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	299
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	300
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)... ...	300
श्री हरि प्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	300
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	300
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	300
श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	300
श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई) ...	301
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	301
श्री राकेश गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	301
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	301
मा0 सदस्यों की उपस्थिति तथा नाम में सुधार विषयक श्री अध्यक्ष के निर्देश	301-302
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	302-304
जिला अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग कटेहरी बाजार मछली मण्डी से पिलखावां मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	304-305

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना के दौराला में शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य	305-308
सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद् इटावा क्षेत्र में जल भराव के निदान के सम्बन्ध में श्रीमती सरिता भदौरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	308-309
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा रवनियां में जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो चुकी सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेचई सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	309-310
नियोजन विभाग के अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग के उप निदेशक के पदों पर प्रोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	311
चीनी मिल गेट एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य... ...	311-313
जनपद चित्रकूट तथा बांदा में श्रम विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य ...	313-316
विधान सभा क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम मगरौल, तहसील-कालपी में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	316-317
श्री अध्यक्ष द्वारा अगले दिन गैर सरकारी दिवस पर गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा कराये जाने विषयक सूचना	317
नत्थियाँ	318-323

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी, 2024 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-355

1.	अंकित भारती, श्री	गाजीपुर	
2.	अंकुर तिवारी, श्री	सन्तकबीरनगर	
3.	अखिलेश, श्री	आजमगढ़	
4.	अजय, श्री	गोण्डा	
5.	अजय कुमार, डॉ0	बागपत	
6.	अजय सिंह, श्री	बस्ती	
7.	अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	
8.	अजीत सिंह पाल, श्री	कानपुर देहात	
9.	अताउर रहमान, श्री	बरेली	
10.	अतुल गर्ग, श्री	गाजियाबाद	
11.	अतुल प्रधान, श्री	मेरठ	
12.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	
13.	अनिल प्रधान, श्री	चित्रकूट	
14.	अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री	सन्तकबीरनगर	
15.	अनिल कुमार मौर्य, डॉ0	सोनभद्र	
16.	अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	
17.	अनिल कुमार सिंह, श्री	उन्नाव	
18.	अनिल पाराशर, श्री	अलीगढ़	
19.	अनुपमा जायसवाल, श्रीमती	बहराइच	
20.	अनुराग सिंह, श्री	मिर्जापुर	
21.	अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री	अलीगढ़	
22.	अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती	हाथरस	
23.	अभय सिंह, श्री	अयोध्या	
24.	अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री	कानपुर नगर	
25.	अमन गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी	
26.	अमरेश कुमार, श्री	लखनऊ	
27.	अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	
28.	अमित सिंह चौहान, डा0	अयोध्या	
29.	अमिताभ बाजपेई, श्री	कानपुर नगर	
30.	अरमान खान, श्री	लखनऊ	
31.	अरुण कुमार, डॉ0	बरेली	
32.	अर्चना पाण्डेय, श्रीमती	कन्नौज	
33.	अलका सिंह, श्रीमती	हरदोई	
34.	अवधेश सिंह, डॉ0	वाराणसी	
35.	अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री	चित्रकूट	
36.	अशरफ अली खान, श्री	शामली	
37.	अशोक कुमार, श्री	रायबरेली	
38.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर	
39.	असीम अरुण, श्री	कन्नौज	
40.	आकाश सक्सैना (हनी), श्री	रामपुर	
41.	आदित्यनाथ योगी, श्री	गोरखपुर	
42.	आनन्द कुमार यादव, श्री	बहराइच	
43.	आर0 के0 पटेल, डॉ0	जौनपुर	
44.	आर0 के0 वर्मा, डॉ0	प्रतापगढ़	
45.	आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़	
46.	आलमबदी, श्री	आजमगढ़	
47.	आशा मौर्य, श्रीमती	सीतापुर	
48.	आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री	हरदोई	
49.	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं	
50.	आशु मलिक, श्री	सहारनपुर	
51.	इकबाल महमूद, श्री	सम्भल	

52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
55. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
56. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
57. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
58. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
61. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
64. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
65. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
66. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
69. कैलाश, श्री चन्दौली
70. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
71. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
72. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
73. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
74. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
75. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
76. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
77. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
78. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
79. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
80. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
81. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
82. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
83. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
85. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
86. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
87. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
88. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
89. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
90. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
91. जयमंगल, श्री महराजगंज
92. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
93. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
94. जाहीद, श्री भदोही
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
96. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
97. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
98. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
99. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
100. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
101. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
102. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
103. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
104. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
105. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
106. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
107. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
108. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
109. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
110. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
111. दुधराम, श्री बस्ती
112. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
113. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
114. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
115. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर

116. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
118. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
119. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
120. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
121. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
122. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
123. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
124. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
127. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
128. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
129. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
130. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
131. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
132. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
133. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
134. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
135. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
136. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
137. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
138. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
139. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
140. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
143. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
144. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
145. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
146. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
147. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
152. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
153. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
156. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
157. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
158. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
159. बाबूराम, श्री पीलीभीत
160. बाबूलाल, श्री आगरा
161. बावन सिंह, श्री गोण्डा
162. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
163. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
164. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
165. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
166. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
167. बेदी, श्री गाजीपुर
168. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
169. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
170. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
171. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
172. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
173. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
174. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
175. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
176. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
177. मनीष रावत, श्री सीतापुर
178. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
179. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली

180. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
181. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
182. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
183. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
184. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
187. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
188. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
189. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
190. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
191. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
192. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
193. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
194. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
195. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
196. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
197. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
198. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
199. मेघश्याम, श्री मथुरा
200. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
201. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
202. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
203. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
204. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
205. योगेश धामा, श्री बागपत
206. योगेश वर्मा, श्री खीरी
207. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
208. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
211. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
212. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
213. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
214. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
215. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
216. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
220. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
221. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
222. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
223. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
224. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
225. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
226. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
227. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
228. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
229. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
230. राजमणि, श्री प्रयागराज
231. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
232. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
233. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
234. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
235. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
236. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
237. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
238. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
239. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
240. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
241. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
242. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
243. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
244. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर

245. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
246. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
247. रामकेश निषाद, श्री बांदा
248. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
249. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
250. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
251. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
252. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
253. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
254. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
255. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
256. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
257. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
258. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
259. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
260. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
261. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
262. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
263. लकी यादव, श्री जौनपुर
264. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
265. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
266. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
267. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
268. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
269. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
270. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
271. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
272. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
273. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
274. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
275. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
276. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
277. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
278. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
279. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
280. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
281. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
282. विपुल दुबे, श्री भदोही
283. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
284. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
285. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
286. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
287. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
288. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
289. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
290. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
291. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
292. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर
293. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
294. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
295. शशांक वर्मा, श्री खीरी
296. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
297. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
298. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
299. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
300. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
301. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
302. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
303. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
304. संग्राम सिंह, श्री बलिया
305. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
306. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
307. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
308. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र

309. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
310. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
311. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
312. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
313. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
314. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
315. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
316. सभाकुंवर, श्री देवरिया
317. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
318. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
319. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
320. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
321. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
322. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
323. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
324. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
325. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
326. सुधाकर सिंह, श्री मऊ
327. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
328. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
329. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
330. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
331. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
332. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
333. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
334. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
335. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
336. सुरेश राही, श्री सीतापुर
337. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
338. सुशान्त सिंह, कुँवर बिजनौर
339. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
340. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
341. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
342. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
343. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
344. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
345. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
346. स्वामी ओउ्मवेश, श्री बिजनौर
347. हंसु राम, श्री बलिया
348. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
349. हरिओम, श्री कासगंज
350. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
351. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
352. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
353. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
354. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
355. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप) एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:09] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डीजल के दामों में वृद्धि से किसानों को फसलों की सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्य हेतु सब्सिडी पर डीजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना

***1-श्री अभय सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल के दामों में वृद्धि से किसानों को फसलों की सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्य हेतु अत्यधिक धन वहन करने की समस्या के दृष्टिगत किसानों को कृषि कार्य हेतु सब्सिडी पर डीजल उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

किसानों को डीजल पर सब्सिडी दिये जाने की कोई कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा नहीं बनाई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, आपने हमें किसानों से जुड़ी समस्याओं पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। डीजल बहुत महंगा हो गया है और किसान डीजल का बहुत प्रयोग करता है। चाहे सिंचाई हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे थ्रेसर हो एवं अन्य संयंत्र भी डीजल से ही चलते हैं। हमारे अवध क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे-छोटे किसान हैं जिनके पास एक एकड़, डेढ़ एकड़ एवं पौना एकड़ की जमीनें हैं। हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि उनको खेतों की सिंचाई करनी होती है और जब वह सिंचाई करने के लिए बिजली विभाग में विद्युत कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र देते हैं, तो बिजली विभाग किसानों को सिंचाई के लिए कनेक्शन का इस्टीमेट कम-से-कम एक लाख से दो लाख रुपये का बनाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि किसान इन समस्याओं का निस्तारण कर्जा लेकर भी नहीं कर पाता है और सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आमदनी का दोगुना पैसा मिले। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या छोटे एवं गरीब किसानों को मुफ्त बोरिंग व सरकारी खर्च पर ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली कनेक्शन दिलाएंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने किसानों की समस्याओं को बिल्कुल दर-किनार करते हुए और बहुत कड़े शब्दों में लिख दिया कि हम किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे, कोई सुविधाएं नहीं देंगे। हमने अध्ययन किया है और हमने बजट को भी देखा है कि

उसमें पी0एम0 कुसुम योजना है। जिसमें सोलर पम्प की व्यवस्था की गयी है। सोलर पम्प की व्यवस्था दो एकड़ एवं उससे ऊपर वाले किसानों के लिए की गयी है, लेकिन छोटे एवं मझौले किसान जिनके पास एक एकड़, डेढ़ एकड़ एवं पौना एकड़ जमीन है उनके लिए सोलर पम्प की व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि जो पी0एम0 कुसुम योजना है, जिसमें सोलर पम्प के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी देकर किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना चाहते हैं। क्या उसकी व्यवस्था छोटे किसानों के लिए भी करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो पहला प्रश्न किया है वह आज के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मा0 सदस्य ने कहा है कि दो हेक्टेयर से ऊपर वाले किसानों को पी0एम0 कुसुम योजना का लाभ दिया जायेगा। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पी0एम0 कुसुम योजना के भीतर लघु, सीमान्त एवं सामान्य कृषक शामिल हैं। इसमें जोत की कोई पाबन्दी नहीं है। इसको आपने गलत ट्विस्ट कर दिया है। उसमें लिखा है कि दो हेक्टेयर तक के किसानों को प्राथमिकता देंगे। यदि किसान के पास 10 डिसमिल भी खेती है, तो वह किसान पी0एम0 कुसुम योजना का लाभ पाने का हकदार है। यह आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार 30 हजार सोलर पम्प खोले हुए है। हम 15-20 फरवरी के आस-पास में फिर 30 हजार सोलर पम्प खोलने वाले हैं। इस तरीके से इस वर्ष कम-से-कम 40 हजार सोलर पम्प लगायेंगे। हम लोग 48 हजार सोलर पम्प लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसीलिए बजट में गत वर्ष से दोगुनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आपने डीजल के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसी लोकप्रिय सरकार है जिसने अधिकांश राज्यों की तुलना में डीजल पर सबसे कम वैट लगाया है। जहां-जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता विपक्ष दौरा करने गये थे। वह कल कह रहे थे कि पी0डी0ए0 कहां है। जहां वह पी0डी0ए0 बनाने प0 बंगाल और तमिलनाडु गये थे, उनके वहाँ डीजल के क्या रेट हैं और उत्तर प्रदेश में क्या हालत है ? हमारी सरकार समावेशी सरकार है और हर किसान एवं नागरिक की चिन्ता करती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम वैट 12.76 प्रतिशत रखा गया है। हमारे डीजल का मूल्य 89.74 रुपये है, यह रेट दिनांक 24-01-2024 से चला आ रहा है। इससे पहले की बात पूछेंगे तो वह भी बता देंगे। वह पश्चिम बंगाल गये थे। पश्चिम बंगाल में 15.33 रुपये वैट है, हमारे यहां से लगभग 2.5 प्रतिशत वैट ज्यादा है। वहां पर 92.74 रुपये, हमारे यहां से 3 रुपये से ज्यादा डीजल का पश्चिम बंगाल सरकार लोगों से वैट वसूल रही है। उसके बाद वह चेन्नई गये। चेन्नई के भीतर 17.28 रुपये वैट है।

94 रुपये 22 पैसे चेन्नई में डीजल का रेट है, 04 रुपये 48 पैसा उत्तर प्रदेश से ज्यादा लिया जा रहा है। झारखंड में 94 रुपये 63 पैसे है, 04 रुपये 89 पैसे उत्तर प्रदेश से ज्यादा लिया जा रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इस पर एक अनुपूरक हम भी पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

पहले वे पूछ लें और जवाब आ जाये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

आंध्र प्रदेश के भीतर 21.66 प्रतिशत वैट है। आप कह रहे थे कि ये किसान विरोधी हैं, किसानों की चिन्ता नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा चिन्ता करने वाली यदि कोई सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम पूरी तरह से उनकी चिन्ता कर रहे हैं। यही वजह है कि आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद किसान शांति से है, कहीं आन्दोलित नहीं है, यह हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। धन्यवाद।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने मा0 मंत्री से यह नहीं पूछा कि बंगाल में किसानों की क्या स्थिति है और चेन्नई में क्या स्थिति है ? हमने इसमें सिर्फ दो चीजें पूछीं कि पी0एम0 कुसुम योजना है, जिसमें बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

उस पर तो उन्होंने कहा है कि 2 हेक्टेयर तक सबसे पहले लेंगे, उसके बाद प्वांइट डेसीबल भी हो तो भी देंगे। उसका जवाब दिया है।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, 2 हेक्टेयर में हमारे यहां 20 बीघा जमीन आती है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा है कि 2 हेक्टेयर से कम वालों को देंगे, ये नहीं कहा है कि 2 हेक्टेयर से ऊपर वालों को देंगे। यही जवाब आया है।

श्री अभय सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, 2 हेक्टेयर वालों को प्राथमिकता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

2 हेक्टेयर तक वालों को प्राथमिकता देंगे। 2 हेक्टेयर तक का मतलब है कि 2 हेक्टेयर से नीचे वालों को प्राथमिकता देंगे, ऊपर वालों को नहीं। मा0 मंत्री जी आपने यही कहा है न कि 02 हेक्टेयर तक वालों को पहले प्राथमिकता देंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मैंने यह कहा है कि किसी भी किसान के पास यदि 10 या 15 डेसीबल भी खेती है और मैंने ये कहा कि 02 हेक्टेयर के नीचे वालों को प्राथमिकता देंगे उसमें भी महिलाओं और अनुसूचित जातियों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। आप पी0डी0ए0 का शोर करते हैं, लेकिन

भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज की चिन्ता करती है और सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, इसलिए हमने सबकी चिन्ता किया है।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, किसान बिजली के लिये अप्लाई करता है तो क्या उसको सरकारी खर्च पर बिजली कनेक्शन दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

अब बिजली का जवाब कृषि मंत्री थोड़ी देंगे, वह आप बिजली मंत्री जी से पूछियेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक अनुपूरक हम भी पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आपने परमिशन दे दी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको कोई परमिशन नहीं दी है, जितनी आपको परमिशन दूंगा उतना ज्यादा आप कोपभाजन बनेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, लेकिन किसान का कोपभाजन तो नहीं बनेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल-कूद में प्रोत्साहन देने के लिए मिनी स्टेडियम बनाने विषयक

***2-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेल-कूद में प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तों क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण की योजना संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी ने बहुत बुद्धिमानी से मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया है। ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया है। बिना किसी भूमिका के मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार है, मेरे विधान सभा क्षेत्र-23, चांदपुर, जनपद बिजनौर में तीन विकास खण्ड-हल्दौर, नूरपुर व जलीलपुर आते हैं। विकास खण्ड हल्दौर के गांव-गांगू नगला, नूरपुर विकास खण्ड के गांव-मुराहर व जलीलपुर विकास खण्ड के गांव-पीपलसाना में स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध है। मैं अपने बहुत ही सम्मानित विद्वान मा0 युवा कल्याण मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि मेरे बताये गये तीनों विकास खण्डों के तीनों गांवों में तीन स्टेडियम बनाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? दूसरा, मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि नौजवान स्टेडियम में दौड़ लगाया करेंगे, कबड्डी खेला करेंगे, कुश्ती लड़ा करेंगे, वॉलीबॉल खेला करेंगे, फुटबॉल खेला करेंगे, गोला फेंका करेंगे, भाला फेंका करेंगे, ऊँची कूद, लम्बी कूद लगाया करेंगे आदि खेल खेला करेंगे। उनको आगे बढ़ाने के लिए एक सिखाने वाला कोच प्रत्येक स्टेडियम में अवश्य रखना पड़ेगा। मैं अपने विद्वान मा0 मंत्री से पूछना चाहूंगा कि प्रत्येक स्टेडियम में एक-एक कोच को नियुक्त करने पर विचार करेंगे ? जवाब देने से पहले मैं मा0 मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं।

आपका संरक्षण चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी। माननीय युवा कल्याण मंत्री महोदय जवाब देने से पूर्व स्वामी ओउ्मवेश आपसे विनती करता है।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ मक्खन लगाने से कभी आपको कोई फायदा हुआ है ?

(हँसी)

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मैं साधु हूँ, साधु को भिक्षा देने पर पुण्य मिलता है। मैने लोक निर्माण मंत्री जी से माँगी थी सड़क, चाँदपुर से बास्टा तक का चौड़ीकरण, उन्होंने तत्काल दे दी। मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया था, तत्काल निर्देशित कर दिया। मैंने जल शक्ति मंत्री जी से माँगा था, जहानाबाद से नारगौर तक तटबन्ध, स्वीकृत कर दिया, मेरे पास जवाब आ गया है, सर्वेक्षण करा लिया गया है। यह मेरे पास लिखित रूप में आ गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैंने पल्ला फैलाकर माँगा था, तटबन्ध, तुरन्त दे दिया। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। डेंगू आने पर उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अपने बड़ों का अनुसरण करने से पुण्य मिलता है। अतः मेरे कमण्डल को खाली न रहने देना, मेरा कमण्डल भर देना, माननीय युवा कल्याण मंत्री जी, धन्यवाद।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इसका उत्तर दिया है। हमने जो जवाब दिया है, शासनादेश 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, इस सरकार ने खेलों के ऊपर सबसे ज्यादा रुचि भी दिखायी है और उसी हिसाब से बजट में प्रॉविजन भी किया गया है और पहली बार उत्तर प्रदेश में 62 करोड़ रुपया बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलम्पिक में या एशियन गेम्स में या कॉमन वेल्थ गेम्स में पदक जीते हैं, उनको पुरस्कृत करने और खासकर उनको सेवायोजित करने का काम किया है। मान्यवर, इसमें जो व्यवस्था है, उसमें यह है कि पहले हम उनको प्राथमिकता देंगे, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में एक भी शासकीय स्टेडियम नहीं है। मान्यवर, ऐसे 07 जनपद हैं। कुल तो ऐसे 20 जनपद हैं, उसमें 07 जनपद ऐसे हैं, जिनको हम प्राथमिकता देने जा रहे हैं। यह हम आपको बता दें, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, देवरिया, चन्दौली, श्रावस्ती, फतेहपुर, इटावा, औरैया, झाँसी, चित्रकूट, महोबा, हापुड़, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर। यह इतने जिले हैं जहाँ पर एक भी शासकीय स्टेडियम नहीं है। तो हमने यह व्यवस्था की है कि पहले 07 जनपद, जिस प्रकार से हमारी बजट व्यवस्था है, उसके हिसाब से पहले 07 जनपद ले रहे हैं और यह जनपद हैं-झाँसी, चित्रकूट, सन्तकबीरनगर, फतेहपुर, चन्दौली, सहारनपुर और सिद्धार्थनगर। मान्यवर, आपके जनपद में अभी एक स्टेडियम है, इस वजह से इसको ले तो लेंगे, लेकिन बाद में ही लेंगे, हम आपका कमण्डल खाली नहीं रखेंगे, यह हम आपको बताये दे रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, उसकी जानकारी दे दी। अभी तक जो व्यवस्था है मान्यवर हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्रों में 124 स्टेडियम हैं और यह 124 स्टेडियम फँक्शनल हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न था, कोच रखने के सम्बन्ध में, यह सही है कि कोच के माध्यम से हम बेहतर खिलाड़ी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ग्रामीण स्तर के ऊपर कोच रखने की जो हमारी व्यवस्था है, वह अभी लागू नहीं हो पायी है। लेकिन नेशनल लेविल के ऊपर और प्रदेश लेविल के ऊपर कोच रखने की व्यवस्था के लिए हमने बजट में भी खासतौर से प्रॉविजन किया है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में अध्ययनरत् खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय डेढ़ लाख रुपये प्रति माह पर प्रशिक्षण हेतु आबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। अभी उच्च स्तर पर कोच की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपकी बात का संज्ञान ले लिया है और जैसी ही परिस्थिति बनेगी वैसे ही उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन मान्यवर, आपका कमण्डल खाली नहीं रखेंगे, यह हम आपसे बता रहे हैं।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मोहम्मद शमी जो मेरे क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, उसने वर्ल्ड कप भी खेला है तथा मा0 मुख्य मंत्री जी जुलाई में घोषणा भी कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसके ऊपर काम तो हो रहा है।

श्री महबूब अली-

मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था स्टेडियम के लिए, मा0 मंत्री जी ने कहा कि वहां पर रिक्त स्थान है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अन्दर केवल एक कोच है।

श्री अध्यक्ष-

वह भी तो बता रहे हैं कि पूरे पचास की व्यवस्था की गई है।

श्री महबूब अली-

जब अमरोहा में बनाने की घोषणा की बात है, तो आज उस लिस्ट में भी नहीं है, जो मा0 मंत्री जी ने पढ़ी है। मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी उन जनपदों के अन्दर स्टेडियम बनाने की बात नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 2022 व 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगवार व निवेशकवार कुल निवेश तथा निवेशित उद्योगो में कार्य की प्रगति का विवरण

***3-श्री सचिन यादव तथा डॉ0 रागिनी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल कितनी धनराशि के निवेश उद्योगवार व निवेशकवार प्राप्त हुए ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2022 में हुई इन्वेस्टर समिट में प्राप्त निवेश से कितने निवेशित उद्योगों में कार्य का पूर्ण रूप से संचालन प्रारम्भ हो चुका है एवं शेष में क्या प्रगति है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

प्रदेश सरकार द्वारा वृहद् औद्योगिक निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' का आयोजन कराया गया, इस दौरान कुल रुपये 33,50,000.00 (रु0 तैंतीस लाख पचास हजार करोड़) निवेश के 19,058 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन नहीं किया गया था, अपितु वर्ष 2018 में आयोजित 'इन्वेस्टर्स समिट-2018' के परिप्रेक्ष्य में तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग

समारोह का आयोजन माह जून, 2022 में किया गया, जिसमें प्राप्त कुल 1406 निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष 536 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 870 औद्योगिक इकाइयां धरातल पर कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

सम्बन्धित विवरण की 20 प्रतियां[†] सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर था और मैं मा0 मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और आज यहां पर मा0 मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद आज वह कहीं बिजी हैं, लेकिन रात में उन्होंने छः सौ पेजों का जवाब भेजा हुआ है। मैं उनके डिटेल्ड जवाब के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डिटेल्ड जवाब दिया। सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो हालत है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल आदरणीय नेता सदन जी बात कर रहे थे कि अगले महीने दस लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है, उसका भूमि पूजन चालू करेंगे, लेकिन अखबारों में कुछ अलग तस्वीर नजर आती है।

श्री अध्यक्ष-

अखबार का संज्ञान नहीं लिया जा सकता, आप अपनी बात कहिए।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सारे जो विभाग हैं उनको आदेश दिया है कि इसकी तैयारी करें, लेकिन स्थिति यह है कि जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको जमीन नहीं मिल पा रही और जो उद्योग लगाना चाह रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में उनके लिए जमीन नहीं है, प्राईवेट जो जमीन है वह महंगी है और अगर महंगी जमीन खरीदने जाते हैं, तो महंगी जमीन के आस-पास इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो जो इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर उद्योग बाहर से आएंगे या उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो हो सकता है कि टैक्स कलेक्शन रेवन्यू हमारा बढ़े और साथ में नौजवानों को भी रोजगार मिले, लेकिन उस पर भी काम होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत ही नहीं हुई। सरकार के पास जो रिकॉर्ड है वह मैं बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में जो एम0ओ0यू0 साइन हुए थे, वह वर्ष 2018 में टोटल 81 हुए थे और वर्ष 2019 में 290 हुए जो जवाब में लिखा हुआ है और वर्ष 2022 में 1406 हुए, लेकिन इम्प्लीमेन्टेशन देखा जाएगा जो आपके ही उत्तर में आया है तो 25 परसेण्ट इम्प्लीमेन्टेशन ड्रॉप हो गया और 75 परसेण्ट दिखा रहे हैं कि कमिटमेन्ट है, अगर इसी तरह से ग्रोथ दिखाते रहेंगे कागजों में जो इस बार इन्होंने 235 परसेण्ट ग्रोथ बताई है कागजों में अगर उसी ग्रोथ को मान लिया जाए और ड्रॉप प्रोजेक्ट को भी उसी परसेण्टेज से

[†] छापी नहीं गई।

मान लिया जाए तो शायद दस परसेण्ट भी जमीन पर नहीं उतर पाएंगे, यह स्थिति है आप ही के जवाब के अनुसार तो मेरा जो अनुपूरक है, क्योंकि मेरे ही साथ डॉ0 रागिनी जी का भी यही प्रश्न है, तो मैं तीनों अनुपूरक पर आता हूँ और मैं आपसे यह संरक्षण चाहता हूँ कि अनुपूरक का जवाब स्टेट फॉरवर्ड मिल जाए, घुमा-फिरा के जवाब न मिले।

श्री अध्यक्ष-

यह जवाब तो मंत्री जी को देना है।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, संरक्षण तो आपसे ही चाहिए होगा।

श्री अध्यक्ष-

मैं दूंगा।

श्री सचिन यादव-

महोदय, मेरा जो पहला अनुपूरक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य नौजवानों को रोजगार देने का है, तो क्या हम एक ऐसा सेण्ट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर जो उद्योग हमारे यहां की जनता के पैसों से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो यह जो उद्योग लगने वाले हैं, वह रोजगार के लिए सेण्ट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनेगा।

जहाँ पर उन उद्योगों से जो रोजगार मिल रहा है उनके वहाँ पर रिकार्ड्स रहें, जिससे हम लोगों को असलियत पता चल जाए कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अगर ऐसा प्लेटफार्म बनाएंगे तो कब तक, यदि नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं ? दूसरा जो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो जाते हैं आप देखेंगे कि जो जवाब आया है उसमें 5 साल पुराने प्रोजेक्टों को ड्रॉप दिखाया जा रहा है। 5 साल तक यदि प्रोजेक्ट के ड्रॉप होने का इन्तजार कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका इम्प्लीमेन्टेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या ड्रॉप क्राइटेरिया को आप प्रॉपर बनाएंगे, जिससे जो कम्पनीज एम0ओ0यू0 साइन कर देते हैं और उसके बाद वह प्रोजेक्ट नहीं लगाते हैं तो उस पर जल्दी से ड्रॉप कार्रवाई हो जाए। अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया बनाएंगे तो कब तक और यदि नहीं बनाएंगे तो क्यों नहीं ? तीसरा और आखिरी अनुपूरक मेरा है चाहे उसका जवाब अभी नहीं हो तो बाद में डिटेल में हम लोगों को भिजवा दिया जाए कि जो 19000 एम0ओ0यू0 साइन किये हैं 33 लाख करोड़ के उनमें से कौन सी वह कम्पनीज हैं जो यू0पी0 में पहले से चल रही हैं और एक्सटेंशन लिया हुआ है, ऐसी कितनी कम्पनियाँ हैं और यू0पी0 के बाहर से या देश के बाहर से पहली बार जो कम्पनीज आई हैं उसका बायफरकेशन यदि हम लोगों को बता दें तो हम लोगों को असलियत पता चलेगी कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सक्सेसफुल था या नहीं था।

(मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर देने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या मंत्री जी नहीं हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मेरा यह निवेदन है कि मा0 खेल मंत्री जी भी नहीं थे, मा0 उद्योग मंत्री भी नहीं हैं। अगर सम्बन्धित विभागीय मंत्री जी स्वयं अपने विभाग के प्रश्न का जवाब दें तो मुझे लगता है कि प्रभावी ढंग से दे सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर हम समझ सकते हैं कि सारे विभागों का दवाब होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उद्योग मंत्री जी आज उपस्थित नहीं हैं। उनके बेटे की तबियत कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

कोई बात नहीं, ठीक है। यदि ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं तो कोई बात नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्तमान योगी सरकार ने बड़े ही पवित्र भावना से यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट किया था और पहले इन्वेस्टर्स समिट में 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये के एम0ओ0यू0 हुए थे और उसमें उसकी जो ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, उसका जिक्र हमने अपने उत्तर के दूसरे पार्ट में किया है। मा0 सदस्य ने अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट में यह पूछा है कि क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2022 में हुई इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश से कितने निवेशित उद्योगों में कार्य का पूर्ण रूप से संचालन प्रारम्भ हो चुका है, तो मैं आपको बता दूँ कि वर्ष 2022 में कोई इन्वेस्टर्स समिट नहीं हुआ था वर्ष 2022 में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, लेकिन अभी तक जो स्थिति है हमने तीन ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की है-ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी-1, ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 और ग्राउण्ड बेकिंग सेरेमनी 3 इन तीनों सेरेमनी में मिलाकर 859 उद्योग हमारे जमीन पर उतरे हैं और मान्यवर, जहाँ से आप आते हैं वहाँ भी दो उद्योग जमीन पर उतरे हैं। आपको नाम बता दें ये है मेसर्स अतुल इंडस्ट्रीज और दूसरा मेसर्स सन ग्लास वर्क्स हैं। मेसर्स अतुल इण्डस्ट्रीज में 60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट और मेसर्स सन ग्लास वर्क्स जो कि हाई क्वालिटी ग्लास को बनाने के लिए लगी है इनका 45 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है जो कि जमीन पर उतरा है आपके फिरोजाबाद क्षेत्र में। दूसरी बात मान्यवर, इन 859 का जो ब्रेकअप है वह यह है जैसा कि इन्होंने अपने प्रश्न के दूसरे पार्ट में पूछा है इसमें 536 यूनिटों पर काम शुरू हो गया है और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिला है। ये 859 परियोजनाएँ 1 लाख 29 हजार 372 करोड़ की जमीन पर उतर चुकी हैं और आज की तारीख में फंक्शनल हैं। इसकी सूची हम आपको भेज दे रहे हैं। मान्यवर, हमने इतनी तैयारी किसी प्रश्न में शायद आज तक नहीं की होगी जितनी इसमें की है। 19000 एम0ओ0यू0 का विवरण हमने इनको दिया। हम इसे विस्तीर्णता के आधार पर खारिज करा सकते थे। अगर आपसे अनुरोध करते तो शायद आप खारिज कर देते। इसमें

हमने पूरे 19000 एम0ओ0यू0 दाखिल किए। हमने सोचा बहुत बार इसमें सवाल उठ चुका है जवाब जरूर देंगे। यह अपने आप में इस बात का द्योतक है कि हम न इस बात को छुपाना चाहते हैं और न ही हम आपको भटकाना चाहते हैं। सरकार की मंशा हर स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने की है रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा पैदा हों यह सरकार की मंशा है इसी निमित्त यह ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है।

अभी इस बार भी टेंटेटिव डेट 19 तारीख दी गयी है। फिर से जितने एम0ओ0यू0 हुए हैं, उसकी ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। तो आप ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपके ही जनपद में 4 स्थानों पर जो पेण्डिंग है, जो अभी तक प्रक्रियाधीन है, वह मिलने जा रही है। श्री विकास बंसल सन ऑफ श्री जयद्रथ बंसल, फिरोजाबाद, इनकी एक इण्डस्ट्री है, जो प्रक्रियाधीन है। श्री बाल कृष्ण अग्रवाल, ग्लास इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, फिरोजाबाद, यह 30 करोड़ की लागत से प्रक्रियाधीन है। श्री एफ0एस0 यूनिवर्सिटी, फिरोजाबाद, 15 करोड़ रुपये की लागत से यह प्रकियाधीन है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इसमें अभी तक 3 लाख 31 हजार 767 लोगों का यह रोजगार सृजित हुआ। सारे के सारे लोग इस समय इम्पलाईज़ हैं आज की तारीख में, आप चाहे जब पता कर लेना। कुल मिलाकर सरकार की मंशा पर सवाल मत खड़ा करिए और हर तरह से सरकार यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेण्ट आये। हमने ऐसी भी पॉलिसीज़ बनायी हैं। 20 सेक्टोरल पॉलिसी अलग से बनायी है। आज तक फॉर्चून 500 की पॉलिसी किसी स्टेट के पास नहीं है। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट की पॉलिसी की है। आप तो 10-12 साल विदेश में रहे हैं, आपको अच्छी जानकारी है, इसलिए हम आपसे यह बात कह रहे हैं वरना शायद आपसे कहते भी नहीं। इसलिए कि आप समझदार हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर आये हैं हालांकि जीते 1 ही हजार वोट से हो लेकिन अच्छी बात है।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे गुरू द्रोणाचार्य हैं, हम उनके एकलव्य है। हम उनको गुरू ही मानते हैं लेकिन मैंने जो तीनों अनुपूरक किये और तीनों अनुपूरक पर मैंने मंशा पर सवाल नहीं उठाया था, मैंने इम्प्लीमेण्टेशन पर सवाल उठाया था। रोजगार पर सवाल उठाया था कि आप जो रोजगार का वायदा कर रहे हैं, मैंने पूछा कि कहीं सेण्ट्रलाइज़ प्लेटफार्म बनाएंगे, जहां पर रोजगार को आप मॉनीटर कर सकें कि हमें सचमुच से रोजगार से फायदा मिल रहा है। ड्रॉप क्रायटेरिया पर मैंने पूछा था कि क्या उस पर सरकार कोई कदम उठाएगी ? तीसरा जो हमारे फिरोजाबाद जिले की बात करें तो जो भी इण्डस्ट्री लगी है या लगने वाली हैं, जो पहले से ही संचालित है, नयी नहीं आयी उन्होंने अपना एक्सटेंशन किया है तो उसमें सरकार का कितना योगदान है या नहीं है वह एक अलग डिबेट का विषय है। मैंने इसीलिए अपना तीसरा अनुपूरक पूछा कि पहली बार कौन सी इण्डस्ट्री आयी क्योंकि

फिरोजाबाद में पहली बार कोई नयी इण्डस्ट्री बाहर से आयी नहीं। मुझे तीनों अनुपूरक का जवाब नहीं मिल पाया, मंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

डॉ0 रागिनी।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सचिन जी ने कहा कि मैं एकलव्य हूँ, वह एकलव्य का अंगूठा लिया था, यह पूरा हाथ ले लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनका हाथ हमारे पक्ष में उठे, हम इसका स्वागत करेंगे।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। सर्वप्रथम बहुत ही हर्ष के साथ यह कहना चाहूंगी कि श्री सचिन यादव और उनके जैसे कई हजारों-लाखों युवा इस देश का गौरव हैं क्योंकि यह वह युवा हैं जिन्होंने अमेरिका और उसके जैसे जो भी विकसित देश हैं, वहां की करोड़ों की नौकरियों को ठुकराया और आज अपने देश के उत्थान के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। यह वह युवा हैं जो आज देश और प्रदेश की राजनीति को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इन कागजी विकासों को देख-देख कर हताश भी हो रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस क्वेश्चन को वह रिजेक्ट भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने काफी मेहनत करके हमारे प्रश्नों के उत्तर को तैयार किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप पिछला रिकार्ड दिखवा लें कि आज तक 600 पेज का उत्तर कभी आया हो।

डॉ0 रागिनी-

जी बिल्कुल मा0 मंत्री जी। मैं अपने प्रश्न पर आऊँगी। मेरा पहला प्रश्न यह है कि अभी तक का विगत 5 वर्षों में अपने प्रदेश का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है ? और साथ-ही-साथ आज इस रेट पर हमारे प्रदेश का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ इण्डेक्स क्या है और इस इण्डस्ट्रियल ग्रोथ रेट के हिसाब से आप जो वन ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करते हैं, आप कितने सालों में अपने प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं? यह मेरा पहला सवाल है, मेरा दूसरा सवाल यह है माननीय मंत्री जी आपने आंकड़ों की बात की, जो पहला इंवेस्टर्स समिट मीट रहा उसमें लगभग साढ़े चार लाख करोड़ के लगभग 1400 एम0ओ0यू0 साईन हुए और आज 6 वर्षों में उसका 40 परसेंट सिर्फ और सिर्फ शुरू हो पाया है, खत्म भी नहीं हुआ है। उस हिसाब से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मीट है उसमें प्रीवियस एम0ओ0यू0 के

कम्पेरेजिन में 10 गुना एम0ओ0यूज0 साईन हुए हैं, साढ़े 35 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 साईन हुए हैं। जब आप विगत 6 वर्षों में 2 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 को आज धरातल पर खत्म नहीं कर पाये है। अध्यक्ष महोदय, आजादी को आज 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसको पहुंचाने में तो मुझे लगता है 150-200 साल लग जायेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि यह जो दूसरा इन्वेस्टर्स समिट ग्लोबल मीट हुआ है उसके कार्यों को आप क्या मापते हैं कि कब तक इसको फिनिश करके देंगे और तीसरा सवाल क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउण्ड से हूँ तो मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि जो आपका पहला इंवेस्टर्स समिट मीट हुआ उससे आज धरातल पर इस प्रजेन्ट समय में कितने मेडिकल रिलटेड काम हैं जो पूरी तरीके से किये जा चुके हैं और आज हम प्रत्यक्ष तरीके से उसको सामने देख सकते हैं। बहुत-बहुत आभार अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पहले सवाल में वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी की बात कही। इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की बात कही, यह वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी जो आज है, जब 2017-18 में हमारी सरकार आयी थी, उस समय हमारा एक्सपोर्ट मात्र 88000 करोड़ रुपये था। यह रिकार्डेड फैक्ट है और आज हमारा एक्सपोर्ट लगभग 200000 करोड़ रुपये है। यह अपने आपमें हमारी आर्थिक स्थिति की स्ट्रैन्थ शो करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है? उस समय हमारी आमदनी पर कैपिटा इनकम 52000 रुपये थे आज हमारी आमदनी पर कैपिटा इनकम 83000 रुपये से ज्यादा है, ये रिकार्डेड है। इस आंकड़े को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये अपने आपमें यह बताता है कि जो आर्थिक स्थिति लगातार नीचे की तरफ जा रही थी उसे अब हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि इस स्पीड से बढ़ें, देखिये अगर कोई आदमी 20 रुपये का घड़ा खरीदता है तो वह 4 बार ठोकता है तो जो लोग 100, 200, 500 और 1000 करोड़ रुपये लगाने आते हैं वो भी हर तरीके से उस चीज को तौलते हैं और एक-एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में 3-3 साल लगते हैं। हमने जो ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले 2019 में की, फिर उसके बाद 2020 में की फिर उसके बाद 2022 में की। हमारी मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप उसके ऊपर संदेह करें। वर्तमान में इस समय हमारी 894 योजनाएं ऐसी हैं जो 67623 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है और आज की तारीख में प्रक्रियाधीन हैं। हम आपको उसकी भी सूची दे सकते हैं लेकिन इस वक्त नहीं दे सकते। ये अपने आप में यह शो करता है कि जिन लोगों ने एम0ओ0यू0 किये उसमें से 536 योजनाएं तो जमीन पर उतर आयीं, उसमें प्रोडेक्शन चालू है और 894 योजनाएं ऐसी हैं जो इस समय प्रक्रियाधीन है। आपके कई सवालों के जवाब में यह काफी होता है। मान्यवर, इसलिए किसी प्रकार की इन्हें शंका नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध भी है कि वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश बनायेंगे और आज चाहे 2022-23 की हमारी ए0जी0 की रिपोर्ट देख लें कि आज तक इतनी अच्छी रिपोर्ट पिछले

15 साल में नहीं आयी जितनी अच्छी रिपोर्ट 2022-23 की आयी है। आप तो बहुत पढ़ी-लिखी हैं हमारी 2022-23 की ए0जी0 की रिपोर्ट देख लीजिये कि क्या स्थिति है इसलिए शंका मत कीजिये। जो आपने पूछा है उसे हम आपको भेज भी देंगे।

डॉ0 रागिनी-

अध्यक्ष महोदय, मैं बस आखिरी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि बार-बार ये सरकार वह खरगोश क्यों बनना चाहती है जो यह देखता है कि हमने पीछे किसे छोड़ दिया यह सरकार वह क्यों नहीं बनना चाहती है जो यह देखे कि आज पर कैपिटा इनकम की अगर बात हो तो विकसित देशों से हमारा पर कैपिटा इनकम कितना पीछे है और हम किस तरीके से विकसित बन सकते हैं, उसकी तरफ यह सरकार क्यों नहीं देखती है? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन यह था कि आज अपने प्रदेश का हेल्थ सिस्टम सबसे कमजोर है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कोई ऐसा काम आज धरातल पर हो चुका है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। यह मेरा आखिरी सवाल है और मंत्री जी से निवेदन है कि इसका जवाब जरूर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

डब्ल्यू0एच0ओ0 की रिपोर्ट को तो पढ़ लीजिये और एन0एम0सी0 की रिपोर्ट देख लीजिये।

डॉ0 रागिनी-

एन0एम0सी0 में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी काम जो किया गया हो इन्वेस्टर्स समिट मीट के अन्तर्गत बस उसे बता दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इन्वेस्टमेन्ट समिट मीट में उनका भी एम0ओ0यू0 है। आपने अगर उसे देखा होता तो शायद ये सवाल नहीं करती। जो एम0ओ0यू0 हैं उसे आप देख लीजिये। उसमें मेडिकल इक्विपमेन्ट्स बनाने के लिए भी है और हर प्रकार से मेडिकल फैसल्टी को आगे बढ़ा रही है। आप उसे देखिये, हम निकलवाकर आपको भिजवा देंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

हम सिद्धार्थनगर जिले से आते हैं, वह उद्योग शून्य जिला है। हमारे जिले में भी एम0ओ0यू0 हुए थे तो क्या इस ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में उनमें से भी कोई है जिसके कारण सिद्धार्थनगर में भी उद्योग लग जाये। यदि ऐसी कोई सूचना हो तो बताने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस समय जहां पर ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, क्षमा करेंगे कि इस समय मेरे पास वो सूची नहीं है क्योंकि वह सूची अभी बन रही है लेकिन यह हम आपको पता करके बतला देंगे, भिजवा देंगे।

प्रदेश में निवसित कोल आदिवासियों को अन्य प्रदेशों की भांति अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाये जाने की मांग

***4-श्री अनिल प्रधान-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवासित कोल आदिवासियों को अन्य प्रदेशों की भांति अनुसूचित जनजाति का दर्जा सरकार प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री असीम अरुण)-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम-1976 में उ0प्र0 अनुसूची के क्रमांक-49 पर कोल जाति अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध है।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में शोध संस्थान द्वारा 'कोल' अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं नृजातीय सर्वेक्षण अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि इस जाति में आदिम प्रवृत्ति, भिन्न संस्कृति एवं अन्य समुदायों से सम्पर्क में संकोच, भौगोलिक अलगाव पिछड़ेपन के संकेत चिन्ह विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में कोल जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है की संस्तुति की गयी थी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07-01-2022 द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुये नये प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुसूचित जाति श्रेणी से अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने सम्बन्धी ऐसे प्रकरणों में निर्धारित सम्प्रति संवैधानिक व्यवस्थानुसार/प्रक्रियानुसार भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार

श्री अनिल प्रधान-

धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने समाज के अन्तिम पायदान पर बैठे कोल आदिवासियों के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का मुझे मौका दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, प्रयागराज समेत कई जिलों में लगभग साढ़े सात लाख की आबादी कोल आदिवासियों की है और यह सभी जानते हैं कि वह आदिकाल से आदिवासी हैं। भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा 1965 में बनी बी0एन0 लोकुर की कमेटी ने भी कोल जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। जनजाति की सूची में इन्हें

सम्मिलित न करने के कारण इनका सामाजिक और आर्थिक न्याय के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा। वन अधिकार कानून, 2008 के तहत जो अधिकार हैं उनका भी पालन नहीं हो पा रहा है और इनको अपनी पुश्तैनी भूमि पर अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, 2013-14 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। पिछले साल जो सदन हुआ था उसमें भी यह प्रश्न सदन में आया था, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 2013-14 वाला प्रस्ताव 07-01-2022 को सेन्ट्रल गवर्मेंट द्वारा निरस्त किया जा चुका है। चूंकि पिछली बार जब क्वेश्चन था तब इसका जवाब नहीं आया था। मेरा पहला अनुपूरक यह है कि जो 07-01-2022 को सेन्ट्रल गवर्मेंट ने जिन बातों का जिक्र करके इस प्रस्ताव को निरस्त करने का काम किया है। जो निरस्त-पत्र है उसके बिन्दु संख्या-3 में यह अंकित है कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः कोल जाति के सन्दर्भ में पूर्ण अध्ययन संचालित करते हुए अतिरिक्त जानकारी के साथ प्रस्ताव मांगा है। 2 साल हो गया परन्तु अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेन्ट्रल गवर्मेंट को प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो मेरा पहला अनुपूरक यह है कि क्या माननीय मंत्री जी सदन में इस बात को बताने का कष्ट करेंगे कि पुनः जो जानकारी उनके द्वारा मांगी गयी थी, उसको ऐड करके प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा और अगर भेजा जायेगा तो कब तक भेजा जायेगा। मेरा जो दूसरा अनुपूरक यह है कि कोल जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने के लिए विधिक, विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए और भारत सरकार से इसकी प्रबल पैरवी करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है और अगर तैयार है तो कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है? जो दूसरे प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेश उनमें इन्हें एस0टी0 का दर्जा मिला हुआ है, मेरे दो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, जिन्हें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री असीम अरुण-

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए भारत के पार्लियामेंट को ही अधिकार है। एक बिंदी भी इधर से उधर करने का अधिकार राज्य सरकार को इसमें नहीं है। इसीलिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय जाते हैं और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है यदि उचित पाया जाता है तो माननीय लोक सभा, राज्य सभा, माननीय राष्ट्रपति जी की पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद उसे किया जाता है। सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है और कुछ समुदायों की विशेषतया ऐसी समस्याएं थीं, जैसे गौड़ समाज के चार जिले ऐसे हैं जहां पर उनको एस0टी0 का दर्जा नहीं था। हम लोग उसको दिलाने में सफल हुए और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और फायदा पहुंचा है। अब कोल समुदाय की बात करें तो कोल समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में उत्तर प्रदेश में परिभाषित है, यह संविधान की अनुसूची में ही परिभाषित है। अन्य कई राज्यों में

जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के रूप में भी परिभाषित है तो अभी तक कुल सात बार अध्ययन के बाद केन्द्र सरकार में यह प्रस्ताव भेजा गया और सातों बार यह प्रस्ताव वापस लौट आया। इस बार जब लौट करके आया तो मैंने इसका गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि जो विषय मांगे जाते हैं, जैसे कि 4 प्रमुख विषय हैं इसमें आदिम प्रवृत्ति होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, सम्पर्क में संकोच होना चाहिए। भौगोलिक अलगाव की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम इसका बहुत गहन अध्ययन करा रहे हैं जिससे कि अगर ये विशिष्टताएं पायी जाती है तो हम लोग एक ऐसा प्रस्ताव भेजें जो सातों बार की तरह लौट करके न आये और वो पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाय तो स्वीकृत होकर आये।

श्री अनिल प्रधान-

2013-14 में समाजवादी सरकार में प्रस्ताव गया और 2017-22 के बीच में आपकी सरकार थी तो पाँच साल में इन्होंने पैरवी नहीं की। दूसरी चीज मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल का समय हो गया उसको वापस आये हुए इन 02 सालों में प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किया। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जो सूचना भारत सरकार से मांगी गयी है, उन सूचनाओं को पूर्ण करके आप भारत सरकार को प्रस्ताव कब भेजेंगे और उसको स्वीकृत कराने के लिए डबल इंजन की सरकार क्या काम करेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री असीम अरुण-

मान्यवर, इसके लिए एक अनुसंधान केन्द्र की व्यवस्था की गयी है जो बहुत गहनता के साथ इसका परीक्षण करता है क्योंकि 7 बार यह लौट आया है। हम यह मानें कि हमारे अध्ययन में कुछ कमी थी जिसकी वजह से यह स्वीकार नहीं हुआ, इसे हम फिर जल्दी से भेज दें और फिर वह आठवीं बार लौट आये तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी। उसका बहुत गहन अध्ययन होता है।

श्री अनिल प्रधान-

उसको भेजने में कितना समय लगेगा। 02 साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह सारी जानकारी करके भेजेंगे। उसके लिए समय निर्धारित नहीं हो सकता है। विषय यह है कि यह पहले गया था और अस्वीकार हो गया। इसे आधा-अधूरा सिर्फ पोलिटिकल कारण से नहीं भेजना है कि वहां भेज दिया और बता दें उसको करवाना चाहते हैं इसीलिए उसके ऊपर पूरा अध्ययन करके सारे बिंदु उसके ऊपर समायोजित करके भेजना चाहते हैं मंत्री जी ने ऐसा कहा। वह गम्भीरता से उसको भेजना चाहते हैं ताकि वहां पर स्वीकार हो जाय। इसका उत्तर आ गया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों हेतु अंक प्रतिशत के आधार को समाप्त कर आय सीमा को आधार मानकर शुल्क प्रतिपूर्ति कराये जाने विषयक

***5-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के पात्रता हेतु अंक प्रतिशत एवं अल्प आय सीमा के आधार पर निर्धारित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त संस्थानों में छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अंक प्रतिशत का आधार समाप्त कर आय सीमा का आधार मान कर सुनिश्चित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

जी नहीं।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना बजट आधारित फण्ड एडेड योजना है, जिसके अन्तर्गत पात्र छात्रों को उपलब्ध बजट की सीमा में वरीयता श्रेणी के आधार पर धनराशि भुगतान की जाती है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण पाठ्यक्रमों में उच्च अंक प्रतिशत पाने वाले समस्त पात्र छात्रों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से अंक प्रतिशत निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत माता-पिता की आय सीमा रु0 2.00 लाख वार्षिक निर्धारित है। उक्त सीमा के अन्तर्गत समस्त पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को लाभान्वित किया जाता है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 2.00 लाख (रुपये दो लाख) तक अथवा उससे कम है, को ही नियमावली में निर्धारित वरीयता के अनुसार लाभान्वित किया जाता है। छात्रों को उनके गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत की मेरिट के आधार पर लागू भुगतान की व्यवस्था के कारण योजना में पारदर्शिता बनी रहती है तथा मेधावी छात्रों को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी करोड़ों-करोड़ नौजवान बच्चों से जुड़ा मेरा प्रश्न है जो दशमोत्तर या उससे उच्च शिक्षण संस्थानों, तकनीकी, व्यवसायिक, मेडिकल एवं पैरामेडिकल सहित विभिन्न जगहों पर अध्ययनरत् है। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि जो

गरीब, अल्प आय वर्ग के लोग, न्यूनतम आय वर्ग, लो इनकम वाले लोग हैं सरकार उनके लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की व्यवस्था करें। मान्यवर, पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार में सामान्य व पिछड़ों को लो इनकम के आधार पर सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार तकनीकी, व्यवसायिक, मेडिकल, पैरामेडिकल में था। मान्यवर, आज लो इनकम के साथ-साथ हाई मेरिट जोड़ दिया गया है कि अगर वो लो इनकम वाले भी हों, हाई मेरिट वाले भी हों तभी उनको दिया जायेगा। मान्यवर, मैं कोई नौकरी देने की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन सबको सामान अवसर मिल जाय, पढ़ने के लिए। मैं सरकार से चाहूंगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-45, 46 में समान अवसर सबको पढ़ने की बात कही गयी है और मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह व्यवस्था भी है संविधान निर्माता डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। पूना पैक्ट 1932 के आर्टिकल-7 में अनिवार्य शिक्षा की बात महात्मा गांधी और बी0आर0 अम्बेडकर जी के बीच में हुई थी। मान्यवर, मेरा प्रश्न करोड़ों-करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, कम-से-कम उनको अगर पढ़ा देंगे तो वह अपने आप नौकरी ढूंढ़ने के लायक हो जायेंगे। लायक बनाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा। आज माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं और माननीय मंत्री जी भी हैं कि अगर हाई मेरिट को आप समाप्त करते हुए सिर्फ लो इनकम के आधार पर सबको पढ़ने की व्यवस्था करा देंगे यही मान्यवर मेरी आपसे गुजारिश है। माननीय मंत्री जी आपसे मेरी आग्रह है कि दशमोत्तर एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में तकनीकी, व्यवसायिक, मेडिकल, पैरामेडिकल सहित सभी अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को हाई मेरिट जो अंक प्रतिशत की व्यवस्था को समाप्त करके क्या लो मेरिट के आधार पर प्रवेश दिलाने का काम करेंगे।

श्री असीम अरुण-

अध्यक्ष महोदय, यह छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति का सही तकनीकी शब्द है। सामान्य वर्ग के लिए दो लाख से कम पारिवारिक आय के परिवारों को अनुमन्यता है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी है। यहां पर सामान्य वर्ग की बात हो रही है इसलिए मैं एक ही विषय को अभी रखूंगा। यह एक बजट इनडेड स्कीम के रूप में प्रचलित रही है। यानि 2016-17 की अगर बात करें तो 653 करोड़ का प्राविधान उस समय की सरकार ने किया और जितने छात्र उसमें अनुमन्य हो पाये, एक मेरिट निकाला गया और उसके आधार पर उनको छात्रवृत्ति दी गयी। इसको अब बढ़ाते-बढ़ाते वर्तमान वित्तीय वर्ष की बात करें तो 803 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया। यानि 150 करोड़ इसको और बढ़ा दिया गया। इस बजट में इसको और बढ़ाया गया है। कोशिश यह है कि हम बजट बढ़ाते-बढ़ाते इसको हर छात्र को आच्छादित कर पायें लेकिन जितना बजट है उस हिसाब से छात्र भी हमारे बढ़ते जाते हैं। यह पाया गया कि लगभग 60-62 प्रतिशत के आस-पास इसका कट ऑफ जाता है। इसमें कई सारी कटैगरी है, मौटे तौर पर बता रहा हूं, जिनको हम लोग छात्रवृत्ति देने में सफल होते है। क्योंकि यह बजट अण्डर

स्कीम है, बजट बढ़ा है। बहुत बजट पूर्व से बढ़ा दिया गया है, यह बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में बजट और बढ़ायेंगे। प्रयास होगा कि हम हर बच्चे को छात्रवृत्ति दे पायें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अभी तक इनकी जो व्यवस्था है उसमें पहले राजकीय विद्यालय हैं फिर एडेड विद्यालय है उसके बाद प्राइवेट विद्यालय हैं तो उसमें भी प्राइवेट विद्यालयों का नम्बर नहीं आता है। मान्यवर, राम राज्य की सरकार है बजट की कोई कमी नहीं है। सरप्लस इनके पास रेवेन्यू है तो देने में क्या दिक्कत है? कम-से-कम कह तो दें माननीय मंत्री जी कि सभी को लो इनकम के आधार पर पढ़ा तो देंगे। मान्यवर, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। पढ़ा दें, मैं यही कह रहा हूँ।

प्रदेश में मंहगाई और वृद्धजनों की परेशानियों के दृष्टिगत वृद्धावस्था पेंशन की राशि को दोगुना किये जाने विषयक

***6-डॉ0 अजय कुमार**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महंगाई और वृद्धजनों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धावस्था पेंशन की राशि को दोगुना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

शासनादेश सं.-2011/26-2-2021-100(1)/2017, दिनांक 16-12-2021 के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को प्रदान की जा रही पेंशन राशि रु0 500/-प्रति माह प्रति लाभार्थी से बढ़ाकर जनवरी, 2022 से रु0 1000/-प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अजय कुमार-

मेरा आज बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है कि महंगाई और वृद्धजनों की परेशानी को देखते हुए क्या सरकार वृद्धावस्था पेंशन की राशि को दुगना करने पर विचार करेगी। मान्यवर, मुझे मालूम है कि वर्तमान में 55 लाख वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। मान्यवर, बुजुर्ग अपने जीवन का लगभग 40-50 वर्ष अपने परिवार की देखभाल के लिए और प्रदेश में भी अपना योगदान दे चुके होते हैं, आज वो वृद्ध हैं। बढ़ती उम्र में बीमारियां घेर लेती हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग लाचार भी हैं, गरीब भी हैं उनकी देखभाल करने वाले कई ऐसे परिवार हैं, जिनमें से बहुसंख्य में जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे संवेदनशील अपने बुजुर्गों के लिए संवेदनशील सरकार है और जो सरकार आवारा पशुओं के लिए इतनी संवेदनशील है वो अपने वृद्धों के लिए कैसे संवेदनहीन हो सकती है। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

आवारा पशु और वृद्धावस्था पेंशन से क्या मतलब है? आप तो महापुरूष हैं।

डॉ0 अजय कुमार-

यह खुशी की बात है कि नेता सदन भी हमारे बीच हैं तो मैं चाहूंगा सरकार से कि वृद्धजनों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री असीम अरुण-

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रचलित है ....

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

16 सितम्बर, 2021 से पूर्व यह 500 रुपये थी और इसको डबल करके 1,000 रुपये किया गया है। सरकार वृद्धजन की सेवा के लिए बहुत संवेदनशील है और अनेकानेक स्कीम चल रही है। पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक परिषद् का गठन किया, जो सभी विभागों का समन्वय करता है। मुख्य रूप से इसमें स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान है, सुरक्षा का भी योगदान है और सब मिल करके अपने वरिष्ठजन की सेवा करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। साथ-साथ एक विषय है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, समाज की मुख्यधारा में उनका योगदान लिया जाये। एक्टिव एजिंग का एक कान्सेप्ट दिया गया है, उसको और मजबूत किया जा रहा है, उसको पॉपुलराइज किया जा रहा है और उसके जरिये हम लोग कार्य कर रहे हैं और रही बात स्पष्ट रूप से इसको बढ़ाने की तो अपने संकल्प पत्र में भी वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने का संकल्प है। निश्चित रूप से इस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, यह अध्ययन का विषय है, यह नियोजन का विषय है और हम लोग इसको संकल्प पत्र के अनुसार समय आने पर जरूर बढ़ायेंगे।

प्रदेश में स्थापित आई0टी0आई0 केंद्रों में एक जिला एक उद्योग योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक तकनीकी शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की मांग

***7-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित आई0टी0आई0 केन्द्रों में कौन-कौन सी ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है ? क्या सरकार एक जिला एक उद्योग योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में चयनित उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक तकनीकी शिक्षा उस जिले में स्थापित आई0टी0आई0 केन्द्रों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 84 व्यवसायों/ट्रेडों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0ई0टी0), भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, मानकों एवं मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है (संलग्न-1)†

आई0टी0आई0 में एन0सी0वी0ई0टी0 के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, मानकों एवं मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ओ0डी0ओ0पी0 के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले अपने तारांकित प्रश्न पर मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने हेतु आपका धन्यवाद, खैर-मक्दम करता हूँ। अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा यह प्रश्न इस सरकार की कई वर्ष से घोषित एक जिला, एक उद्योग योजना के सही क्रियान्वयन में सहायक बिन्दु को उजाकर करने के उद्देश्य से पूछा गया था। परन्तु सवाल का उत्तर औपचारिक रूप से दिये जाने में मेरा अच्छा उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के आई0टी0आई0 संस्थानों में जिन 84 व्यवसाय अथवा ट्रेडों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें एक जिला, एक उद्योग से सम्बन्धित कितने व्यवसाय सम्मलित हैं ? क्या सरकार ने एक जिला, एक उद्योग से सम्बन्धित समस्त व्यवसायों का प्रशिक्षण आई0टी0आई0 संस्थानों में चलाने हेतु अपने स्तर से कोई प्रयास करेगी? क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हर वर्ष आई0टी0आई0 में बहुत से बच्चे जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं, जो गरीब हैं, जिनके माँ-बाप उनके लिए पैसों को अरेंज नहीं करा पाते हैं तो वह आई0टी0आई0 में एडमिशन लेते हैं। 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश, प्रदेश भर में बहुत से आई0टी0आई0 मानक अनुसार प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र, रोजगार देने योग्य नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश भर में बहुत से आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण ले रहे छात्र, न ही रोजगार योग्य हैं, न ही स्वरोजगार योग्य हैं। इसमें छात्रों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उसका सिलेबस, आई0टी0आई0 के मानक अनुसार, रोजगार बनाने व देने योग्य बनाने हेतु कोई पहल करेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने एक जिला, एक उद्योग से सम्बन्धित समस्त व्यवसायों को प्रशिक्षण सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, भारत सरकार को कोई सिफारिश भेजी है या भेजने की कोई योजना बनाई है ?

नोट :-† देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-318-319 पर।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न में जिज्ञासा प्रकट की गई है, जो हमारा विभाग है, वह एन0सी0वी0ई0टी0 के जो कोर्सेज तैयार होते हैं, वो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित हैं, उन्हीं कोर्सेज के अनुसार आई0टी0आई0 में व्यवसाय तय होते हैं। उसी की सूची मैने प्रश्न के जवाब के साथ संलग्न की है और एन0सी0वी0ई0टी0 के आधार पर ही जिन कोर्सेज को लागू किया गया, वह इसके अन्दर होते हैं। जो ओ0डी0ओ0पी0 का विषय है, जो माननीय मुख्य मंत्री, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत ही महत्वाकाँक्षी योजना है और हर जनपद को प्रत्येक उत्पाद से जोड़ने का जो क्रम सरकार के द्वारा लगातार चल रहा है, वहाँ पर लगातार प्रशिक्षण भी चल रहा है। ओ0डी0ओ0पी0 के प्रोडक्ट्स व प्रशिक्षण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उसके माध्यम से होता है। लेकिन जो हमारा दूसरा डिपार्टमेण्ट है, कौशल विकास का, कौशल विकास के माध्यम से प्रत्येक जनपद के अन्दर कहीं न कहीं जितने भी ओ0डी0ओ0पी0 के प्रोड्क्ट्स हैं, उनके साथ हमारा कौशल विकास का प्रशिक्षण का काम चल रहा है और उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। हालाँकि यह प्रश्न का पार्ट नहीं है, पर वह सूची में माननीय सदस्य के पास पहुँचा दूँगा।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत छोटी-सी बात पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश भर से आई0टी0आई0 में प्रशिक्षण ले रहे छात्र, जो हमारे इन्स्टीट्यूट हैं वह इस लायक नहीं है। यह वर्ष 2023 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। वह बच्चे न ही रोजगार के लिए योग्य हैं, न ही उनको किसी योजना में नौकरी मिल पाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुय, आप सिलेबस आई0टी0आई0 के मानक अनुसार रोजगार योग्य बनाने व देने की कोई पहल करेंगे ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

मान्यवर, जैसाकि मा0 सदस्य के द्वारा कहा गया है कि आई0टी0आई0 में जो प्रशिक्षण हो रहा है, वह रोजगार के लायक नहीं हैं। इसका मतलब है कि पूरे विभाग पर इन्होंने प्रश्नचिन्ह लगा दिया। यह तो हो सकता है कि कुछ लोगों को रोजगार न मिले लेकिन आई0टी0आई0 हमारा बहुत शानदार तरीके से प्रशिक्षण देने का काम करता है। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में, टाटा के साथ मिलकर 150 आई0टी0आई0 को डेवलप कर रहे हैं और निश्चित रूप से वर्तमान में क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं, जिसमें हमारे पास इण्डस्ट्री 4.0 की डिमाण्ड है, जो सर्वे नीति आयोग के द्वारा होता है उसी आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, सोलर, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिंग डिजाइनिंग, थ्री डी प्रिंटिंग, साफ्टवेयर स्किलिंग मेकट्रॉनिक्स, जी0ओ0टी0 होटल, हेल्थ केयर आदि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिमांड है, उन सब में हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। टाटा स्वयं भी आ करके उनको

प्रशिक्षित करने का काम करेगा। जो आई0टी0आई0 चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में हों, उनका परिणाम बहुत अच्छा है। हमारे प्रतिमाह रोजगार के मेले भी लगते हैं, मण्डल स्तर पर, जिला स्तर पर भी और माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर उसको ब्लाक स्तर पर भी लगवाया है। प्रत्येक माननीय विधायक को उसकी सूचना भेजी है कि ब्लाक स्तर पर जा करके उसमें वह स्वयं भी प्रतिभाग करें। तो मुझे लगता है कि उनको नौकरी के लिए सेवा का अवसर प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में लगातार मिल रहा है।

प्रदेश में दशमोत्तर के छात्र-छात्राओं को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति देने विषयक कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

***8-श्री राम सिंह पटेल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दशमोत्तर के छात्रवृत्ति के आवेदनकर्ता छात्र-छात्राओं को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति देने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् तथा छात्रवृत्ति की वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन करने वाले पात्र एवं सही डाटा वाले अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि प्रदेश स्तर से तथा 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भारत सरकार द्वारा छात्रों के आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान की जाती है।

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा भी उक्त प्रक्रिया के तहत आनलाइन आवेदन किया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत एवं नियमावली में निर्धारित वरीयता श्रेणी के आधार पर उनके आधार सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जाता है।

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना फण्ड एडेड योजना होने के कारण छात्रों की देयता को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं किया जाता है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजाति (75 प्रतिशत केन्द्रांश व 25 प्रतिशत राज्यांश की समेकित धनराशि राज्य स्तर पर) के पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट की सीमा के अन्तर्गत एवं नियमावली में निर्धारित वरीयता श्रेणी के आधार पर छात्रों के आधार सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम सिंह पटेल-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से अपने प्रश्न के सम्बन्ध में तीन अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 तक दशमोत्तर के कितने छात्र-छात्राओं ने छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया। दूसरा प्रश्न क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दी गयी और कितने छात्र शेष रह गये थे। मान्यवर, एक छोटा-सा अनुपूरक और है क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि शेष छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार देगी या नहीं देगी ? मेरे तीन अनुपूरक हैं, इनका जवाब चाहता हूँ।

श्री असीम अरूण-

मान्यवर, जो अन्तिम प्रश्न है कि सबको देंगे या नहीं देंगे ? प्रश्न संख्या-4 में यह बात आ गयी है कि बजट अण्डर स्कीम है और हमारा प्रयत्न है कि हम बजट को बढ़ाते जायें। हम लोगों ने इस साल से बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस को लागू किया है। छात्रवृत्ति में जो भी पूर्व सरकारों में घपले हुये थे, उसको लगभग पूरी तरीके से ठीक करने में सफल हुये हैं। अब बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस आने के साथ में, केवल गम्भीर छात्र ही छात्रवृत्ति के पात्र रहेंगे, जिसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है वह पात्र नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि एक ओर जो लीकेज था वह भी ठीक हो जायेगा। हम बजट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा छात्रों को 15.49 कर पायेंगे। मा0 सदस्य ने लाभान्वित छात्रों की संख्या पूछी है, उसमें अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति के कुल 9 लाख 39 हजार 695 छात्र वर्ष 2022-23 में लाभान्वित हुये। सामान्य वर्ग दशमोत्तर के 7,04,505 अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर के 6 हजार 427 छात्र लाभान्वित हुये हैं। अगर विवरण चाहिए तो मैं और भी डिटेल प्रस्तुत कर दूंगा।

प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने विषयक कार्य योजना का विवरण

***9-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा एफ0डी0आई0 (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) हेतु उनको प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो प्रदेश के समुचित विकास करने तथा उसको मुख्य धारा में लाने हेतु क्या सरकार द्वारा कम्पनियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर उनके साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त के परिणामों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ0डी0आई0) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 प्रख्यापित की गयी है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित नीति के क्रम में विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से विभिन्न आयोजनों यथा-वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 'दावोस' में प्रतिभाग करते हुए विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घरानों यथा-माइक्रोसाफ्ट, टाटा ग्रुप एवं काल्सबर्ज इत्यादि के साथ भेंट-वार्ता की गयी। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में विदेशी पूँजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने हेतु एफ0डी0आई0 कान्क्लेव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने औद्योगिक विभाग के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। पहले तो कहेंगे कि जो बुन्देलखण्ड में बीडा की स्थापना हुयी। 57 साल नोएडा और ग्रेटर नोएडा को लगे तो हमारे यहाँ कम समय में अगर बुन्देलखण्ड में उद्योग स्थापित हो जाये तो हम बड़ा आभार व्यक्त करेंगे।

दूसरा, मैं काल्पी से आता हूं, बुन्देलखण्ड की यमुना के किनारे से, वहां हैण्डमेड कागज उद्योग का धन्धा था, कालीन का था और पॉवरलूम का था। पॉवरलूम और कालीन दोनों बन्द हो गये, लेकिन हैण्डमेड पेपर अभी बन रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जनपद जालौन का हैण्डमेड पेपर लिया गया है। इसमें दिक्कत यह है कि बनाने वाले बनाते तो हैं, लेकिन सप्लाई नहीं है, जैसे प्रदेश सरकार में फाइलों में उस पेपर को लिया जाय तो उनको प्रोत्साहन मिल सकता है और वह उठ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हैण्डमेड पेपर पर पहले जीएसटी नहीं लगती थी, यह पाँच साल 2007 से 2012 तक फ्री रहा, लेकिन अब इस पर 18 परसेंट जीएसटी है, मेरा निवेदन है कि अगर 5 परसेंट जीएसटी कर दी जाय तो वह जिन्दा हो जायेंगे अन्यथा सौ इकाइयों में 50 इकाई बची हैं, धीरे-धीरे वह खत्म हो जायेंगी। यह तो मान्यवर, मेरे क्षेत्र का विषय था, मैंने प्रश्न किया था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) हेतु उनको प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई योजना है ? इसमें हमें जवाब मिला कि प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 प्रख्यापित की गयी है। मेरा एक ही अनुपूरक है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में अभी तक कितने प्रस्ताव किन-किन कम्पनियों के प्राप्त हुए व इससे कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ है। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि भेंट-वार्ता में सरकार का कितना पैसा

खर्च हुआ और इन कम्पनियों द्वारा कितना निवेश प्रदेश को प्राप्त हुआ है और कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के पहले पार्ट में देख लें कि जो हमने अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीति फ्लोट की है वह 01-11-2023 को की है। अभी-अभी यह नीति फ्लोट की, इसके पहले काफी वर्षों से उत्तर प्रदेश में यह नीति थी ही नहीं और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने इस नीति को फ्लोट किया है। नवम्बर में नीति फ्लोट हुई, लेकिन उसके साइलेंट फीचर ऐसे हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। 75 से 80 परसेंट लैण्ड कास्ट पर सब्सिडी दी जा रही है, प्लान्ट और मशीनरी पर 25 परसेंट से 30 परसेंट सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है और उत्तर प्रदेश में अगर सेल हो तो 100 परसेंट जीएसटी का फायदा उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर यूपी के निवासियों को रोजगार दें तो 5 हजार प्रतिमाह सब्सिडी वर्कर को देंगे, यह सब्सिडी 500 व्यक्तियों की सीमा तक 5 वर्षों तक मिलेगी। यह बहुत ज्यादा एल्योरमेंट वाली पॉलिसी है, इसको देखकर लोग आ सकते हैं। आपने जो दावोस के बारे में पूछा तो हमने जिक्र किया है कि इन लोगों से वार्ता हुई लेकिन बातचीत जमीन पर केवल हिन्दुजा ग्रुप की अशोक लीलैण्ड वालों की आयी, वह 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यह अपने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा सुखद है। इन लोगों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी यह जमीन पर नहीं उतरी है। अभी तक किसी स्टेट ने इस तरह की पॉलिसी फ्लोट नहीं की। मैंने पहले प्रश्न के जवाब में बता दिया था कि 19 तारीख को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी है और उसी दिन उसका शिलान्यास भी होगा।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, हमारे काल्पी वाले के विषय में नहीं बताया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस विधान सभा में पहले भी यह बात कई बार आयी कि हम आपकी बात को प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर सभी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे लोग मिल कर फैसला करते हैं अकेला हमारा प्रदेश नहीं करता है। मैंने इस बात को नोट कर लिया है, जीएसटी काउंसिल में इस बात को रखा जायेगा।

प्रदेश में पंजीकृत कुष्ठ रोगियों की संख्या तथा उनके आजीविका के साधन उपलब्ध कराने विषयक विवरण

***10-श्रीमती पिंकी सिंह-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान तक कुल कितने कुष्ठ रोगी पंजीकृत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि पंजीकृत कुष्ठ रोगियों में से

कितने कुष्ठ रोगी जीविका चलाने में असमर्थ हैं ? क्या सरकार जीविका चलाने में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को किसी निश्चित अवधि तक आजीविका के साधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

वर्तमान में प्रदेश के कुष्ठ रोगियों को पंजीकृत किये जाने की कोई योजना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित नहीं है, अपितु कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुये दिव्यांगजन को कुष्ठावस्था पेंशन के रूप में रु0 3000/-प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से कुष्ठावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में माह दिसम्बर, 2023 में कुल 9891 पंजीकृत कुष्ठ रोगियों को उपचार प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास तक कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुये अद्यतन 11671 दिव्यांगजन को कुष्ठावस्था पेंशन के रूप में रु0 3000/-प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से कुष्ठावस्था पेंशन प्रदान की गयी है।

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुये ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी आय गरीबी की रेखा की सीमा के अन्दर हो, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, किसी भी आयु वर्ग के हों तथा सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहा हो और उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत चाहे कुछ भी हो, उन्हें रु0 3000/-प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से कुष्ठावस्था पेंशन अनुमन्य है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, उ0प्र0 के अन्तर्गत कुष्ठजनित दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों को निःशुल्क रिकान्स्ट्रक्टिव शल्य-क्रिया काल में लॉस ऑफ वेजेज के रूप में रु0 12,000/-प्रदान किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसे संवेदनशील मसले पर प्रश्न पूछने का मौका दिया। महोदय मेरा प्रश्न समाज के उस वर्ग से सम्बन्धित है, जिसे उसके अपने भी उपेक्षित कर देते हैं। इस स्थिति में कुष्ठ रोग से घिरे व्यक्ति को बेहद ही मानसिक और आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। महोदय जहां 10 लाख की जनसंख्या पर एक मामले की बात आती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है और आज जहां एक मामले की बात पर तीसरा स्थान हो, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर समाप्त करने की और कोई नैतिक रूप से रेखा बनानी चाहिए। महोदय मेरे दो अनुपूरक हैं, मेरा पहला अनुपूरक मा0 मंत्री जी से है कि क्या सरकार एन0एल0ई0पी0 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उनमूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोगियों की आर्थिक, समाजिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण कराने के कार्य के साथ-साथ जो उन्हें

धनराशि गुजारा भत्ते के रूप में दी जाती है क्या उसको बढ़ाकर 6 हजार रुपये करने का काम करेगी ? मेरा दूसरा अनुपूरक है कि क्या सरकार कुष्ठ रोगियों का विशेष सर्वे कराकर उनमें से आवासहीन पात्रों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगी ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मा0 सदस्या का जो प्रश्न है, वह कुष्ठ रोगियों को मिलने वाली भरण पोषण की राशि को बढ़ाने के सन्दर्भ में है। इस सन्दर्भ में आपके माध्यम से मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो धनराशि 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोगियों को मात्र 2500 रुपये मिलती थी, आदरणीय योगी जी की सरकार में उस धनराशि को बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया, भविष्य में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी बात जहां तक आपने कुष्ठ रोगियों के सर्वेक्षण की बात कही है, तो इस सन्दर्भ में हम प्रयास करेंगे, हालांकि हमारा विभाग केवल कुष्ठ रोगियों को पेंशन देने पर विचार करता है और आवास की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध हमारी सरकार की तरफ से की जा रही है। चूंकि कुष्ठ रोगियों की संख्या शुरुआती जांच के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध होती है। उसका पूरा डेटा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और सुनिश्चित करता हूँ कि कुष्ठ रोगियों के प्रत्येक सुविधा के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है, भविष्य में भी हम इनका ध्यान रखेंगे।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मा0 मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग भी सरकार के अण्डर में ही है, तो मा0 मुख्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि इस पर सरकार गहनता से विचार कर लेगी, तो इस रोग को पूर्णतया उत्तर प्रदेश से समाप्त किया जा सकता है। उसके लिए जहां सरकार ने 2500 रुपये को बढ़ाकर 3000 रुपये किया, तो वहीं मैं यह बताना चाहूंगी के जो तत्कालिक सरकार थी, उस दौरान 2500 रुपये के साथ-साथ साढ़े 3 लाख रुपये का आवास भी दिया जाता था, जहां आज प्रधानमंत्री आवास देने की जो बात सरकार कर रही है, उसकी धनराशि उससे अपेक्षाकृत कम है, उसको भी बढ़ाने का विचार करें।

प्रदेश में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक

***11-श्री पंकज पटेल (अनुपस्थित)-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के उपरान्त पॉलिथीन उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जी हाँ।

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)-2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा समस्त प्रकार की निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, टम्बलर के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिबन्धित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12-08-2021 दिनांक 01-07-2022 से चिन्हित सिंगल यूज़ प्लास्टिक आईटम्स को प्रतिबन्धित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने एवं कृषि उपज बढ़ाने विषयक योजना

***12-श्री अखिलेश, श्री जियाऊर्रहमान तथा श्री लालजी वर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने एवं कृषि उपज बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश के किसानों की कृषि उपज बढ़ाने एवं आमदनी को दोगुना करने हेतु निम्नवत् योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

1-बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की योजना।

2-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना।

3-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी।

4-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम।

5-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर)।

6-संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना (राज्य सेक्टर)।

7-कृषोन्नति योजना (बीज ग्राम योजना) (केन्द्र सेक्टर)।

8-परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0)।

9-नमामि गंगे।

10-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

11-वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम)।

12-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना।

13-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन0एफ0एस0एम0)।

14-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम)।

15-खेत तालाब योजना।

16-नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) NMEO-OS।

17-नेशनल मिशन ऑन एडबिल ऑयल (ट्री बोर्न ऑयल सीड्स) NMEO-TBO।

18-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन।

19-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना।

20-प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू योजना।

21-पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।

22-विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना।

23-गन्ना किसानों को उन्नतिशील बीज उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक तकनीकी से बुवाई कर उत्पादकता और रिकवरी को बढ़ाया जाना एवं गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करना।

24-दिनांक 24 मई, 2020 से 45 नासवान प्रकृति के कृषि उत्पादों को मण्डी शुल्क से मुक्त करते हुए इनके व्यापार को मण्डी परिसर के बाहर किये जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। मण्डी परिसर के अन्दर इन वस्तुओं का व्यापार करने पर 01 प्रतिशत प्रयोक्ता प्रभार लगाया गया तथा विकास शुल्क से मुक्त रखा गया है। दिनांक 27 नवम्बर, 2020 को मण्डी शुल्क को 2 प्रतिशत से घटाकर 01 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ है।

प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त निम्न योजनाएं/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि करोड़ रुपये में)

क्रम	योजना का नाम	वर्ष 2023-24	कुल
1	राज्य मिलेट्स पुनरोद्धार योजना हेतु	55.65	186.26
2	निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	30.24	120.96

क्रम	योजना का नाम	वर्ष 2023-24	कुल
3	राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम (राज्य सेक्टर)	28.64	114.56
4	आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना (एफ0पी0ओ0)	100 करोड़ प्रति वर्ष	100 करोड़ प्रति वर्ष

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत योजना के प्रारम्भ से अब तक प्रदेश में 2.62 करोड़ किसानों को उनके बैंक खाते में कुल धनराशि रु0 62998.69 करोड़ स्थानान्तरित करते हुए लाभान्वित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अखिलेश-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 मंत्री जी से कृषि उपज और किसानों की आय से सम्बन्धित प्रश्न किया है। बहुत लम्बे-चौड़े ब्यौरे के साथ मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है। हम मा0 मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से बार-बार यह दावा किया जाता है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना हुई है। हम पूछना चाहते हैं कि वह कौन सा मानक है, जिसको आप किसानों की आय नापने का पैमाना बनाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेशनल सैम्पल सर्वे की रिपोर्ट और राज्य सभा में 23 जुलाई, 2021 को मा0 केन्द्रीय मंत्री महोदय द्वारा किसानों की आय से सम्बन्धित एक प्रश्न के जवाब में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों की मासिक आय रु0 8058/-है। अगर इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अन्दर आंकड़ा लिया जाये, तो किसानों की आय वर्ष 2022 में रु0 16,116/- होनी चाहिए।

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से बार-बार यह दावा किया जाता है कि किसानों की आय दोगुना हुई है, तो हमारा सवाल है कि सरकार के दावे की कितनी सच्चाई है ? क्या वर्ष 2024 में आज की तारीख में किसानों की आय रु0 16,116/-है ? मा0 मंत्री जी से हम यह भी पूछना चाहते हैं कि यदि किसानों की आय दो गुना नहीं हुई, तो क्या भविष्य में कोई ऐसी डेड लाइन आप निर्धारित करेंगे, जहाँ इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाएं ? साथ ही साथ हम यह भी पूछना चाहते हैं कि वह कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, जिनकी सुविधा दे करके किसानों की आय को दोगुना किया जायेगा ? मा0 अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री महोदय से हमारा अगला अनुपूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कितने अनुपूरक करेंगे। पहले कितने अनुपूरक कर चुके। ये कौन सा वाला अनुपूरक है ?

श्री अखिलेश-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट और लूँगा। क्या सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों को सरकारी/सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। किसानों की आय दो गुना करने के लिए सिंचाई, पशुपालन व मत्स्य पालन का भी बड़ा महत्व है, तो क्या सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तर्ज पर सीमान्त और लघु किसानों को फ्री बोरिंग की व्यवस्था करेगी या पशुपालन के लिए अनुदान दे करके ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इसमें तीन मा0 सदस्यों का प्रश्न है, तो मैं उन सबसे कहता हूँ कि पहले प्रश्न कर लें, तो आप एक साथ उत्तर दे दीजिएगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले इनके प्रश्न का उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

फिर 12.20 हो जायेगा और आपका नम्बर ही नही आयेगा। मा0 मंत्री जी आव जवाब दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, राज्य सभा में मा0 केन्द्रीय मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह इस समय मेरे सामने नहीं है। उस उत्तर का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ तक सांख्यिकी की रिपोर्ट है और मा0 वित्त मंत्री जी ने भी आपके सामने बताया है कि वर्ष 2016-17 में रु0 52000 जो किसानों की आय थी, वह बढ़कर रु0 96000/-प्रति व्यक्ति हो गयी है।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा के कुछ बोलने पर)

पूरे उत्तर का जवाब आ जाने दीजिए। इसमें विशेष रूप से कृषि की भी बहुत बड़ी भूमिका है। विगत वर्षों में मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो प्रयास किये हैं, उसकी इनको विस्तार से जानकारी दी है कि कितनी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। उन योजनाओं का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का किसान आज खुशहाल है। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार वर्ष 2017 में बनी थी, उसके पूर्व किसान आत्महत्या कर रहे थे। आर्थिक दबाव के कारण करते थे। उनके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। उनके उत्पादों की ठीक प्रकार से खरीद नहीं होती थी। एम0एस0पी0 भारत सरकार तय करती थी, लेकिन ये खरीददारी नहीं करते थे। खरीददारी कर लिया, समय पर भुगतान नहीं होता था उस समय किसानों को कभी सोसायटी पर, तो कभी बैंक पर छः-छः माह का चक्कर लगवाते थे।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नियोजित तरीके से यह योजना बनाकर पहले 86 हजार किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये। वह कर्जे जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किसानों ने कृषि के लिए लिये थे, लेकिन आपकी गलत नीतियों के परिणामस्वरूप वह आत्महत्या कर रहे थे, उस आत्महत्या के दबाव से मुक्त हो सके और खेती कर सके, इसके लिए कर्जमाफी की है। दूसरा हम लोगों नेएम0एस0पी0 के आधार पर रिकॉर्ड खरीददारी करायी है। किसानों को पिछले वर्षों के भीतर हमने 2017 से लेकर अब तक निरन्तर इस बात का प्रयत्न किया है और हम उनको प्रतिवर्ष साढ़े 5 लाख से लेकर सवा 8 लाख क्विंटल तक उन्नतशील बीज 50 परसेन्ट अनुदान पर दे रहे हैं। राज्य के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादन पर विशेष बल दिया है, क्योंकि आज भी हमारे देश के भीतर दलहन, तिलहन का आयात होता है और यह हाई वैल्यू क्राफ्ट हैं, जिसमें अच्छी आमदनी हो सकती है। इसके लिए गत वर्ष से राज्य स्तर की विशेष योजना चलाकर हम दलहन, तिलहन योजना चला रहे हैं, जिससे हम लोगों ने लगभग 17 लाख किसानों को इस साल और पिछले साल दलहन, तिलहन के बीजों के निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराये हैं।

इसी तरीके से आपने सोलर पम्प की बात कही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ऐसी सरकार है, जो अपने कार्यकाल के भीतर 51 हजार से ज्यादा सोलर पम्प लगा चुकी है। 30 हजार सोलर पम्प हम खोले हुए हैं। 20 हजार के करीब किसान भाइयों ने टोकेन भी जमा कर दिया है। जिन्होंने नहीं जमा किया है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वह जल्दी टोकेन जमा कर दें जितना जल्दी जमा करेंगे हमारी कोशिश है कि हम तत्परता के साथ 15 मार्च के पहले 30 हजार किसानों के सोलर पम्प को स्थापित करा देंगे। इसी प्रकार से 44 हजार सोलर पम्प हम और खोलने वाले हैं। पहली कड़ी में फरवरी के अन्त तक हम 30 हजार सोलर पम्प और खोलेंगे। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार के कॉम्बिनेशन से ऊपर उठकर 10 परसेन्ट टॉपअप देने का फैसला किया है, जिससे कि इस साल हम 68 हजार करोड़ रुपया और ज्यादा किसानों पर खर्च करेंगे। गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा गन्ने का भुगतान हुआ है। इस साल भी जो गन्ने की पेराई हो रही है, उस गन्ना पेराई का 68 परसेन्ट से ज्यादा हम गन्ना मूल्य का भुगतान करा चुके हैं। आपके जमाने में तो 3-3 साल के बकाया रहते थे। यह व्यवस्था में सुधार करने का काम हम लोगों ने किया है।

राज्य के भीतर राज्य श्रीअन्न योजना चला रहे हैं। बुन्देलखण्ड में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती से बुन्देलखण्ड के सभी सातों जनपदों के 47 विकास खण्डों के भीतर हम कैसे हाई वैल्यू और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ लोगों को अच्छी आमदनी करा सकें, इसकी व्यवस्था की गयी है। रिकॉर्ड एम0एस0पी0 पर खरीददारी हुई है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके बीच चर्चा भी की थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की

सरकार में राज्य के भीतर पहली बार साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बाजरे की खरीददारी हुई है और उसके माध्यम से 878 करोड़ रुपया किसानों को भुगतान किया है। हम लोगों ने ज्वार, मक्के, मूंगफली की खरीददारी करायी है। क्या आपने कभी इसको किया है ? जिन लोगों ने नहीं किया है, उनको किसानों पर बोलने का कोई हक नहीं है, हमारी सरकार उनका ध्यान कर रही है। व्यवस्थित तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दिया है, लेकिन इसमें आमदनी बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं है। किसानों की आमदनी दो तरह से दोगुनी होगी। एक तो उसकी उत्पादन लागत कम हो और साथ ही साथ समर्थन मूल्य दोगुना हो। उत्पादन लागत घटी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मा0 कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इनके जितने भी कृषि फार्म हैं, उनमें प्रति क्विंटल गेहूं, धान की क्या लागत मूल्य आती है ? उसके सापेक्ष समर्थन मूल्य है या नहीं है ? दूसरा लागत मूल्य घटाने के लिए डीजल में सब्सिडी हो, साथ-साथ कीटनाशक दवाओं में सब्सिडी हो, खादों में सब्सिडी हो। खाद में तो 50 किलो की बोरी 40 किलो की कर दी है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि मा0 मंत्री जी इस पर जवाब दें कि इनका जो कृषि फार्म है, उसकी लागत मूल्य के सापेक्ष क्या किसान को अपनी तरफ से विशेष बोनस देते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं इनको यह बता दूं कि आपने बहुत गलत तथ्य रखा। आपकी सरकार ऐसी थी जिसके भीतर आप मंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर यूरिया टैक्स पर जजिया कर ए0सी0टी0एन0 टैक्स लगाती थी। आपके जमाने में 50 के0जी0 की यूरिया को तीन सौ पैंतीस रुपया में पर बैग किसानों को दिया जाता था। मा0 योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में आने के बाद ए0सी0टी0एन0 टैक्स खत्म किया गया। 50 किग्रा0 की 335 रु0 बोरी की यूरिया कम होकर 299 रुपये हो गई और 45 किग्रा0 यूरिया 266.50 पैसे में किसान को मिलने लगी है। भारत सरकार ने पैंतालीस के0जी0 के और बैग किट जारी किये, जिस पर 266.50 देते हैं, जब आप दो सौ निन्यानबे रुपये वसूल रहे थे, इसलिये मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसान की लागत को घटाने का काम किया है। दूसरी बात पोटाश पर 71.35 कीमतों में कमी किया गया है। मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद डी0ए0पी0 की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। यूरिया के कीमतों में हम लोगों ने छत्तीस रुपये तक की कमी किया और पोटाश के भीतर भी इकहत्तर रुपया पैंतीस पैसे कम ही किया है और इस प्रकार से हमने अनुदानित आधार पर बीज दिया है। किसानों को खाद के माध्यम से भी राहत दिया है और नलकूपों में भी पिछले वर्ष से पचास प्रतिशत निजी नलकूप के बिजलीदरों में किसानों को छूट दी गई है।

इस साल उसकी वसूली नहीं हो रही है। इसलिये यह हमारे बजट के भीतर उसके प्रावधान किये गये हैं, साथ-साथ में बड़े पैमाने पर सोलर पम्प के द्वारा किसान भाइयों को भी एक सौ पचास दिन बिना बिजली, डीजल के वह काम कर सकें, खेती कर सकें, इसकी गारण्टी देने का काम मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। जहां तक आपने डीजल की बात कही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने जो पूछा है वह इन्होंने बताया नहीं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, डीजल को भी देश के अन्दर सबसे कम यदि कहीं पर डीजल का रेट है, तो वह उत्तर प्रदेश है। यह मैंने पहले भी बताया था और आज भी मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पी0डी0ए0 देखने जाते हैं वहां पी0 डी0 ए0 का ध्यान नहीं है। पी0डी0ए0 वहां पर नहीं है अगर पी0डी0ए0 कहीं पर है, तो मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में है, किसानों के साथ है।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद मा0 मंत्री जी। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।†

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति पिछड़ी जाति के छात्रों के लिये छात्रावास बनाये जाने की मांग

***13-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-**

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास की व्यवस्था की भांति हर जिला मुख्यालय पर पिछड़ी जाति के लिए छात्रावास बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राजकीय शिक्षण संस्थानों के परिसर में छात्रावास निर्माण की केन्द्र/राज्य पोषित योजना संचालित है। जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर छात्रावास का निर्माण कराया जाता है। हर जिला मुख्यालय पर छात्रावास बनाने की वर्तमान में राज्य सरकार की अलग से कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

नोट :-† तारांकित प्रश्न सं0-12 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में आलू भण्डारण के सापेक्ष भण्डारण केन्द्र तथा आलू किसानों की समस्याओं को दूर किये जाने विषयक

***14-श्री शहज़िल इस्लाम अंसारी-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आलू की पैदावार के सापेक्ष भण्डारण केन्द्र और मांगानुरूप प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 5 वर्षों में आलू भण्डारण और प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रदेश ने कितनी प्रगति की है ? क्या सरकार आलू किसानों की समस्याओं को दूर करने के किए गए प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, कृषि विपणन तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

जी हाँ।

क-वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल 1909 शीतगृह क्रियाशील थे, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 154.54 लाख मी0 टन थी। वर्ष 2022-23 में क्रियाशील शीतगृहों की संख्या 1994 हो गई तथा भण्डारण क्षमता 165.51 लाख मी0 टन हो गई। इस प्रकार विगत 05 वर्षों में आलू भण्डारण की क्षमता में 10.97 लाख मी0 टन की वृद्धि हुई है।

ख-विगत 05 वर्षों में प्रदेश में विभागीय अनुदान द्वारा आलू प्रसंस्करण के क्षेत्र में कुल 07 यूनिट/इकाइयों की स्थापना की गयी है।

जी हाँ।

आलू किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए आलू भण्डारण क्षमता को बढ़ाने हेतु नये शीतगृहों का निर्माण तथा आलू उत्पादों के प्रसंस्करण की नई इकाइयाँ स्थापित करायी जा रही हैं। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 योजनान्तर्गत कुल 05 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी परियोजना लागत धनराशि रु0 80.85 करोड़, अनुदान धनराशि रु0 72.39 करोड़ है, जिनको लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल0ओ0सी0) निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के दृष्टिगत कर्ज माफ किये जाने विषयक

***15-डॉ0 पल्लवी पटेल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के दृष्टिगत उनका 5 लाख तक का कर्ज माफ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

शासनादेश संख्या-540बी/क0नि0-6-2017-01 (बी)/2017, दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण

मोचन योजना लागू की गयी, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2022-23 में कुल 45,57,526 (पैंतालीस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ छब्बीस) पात्र कृषकों को धनराशि रुपया 2,54,23,71,59,433.00 (पच्चीस हजार चार सौ तेईस करोड़ इकहत्तर लाख उनसठ हजार चार सौ तैंतीस रुपये) का भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने तथा उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू करने विषयक

***16-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार की अनुदानित लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने की कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राकेश सचान)-

जी हां।

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में परियोजना लागत रु0 50 लाख तक की परियोजनाओं की स्थापना में परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक 'मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में रु0 25 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। इसी प्रकार 'एक जनपद एक उत्पाद' के अन्तर्गत वित्त पोषण योजना में परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान अधिकतम रु0 20 लाख की सीमा तक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' एवं 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनाओं के अन्तर्गत कौशल विकास एवं टूलकिट वितरण के माध्यम से पारम्परिक उत्पादों से जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुये आधुनिक टूलकिट उपलब्ध करायी जाती है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत सरकार की योजना 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति हेतु 20.70 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 0.57 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है। मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने पास से लगाना होता है, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन हेतु परियोजना लागत

का मात्र 5 प्रतिशत अंशदान अपने पास से लगाना होता है। 'एक जनपद एक उत्पाद' वित्त पोषण योजना विभिन्न श्रेणी के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने व विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना विभिन्न श्रेणी के पारम्परिक कारीगरों को बढ़ावा देने के लिये लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याण हेतु योजनाओं में पारदर्शिता लाकर सभी को लाभ दिलाने की मांग

***17-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याण हेतु कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान में संचालित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त योजनाओं के संचालन के बाद भी कतिपय दिव्यांग इससे वंचित हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं में पारदर्शिता लाकर सभी दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उन्नयन हेतु मुख्य रूप से निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

(1) दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना।

(2) कुष्ठावस्था पेंशन योजना।

(3) कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना।

(4) दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना।

(5) शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

(6) शल्य चिकित्सा अनुदान योजना।

(7) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा।

(8) बचपन डे-केयर सेण्टर संचालन योजना।

उपर्युक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये योजनावार पृथक-पृथक पात्रता निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजन द्वारा आवेदन किये जाने के उपरान्त पात्र पाये जाने की स्थिति में उन्हें योजना का लाभ प्राप्त होता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों हेतु डीजल, डी0ए0पी0 एवं पोटाश का मूल्य कम किये जाने की मांग

***18-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डीजल के दामों में हुई वृद्धि के दृष्टिगत किसानों को खेती के कार्य हेतु कम मूल्य पर डीजल उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में प्रति वर्ष औसतन कितनी मात्रा में फास्फेटिक उर्वरक की खपत होती है तथा उसमें रबी सीजन में कितनी खपत होती है ? क्या यह सही है कि वर्तमान वर्ष में खरीफ सीजन के बाद डी0ए0पी0 एवं पोटाश के मूल्य में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में डी0ए0पी0 एवं पोटाश का मूल्य कम करके पूर्व के मूल्य पर लायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 33.88 लाख मी0टन फास्फेटिक उर्वरकों (डी0ए0पी0, एन0पी0के0 एवं एस0एस0पी0) की खपत होती है, जिसमें से रबी सीजन में औसतन खपत 22.13 लाख मी0 टन होती है।

डी0ए0पी0 एवं पोटाश के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। डी0ए0पी0 उर्वरक पूर्व की भाँति रु0 1350.00 प्रति बैग (50 कि0ग्रा0) की दर से वर्तमान में उपलब्ध है जबकि पोटाश के मूल्य में दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से रु0 45.00 प्रति बैग (50 कि0ग्रा0) की दर से कमी हुई है। फलस्वरूप वर्तमान में पोटाश रु0 1700.00 से घटकर रु0 1655.00 प्रति बैग की दर से उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थापित की गई नई औद्योगिक इकाईयों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***19-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के किन-किन जनपदों में सरकार की नई औद्योगिक इकाई स्थापित कराने की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

राज्य सरकार प्रदेश के समस्त जनपदों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति कनेक्टिविटी एवं विनियामक

व्यवस्था (रेगुलेटरी कम्पलाएन्सेज) में व्यापक सुधार किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कई एक्सप्रेस-वेज यथा-यमुना एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे विकसित किए गए हैं इनके समीप औद्योगिक गलियारे का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करते हुए जनपद झांसी में 14000 हे0 भूमि पर लगभग रु0 6,312.00 करोड़ की लागत से औद्योगिक टाउनशिप एवं गलियारे का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में औद्योगिक इकाइयों को लगाये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022' के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में 20 सेक्टोरल नीतियाँ प्रख्यापित की गयी हैं, जो प्रदेश में स्थापित होने वाली समस्त औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार नौजवानों हेतु 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने की मांग

***20-श्री अतुल प्रधान-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को देने हेतु कानून बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश में जो उद्योग स्थापित हैं उनमें अधिकांशतः आस-पास के क्षेत्रों (स्थानीय) से ही कार्मिक लिये जाते हैं। हर उद्योग में अलग-अलग कौशल/स्किलसेट की आवश्यकता होती है एवं जो कार्मिक हैं, यदि इनके पास सम्बन्धित ट्रेड का कौशल/स्किलसेट नहीं होने पर उद्योगों की उत्पादकता प्रभावित होगी।

प्रदेश में स्थानीय बेरोज़गार नौजवान युवकों को स्वरोजगार/रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक योजनायें संचालित की जा रही हैं। इसमें 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' में परियोजना लागत रु0 50 लाख तक की परियोजनाओं की स्थापना में परियोजना लागत का 15 से 35 प्रतिशत तक, 'मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना' में रु0 25 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 25 प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। इसी प्रकार 'एक जनपद एक उत्पाद' के अन्तर्गत वित्त पोषण योजना में परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत तक का अनुदान अधिकतम रु0 20 लाख की सीमा तक उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' एवं 'एक जनपद एक उत्पाद' कौशल विकास एवं टूलकिट वितरण योजना में पारम्परिक उत्पादों में जुड़े कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुये आधुनिक टूलकिट उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिताओं हेतु बिल भुगतान विषयक

1-डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में यू0 पी0 पी0 एल0 द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं हेतु लगाये गये टेण्ट आदि का वित्तीय वर्ष 2023-24 के बकाया बिलों की धनराशि लगभग 10 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त बकाया धनराशि कब तक क्रिकेट एसोसिएशन से सरकारी खाते में जमा करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

प्रश्नगत खेल प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराया गया है, जिससे उल्लिखित बिल भुगतान की कार्यवाही खेल विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरिलिखित स्वतः स्पष्ट स्थिति के कारण।

प्रदेश के बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल में दुसाध जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

2-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ढाढ़ी जाति दुसाध जाति की उपजाति के अन्तर्गत चिन्हित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के बस्ती, गोण्डा तथा देवीपाटन मण्डल में उक्त जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि ढाढ़ी किस जाति के अन्तर्गत आते हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में उ0प्र0 की अनुसूची के क्रमांक-33 पर 'दुसाध' (Dusadh) जाति अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है।

समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-97/2021/1898/ 26-3-2021, दिनांक 06 अगस्त, 2021 के क्रमांक-15 पर जनपद बलिया में दुसाध जाति विमुक्त जाति की सूची में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के साथ सूचीबद्ध है।

उपरिवर्णित राजपत्र तथा शासनादेश में ढाढ़ी जाति का उल्लेख दुसाध अनुसूचित जाति की उपजाति के रूप में अंकित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ढाढ़ी जाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त जाति की किसी भी सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस-वे की टेल पर अधिग्रहीत कतिपय ग्रामों की भूमि के सर्किल रेट में भिन्नता विषयक

3-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस-वे की टेल पर यूपीडा द्वारा ग्रीन फील्ड औद्योगिक गलियारा विकसित करने हेतु सोरांव तहसील की ग्राम माधोपुर मालक चतुरी, ग्राम जुड़ापुर दादू, ग्राम बारी, ग्राम सराय लालखातून में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया व समान भूमि पर विभिन्न ग्राम पंचायत के सर्किल रेट में भारी भिन्नता होने से किसानों को भारी आर्थिक क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्किल रेट आदि की विसंगतियों को दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सिंह सैनी)-

जी नहीं।

जनपद प्रयागराज की तहसील सोरांव में औद्योगिक गलियारा के निर्माण हेतु ग्राम माधोपुर मलाक चतुरी, ग्राम जूड़ापुर दांदू, ग्राम बारी, ग्राम सरांय लाल खातून में भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-01 के अनुसार दर का निर्धारण किया जाता है, उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, क्रय किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि के आस-पास परियोजना प्रारम्भ होने अथवा परियोजना के अनुमोदन प्रदान किये जाने के दिनांक से 06 माह पूर्व के निष्पादित विक्रय विलेखों (बैनामों) में अंकित भूमि की दर तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत

निर्धारित सर्किल दर में से जो अधिक हो, के आधार पर अधिक मूल्य पर ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस प्रकार की सर्किल रेट आदि की कोई विसंगति नहीं पायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्वदशम्/दशमोत्तर के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

4-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 से दिनांक 18-12-2023 तक पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु कितने आवेदन किए गए थे ? क्या सरकार बताएगी कि कुल आवेदक के सापेक्ष कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त हो रही है तथा कितने आवेदक अवशेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) में छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 से दिनांक 18.12.2023 तक पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में आवेदनों की संख्या का वर्षवार, वर्गवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	पूर्वदशम्			दशमोत्तर		
	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
2020-21	406446	3884	133236	982056	14214	649851
2021-22	464701	3528	178751	1474713	18962	1071809
2022-23	552954	3941	192842	1363312	15804	901486
2023-24	397538	2881	151969	432763	11977	516971

1-वर्ष 2020-21 से दिनांक 18-12-2023 तक पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में भुगतानित आवेदकों की संख्या का वर्षवार, वर्गवार विवरण निम्नवत है :-

वर्ष	पूर्वदशम्			दशमोत्तर		
	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग
2020-21	362511	2007	118153	802648	8132	500204
2021-22	320390	815	124193	1229471	8930	538642
2022-23	386139	1579	172566	939695	6427	704506
2023-24	माह मार्च, 2024 में पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं के पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।					

2-वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 21,706 छात्रों को भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विमुक्त व घुमन्तू जातियों हेतु राज्य स्तरीय विमुक्त एवं घुमन्तू जाति विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना कराने विषयक

5-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

द्वितीय सत्र, 2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या-08 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवासित लगभग 24 प्रतिशत विमुक्त एवं 02 प्रतिशत घुमन्तू जातियों के विकास और कल्याण के लिए एक राज्य स्तरीय 'विमुक्त एवं घुमन्तू जाति विकास और कल्याण बोर्ड' की स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो बोर्ड द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

इस सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाने की मांग

6-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

जी हाँ।

मद्य निषेध विभाग, उ0प्र0 द्वारा 05 वर्ष तक की कार्य योजना बनाई गयी है, जिसके तहत विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से युवकों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु उनको नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के सम्बन्ध में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराने एवं ब्याज मुक्त ऋण दिलाने की माँग

7-डॉ0 पल्लवी पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराये जाते हैं एवं अनुदान की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।

प्रदेश में कृषकों के लिये विभिन्न फसलों के बीजों पर केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुमन्य किया गया है।

केन्द्र पोषित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक वितरित बीज पर अथवा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित बीज पर भी राज्य सरकार द्वारा बीज मूल्य के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य दलहन और तिलहन योजना तथा उ0प्र0 राज्य श्रीअन्न पुनरोद्धार योजना के अन्तर्गत इच्छित किसानों को उन्नत किस्म के निःशुल्क बीज के मिनीकिट उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में विमुक्त जनजातियों हेतु निर्गत शासनादेश का अनुपालन कर छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक

8-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विमुक्त जनजातियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु शासनादेश संख्या-97/2021/1898/26-3-2021, दिनांक

06 अगस्त, 2021 के अनुपालन के क्रम में प्रदेश में अद्यतन कितने छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण-पत्र जारी किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

प्रदेश के 10 जनपदों से अद्यतन प्राप्त सूचनानुसार कुल 1735 छात्र/छात्राओं को विमुक्त जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। शेष जनपदों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक समुदाय हेतु पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजनान्तर्गत अपात्रता का कारण बताने विषयक

9-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना अन्तर्गत प्रदेश के पिछड़े वर्ग सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उक्त योजना के पात्र नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त लोगों के पात्र न होने का कारण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-21/2016/396/64-2-2016-1(66)/2006, दिनांक 18 जुलाई, 2016 के द्वारा अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित है, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पात्र नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के बाद स्थापित कम्पनियों का विवरण उपलब्ध कराने की मांग

10-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के बाद प्रदेश में अब तक कितनी कम्पनियां स्थापित हुईं तथा कितने लोगों को रोजगार मिला है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित 'इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों के साथ रुपये 4.28 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों

(एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गए। इसके पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा 03 ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह जुलाई, 2018 में आयोजित किया गया था, जिसके अन्तर्गत 66 परियोजनायें संचालित की जा चुकी हैं, जिसमें 2,05,441 रोजगार का सृजन हुआ है।

द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह जुलाई, 2019 में आयोजित किया गया, जिसके अन्तर्गत 257 परियोजनाओं का संचालन प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें 90,871 रोजगार का सृजन हुआ है।

तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह 03 जून, 2022 को आयोजित किया गया था, जिसके अन्तर्गत 536 परियोजनाओं का संचालन प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें 47,916 रोजगार का सृजन हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

42वीं जूनियर प्रतिभा नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली निकिता सिंह पटेल को सम्मान एवं सहयोग दिलाये जाने विषयक

11-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 42वीं जूनियर प्रतिभा नेशनल शूटिंग बाल प्रतियोगिता में 22 प्रदेशों को हराकर राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली विधान सभा क्षेत्र सगड़ी, आजमगढ़ निवासी निकिता सिंह पटेल को उत्साहवर्धन के लिए सम्मान, सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ नान रिकरिंग ग्राण्ट फार फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन रूल्स-1981 के नियम-7 में निर्धारित अर्हता एवं शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने के कारण उत्तर प्रदेश शूटिंग बाल एसोसिएशन शासन की गाइड लाइन्स स्वीकार करने वाले मान्यता प्राप्त/सम्बद्धता प्राप्त प्रदेशीय क्रीडा संघों की सूची में सम्मिलित नहीं है। खेल विभाग द्वारा शासन की गाइड लाइन्स स्वीकार करने वाले मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त प्रदेशीय खेल संघों/उनके खिलाड़ियों को पदक प्राप्त करने पर शासनादेशों में अनुमन्य व्यवस्था के अन्तर्गत पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वालों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, यूपीडा के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर के रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण हेतु विभिन्न चरणों में यूपीडा द्वारा भूमि आवंटन किये गये हैं। यहां पर विभिन्न कम्पनियों द्वारा (डी0पी0आर0 के माध्यम से) कुल 934 लोगों के रोजगार के अवसर एवं रु0 547 करोड़ के निवेश प्रस्तावित किये गये हैं।

बुन्देलखण्ड डिफेंस कॉरिडोर में अवस्थापना एवं विकास का कार्य विभिन्न चरणों में अभी प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में निर्मित पार्क सैदनपुर छपिया का नामकरण पं0 दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर करने के सम्बन्ध में

13-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में निर्मित पार्क सैदनपुर छपिया का नामकरण पं0 दीन दयाल उपाध्याय करने के नाम पर अथवा पार्क में उनकी आदमकद मूर्ति लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद जौनपुर में सरकारी संस्था/प्राइवेट संस्था को आवंटित डी0ए0पी0 खाद का विवरण उपलब्ध कराने विषयक

14-श्री जगदीश नारायण-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में वर्तमान में कुल कितना डी0ए0पी0 खाद का आवंटन हुआ है एवं उक्त में कितना सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र को मिला तथा कितना प्राइवेट संस्था को आवंटित हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद जौनपुर में वर्तमान वर्ष 2023-24 में दिनांक 24 जनवरी, 2024 तक कुल 24112.00 मै0 टन डी0ए0पी0 उर्वरक का आवंटन हुआ, जिसमें से 7692.00 मी0 टन सहकारी क्षेत्र को आवंटित हुआ तथा 16420.00 मी0 टन प्राइवेट क्षेत्र को आवंटित हुआ है। सरकारी क्षेत्र द्वारा उर्वरकों का विक्रय नहीं कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

15-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्रसं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु नीति बनाये जाने विषयक

16-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था न होने से अधिकांश सड़कें जर्जर हैं ? क्या सरकार मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई उक्त सड़कों के अनुरक्षण हेतु कोई ठोस नीति बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् के स्वामित्व के 22 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत का कार्य उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् कराया गया है :-

वित्तीय वर्ष	मार्गों की संख्या	विभाग
2017-18 से पूर्व	05	अन्य विभाग
2017-18	14	मण्डी परिषद्
2020-21	01	मण्डी परिषद्
2021-22	02	मण्डी परिषद्
योग :	**22**	

अन्य विभाग द्वारा मण्डी परिषद् के स्वामित्व के 05 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराई गई, परन्तु अभिलेखीय रूप से यह मार्ग हस्तगत न किये जाने के कारण वर्तमान में भी मण्डी

परिषद् के स्वामित्व में हैं। इन 05 सम्पर्क मार्गों में से आवश्यकतानुसार वर्ष 2023-24 में 02 सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति निर्गत की गयी है-

(1) बड़कापुर से बीर खेत लम्बाई-1.80 किमी

(2) सम्पर्क मार्ग गोल्हईपुर लम्बाई-0.20 किमी0

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बभनजोत/छपिया/मनकापुर के कृषक सम्मान निधि से वंचित किसानों को निधि दिलाये जाने के सम्बन्ध में

17-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत/छपिया/मनकापुर के कृषक सम्मान निधि के अन्तर्गत छूटे हुए किसानों को सम्मान निधि सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थी कृषकों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को योजनान्तर्गत लाभ देने हेतु शामिल करने, मृत्यु एवं अपवर्जन श्रेणी में आने पर उन्हें अपात्र करने की कार्यवाही चलती रहती है, यह एक सतत् प्रक्रिया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषकों की सुविधा हेतु पीएम-किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से पंजीकरण की सुविधा भारत सकरार द्वारा दी गयी है। किसान www.pmkisan.gov.in के माध्यम से कहीं से भी अपना रजिस्ट्रेशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कर अथवा करा सकता है।

रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सत्यापन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भारत सरकार द्वारा योजना का लाभ स्वीकृत किया जाता है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है, जो योजना लागू रहने तक चलती रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी में कानपुर हाई-वे पर कोछाभांवर में बन्द चीनी पात्र विकास केन्द्र की खाली पड़ी भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स स्थापित कराये जाने विषयक

18-श्री रवि शर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी में कानपुर हाई-वे पर कोछाभांवर में बन्द चीनी पात्र विकास केन्द्र की खाली पड़ी साढ़े चार एकड़ भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स स्थापित करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्री

कॉर्पोरेशन (यू0पी0एस0आई0सी0) के पास प्रस्ताव लम्बित है ? क्या सरकार झाँसी के उद्यमियों को लाभ पहुंचाने हेतु उक्त भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हाँ।

जनपद झांसी में कानपुर हाई-वे पर कोछाभांवर में बन्द चीनी पात्र विकास केन्द्र की खाली पड़ी साढ़े चार एकड़ भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स स्थापित करने हेतु उपायुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र झांसी द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्री कार्पोरेशन लि0 (यू0पी0एस0आई0सी0) कानपुर से किये गये अनुरोध के क्रम में संयुक्त आयुक्त उद्योग (क्लस्टर), उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-497, दिनांक 29-11-2022 द्वारा निर्देश दिये गये कि फ्लैटेड फैक्ट्री से लाभान्वित होने वाले सभी हितधारकों के मध्य सर्वे कराते हुए मांग के सम्बन्ध में आकलन कर लिया जाये, यदि विभिन्न हितधारकों द्वारा फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना पर बल दिया जाये, तो तद्नुसार प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत प्रस्तुत किया जाये। उक्त के क्रम में जनपद झाँसी में उपायुक्त, उद्योग झाँसी द्वारा दिनांक 12-12-2022 को महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यापारिक संगठनों एवं उद्यमियों के साथ आहूत बैठक में मात्र 02 उद्यमियों द्वारा ही प्रतिभाग किया गया। बैठक में फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना हेतु हितधारकों द्वारा रुचि न दिखाये जाने के कारण प्रस्ताव पर कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण के सम्बन्ध में

19-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम एवं ओपेन जिम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो कितने और कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम एवं ओपन जिम बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण योजना संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम सभाओं का सर्वे कराकर सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री मोहन वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम सभाओं का सर्वे कराकर (जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी 25 प्रतिशत से ऊपर है) सामुदायिक भवन निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 54/2022/264/26-3-2022-10 (15)/2007, दिनांक 10-05-2022 में दी गयी व्यवस्था/मानकों के अनुसार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं योजनान्तर्गत बजट की उपलब्धता होने पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में फसलों के खर-पतवार एवं अन्य बीमारियों के रोकथाम हेतु कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराने की मांग

21-श्री जगदीश नारायण-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसलों के खर-पतवार तथा अन्य बीमारियों के रोकथाम हेतु कीटनाशक दवा जिलेवार सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त आवंटन की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा खरीफ एवं रबी फसलों हेतु कृषि रक्षा रसायनों का आवंटन, फसलों के आच्छादन, विगत वर्ष सामायिक कीट/रोग एवं खर-पतवार के प्रकोप की स्थिति तथा विगत वर्ष की खपत के अनुसार जनपदवार आवंटन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में निर्वाण उपायुक्त उद्योग, फिरोजाबाद द्वारा नये उद्योगों की स्थापना हेतु एम0 ओ0 यू0 द्वारा शासन व प्रशासन को भ्रमित करने की जांच के सम्बन्ध में

22-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक : एम0एस0/98/2023/1218, दिनांक 23-06-2023, जोकि जनपद फिरोजाबाद में निर्वाण उपायुक्त उद्योग, फिरोजाबाद द्वारा नये उद्योगों की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 द्वारा शासन व प्रशासन को भ्रमित करने की जांच के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

उक्त पत्र दिनांक 23-06-2023 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है। यह पत्र आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, कानपुर को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जाँच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज एवं रामनगर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज एवं विकास खण्ड रामनगर में खेल स्टेडियम का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण योजना संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश के किसानों को पारदर्शी माध्यम से अनुदानित कृषि यंत्र दिलाये जाने की मांग

24-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश में किसानों को बंटने वाले अनुदानित कृषि यंत्रों को दलालों के मार्फत बांटे जाने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा कोई भी यंत्र दलालों के माध्यम से वितरित नहीं किया जाता है। विभागीय पोर्टल www.upagriculture.gov.in पर पंजीकृत कृषक कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। बुकिंग के उपरान्त पूर्ण पारदर्शी एवं कम्प्यूटराइज्ड ई-लाटरी के माध्यम से चयनोपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार चयनित कृषि यंत्र क्रय कर अनुदान प्राप्त कर सकता है। लाथार्थी कृषकों का चयन पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से किये जाने के लिए ई-लाटरी प्रणाली को अपनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को निधि दिलाये जाने विषयक

25-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश में किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को आवश्यक कागजात बनवाने में आ रही दिक्कतों से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक उक्त का निराकरण कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

भारत सरकार द्वारा पूर्व में किसानों को योजना सम्बन्धी परेशानियों से निजात पाने के लिए, योजना को पूर्णतः ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में कृषक www.pmkisan.gov.in पर जाकर स्वतः या किसी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से सरलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा सकते हैं व पात्रता की स्थिति में आने पर योजना का नियमानुसार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा तहसील व ग्राम स्तर पर कैम्प लगाकर भी कृषकों के समस्याओं का निराकरण किया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामवार कैम्प लगाकर कृषकों की समस्याओं का निदान किया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत युवाओं की प्रतिभा को निखारने हेतु मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने विषयक

26-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत युवाओं को खेलने व उनके प्रतिभा को निखारने हेतु मिनी स्टेडियम सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण योजना संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में बने वनपुरवा स्टेडियम के रख-रखाव हेतु धन आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री जगदीश नारायण-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर में बने वनपुरवा स्टेडियम के रख-रखाव हेतु सरकार धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

शासन के पत्र दिनांक 04 जनवरी, 2024 द्वारा प्रश्नगत स्टेडियम के अनुरक्षण हेतु रुपये 49.45 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा जर्जर बटेश्वर मुख्य मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

28-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित शिकोहाबाद बटेश्वर मुख्य मार्ग से ग्राम खितौली तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढा युक्त है ? क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

सम्पर्क मार्ग 'बटेश्वर मार्ग से खितौली' लम्बाई 0.83 किमी0 का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1995-96 में कराया गया था। वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रहण कर मरम्मत कार्य करा दिया गया है।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रहण कर मरम्मत करा दिये जाने के फलस्वरूप मण्डी परिषद् स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विधान लगा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा आलमपुर से बाछेमई तक जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की माँग

29-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ग्राम आलमपुर से बाछेमई तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढा युक्त है, जिससे आम-जनों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

सम्पर्क मार्ग 'जायमई से बाछेमई लहटई आलमपुर' लम्बाई-3.50 कि0मी0 मण्डी परिषद् के स्वामित्व का मार्ग की चैनेज 0.00 से 1.50 किमी0 में लोक निर्माण विभाग द्वारा चौड़ीकरण कराते हुए पुनर्निर्माण करा दिये जाने के फलस्वरूप मण्डी परिषद् के स्वामित्व का मात्र 2.00 कि0मी0 का मार्ग शेष है।

अवशेष लम्बाई 2.00 कि0मी0 की मरम्मत हेतु मण्डी परिषद् पत्रांक-1750, दिनांक 01-12-2023 द्वारा धनराशि आवंटित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा पुन्छा-नसीरपुर मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

30-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित पुन्छा-नसीरपुर मार्ग से गुढ़ा तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढा युक्त है, जिससे आमजनों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग 'पुन्छा नसीरपुर मार्ग से गुढ़ा' मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में ग्राम आलीपुर से मातादीन की ठार तक जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्ग का नव निर्माण कराये जाने विषयक

31-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में ग्राम आलीपुर से बालादीन की ठार तक मार्ग कच्चा एवं गड्ढा युक्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग ग्राम आलीपुर से बालादीन की ठार तक नवीन सम्पर्क मार्ग की श्रेणी में है।

जिलाधिकारी द्वारा मण्डी समिति का अनुमोदित प्रस्ताव, आवश्यकता, औचित्य एवं मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत नवीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत पिड़सरा से सकतपुर तक जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

32-श्री सर्वेश सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित पिड़सरा से सकतपुर तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार सड़क का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पिड़सरा से सकतपुर लम्बाई 1.30 किमी0 मण्डी परिषद् के स्वामित्व का मार्ग है, जिसकी मरम्मत का कार्य वर्ष 2019-20 में कराया गया था। शिकोहाबाद-मैनपुरी फोर लेन मार्ग के निर्माण के समय भारी वाहनों के अत्यधिक आवागमन के

कारण 200 मीटर लम्बाई में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत हेतु उप निदेशक (निर्माण), आगरा द्वारा एन0एच0ए0आई0 से अनुरोध किया गया है।

शासनादेश के अनुसार क्षतिग्रस्त लम्बाई 0.20 किमी0 की मरम्मत का दायित्व एन0एच0ए0आई0 का है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के लाभ हेतु परिवार की आय का मानक एवं आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने विषयक

33-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कितनी-कितनी वार्षिक आय वाले परिवारों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ? क्या सरकार उक्त योजना के लाभ हेतु वार्षिक आय एवं दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोत्तरी पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080/-एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460/-वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों की अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु प्रति शादी रु0 20000/-की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड भटनी व तरकुलवा में मिनी स्टेडियम बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

34-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भटनी के सल्लहपुर व विकास खण्ड तरकुलवा के सरवनइया/गोपालपुर में मिनी स्टेडियम बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-7 न0 012524 दिनांक 25-05-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हाँ।

शासन के पत्र दिनांक 16-08-2023 के माध्यम से उक्त पत्र महानिदेशालय में प्राप्त हुआ था, जिसे महानिदेशालय के पत्र दिनांक 12-09-2023 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी, देवरिया से सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त न होने पर पुनः शासन के पत्र दिनांक 01-02-2024 द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14-03-2023 के आलोक में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए सुसंगत प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर मण्डल में उद्यान विभाग को आवंटित बजट का विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक

35-श्री नाहिद हसन-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर मण्डल में उद्यान विभाग को वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक 22-12-2023 तक मदवार कुल कितना बजट आवंटित हुआ ? क्या सरकार बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में कोल्ड स्टोरेज लगाने हेतु सब्सिडी आधारित कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर मण्डल के किन-किन ब्लॉक्स को कोल्ड स्टोरेज लगाने हेतु चयनित किया गया है ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

सहारनपुर मण्डल में वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 22-12-2023 तक आवंटित धनराशि का मदवार विवरण :-

क्र0-सं0	मद का नाम	आयोजनेत्तर	पर ड्राप मोर क्राप	आयुष मिशन	मिशन	आर0के0 वी0वाई0	कुल धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	वेतन	1601.06					1601.06
02	मजदूरी	137.16			2.49		139.65
03	महंगाई भत्ता	532.42					532.42
04	यात्रा व्यय	8.46			0.05		8.51
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.47					3.47
06	अन्य भत्ते	0.55					0.55
08	कार्यालय व्यय	5.11			0.69		5.80
09	विद्युत देय	20.93					20.93
10	जलकर/जल प्रभार	2.55					2.55
11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.19			0.44		3.63
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.10					1.10

1	2	3	4	5	6	7	8
13	टेलीफोन पर व्यय	1.26			0.03		1.29
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.29			0.46		7.75
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.20					0.20
17	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	9.95					9.95
18	प्रकाशन	0.55			0.45		1.00
19	विज्ञापन				0.40		0.40
20	सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन	41.55					41.55
21	छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन	0.26					0.26
24	वृहत् निर्माण कार्य					79.60	79.60
27	सब्सिडी	141.61	3677.93	40.15	288.81	141.87	4290.37
29	अनुरक्षण	30.90			0.1		31.00
42	अन्य व्यय	45.67	23.12		3.96	11.75	84.50
43	सामग्री एवं सम्पूर्ति	101.67			2.54		104.21
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	21.44	8.78				30.22
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.45					0.45
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.95			0.7		2.65
49	चिकित्सा व्यय	25.10					25.10
51	वर्दी व्यय	0.63					0.63
55	मकान किराया भत्ता	70.93					70.93
58	आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.82			0.5		1.32
	योग :	**2818.25**	**3709.83**	**40.15**	**301.62**	**233.22**	**7103.07**

जी हां।

भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग (उद्यान), कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों-2014 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर अधिकतम भण्डारण क्षमता-5000 मीट्रिक टन तक, प्रति इकाई 35 प्रतिशत अनुदान धनराशि क्रेडिट लिंक्ड बैंक एडेड सब्सिडी के रूप में अनुमन्य है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप-1 (अधिकतम-5000 मी0 टन)-मेजानाइन स्ट्रक्चर विथ लार्ज (आफ 250 मी0 टन) टाइप, विथ सिंगल टेम्परेचर जोन पर परियोजना लागत धनराशि रु0 400.00 लाख (रु0 8000 प्रति मी0 टन अधिकतम क्षमता 5000 मी0 टन) का 35 प्रतिशत, अधिकतम रु0 140.00 लाख प्रति लाभार्थी, क्रेडिट लिंक्ड बैंक एडेड सब्सिडी के रूप में देय है।

कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप-2 (अधिकतम-5000 मी0 टन) :-पी0ई0बी0 स्ट्रक्चर फार मल्टिपिल टैम्परेचर एण्ड प्रोडेक्ट यूज, 6 चैम्बर से अधिक (आफ 250 मी0 टन) एण्ड बेसिक मटेरियल हैण्डलिंग इक्यूपमेंट पर परियोजना लागत धनराशि रु0 500.00 लाख (रु0 10,000 प्रति मी0 टन0 अधिकतम क्षमता 5000 मी0 टन) का 35 प्रतिशत अधिकतम रु0 175.00 लाख तक क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है। उक्त के अतिरिक्त शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु 27 जनपदों के 58 विकास खण्डों में 01-01 शीतगृह, कुल 58 शीतगृहों को राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत अनुमन्य अनुदान के साथ-साथ 15 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सहायता टॉपअप के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित किये जाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत किसी स्थान व विकास खण्ड को चयनित नहीं किया जाता है।

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु सहारनपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद शामली के विकास खण्ड-कैराना एवं बनत में 02 व्यक्तियों द्वारा आवेदन किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	जनपद	विकास खण्ड	लाभार्थी का नाम	परियोजना लागत	अनुमन्य परियोजना लागत	अनुदान धनराशि	भण्डारण क्षमता (मी0 टन)
1	शामली	कैराना	श्री सुमित कुमार	247.00	148.1432	51.8501	1851.79

2		बनत	श्री परवीन कुमार	291.26	267.81	93.73	3525.36
कुल योग :				**538.26**	**415.9532**	**145.5801**	**5377.15**

सहकारी और सरकारी स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने विषयक

36-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी और सहकारी स्टोर पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध नहीं होने के कारण निजी दुकानदारों द्वारा नैनो यूरिया अथवा उक्त के स्थान पर अन्य चीज बेचे जाने से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि तक सरकारी एवं सहकारिता की दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना तथा निजी दुकानदारों द्वारा बिना मिलावट के यूरिया बिकवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश सरकार कृषकों को गुणवत्तायुक्त यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सहकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बिक्री केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

प्रदेश में रबी सीजन में लक्ष्य के सापेक्ष यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता निम्नवत् रही :-

(दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से दिनांक 25 जनवरी, 2024 तक)

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

उर्वरक	लक्ष्य	उपलब्धता
यूरिया	28.63	40.13
डी0ए0पी0	13.42	14.10
एन0पी0के0	3.35	7.00
एम0ओ0पी0	1.09	1.22
एस0एस0पी0	2.62	3.44
योग :	**49.11**	**65.89**

सहकारी एवं निजी बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 में उल्लिखित उर्वरकों यथा-नैनो यूरिया व अन्य उर्वरक कृषकों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बिक्री की जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रदेश में गुणवत्तायुक्त यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरक सुगमतापूर्वक कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया में सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था आश्रम को आवंटित धनराशि का विवरण

37-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में सरकार द्वारा वृद्धावस्था आश्रम संचालित है ? यदि हां, तो क्या उक्त वृद्धावस्था आश्रम में विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 एवं 2023-24 में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनपद बलिया में वृद्धावस्था आश्रम निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री असीम अरूण-

जी हाँ।

जनपद-बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से 150 वृद्ध संवासियों की क्षमता का वृद्धाश्रम संचालित है। उक्त वृद्धाश्रम को विगत 03 वित्तीय वर्षों में आवंटित की गयी धनराशि निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2021-22	रु0 60,22,901/-
2022-23	रु0 63,95,902/-
2023-24 (माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 तक)	रु0 51,87,874/-

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डॉ0 रागिनी-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती में भानपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पडरिया दत्तू सेहमो मार्ग का पुनर्निर्माण कराने विषयक

39-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में भानपुर तहसील के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित ग्राम पडरिया दत्तू से सेहमो मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य वर्ष 2017 में कराया गया था। वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है, तो सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के करायी जाती है। उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है तो, विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद किरोजाबाद के खैरगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु पर कार्यवाही किये जाने विषयक

40-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र में 17 नवम्बर, 2020 को जहरीली शराब के कारण तीन लोगों की मौत से जुड़े मामले में अब तक हुई कार्रवाई के प्रमुख तथ्य सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल-

जनपद फिरोजाबाद के खैरगढ़ थाना क्षेत्र में 17 नवम्बर 2020 को जहरीली शराब के कारण 03 लोगों की मौत से जुड़े मामले में तत्समय अभियुक्त 1-श्यामवीर पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी शेखपुरा, खैरगढ़, फिरोजाबाद, 2-व्यापारी पुत्र रामभान, निवासी-शेखपुरा, खैरगढ़, फिरोजाबाद, 3-घासीराम पुत्र रामप्रसाद उर्फ मोटे, निवासी शेखपुरा, खैरगढ़, फिरोजाबाद के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा 272 एवं 304 तथा आबकारी अधिनियम की धारा 60, 60 (क) व 63 में मुकदमा दर्ज कराते हुए थाना खैरगढ़ में एफ0आई0आर0 संख्या-180, दिनांक 20-11-2020 तथा एफ0आई0आर0 सं0-183, दिनांक 22-11-2020 दर्ज करायी गयी।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के विरुद्ध उ0 प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 व 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दिनांक 10-01-2021 को एफ0 आई0 आर0 संख्या 001 थाना-खैरगढ़, फिरोजाबाद में 1-सुखवीर

सिंह पुत्र फेरू सिंह, निवासी विदरखा, फिरोजाबाद, 2-रामू उर्फ रामगोपाल पुत्र चोब सिंह, निवासी दिखतौली, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, 3-लव उर्फ मालिक पुत्र श्री सत्य प्रकाश आरोंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, 4-कन्हैया पुत्र हरी सिंह, निवासी विदरखा, फिरोजाबाद, 5-हरदेश यादव उर्फ सुशील पुत्र विश्राम सिंह, निवासी महादेव नगर, रामगढ़, फिरोजाबाद, 6-महेश उर्फ बट्टा पुत्र रामगोपाल, निवासी मोहल्ला खेड़ा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, 7-राम अवतार पुत्र राम प्रकाश, निवासी बिजौली खैरगढ़, फिरोजाबाद, 8-अवधेश पुत्र दुर्गा प्रसाद, बिजौली, खैरगढ़, फिरोजाबाद 9-व्यापारी उर्फ सत्यवीर पुत्र रामभान, निवासी शेखपुरा खैरगढ़, फिरोजाबाद, 10-घासीराम पुत्र रामप्रसाद, निवासी शेखपुरा, खैरगढ़, फिरोजाबाद, 11-श्यामवीर पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी-शेखपुरा खैरगढ़, फिरोजाबाद के विरुद्ध दर्ज करायी गयी।

उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, फिरोजाबाद को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाते हुए कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय प्रयागराज से सम्बद्ध किया गया एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3 जसराना व क्षेत्रीय प्रधान आबकारी सिपाही को निलम्बित कर मुख्यालय, प्रयागराज से सम्बद्ध कर दिया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में तैनात 03 अन्य आबकारी सिपाहियों को निलम्बित कर कार्यालय उप आबकारी आयुक्त, आगरा प्रभार, आगरा से सम्बद्ध कर सभी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के पिछड़ी जाति के गरीब व निराश्रित परिवार की पुत्रियों को शादी अनुदान से लाभान्वित कराये जाने विषयक

41-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में पिछड़ी जाति के गरीब एवं निराश्रित परिवार की पुत्रियों को शादी अनुदान हेतु आनलाइन/ऑफलाइन तहसीलवार कितने आवेदन किये गये हैं तथा आवेदन के सापेक्ष वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में तहसीलवार कितने-कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार अवशेष परिवार की पुत्रियों को शादी अनुदान से लाभान्वित कराकर सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

शादी अनुदान योजनान्तर्गत जनपद बलिया में पिछड़ी जाति (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आनलाइन/आफलाइन तहसीलवार किये गये आवेदन एवं आवेदनों के सापेक्ष वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में लाभान्वितों का तहसीलवार विवरण निम्नवत हैं :-

तहसील का नाम	वर्ष 2021-22		वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24	
	कुल आवेदनों	कुल लाभान्वितों	कुल आवेदनों	कुल लाभान्वितों	कुल आवेदनों	कुल लाभान्वितों

	की संख्या	की संख्या	की संख्या	की संख्या	की संख्या	की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
बैरिया	1169	278	652	156	314	159
बलिया	3376	378	1564	145	449	126
1	2	3	4	5	6	7
बांसडीह	3290	605	1649	222	588	225
बेल्थरा रोड	1447	112	640	39	146	35
रसडा	988	40	497	12	52	10
सिकन्दरपुर	1280	131	628	34	171	51

नहीं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में उपलब्ध बजट की सीमा तक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। शासनादेश संख्या-21/2016/396/64-2-2016-1(66)/2006, दिनांक 18 जुलाई, 2016 के बिन्दु संख्या-4 (xvi) के प्राविधानानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जाती है। अतः नियमानुसार विगत वर्ष के अवशेष आवेदकों को योजना से लाभान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर अन्तर्गत चाँदपुर अम्हेडा मार्ग से ग्राम अज्जूनंगली तक जीर्ण-शीर्ण मार्ग का पुनर्निर्माण कराने विषयक

42-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-अम्हेडा मार्ग से ग्राम अज्जूनंगली तक का राज्य मण्डी परिषद् द्वारा डामरीकरण कर बनाया गया मार्ग जीर्ण-क्षीर्ण हो गया है तथा मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना तथा क्षेत्रवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

सम्पर्क मार्ग ''चांदपुर-अम्हेड़ा ग्राम-अज्जूनंगली'' का मरम्मत कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया था। मार्ग पर शुगर मिल के भारी वाहनों के आवागमन से वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के करायी जाती है। अनुरक्षण नीति-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष

पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है तो, विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत छाछरी-स्याऊ मार्ग से शेखुपुरा घनसुरपुर तक जीर्ण-शीर्ण मार्ग का मम्मतीकरण कराने विषयक

43-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत छाछरी-स्याऊ मार्ग से शेखुपुरा घनसुरपुर तक का राज्य मण्डी परिषद् द्वारा डामरीकरण कर बनाया गया मार्ग जीर्ण-शीर्ण हो गया है तथा मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना तथा क्षेत्रवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

सम्पर्क मार्ग 'छाछरी-स्याउ मार्ग से शेखपुर धनसुरपुर तक' का मरम्मत कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया था। भारी वाहनों के आवागमन के कारण वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के करायी जाती है। अनुरक्षण नीति-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है तो, विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के चाँदपुर-गजरौला मार्ग से रामपुर नजराना तक जर्जर मार्ग का पुनर्निर्माण कराने की मांग

44-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के चाँदपुर-गजरौला मार्ग सें रामपुर नजराना तक का मण्डी परिषद् द्वारा डामरीकरण कर बनाया गया मार्ग जीर्ण-शीर्ण तथा मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना तथा क्षेत्रवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

सम्पर्क मार्ग 'चांदपुर-गजरौला मार्ग से रामपुर नजराना तक' का मरम्मत कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया था। भारी वाहनों के आवागमन के कारण वर्तमान में मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के करायी जाती है। अनुरक्षण नीति-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है तो, विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के फीना-धनौरा मार्ग से मलेशिया तक जर्जर मार्ग का पुर्ननिर्माण कराये जाने विषयक

45-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के फीना-घनौरा मार्ग से मलेशिया तक का मण्डी परिषद् द्वारा डामरीकरण कर बनाया गया मार्ग जीर्ण-शीर्ण तथा मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना तथा क्षेत्रवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

सम्पर्क मार्ग 'चांदपुर के फीना-घनौरा मार्ग से मलेशिया तक' का मरम्मत कार्य वर्ष 2017-18 में कराया गया था। मार्ग पर गन्ना सेंटर स्थापित है, भारी वाहनों के आवागमन से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

मण्डी परिषद् द्वारा 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के करायी जाती है। अनुरक्षण नीति-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है तो, विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

46-श्री कवीन्द्र चौधरी-

[दिनांक-07-02-2024 को 01-बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-206 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती में औद्योगिक क्षेत्र में पार्क व अपशिष्ट गृह का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

47-श्री कविन्द्र चौधरी

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के औद्योगिक क्षेत्र में पार्क बनाने व कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट को डालने के लिए आरक्षित भू-खण्डों पर कोई कार्य नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त भू-खण्डों पर पार्क व अपशिष्ट गृह का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'

औद्योगिक क्षेत्र बस्ती में स्थित कारखानों/उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को डालने के लिए कोई भू-खण्ड आरक्षित नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों का निस्तारण सम्बन्धित उद्योगों द्वारा स्वयं अपने स्तर से ही किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों में दी जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

48-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई है ? क्या सरकार उक्त का वर्षवार, श्रेणीवार, छात्रों की संख्यावार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार की प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के अन्तर्गत पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) में छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्रदान की जाती है। जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम् (कक्षा 9-10) तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में भुगतानित छात्रों की संख्या का वर्षवार, वर्गवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	दशमोत्तर			पूर्वदशम्		
	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग

1	2	3	4	5	6	7
2013-14	1095526	14729	664531	428331	5045	227009
2014-15	938264	8449	370913	193882	1665	21251
1	2	3	4	5	6	7
2015-16	722031	6840	427799	83364	471	15564
2016-17	1137851	14909	580621	323179	3587	79978
2017-18	1280515	15610	571782	416860	4064	77777
2018-19	1143804	15238	600069	524426	4064	62326
2019-20	1360376	12366	699359	541386	4004	88113
2020-21	802648	8132	580621	362511	2007	118153
2021-22	1229471	8930	571782	320390	811	124193
2022-23	939695	6427	600069	386139	1579	172566
योग	**10650181**	**111630**	**5667546**	**3580468**	**27297**	**986930**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

समाज कल्याण विभाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार सम्पूर्ण भारत में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं योजनान्तर्गत आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

49-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 06-02-2024 को 01-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-202 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

50-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक उपयोग किन्तु फसलों द्वारा नाइट्रोजन को बेहद कम ग्रहण किए जाने के कारण पर्यावरण में

इसका रिसाव बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने के लिए इस स्थिति से निपटने हेतु बनाई गई योजना का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

फसलों में मृदा परीक्षण के आधार पर संस्तुत मात्रा में नत्रजन उर्वरकों का उचित समय पर एवं उपयुक्त विधि के द्वारा उपयोग किये जाने पर पौधे के द्वारा अधिक मात्रा में नत्रजन ग्रहण किया जाता है तथा पर्यावरण पर इसका रिसाव न्यून रहता है।

पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश सरकार बेहद संवेदनशील है। संतुलित मात्रा में उपयुक्त विधि से उर्वरकों का उपयोग करने, हरी खाद एवं कम्पोस्ट खाद का उपयोग करने हेतु जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के महिला बाक्सर तैयार करने हेतु महिला बाक्सिंग एकेडमी स्थापित करने के सम्बन्ध में

51-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के महिला बॉक्सर तैयार करने हेतु जनपद लखनऊ में मलिहाबाद में संचालित जोश बॉक्सिंग एकेडमी की भांति प्रदेश में अन्य स्थानों पर महिला बॉक्सिंग एकेडमी स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नही।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों यथा-बलरामपुर, बहराइच, भदोही व महाराजगंज में विभागीय बॉक्सिंग प्रशिक्षकों तथा जनपद इटावा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, प्रयागराज, बदायूँ, फर्रुखाबाद, वाराणसी, बागपत (बड़ौत तथा खेकड़ा में), मथुरा, बलिया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, खेकड़ा (बागपत) में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों द्वारा स्थानीय बॉक्सिंग खेल के प्रशिक्षण शिविर संचालित हैं, जहां पर बालक/बालिकाओं को बॉक्सिंग खेल में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा बाक्सिंग के 15-15 खिलाडियों हेतु जनपद मेरठ तथा जनपद झाँसी में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास संचालित हैं। उक्त छात्रावास के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा तथा खेल किट की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने हेतु शासनादेश दिनांक 17-10-2016 द्वारा व्यवस्था की गयी है।

जनपद फिरोजाबाद के नगर पालिका शिकोहाबाद में सी0एन0जी0, पी0एन0जी0 तथा प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक एम0एस0/98/2023/1206, दिनांक 02-06-2023 एवं एम0एस0/98/2023/1295, दिनांक 04-09-2023 जो जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के नगर पालिका, शिकोहाबाद में सी0एन0जी0 पम्प/प्वाइन्ट स्थापित कराने, पी0एन0जी0 गैस की आपूर्ति किये जाने तथा प्राकृतिक गैस उद्योगों को उपलब्ध कराने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जसवन्त सिंह सैनी-

जी नहीं। औद्योगिक विकास विभाग में अप्राप्त है।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02-06-2023 मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है। जिस पर आईजीआरएस पोर्टल पर मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ संख्या-18147230099715 सृजित हुआ है। उक्त पत्र दिनांक 09-06-2023 को ऊर्जा तथा खाद्य एवं रसद विभाग को अंतरित किया गया है। उक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में ऊर्जा तथा खाद्य एवं रसद विभाग एवं जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा पोर्टल पर आख्या अपलोड की गई है।

उक्त सन्दर्भ दिनांक 10-08-2023 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को संदर्भित किया गया है। सम्प्रति उक्त सन्दर्भ संख्या-18147230099715 निस्तारित दर्शित है।

पत्र दिनांक 04-09-2023 मा0 सदस्य के पूर्व पत्र दिनांक 02-06-2023 का अनुस्मारक है। कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापा नहीं गया।

जनपद फिरोजाबाद में तत्कालीन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा धनराशि के दुरुपयोग की जाँच कराने सम्बन्धी

53-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक एम0एस0/98/2023/1206, दिनांक 02-06-2023 एवं एम0एस0/98/2023/1295, दिनांक 04-09-2023 जो जनपद फिरोजाबाद में तत्कालीन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, फिरोजाबाद के द्वारा उक्त धनराशि के दुरुपयोग की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

औद्योगिक विकास विभाग एवं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पत्र दिनांक 02-06-2023 एवं दिनांक 04-09-2023 प्राप्त नहीं हुये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

54-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[दिनांक 06-02-2024 को 01 मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-204 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज दिये जाने की मांग

55-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झारखण्ड राज्य की भाँति प्रदेश में भी किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश में कृषकों को विभिन्न फसलों के बीजों पर बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है एवं अनुदान की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तान्तरित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं/राज्य योजना के अन्तर्गत आयोजित फसल/क्लस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत चयनित कृषकों को वितरित बीजों पर 100 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 तक कृषकों को मिलेट्स, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के निःशुल्क बीज मिनीकिट का वितरण की योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, जिसमें कृषकों को निर्धारित मात्रा के बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित करने का प्राविधान किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जिलाधिकारी कार्यालय जौनपुर द्वारा गोंड जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी कराये जाने विषयक

56-श्री विनय प्रकाश गोंड-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी कार्यालय जौनपुर द्वारा गोंड जाति के लोगों का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जिलाधिकारी, जौनपुर से प्राप्त आख्यानुसार जनपद जौनपुर की ऐसी तहसीलें जहाँ गोंड जाति के लोग निवास करते हैं, में गोंड जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण करने के उपरान्त गोंड जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

निदेशक अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के पत्र पर जिलाधिकारी भदोही द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

57-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-181 के उत्तर के क्रम में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के पत्र दिनाँक 17-11-2023 द्वारा जनपद भदोही के जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 17-11-2023 के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी, भदोही के पत्र संख्या 3073/स0क0/वि0स0प्र0 /2023-24, दिनांक 03 फरवरी 2024 द्वारा तहसीलदार (तहसील-ज्ञानपुर, जनपद भदोही) की आख्या उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि श्री रामआसरे पुत्र जयराम, निवासी ग्राम जोधापुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही अनुसूचित जाति के नहीं हैं, उनका सम्बन्ध पिछड़ी जाति के चौहान (सिंह) जाति से है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के पडरौना शहर में रेलवे स्टेशन पर रसायनिक खाद का रैक प्वाइन्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में

58-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के पडरौना शहर में रेलवे स्टेशन पर रैक प्वाइंट की सुविधा होने के बावजूद रासायनिक खाद का रैक प्वाइंट देवरिया में लगाये जाने के कारण पडरौना से देवरिया जनपद की दूरी 54 किमी0 होने से क्षेत्र के लाखों किसानों को परिवहन के रूप में अतिरिक्त धनराशि व्यय करने के साथ ही साथ असुविधा का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार रासायनिक खाद का रैक प्वांइट पडरौना में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद कुशीनगर के पडरौना रेलवे स्टेशन के रैक प्वाइंट को उर्वरकों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा माह जनवरी, 2024 से क्रियाशील कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मैला ढोने वाले लोगों को पुनर्वासित करने की योजना का विवरण उपलब्ध कराने विषयक

59-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मैला ढोने वाले लोगों को पुनर्वासित करने की योजना है ? यदि हां, तो विगत 5 वर्ष में कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरुण-

जी हाँ।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अन्तर्गत मैनुअल स्कैवेन्जरों (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के पुनर्वासन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्वरोजगार योजना (एस0आर0एम0एस0) संचालित है। उक्त योजना के सफल संचालन, क्रियान्वयन तथा समन्वय हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 (अनुगम) राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सी है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण में 32,473 चिन्हित स्वच्छकारों (परिवार में से एक) को रु0 40,000/-की दर से रु0 12989.20 लाख की एकमुश्त नकद सहायता सीधे स्वच्छकारों के खाते में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है।

मैनुअल स्कैवेन्जर्स के पुनर्वासन की स्वरोजगार योजना (एस0आर0एम0एस0) के अन्तर्गत स्वरोजगार की विभिन्न परियोजनाओं में रु0 25,000/-से रु0 15.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें रु0 12,500/-से रु0 3.25 लाख तक अनुदान अनुमन्य है। ऋण हेतु इच्छुक स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अब तक 632 स्वच्छकारों को रु0 553.805 लाख अनुदान की धनराशि अवमुक्त करते हुए उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में प्रशिक्षित एवं सेवायोजित युवाओं का विवरण उपलब्ध कराने विषयक

60-श्री सचिन यादव-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में जनपदवार कुल कितने बेरोजगार युवा नामांकित, प्रशिक्षित एवं सेवायोजित किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्षों में इस योजना पर जनपदवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के जनपदवार बेरोजगार युवाओं को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित एवं सेवायोजित किये जाने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

प्रदेश में संचालित केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कुल 21066 अभ्यर्थियों का नामांकन किया

गया है। कुल नामांकित अभ्यर्थियों में से 15965 को कौशल प्रशिक्षित किया गया है एवं उनमें से 1282 को सेवायोजित किया गया है

वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्रदेश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक) संचालित नहीं हुई है। किन्तु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में अन्य योजनाओं के माध्यम से वर्तमान तक 5.57 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षित कराते हुए 1.20 लाख को रोजगार प्रदान कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में प्रशिक्षित किये गये 15965 प्रशिक्षार्थियों पर रु0 3047.43 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत संचालित बिल्डिंग एवं अदर कंस्ट्रशन वर्क्स योजनान्तर्गत ट्रेनिंग पार्टनर को भुगतान किये जाने विषयक

61-श्री पंकज पटेल-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत संचालित बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 से दिनाँक 29-12-2023 तक इनसे सम्बद्ध ट्रेनिंग पार्टनर को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समय-सीमा निर्धारित कर उक्त भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 97 ट्रेनिंग पार्टनर्स को श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष रु0 546.42 लाख का भुगतान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले ट्रेनिंग पार्टनर्स के अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा मांग पत्र श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। धनराशि के प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 29-12-2023 तक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने विषयक

62-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में मैनेजमेन्ट कोटा/स्पॉट एडमिशन के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में निर्धारित मैनेजमेन्ट कोटा/स्पॉट प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है।

व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले निजी क्षेत्र के जिन शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र, मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगें, इन्हें छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं है।

अवगत कराना है कि वर्ष 2018-19 से पूर्व तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में प्रवेश परीक्षा में बिना आवेदन किये सीधे छात्रों को प्रवेश देकर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की काफी अधिक धनराशि का दुरूपयोग किया गया, ऐसे छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर कोर्स को अधूरा छोड़ा गया है, इसलिए नियमावली में मैनेजमेन्ट कोटा का उपरोक्त प्राविधान किया गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, लखनऊ के कतिपय आवासों का नवीनीकरण कराये जाने विषयक

63-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कालोनी ट्रांजिट हास्टल डालीबाग, लखनऊ के कतिपय आवासों में सीलन तथा किचन एवं बाथरूमों में 10 वर्षों पूर्व लगे टाईल्स टूट कर गिरने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों में सीलन को दूर कराते हुए किचन एवं बाथरूमों में लगे टाईल्स के नवीनीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्न में सन्दर्भित ट्रांजिस्ट हॉस्टल, डालीबाग कालोनी के आवास संख्या-2/3 में कतिपय सिविल अनुरक्षण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर, मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 05 जनवरी, 2024 प्राप्त हुआ है। अन्य आवासों के सम्बन्ध में सम्बन्धित अध्यासियों का कोई शिकायती-पत्र/अनुरोध-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त आवास में किचेन के क्षतिग्रस्त टाइल्स के स्थान पर नई टाइल्स लगा दी गई है और बाथरूम में खराब सिस्टर्न की मरम्मत कराई गई है। उक्त आवास संख्या-2/3 के ऊपर बने आवास संख्या-3/2 के बाथरूम से आ रही सीलन के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की खेल नीतियों में डेफ श्रेणी को शामिल किये जाने की मांग

64-श्री अतुल प्रधान-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की खेल नीति में डेफ श्रेणी (बधिर) खिलाड़ियों का प्रावधान किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार खेल नीति में डेफ श्रेणी को शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी हां, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश खेल नीति-2023 के बिन्दु-11.2 में पैरा स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने हेतु यह उल्लिखित किया गया है कि नेत्रहीन एवं बधिर खेलों के लिए भी राज्य में सुविधाएं स्थापित की जायेगी एवं डेफ स्पोर्ट्स, ब्लाइंड स्पोर्ट्स व स्पेशल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को पैरा ओलम्पिक खिलाड़ियों की भांति देय सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के युवाओं को उद्यमपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक ब्लाक में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना कराने विषयक

65-श्री अतुल प्रधान

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं को उद्यमपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी नही।

वर्तमान में प्रदेश की सभी तहसीलें सेवित हैं, जिनमें राजकीय अथवा निजी आई0टी0आई0 संचालित हैं। वर्तमान में निर्धारित प्रवेश क्षमता एवं अपेक्षित प्रवेश लेने वाले छात्रों के सापेक्ष पर्याप्त आई0टी0आई0 हैं, अतः नई राजकीय आई0टी0आई0 खोले जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण से प्राप्त नौकरियों का विवरण

66-डॉ0 रागिनी-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की करेंगे कि प्रदेश में तकनीकी कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा किन तथा कितने तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा कितने लोगों को वर्तमान में उक्त प्रशिक्षण से नौकरियां प्राप्त हुई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

प्रदेश में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 84 व्यवसायों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन0सी0वी0टी0) भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम मानकों एवं मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। (संलग्नक-1) वर्तमान में वित्तीय सत्र, 2023-24 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कुल 36843 अभ्यर्थियों को अब तक सेवायोजित कराया गया है। (संलग्नक-2)

इसके अतिरिक्त उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा विभिन्न सेक्टर्स के 386 अल्पकालीन पाठ्यक्रम (जाब-रोल्स) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है (संलग्नक-3)। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 29354 प्रशिक्षार्थियों को विभिन्न कम्पनियों में चयनित कराते हुए सेवायोजित कराया गया है (संलग्नक-4)

उपरोक्त संलग्नक[†]-1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश सरकार द्वारा हाईटेक खेती को बढ़ावा देने हेतु जारी अनुदान योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

67-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश सरकार हाइड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स, पॉलीहाउस, नेट हाउस, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई आदि कौन-कौन सी तकनीक से हाईटेक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को अनुदान दे रही है ? क्या सरकार हाईटेक खेती हेतु अपनी ओर से जारी अनुदान योजनाओं का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हां।

उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस) कार्यक्रम संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत हाई वैल्यू सब्जियों एवं पुष्पों की खेती हेतु क्षेत्रफल 500 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक कुल अनुमन्य इकाई लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में देय है।

हाईड्रोपोनिक्स, एयरोपोनिक्स तकनीकी आधारित कार्यक्रम में अनुदान देय नहीं है।

जी हां।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्रीन हाउस (नेचुरली वेन्टीलेटेड ट्यूबलर स्ट्रक्चर)-

क्र0-सं0	एरिया	अधिकतम अनुमन्य लागत (रु0 में)	अनुदान
1	500 वर्ग मी0 तक	रु0 1060/वर्ग मी0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी
2	500 वर्ग मी0 से 1008 वर्ग मी0 तक	रु0 935/वर्ग मी0	
3	1008 वर्ग मी0 से 2080 वर्ग मी0 तक	रु0 890/वर्ग मी0	
4	2080 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक	रु0 844/वर्ग मी0	

2-शेडनेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर)-

क्र0-सं0	एरिया	अधिकतम अनुमन्य लागत	अनुदान

[†] छापा नहीं गया।

		(रु0 में)	
1	4000 वर्ग मी0 तक	रु0 710/वर्ग मी0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी

3-हाई वैल्यू सब्जी/पुष्प उत्पादन हेतु रोपण सामग्री-

क्र0-सं0	कार्यक्रम	अधिकतम अनुमन्य लागत (रु0 में)	अनुदान
1	पाली हाउस में हाई वैल्यू सब्जी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री	रु0 140/वर्ग मी0	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी
2	पॉली हाउस/शेडनेड हाउस में हाई वैल्यू पुष्प कारनेशन एवं जरवेरा उत्पादन हेतु रोपण सामग्री	रु0 610/वर्ग मी0	
3	पॉली हाउस/शेडनेड हाउस में हाई वैल्यू पुष्प गुलाब एवं लिलीयम उत्पादन हेतु रोपण सामग्री	रु0 426/वर्ग मी0	

4-पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई-

पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के कार्यक्रम सम्पादित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत ड्रिप, मिनी एवं माइक्रोस्प्रिंकलर पर लघु सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान तथा पोर्टेबल, सेमीपरमानेंट एवं रेनगन स्प्रिंकलर पर लघु सीमान्त कृषकों को 75 एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

घटक	श्रेणी	अनुदान पैटर्न प्रतिशत में			
		केन्द्रांश	अनिवार्य राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश (टापअप)	योग
ड्रिप, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर	लघु सीमान्त कृषक	33	22	35	90
	अन्य कृषक	27	18	35	80
पोर्टेबल, सेमी परमानेंट एवं रेनगन स्प्रिंगलर	लघु सीमान्त कृषक	33	22	20	75
	अन्य कृषक	27	18	20	65

प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि कार्य में किसानों के अंग-भंग होने अथवा चोटिल होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

68-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि कार्य में किसानों के अंग-भंग होने अथवा चोटिल होने की स्थिति में सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति देती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने पर निम्नानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है :-

क्र0-सं0	दुर्घटना का प्रकार	देय सहायता धनराशि
1	दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर	रु0 3,00,000.00
2	दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आँखें या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रु0 75,000.00
3	दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आँख की क्षति होने पर	रु0 40,000.00
4	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर	रु0 30,000.00
5	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ तीन अंगुली की क्षति होने पर	रु0 25,000.00
6	अंगूठे की क्षति होने पर	रु0 20,000.00
7	दुर्घटना द्वारा एक हाथ की दो अंगुलियों की क्षति होने पर	रु0 15,000.00
8	किसी एक अँगुली की क्षति होने पर	रु0 05,000.00

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराने विषयक

69-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के अभ्यास हेतु सरकार विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 में प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में चरणबद्ध रूप से बजट की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराये जाने तथा कोच/प्रशिक्षकों की व्यवस्था के साथ-साथ आधुनिक टेस्टिंग मानकों के अनुरूप खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रवेश के युवाओं में खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए मण्डल स्तर पर स्पोर्ट्स कालेज खोलने की मांग

70-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं में खेल की प्रतिभा को निखारने तथा तकनीकी रूप से बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में मण्डल स्तर पर स्पोर्ट्स कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में 03 स्पोर्ट्स कालेज संचालित हैं तथा 03 स्पोर्ट्स कालेज का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश के 12 मण्डल मुख्यालय पर छात्रावास संचालित हैं तथा शेष 06 मण्डल मुख्यालय पर छात्रावास के निर्माण हेतु धन आवंटित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 18 जनपदों में कुल 44 छात्रावास (32 बालकों के एवं 12 बालिकाओं के) संचालित हैं। आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत कुल 670 बालक एवं 220 बालिका कुल 890 बालक/बालिकाओं की संख्या स्वीकृत है। आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, किट, खेल सामग्री आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्ष में प्रशिक्षण एवं सेवायोजित युवाओं का विवरण

71-श्री सचिन यादव-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना अन्तर्गत सरकार द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में जनपदवार कुल कितने ग्रामीण युवा नामांकित, प्रशिक्षित एवं सेवायोजित किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वित्तीय वर्षों में इस योजना पर जनपदवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में उक्त वित्तीय वर्षों के जनपदवार ग्रामीण युवाओं को इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षित एवं सेवायोजित किये जाने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

प्रदेश में संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक कुल 91070 अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है। कुल नामांकित अभ्यर्थियों में से 64047 को कौशल प्रशिक्षित किया गया है एवं उनमें से 32796 को सेवायोजित किया गया है। जनपदवार विवरण संलग्नक-1[†] के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रशिक्षित किये गये अभ्यर्थियों पर कुल धनराशि रु0 5,46,96,92,573.00 व्यय की गयी है।

उक्त वित्तीय वर्षों में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय कालेजों में कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को रोजगार दिलाने की मांग

72-श्री सचिन यादव-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय कालेजों में कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्रों को रोजगार दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके छात्रों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा उक्त को रोजगार दिलाये जाने हेतु किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-320-321 पर।

श्री कपिल देव अग्रवाल-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्कूल स्तर पर छात्र एवं छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो तथा वे अपने अग्रेतर शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के 315 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-9, 10, 11 एवं 12 के इच्छुक छात्र व छात्राओं को उनके दैनिक कक्षा पाठ्यक्रम के साथ-साथ प्रति शैक्षिक दिवस 01/02 घण्टे का कौशल प्रशिक्षण उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट प्रवीण के अन्तर्गत प्रदान किये जाने की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ है। चूँकि छात्र एवं छात्रायें अपनी नियमित शिक्षा के साथ ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसके क्रम मे रोजगार प्रदान कराये जाने का विषय सम्मिलित नही है। अतः स्कूली छात्र एवं छात्राओं हेतु रोजगार दिलाने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में पंजीकृत हुए छात्र एवं छात्राओं में से 2471 द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। चूंकि छात्र एवं छात्रायें अपनी नियमित शिक्षा के साथ ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसके क्रम में रोजगार प्रदान कराये जाने का विषय सम्मिलित नहीं है। अतः जिम्मेदारी निर्धारित करने का विषय स्थापित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में फसलों के नुकसान से बचने के लिए सभी फसलों पर बीमा सुरक्षा कवच दिलाये जाने के सम्बन्ध में

73-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में फसलों के नुकसान से बचाव के लिए दिया जा रहा बीमा सुरक्षा कवच सरकार सभी फसलों पर देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल धान, मक्का, बाजरा, तिल, गेहूँ, जौ, लाही-सरसों व आलू तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल मिर्च, टमाटर व शिमला मिर्च को अधिसूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों के ग्राम पंचायत स्तर पर उत्पादकता के आंकलन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 4 क्रॉप-कटिंग प्रयोग सम्पन्न कराये जाते हैं। ग्राम पंचायत में 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों को ही योजनान्तर्गत अधिसूचित किये जाने का प्राविधान है।

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों को फसल बाहुल्य क्षेत्र वाले विकास खण्डों में अधिसूचित किया गया है।

प्रदेश में कृषि अपशिष्ट प्रबन्धन से जुड़ी सरकारी अनुदान आधारित योजनाओं का विवरण

74-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि अपशिष्ट प्रबन्धन से जुड़ी सरकारी अनुदान आधारित योजनाओं का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ रेज्ड्यू योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। रुपये 05 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ, सहकारी समिति एवं पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों के क्रय पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। फसल अवशेषों को खेत में सड़ाकर खाद के रूप में प्रयोग करने हेतु बायो डिकम्पोजर बोतल/कैप्सूल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी फसलों के बीजों को संरक्षित रखने हेतु जीन बैंक स्थापित करने के सम्बन्ध में

75-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी फसलों के बीजों को संरक्षित रखने हेतु जीन बैंक स्थापित करने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी फसलों के बीजों को संरक्षित रखने हेतु जीन बैंक स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

सूच्य है कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में विन्ध्य क्षेत्र के फलदार एवं वानिकी वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक फील्ड जीन बैंक स्थापित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में स्वरोजगार इकाइयों का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

76-श्री सचिन यादव-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में 116 स्व-रोजगार इकाइयाँ स्थापित करने के लक्ष्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लक्ष्य में से तहसील जसराना में कितने स्व-रोजगार इकाई स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राकेश सचान-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद में 116 स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष सरकार द्वारा संचालित मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 116 स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने हेतु रु0 225.04 लाख मार्जिन मनी की धनराशि वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत अब तक 46 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये रु0 158.58 लाख की मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में सरकार की अन्य रोजगारपरक् योजनाएं यथा-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण सहायता योजना, ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित हैं, जिनके द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार इकाई स्थापित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही एम0एस0एम0ई0 पॉलिसी, 2022 के अन्तर्गत भी विभिन्न लाभ प्रदान किये जाते हैं।

तहसील जसराना में स्वरोजगार हेतु इकाई स्थापना के लिये 04 अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन रु0 62.00 लाख के ऋण स्वीकृति हेतु विभिन्न बैंक शाखाओं को ऑनलाइन प्रेषित किये गये, जिसमें से 01 ऋण आवेदन-पत्र पर बैंक द्वारा रु0 7.00 लाख की स्वीकृति की गयी है एवं 02 ऋण आवेदन बैंक स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं तथा 01 ऋण आवेदन-पत्र आवेदक का सी0आई0डी0आई0एल0 खराब होने के कारण बैंक द्वारा निरस्त किया गया है।

विवरण उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड शिकोहाबाद अन्तर्गत खेतों की क्षारीय मिट्टी को सुधारने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

77-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड शिकोहाबाद, मदनपुर, अराँव, टूण्डला, फिरोजाबाद, जसराना एवं नारखी के खेतों की मिट्टी क्षारीय है ? क्या सरकार ने उक्त के सुधार हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जिप्सम वितरण कार्यक्रम एवं मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए जिप्सम वितरण (राज्य सेक्टर) योजना पूर्व से जनपद में मृदा सुधार हेतु संचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

78-श्री सचिन यादव-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं0-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया में सभी वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरण उपलब्ध कराने विषयक

79-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति व सामान्य जातियों के छात्र/छात्राओं को कितनी संख्या में छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में कितने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित नियमावलियों में जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद बलिया में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है :-

वर्ष	दशमोत्तर				पूर्वदशम			
	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	सामान्य वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग
2021-22	6903	10	2997	19127	16629	924	8189	38304
2022-23	7152	0	3041	23010	14743	394	15455	34343

2023-24	पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निर्गत समय-सारिणी एवं नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में पंजीकृत दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित कर लाभान्वित कराये जाने विषयक

80-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के किन तहसीलों में दिव्यांगजनों को विकलांग उपकरण वितरण किए जाने हेतु पंजीकृत आवेदनों के सापेक्ष कितने दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किये गये तथा कितने आवेदन अवशेष हैं ? क्या सरकार शेष दिव्यांगजनों को उपकरणों से लाभान्वित कराकर उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को रु0 10000/-की सीमा के अन्तर्गत विविध प्रकार के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण यथा-ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, बैसाखी इत्यादि प्रदान किये जाते हैं।

जनपद-बलिया की 06 तहसीलों में पंजीकृत 879 पात्र आवेदकों के सापेक्ष 196 आवेदकों को सहायक उपकरण वितरित किये गये हैं तथा अवशेष 683 आवेदकों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पर्यावरण सन्तुलन के दृष्टिगत जलेसर रोड पर स्थित इण्डस्ट्रियल एरिया में खाली जमीन पर वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में

81-श्री सचिन यादव-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण सन्तुलन के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद में जलेसर रोड पर स्थित इण्डस्ट्रियल एरिया में खाली 50 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपरण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'-

जनपद-फिरोजाबाद में जलेसर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र फिरोजाबाद में अधिग्रहीत लगभग 500 एकड़ भूमि पर औद्योगिक भू-खण्ड, आवासीय भू-खण्ड, संस्थागत भू-खण्ड एवं व्यवसायिक भू-खण्ड विकसित किए गए हैं। जलेसर रोड फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र में मानक के अनुरूप निर्धारित पार्कों, हरित पट्टिका व रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा पर्यावरण संतुलन के दृष्टिगत रखते हुए प्रति वर्ष की भाँति वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जलेसर रोड फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक मुश्त खाली 50 एकड़ जमीन वृक्षारोपण कराए जाने हेतु उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

हरियाणा राज्य की भाँति प्रदेश में कृषि अपशिष्टों को जलाने से रोकने हेतु आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा राज्य की भांति प्रदेश में भी गैर बासमती धान उत्पादित करने वाले किसानों को पराली या अन्य कृषि अपशिष्टों को जलाने से रोकने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप रकबे के आधार पर आर्थिक सहायता दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रदेश के किसानों को पराली तथा फसल अवशेष जलाने से रोकने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ रेज्ड्यू योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। रुपये 05 से 15 लाख तक के परियोजना लागत के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ, सहकारी समिति एवं पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने हेतु फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यंत्रों के क्रय पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। फसल अवशेषों को खेत में सड़ाकर खाद के रूप में प्रयोग करने हेतु बायो डिकम्पोजर बोतल/कैप्सूल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित स्पोर्ट्स कालेज में छात्र-छात्राओं के रहने, खाने व स्पोर्ट्स किट की व्यवस्था कराने विषयक

83-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं तथा उक्त कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के रहने, खाने व स्पोर्ट्स सम्बन्धित किट की व्यवस्था का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 03 स्पोर्ट्स कालेज संचालित हैं :-

1-गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ।

2-वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर।

3-मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई, इटावा।

उक्त कालेजों में छात्र-छात्राओं के रहने, खाने व स्पोर्ट्स किट की व्यवस्था निम्नवत् हैं :-

कालेज में रहने की व्यवस्था-गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में 320 बेड का छात्रावास निर्मित है, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में 150 बेड का 01 बालिका छात्रावास तथा 146 बेड का 02 बालक छात्रावास निर्मित है एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई इटावा में 250 बेड का छात्रावास निर्मित है तथा 250 छात्रों के रहने की व्यवस्था प्रशासनिक भवन के निर्मित कमरों में की गयी है।

खिलाड़ियों की भोजन व्यवस्था-शासन द्वारा निर्धारित मीनू के अनुसार रु0 375/प्रति छात्र प्रतिदिन की दर से खिलाड़ियों को भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

खेल किट की व्यवस्था-उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित तीनों स्पोर्ट्स कालेजों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को निःशुल्क खेल किट/अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समय-सीमा के अन्दर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिलाये जाने तथा सहायता धनराशि को दोगुना किये जाने की मांग

84-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलेवार कितने आवेदन राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार अवशेष आवेदक विधवाओं को किसी निश्चित समयावधि में सहायता देना सुनिश्चित करेगी ? क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान सहायता धनराशि को दोगुना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री असीम अरूण-

प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत 24155 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। जनपदवार सूची संलग्न[†] है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन स्वीकृति एवं भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है। योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-607/26-2-2023-100(02)/2007, दिनांक 01 अगस्त, 2023 में ऑनलाइन आवेदनों के पात्रता सम्बन्धी सत्यापन/पी0एफ0एम0एस0 रिस्पाँस/जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति के उपरान्त अनुदान सहायता धनराशि का भुगतान 45 दिवस के भीतर किये जाने की व्यवस्था की गयी है। 75 दिवस से अधिक विलम्ब के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जाती है।

योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण विशेष अभियान चलाकर इसी वित्तीय वर्ष में कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को रु0 30,000/-प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान सहायता धनराशि का भुगतान किया जाता है। लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली उक्त धनराशि रु0 30,000/-में से रु0 20,000/-केन्द्रांश धनराशि तथा रु0 10,000/-राज्यांश धनराशि सम्मिलित है। योजनान्तर्गत प्रदत्त की जाने वाली धनराशि में वृद्धि किये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रचलित योजना पर व्यय की गई धनराशि का विवरण

85-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने की कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलित हैं ? क्या सरकार विगत 5 वर्षों में मधुमक्खी पालन योजना पर व्यय की गई धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी हाँ।

उद्यान विभाग द्वारा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत प्रदेश के 45 जनपदों में तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के 30 जनपदों में मधुमक्खी पालन योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत प्रति लाभार्थी 50 मौनवंश

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-322-323 पर।

एवं 50 मौनगृह के लिए 01 मौन उपकरण सेट की स्थापना पर कुल धनराशि रु0 2.20 लाख का 40 प्रतिशत अर्थात् धनराशि रु0 0.88 लाख के अनुदान की अनुमन्यता है।

जी हाँ।

विवरण निम्नवत् है :-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0-सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
एकीकृत बागवानी विकास मिशन			
1	2019-20	264.00	236.98
2	2020-21	308.00	272.09
3	2021-22	308.00	217.15
4	2022-23	22.88	17.60
5	2023-24 (माह जनवरी, 2024)	220.00	35.20
	योग :	**1122.88**	**779.02**
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			
1	2019-20	193.60	183.04
2	2020-21	202.40	198.00
3	2021-22	381.92	372.24
4	2022-23	352.00	0.00
5	2023-24 (माह जनवरी, 2024)	176.00	0.00
	योग :	**1305.92**	**753.28**
	कुल योग :	**2428.80**	**1532.30**

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो कमरे का आवास आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक कमरे का आवास आवंटित किये जाने की व्यवस्था है, जिससे उन्हें अपने परिवार एवं माता-पिता को साथ रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? उक्त कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए उन्हें आंगन एवं बरामदा सहित दो कमरे का आवास आवंटित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-12-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 की धारा-4 में राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारी को श्रेणी-1 का आवास आवंटित किए जाने का प्रावधान है।

जी हाँ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवंटन अधिनियम, 2016 की धारा-4 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को श्रेणी-2 का आवास आवंटित किए जाने का प्रावधान नहीं है। उक्त स्थिति से मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 के पत्र संख्या-अ0शा0प0सं0आर0-168एस/बत्तीस-2-2023-3/1/2024, दिनांक 31 जनवरी, 2024 के माध्यम से अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में ससमय आलू का बीज उपलब्ध कराये जाने विषयक

87-श्री सचिन यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आलू के बीज वितरण हेतु किसानों के द्वारा अग्रिम में ही बीज के मूल्य का भुगतान किये जाने के बाबजूद भी उन्हें बीज नहीं मिल पा रहा है ? क्या सरकार किसानों को समय से फसल बोने हेतु आलू बीज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी, नहीं।

वर्ष 2023 में जनपद फिरोजाबाद के लिए प्रजातिवार आलू का आधारीय बीज कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु कुल 3200 कुन्तल आवंटित किया गया, जिसके सापेक्ष कुल 2819.50 कुन्तल बीज वितरित हो पाया। आवंटन/वितरण का विवरण निम्नवत् है :-

प्रजाति का नाम	आवंटित मात्रा (कु0 में)	वितरित मात्रा (कु0 में)
कुफरी बहार	1277.50	1277.50

कुफरी सूर्या	400	384.50
कुफरी पुखराज	225	110
कुफरी मोहन	110	65
कुफरी चिपसोना-1	500	418.50
कुफरी चिपसोना-3	100	100
कुफरी ख्याति	450	341
कुफरी गंगा	137.50	123
योग :	**3200**	**2819.50**

जनपद फिरोजाबाद के कृषकों के मध्य कुफरी बहार आलू बीज की अधिक माँग होने तथा अधिक आवेदन प्राप्त के कारण आलू बीज की उपलब्धता के आधार पर कृषकों को प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर आवेदन-पत्र व जमा धनराशि के अनुसार आलू बीज वितरित किया गया। अवशेष कृषकों को अन्य प्रजाति के आलू बीज लेने का आग्रह किया गया, किन्तु उनके द्वारा अन्य प्रजाति के आलू बीज लेने से मना कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ऐसे कृषकों को उनकी जमा धनराशि तत्काल वापस कर दी गयी।

आलू बीज की उपलब्धता के आधार पर आलू उत्पादक कृषकों को आलू बीज उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

फसलों में नए रोगों, फफूंदियों तथा कीटों के रोकथाम हेतु शोध करवाने तथा कृषि पाठ्यक्रम में शामिल कराने विषयक

88-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसलों में प्रतिवर्ष नए रोगों, फफूंदियों, कीटों और खर-पतवारों के पैदा होने विषयक कोई अध्ययन अथवा शोध कार्य सरकार कराती है ? यदि हां, तो उक्त शोधों से सम्बन्धित जनोपयोगी जानकारी के पत्रक बंटवाने तथा कृषि पाठ्यक्रमों में शामिल कराने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

कृषि विभाग द्वारा फसलों में कीट रोग एवं खरपतवार की रोकथाम हेतु नवीनतम जानकारी राज्य, मण्डल, जनपद स्तर पर आयोजित कृषि गोष्ठियों, किसान मेलों, विकास खण्ड स्तर पर आयोजित आई0पी0एम0, किसान खेत स्कूल के माध्यम से प्रदर्शन एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किसान पाठशाला के माध्यम से कृषकों को प्रदान की जा रही है।

कृषि विभाग के द्वारा प्रकाशित तकनीकी साहित्य के माध्यम से भी कृषकों को नवीनतम शोध तथा कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु तकनीकी संस्तुतियों की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।

कृषि विभाग द्वारा सामयिक कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु निदेशालय स्तर से समस्त जनपदों हेतु एडवाइजरी जारी कर प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कृषकों को जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।

राज्य स्तर पर आयोजित राज्य स्तरीय खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों से सम्बन्धित परामर्श बैठकों में तकनीकी साहित्य में प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से परामर्श कर तकनीकी संस्तुतियों को सम्मिलित कर कृषि ज्ञान मंजुषा, फसल सघन पद्धतियों, कृषि फोल्डर आदि के द्वारा कृषि/कृषि रक्षा कार्य इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूँ के कृषि विज्ञान केन्द्र समरेर के फार्म हाउस को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित कराये जाने की मांग

89-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के कृषि विज्ञान केन्द्र समरेर के फार्म हाउस का मात्र ढांचा बन कर खड़ा है, परन्तु बाउण्ड्रीवाल व अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कृषि विज्ञान केन्द्र समरेर का फार्म हाउस संचालित नहीं हो सका है ? क्या सरकार उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र समरेर के फार्म हाउस को पूर्ण क्षमता से संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत संचालित जनपद बदायूं के कृषि विज्ञान केन्द्र, समरेर के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रदत्त रु0 133.49 लाख की लागत से पूर्ण हो चुका है।

वर्तमान में कृषि विज्ञान केन्द्र, समरेर संचालित है। यहाँ पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन, प्रक्षेत्र प्रयोग परीक्षण इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं एवं इस केन्द्र पर 04 वैज्ञानिकों सहित कुल 07 कार्मिक कार्यरत हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूँ के दातागंज ब्लाक के ग्राम गनगोला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

90-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के ब्लाक दातागंज के ग्राम गनगोला में मिनी स्टेडियम न होने से युवा खिलाड़ियों को अभ्यास करने में समस्या होती है ? क्या सरकार युवा खिलाड़ियों के हितों के लिये ब्लॉक दातागंज के ग्राम गनगोला में मिनी स्टेडियम बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जी नहीं।

जनपद बदायूँ में खेल विभाग का स्टेडियम पूर्व से निर्मित एवं संचालित है। जहाँ युवा खिलाड़ियों द्वारा अभ्यास किया जा सकता है।

ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण योजना, संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित नीति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के उन 20 जनपदों में प्राथमिकता से ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम का निर्माण कराया जाएगा। जहाँ पर एक भी विभागीय स्टेडियम पूर्व से निर्मित नहीं है। जनपद बदायूँ के विकास खण्ड-वजीरगंज, तहसील बिसौली, ग्राम पंचायत बगरैन में विभागीय स्टेडियम निर्माणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में अनाज मण्डी की गत तीन वित्तीय वर्षों में आय का विवरण उपलब्ध कराने विषयक

91-श्री सचिन यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में स्थित अनाज मण्डी की वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 07-01-2024 तक सभी स्रोतों से कितनी आय है ? क्या सरकार बतायेगी की मण्डी में पंजीकृत कृषक एवं व्यापारी की संख्या को बढ़ाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत मण्डी समिति शिकोहाबाद के उपमण्डी स्थल, जसराना की कुल आय निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष में कुल आय (रु0)
2021-22	4,699.00
2022-23	13,97,286.00
2023-24	20,14,695.00 (01-04-23 से 31-01-24 तक)

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत मण्डी समिति शिकोहाबाद के उपमण्डी स्थल जसराना में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या
2021-22	15
2022-23	17
2023-24	23

प्रवर्तन कार्य के माध्यम से बाहर होने वाले अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा रहा है। साथ ही व्यापारियों को लाइसेन्स लेकर व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश के सरकारी क्रय केन्द्रों एवं मण्डी स्थलों पर सी0सी0टी0वी0 लगाने की मांग

92-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को अपनी उपज बेचने में सरकारी क्रय केन्द्रों एवं मण्डी स्थित व्यापारियों द्वारा उनके शोषण से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त सरकारी क्रय केन्द्रों एवं मण्डी स्थलों पर खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु सी0सी0टी0वी0 स्थापित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

जी नहीं।

(उल्लेखनीय यह भी है कि मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी समितियों का विनियमन मण्डी अधिनियम, 1964 व नियमावली, 1965 के अनुसार किया जाता है। मण्डी समितियों में प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायतों का निस्तारण ससमय नियमानुसार कर दिया जाता है।)

प्रश्न ही नहीं उठता है।

(मण्डी परिषद् द्वारा प्रदेश में कुल 251 प्रधान मण्डी स्थल घोषित हैं, जिसमें से कुल 222 प्रधान मण्डी स्थल निर्मित हैं जिनमें व्यापार/प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हैं। प्रदेश की निर्मित सभी मण्डी समितियों में आठ-आठ सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये गये हैं और मांग एवं आवश्यकता के दृष्टिगत सी0सी0टी0वी0 कैमरे मण्डी समितियों में स्थापित कराये जाते हैं।)

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कालरशिप फार्म भरने में हो रही असुविधा को दूर करने विषयक

93-श्री संदीप सिंह-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कालरशिप फार्म भरने में छात्र-छात्राओं का डाटा वेरीफाई न हो पाने के कारण डाटा फारवर्ड नहीं हो रहा है ? क्या सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कालरशिप फार्म भरने में हो रही असुविधा को दूर करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र कश्यप-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल 3289 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन फाइनल रूप से सबमिट किये गये हैं, जिसके सापेक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्तर से कुल 3050 छात्रों के आवेदनों को आनलाइन रिसीव कर 3044 छात्रों के डाटा को आनलाइन वेरीफाई करते हुये सभी 3044 छात्रों के आवेदनों को आनलाइन फारवर्ड किया गया है।

निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार छात्र-छात्राओं को आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन भरने में आने वाली समस्याओं के प्रकरण संज्ञान में आने पर विभाग द्वारा उसका समयान्तर्गत निराकरण कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर अन्तर्गत ग्राम अम्हेडा मार्ग से मोहनपुर, कुण्डा पावटी से बिजनौर-मुरादाबाद हाई-वे से जोड़ने वाले मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

94-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर अम्हेडा मार्ग से ग्राम मोहनपुर के सामने से गुरूकुल कुण्डा होते हुये पोटा से पावटी में बिजनौर-मुरादाबाद हाई-वे को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग जर्जर होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.55 किमी0 है, जिसमें से 3.55 किमी0 (चैनेज 0.00-3.55 कि0मी0) मण्डी परिषद् एवं 1.00 किमी0 (चैनेज 3.55-4.55 कि0मी0) गन्ना विभाग के स्वामित्व का मार्ग है।

गन्ना विभाग के स्वामित्व के 1.00 किमी0 (चैनेज 3.55-4.55 कि0मी0) भाग पर मण्डी परिषद् स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मण्डी परिषद् के स्वामित्व के सम्पर्क मार्गों का 03 वर्ष का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित है, यदि इस अवधि में कोई मरम्मत आवश्यक होती है, तो सम्बन्धित फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त अदायगी के करायी जाती है। अनुरक्षण नीति-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप 08 वर्ष पश्चात् नवीनीकरण एवं 03 से 08 वर्ष की सीमा में यदि आवश्यक है, तो विशेष मरम्मत का कार्य मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

[12:23] मा0 सदस्यों के जन्मदिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान बाल्मीकि, निर्वाचन क्षेत्र खैर, जिला अलीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्वर्गीय लाहौरी लाल है। आपका जन्म दिनांक 08 फरवरी, 1981 को ग्राम रगराना में हुआ था, आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग के राज्य मंत्री के रूप में आप अपना योगदान दे रहे हैं। आपके जन्मदिवस के ऊपर मैं स्वयं और इस सदन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य श्री अनिल कुमार सिंह, निर्वाचन क्षेत्र पुरवा, जिला उन्नाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में दूसरी बार निर्वाचित

हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री ललित मोहन सिंह हैं। आपका जन्म दिनांक आठ फरवरी 1979 को उन्नाव में हुआ था आपने इण्टर मीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की हैं। आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं और इस सदन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनाएं प्राप्त हुई।

कृषि मंत्री द्वारा व्यस्तता के दृष्टिगत कार्य-स्थगन के रूप में आज प्राप्त नोटिस की ग्राह्यता पर अगले दिन सुने जाने का पीठ से अनुरोध

कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि नियम-56 के भीतर मा0 अतुल प्रधान जी ने एक नोटिस आज दे रखा है। तो मुझे आज झांसी में कुछ कार्यक्रम के अन्तर्गत जाना है तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उसको कल ले लिया जाये।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको कल ले लेंगे। मेरा यह निवेदन है मा0 सदस्य कि यदि आप फारमेलिटी करना चाहते हैं तो आज के लिए ही ले लें नहीं तो जो विस्तृत उत्तर जिस विभाग के मा0 मंत्री जी का होता है तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास उससे सम्बन्धित सारी डिटेल्ड जानकारी होगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, नहीं कोई आकड़ों से सम्बन्धित नही है। केवल किसानों की स्थिति के सुधार पर करना है।

श्री अध्यक्ष-

तो सुधार तो वही बता पायेंगे, तो इसमें क्या प्राब्लम है इसको कल ले लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, कल के दूसरे प्रहर में ले लें।

श्री अध्यक्ष-

इसको कल ले लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि फिर कल एक बढ़ा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

कल का कल देखा जाएगा इसको कल ले लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, एक हमारा नियम-56 का न खराब हो, तो कल एक बढ़ा दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिए देखेंगे। श्री अनिल प्रधान जी उसमें उसका जवाब आना होता है।

[12:25] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचना लेते हैं।

आज दिनांक 08 फरवरी, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 54 सूचनाएं प्राप्त हुईं निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई :-

पहली सूचना श्री संदीप सिंह की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत पार्क एवं स्मृति द्वार बनाए जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 मनोज कुमार प्रजापति की जनपद हमीरपुर में अधूरी बेतवा यमुना बाईपास परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री गुलाम मौहम्मद की जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानी में नाली के सी0 सी0 निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा में सरयू घाघरा नदी के विरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सुरेन्द्र चौरसिया की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना हाजी नासिर कुरैशी की मुरादाबाद ग्रामीण में खेल मैदान को सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग ना किए जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के हिंदनगर वार्ड में सीवर लाइन की सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के खेरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रावतपुर में पार्वती नदी के पास चेक डैम बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना ई0 सचिन यादव उर्फ जखई की उत्तर प्रदेश पुलिस के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में गौशाला के निर्माण के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद बुलन्दशहर में कृषि उपकरण की सब्सिडी में अनियमितता के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकंदरपुर में घाघरा नदी के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा के कैनाल बांदा अबरी रोड के नहर की पटरी पर

अवैध कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डा0 वीरेंद्र यादव की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत सिकंडेरपुर सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री निर्मल वर्मा की जनपद सीतापुर के बिसवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री कैलाश नाथ की जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में राप्ती नदी पर पैंटून पुल बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के पयागपुर के ग्राम हुजूरपुर में पानी की टंकी बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राज कुमार सहयोगी की जनपद अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्रीमती अर्चना पाण्डेय की जनपद कन्नौज की तहसील चीबरमऊ के ग्राम में कतिपय मार्गों पर नालों के निर्माण के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर की मस्कारा नदी की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ में कतिपय पौराणिक स्थलों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के चरखारी में राजकीय महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर में कतिपय स्थानों पर अल्पिका/माइनर बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर में ढमोला नदी की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कृषि भूमि आवंटित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठाईसवीं सूचना श्री मनीष असीजा की प्रदेश के समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में हड्डी रोग के उपचार हेतु निःशुल्क सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की विंध्याचल विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूमि को आवासीय घोषित किए जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री मदन भैया की उत्तर प्रदेश के रेसलर कोच को सम्मानित राशि दिए जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री अमरेश कुमार की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट में आबादी हेतु भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावाँ के ग्राम भैडा में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, ग्राम मलिकपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तथा छत्तीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की ओम साई मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई :-

इंजी0 सरवन कुमार निषाद, डॉ0 असीम कुमार, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राम सिंह पटेल डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री रवेन्द्र पाल सिंह, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, मो0 ताहिर खान, मो0 हसन रूमी, श्री जाहीद, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री बम्बा लाल, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री विजय पाल (आढ़ती)।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत पार्क एवं स्मृति द्वार बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[महोदय, मैं एक लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माण्डा की धरती से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी0पी0 सिंह) एवं स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर माण्डा में पार्क एवं स्मृति द्वार बनवाया जाना जनहित के लिए अति आवश्यक है।

मैं सदन के माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माण्डा में पार्क एवं स्मृति द्वार बनाये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

जनपद हमीरपुर में अधूरी बेतवा यमुना बाईपास परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार प्रजापति-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ। अवगत कराना है कि जनपद हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियों में बने पुलों से होकर भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे हमीरपुर शहर में बार-बार जाम की स्थिति पैदा होती है एवं भारी वाहनों के आवागमन से आये दिन जाम की समस्या से जुझना पड़ता है। उक्त समस्या के समाधान के लिये वर्ष 2017 में बेतवा, यमुना, रुहाइननाला बाईपास परियोजना को हरी झंडी मिली थी। उक्त परियोजना के तहत रामपुर तिराहा के पास से यमुना नदी में फोरलेन के पुल बनाकर सिटी फारेस्ट होते हुए बेतवा नदी पार कुछेछा गांव के पास एनएच-34 से जोड़ा जाना है। उक्त बाईपास का निर्माण तो शुरू हो गया है। परन्तु 6-7 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक उक्त बाईपास का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनपद हमीरपुर मे अधुरी बेतवा, यमुना बाईपास परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानी में नाली के सी0 सी0 निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुलाम मोहम्मद-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मेरठ के वि0ख0-जानी के ग्राम नगला कुम्भा में जब्बार पुत्र वकील के मकान से इरशाद पुत्र बरकत अली के मकान तक लम्बाई लगभग 300 मी0 कच्ची नाली है। जिसकी वजह से गाँव की पानी निकासी हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नाली कच्ची होने के कारण पानी की निकासी सही नही हो पाती है। उक्त नाली का सी0सी0 निर्माण कराने हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त नाली का सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा में सरयू घाघरा नदी के विरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र तरबगंज, गोण्डा जो अयोध्या से सटा सरयू घाघरा नदी से घिरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बरसात के समय में बाढ़ की भीषण विभीषिका में कई मार्ग कट जाते है जिसके कारण कई गांवों का सम्पर्क टूट जाता है। सेतु न होने के कारण लोगों को मजबूरन कई माह तक नाव से यात्रा करनी पड़ती है जिससे कई बार दुर्घटना हो जाने के कारण जानमाल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। विधान सभा क्षेत्र का लगभग दो तिहाई भाग बाढ़ प्रभावित है, अति महत्वपूर्ण सेतु विरसिंहपुर में टेढ़ी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

[महोदय, सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि जनपद देवरिया के मेरे विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत पाण्डेयचक-डुमरी मार्ग स्थित हिरन्दापुर (मझरटिया) से डुमरी (रघवापुर) मुख्य मार्ग पूर्व में निर्मित नहर की पटरी मार्ग व बेलवानिया चौराहा से मेहरौना होते हुए सोहनीपार तक नहर के किनारे की सड़क की पिच निर्माण हुए 20 वर्ष हो गये। लगातार पत्राचार करने के बाद भी आज तक कोई विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। जिसका विशेष मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

मुरादाबाद ग्रामीण में खेल मैदान को सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग ना किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी नासिर कुरैशी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-27, मुरादाबाद ग्रामीण के अन्तर्गत गवर्मेंट इण्टर कालेज (जी0आई0सी0) के मैदान में एक हाकी का टर्फ लगना बहुत ज़रूरी है यह मैदान निरंतर उत्तर प्रदेश खेल छात्रावासों को बच्चे दे रहा है। इस पर आज़ादी से पहले से हाकी खेली जा रही है आज इसका हाल बेहाल है शहर की आबादी जहाँ पर बच्चे खेलने वाले हैं वहां से स्टेडियम अधिक दूरी पर है अधिकतर गरीब परिवार के बच्चे स्टेडियम जाने में असमर्थ हैं जिला हाकी संघ की मांग है की इस मैदान पर सरकार द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो खिलाड़ियों को चाहिए होती हैं अगर इस ग्राउंड पर सुविधाएं होंगी तो मोहम्मद फराज़ जैसे कितने अन्य बच्चे भी भारतीय टीम तक का सफर तय कर सकेंगे और ऐसे लोगो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए जो शासन के आदेश को ताक में रखकर अन्य कार्यक्रमों के आयोजन का मैदान में परमीशन दे देते हैं यह जनहित का अति गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तब्य दिये जाने एवं गवर्मेंट इण्टर कालेज (जी0आई0सी0) के मैदान में एक हाकी का टर्फ लगवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के हिंदनगर वार्ड में सीवर लाइन की सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ के हिन्दनगर वार्ड की अधिकांश आबादी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है। उक्त आबादी के मध्य हिन्दनगर मोहल्ले में सीवर लाइन की सुविधा न होने के कारण यहां के निवासियों को असुविधा हो रही है। इस सम्बन्ध में जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार हिन्दनगर मोहल्ले में सीवर लाइन डाले जाने की माँग की जा रही है, जिसका सम्भावित आगणन तैयार कर शासन स्तर पर विचाराधीन है। व्यापक जनहित में हिन्दनगर मुहल्ले में सीवर लाइन डालकर समस्या का समाधान कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद आगरा के खेरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रावतपुर में पार्वती नदी के पास चेक डैम बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आगरा में मेरी विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के अन्तर्गत ब्लाक खेरागढ़ के ग्राम रावतपुरा के पास पार्वती नदी पर कोई भी चैकडेम नही हैं, जिससे आसपास के ग्रामों में जल स्तर काफी नीचे चला गया हैं। जिससे आसपास के ग्रामवासियों को सिंचाई एवं पेयजल हेतु काफी परेशानियाँ हो रही हैं। जनहित में ग्राम रावतपुरा के पास पार्वती नदी पर चैकडेम निर्माण कराना अति आवश्यक हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश पुलिस के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस आवश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ग्राम प्रहरी/चौकीदार रु0 2500/महीने अल्प वेतन में 24x7 दिन निरन्तर ग्राम की रखवाली करते हुये आपराधिक गतिविधियों की सूचना थाने पर देते हैं। किन्तु महंगाई की मार को झेलते हुये इतने कम पैसों में अपने परिवार का पालन पोषण नही कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रहरी/चौकीदारों को परेशानियों का सामना पड़ता रहता है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये चर्चा कराये जाने एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को वेतन में वृद्धि करते हुये राज्य कर्मचारी का दर्जा व पुलिस के अनुरूप वर्दी, अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में गौशाला के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली में आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे किसान बहुत ही परेशान है। किसान रात-रात भर जगकर अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए मजबूर है। जनपद सीतापुर के नीलगाँव में पशुपालन विभाग की 771 हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि स्थिति है। जिसका अधिकांश भू-भाग अनुपजाऊ बंजर है। उक्त पशुपालन विभाग की जमीन पर यदि एक विशाल कान्हा गौशाला का निर्माण करवा दिया जाये तो महोदय किसानों को आवारा पशुओं से निजात मिल जायेगी और गौवंशों और अन्य पशुओं को एक आश्रय स्थल मिल जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र सिधौली के नीलगाँव में पशुपालन विभाग की 771 हेक्टेयर अनुपजाऊ कृषि फार्म भूमि पर विशाल कान्हा गौशाला का निर्माण करवाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु मैं सदन से मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर में कृषि उपकरण की सब्सिडी में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि देश के अन्नदाता किसान के साथ जनपद बुलन्दशहर की विभिन्न पांच तहसीलों में विभिन्न कृषि यंत्र विक्रेता डीलर जिन्होंने इन तहसील में घोटाला किया है-

1-कृषि यंत्र विक्रेता एम0जी0 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रेलवे रोड सबलपुर डिबाई,

2-कृषि यंत्र विक्रेता गुप्ता एग्रीकल्चर इम्लीमेंन्टस रेलवे रोड डिबाई, बुलन्दशहर,

3-कृषि यंत्र विक्रेता कैलाश ज्ञान मोटर्स रेलवे डिबाई, बुलन्दशहर,

4-कृषि यंत्र विक्रेता डी0एल0 एसोसिएट्स निकट नई तहसील जी0टी0 रोड, खुर्जा।

इन सभी कम्पनियों के द्वारा जो कृषि उपकरण सब्सिडी घोटाला किया है उसका मुख्य केन्द्र कृषि यंत्र विक्रेता कैलाश ज्ञान मोटर्स रहा है और अन्य कम्पनियां भी एक ही परिवार के लोगों की व डिबाई की ही कम्पनियां हैं। जिलाधिकारी बुलन्दशहर गठित कमेटी द्वारा कृषि उपकरण घोटाले की जांच में सभी व्यापारियों और जिले के सभी कृषि कर्मचारियों व

अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है और जिलाधिकारी द्वारा सभी दोषी व्यापारियों और अधिकारियों से सम्पूर्ण घोटाले की धनराशि कब तक सरकारी खजाने में जमा करा ली जायेगी सम्पूर्ण घोटाला लगभग 220 करोड़ रुपये का घोटाला है। क्या सभी दोषी फर्मों को काली सूची में डालना ही व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही है जबकि उन्ही व्यापारियों द्वारा नई फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराकर पुनः किसानों को लूटने का कार्य चल रहा है। व्यापारियों द्वारा गबन की हुई धनराशि की वसूली कब तक की जायेगी व व्यापारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 कर कब तक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड किशनी में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत विकास खण्ड किशनी में रठेह मार्ग से रतनपुर होकर समदपुर तक दूरी लगभग 1 किमी0 भिटारा मार्ग से सतियाहार तक दूरी लगभग 2 किमी0 सड़क की हालत बहुत खराब हो गयी है। सड़क खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। भीखपुरा से नगला बस्ती का अवयोरा भाग दूरी लगभग 500 मीटर, रैचन्दा से विक्रमपुर तक दूरी लगभग 1 किमी0 की सड़क भी खराब हो गयी है सड़क खराब होने के कारण क्षेत्र के लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे स्थिति में उपरोक्त सड़कों का अवशेष भागों का निर्माण कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़कों के अवशेष भाग को कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकंदरपुर में घाघरा नदी की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सिकन्दरपुर में घाघरा नदी पर कटान बहुत तेजी से हो रहा है। जिससे ग्राम विहरा, लिलकर, कठौड़ा सिसोटार, पुरूषोत्तमपट्टी, खरीद एवं जिन्दापुर, निपनिया आदि दर्जनों गांव कटान से प्रभावित हो रहे हैं। इस ग्राम के किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समाहित हो गयी है जिससे उपरोक्त ग्राम के किसानों के सामने भुखमरी की समस्या

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पैदा हो गई है। ग्राम परूषोत्तमपट्टी, जिन्दापुर, ग्राम खरीद अत्यन्त कटान से प्रभावित हैं जिन्दापुर से नदी मात्र 500 मी0 पर बह रही है। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बाढ़ विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक मौके पर निरीक्षण करने नहीं गया और न तो कटान की कोई कार्य योजना शासन को भेजी बाढ़ विभाग कहता है कि फ्लड जोन के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि खरीद-दरौली पर बन रहे पक्का पुल के पिलर से सटकर बोल्डर 500 मी0 डालकर रैम्प बना दिया जाय तो यह कटान रुक सकता है एवं किसानों की बाकी जमीन नदी में समाहित होने से बच सकती है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार से तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने एवं कटान से दर्जनों गांव को बोल्डर गिराकर रैम्प बनाकर बचाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बांदा के कैनाल बांदा अबरी रोड के नहर की पटरी पर अवैध कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद बांदा के कैनाल बांदा माइनर बांदा अबरी रोड को क्रास करते हुए बांदा तिन्दवारी बांदा चिल्ला रोड को क्रास करते हुए कनवरा राजवाहा कमवारा तक बनी है। यह शहर के बीच बस्ती से गुजरती है। जगह-जगह नहर की पटरी पर कब्जा करके प्लाटिंग का कार्य कर रहे हैं। अवैध कब्जा को खाली कराया जाना आवश्यक है अवैध कब्जा होने के कारण लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त अवैध कब्जे को खाली कराये जाने हेतु मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सुलेमापुर करौटी राजवाहा पर पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है आये दिन वहा दुर्घटनायें होती रहती हैं।

अतः जनहित में उपरोक्त कार्य को कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर-सम्मनपुर सम्पर्क मार्ग रामनाथ के खेत से गंगिला मुस्तफाबाद बब्बन के खेत तक का सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का नव निर्माण कार्य नही हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद सीतापुर के बिसवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्मल वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-149 के बिसवां, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नगर बिसवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो कि जनपद मुख्यालय से काफी दूर है स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसका सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से विधान सभा क्षेत्र बिसवां के साथ-साथ विधान सभा क्षेत्र सेउता एवं विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर में राप्ती नदी पर पैन्टून पुल बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ शुक्ला-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-291, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत ग्राम बेला कोडरी में राप्ती नदी पर पैन्टून पुल (पीपे का पुल) बनवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

तुलसीपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तुलसीपुर के ग्राम बेला कोडरी से होकर तुलसीपुर विकास खण्ड के कई दर्जन ग्रामों के निवासियों का आवागमन होता है वहां पर स्थित

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राप्ती नदी पर पैन्टून पुल (पीपे का पुल) न होने से क्षेत्रवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के पयागपुर के ग्राम हुजूरपुर में पानी की टंकी बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[महोदय, मैं जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र-247, पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम हुजूरपुर में अधूरी पड़ी पानी की टंकी की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

ग्राम हुजूरपुर में विगत 4-5 वर्षों से पानी के टंकी का निर्माण व पाइप लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। पानी की टंकी तो आधी अधूरी बनी है परन्तु सभी घरों के पानी के लिए पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य अधूरा पड़ा है तथा चर्चा है कि ठेकेदार भाग गया है, जिससे पानी टंकी से लोगों के घरों में शुद्ध पानी पहुंच नहीं पा रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए पानी के टंकी का निर्माण व पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कराकर पानी टंकी चालू कर लोगों के घरों में शुद्ध जल पहुंचाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के गोंडा ब्लॉक को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार सहयोगी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-इगलास, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत गोण्डा ब्लाक को नगर पंचायत बनाना अत्यन्त आवश्यक है तथा उक्त गोण्डा ब्लाक नगर पंचायत बनने के सभी मानक पूरा करता हैं। नगर पंचायत बनने से ब्लाक का विकास तेजी से हो सकेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ के ग्राम में कतिपय मार्गों पर नालों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि जनपद कन्नौज के विधान सभा क्षेत्र-196, छिबरामऊ के अन्तर्गत तहसील छिबरामऊ के ग्राम कुअंरपुर जनू में पानी का समुचित निकास न होने के कारण कुअंरपुर जनू-गदनपुर तुर्रा सम्पर्क मार्ग पर पूरे वर्ष गांव की नालियों का पानी भरा रहता है। जिसके कारण ग्रामवासियों व सम्पर्क मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पडता है, तथा ग्राम के वृद्ध, महिलायें व बच्चों को आने-जाने में गम्भीर परेशानी हो रही है। इसलिये ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों के मार्ग को सुगम बनाने हेतु चमन नगरिया से खरौआ नदी तक सड़क के किनारे लम्बाई लगभग 1200 मी0 का नाला बनाया जाना जनहित में नितांत आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषयक की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद सहारनपुर की मस्करा नदी की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़-02, जनपद सहारनपुर में मस्करा नदी शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए कलसिया से डंडौलीखेड़ा, बहादरा, मलकपुर, बढ़गांव होते हुए चिलकाना में आकर बूढ़ी यमुना में मिल जाती है। मस्करा नदी पर अतिक्रमण होने के कारण इस बार बाढ़ आने से हजारों बीघे किसानों की फसल बर्बाद हो गयी। कई गांव में पानी घुस गया। भारी तबाही किसानों की फसलों की हुई। जनहित में मस्करा नदी का अतिक्रमण व सिल्ट सफाई कार्य कराया जाना आवश्यक है जिससे हजारों बीघा किसानों की फसलों को बचाया जा सके।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ में कतिपय पौराणिक स्थलों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-190, लम्भुआ नगर पंचायत से सटा हुआ सिद्धि प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठ बाबा भोले नाथ का पवित्र मंदिर एवं स्थान जनवारीनाथ धाम है। यहां पर दूर-दूर से हजारों श्रद्धालु दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए आते हैं, किन्तु यहां पर यात्री सुविधाओं यथा-मंदिर निर्माण, सामुदायिक शौचालय, स्नान घर, रसोई घर, सामूहिक भजन कीर्तन हाल, यात्री विश्राम गृह नहीं है तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण अधूरा होने के कारण

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतिक्रमण होता रहता है। जनहित में उक्त जनवारीनाथ धाम में यात्री सुविधाओं, बाउन्ड्रीवाल आदि का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कारवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद महोबा के चरखारी में राजकीय महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र-231, चरखारी (महोबा) में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जिससे समय एवं धन का अपव्यय होता है। जनहित में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर में कतिपय स्थानों पर अल्पिका/माइनर बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार गौतम-

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र-191, कादीपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर से विकास खण्ड अखण्डनगर में ग्राम रूपईपुर से निकलकर पतारखास एवं हरपुर तक जाने वाली अल्पिका के लिए पतारखास एवं हरपुर ग्राम पंचायतों में चकबन्दी द्वारा सभी किसानों से कटौती कर जमीन आरक्षित की गयी है, जिसे कतिपय दबंगों द्वारा कब्जा किया गया। अल्पिका/माइनर बनने से लघु एवं सीमान्त किसानों के साथ-साथ अन्य सभी को भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। जनहित में उपर्युक्त अल्पिका/माइनर का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के सहारनपुर नगर में ढमोला नदी की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-03, सहारनपुर नगर, जनपद सहारनपुर में ढमोला नदी सहारनपुर नगर से निकलती है। इस नदी में बहुत अधिक सिल्ट एवं

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गन्दगी जमा है जिस कारण उसकी तलहटी काफी ऊंची हो गयी है, जिस कारण इस बार बाढ़ आने से नदी से लगती हुई कालोनियों में बहुत अधिक पानी घुस गया था, जिससे हजारों लोगों का घर का सामान बर्बाद हो गया और लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ा। जनहित में इस नदी का सिल्ट सफाई कार्य कराया जाना आवश्यक है, जिससे आने वाले समय में इस नदी से लगी हुई कालोनियों में पुनः यह समस्या उत्पन्न न हो।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कृषि भूमि आवंटित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार, जनपद रायबरेली की प्रार्थिनी श्रीमती रानी पत्नी श्री रमेश कुमार ग्राम छोटी टिकरिया हरदीटीकर वि0क्षे0 जगतपुर जनपद रायबरेली द्वारा कई वर्षों से प्रार्थना-पत्र कृषि की जमीन आवंटन हेतु दिया था, जिसमें जिलाधिकारी रायबरेली के द्वारा प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, ऊँचाहार से करायी गयी, जांच आख्या के अनुसार आवेदिका भूमिहीन है, और इनके पति विकलांग हैं, उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन करने की विहित प्रक्रिया है, भूमि प्रबन्धक समिति हरदीटीकर विकास खण्ड जगतपुर, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये नियमानुसार आवेदिका को कृषि आवंटन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, सुलभ सन्दर्भ हेतु उप जिलाधिकारी, ऊँचाहार की जांच आख्या भी प्राप्त है, परन्तु प्रार्थिनी को अभी तक भूमि आवंटन नहीं की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में कई बार प्रार्थना-पत्र दिये गये, लेकिन अधिकारियों की उदासीनदता के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 के वक्तव्य में स्वीकार करने की कृपा करें।]

प्रदेश के समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में हड्डी रोग के उपचार हेतु निःशुल्क सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, अवगत कराना है उत्तर प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी टूटने के कारण बहुत बड़ी संख्या में नागरिक अपने इलाज हेतु आते हैं।

आधुनिक चिकित्सा पद्धिति में हड्डी जोड़ने हेतु राड, स्क्रू, प्लेट, नेल आदि आवश्यकता होती है, जिनकी कीमत अधिक होती है। इन रोगियों को खुले बाजार से लाने को

मजबूर होना पड़ता है। इस प्रक्रिया में चिकित्सकों के द्वारा भी मनमानी दुकान एवं ब्रांड के कंज्यूमेबल्स मंगाये जाने की शिकायत बहुत आम है।

उक्त परिस्थितियों के आलोक में उत्तर प्रदेश के रोगियों विशेषकर गरीब रोगियों को समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने में आवश्यक कंज्यूमेबल्स नेल, राड, स्क्रू, प्लेट आदि निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रदेश के समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में हड्डी जोड़ने के लिये आवश्यक राड़, नेल, स्क्रू, प्लेट आदि की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के नूरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अवतार सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर (बिजनौर) में ग्राम मेवाजट नहर के पुल से नहर की पटरी तक ग्राम हिरनपुरा तक लगभग 4 कि0मी0 सड़क बननी अवशेष है, जबकि हिरनपुरा से मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग तक पक्की रोड बनी हुई है। यदि उक्त 4 कि0मी0 नहर की पटरी पर पक्का मार्ग बन जाता है, तो यह मुरादाबाद आवागमन के लिए सुविधाजनक एवं मितव्ययी होगा। उक्त नहर पटरी पर शेष मार्ग बना है, केवल 4 कि0मी0 की दूरी में मार्ग कच्चा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से नहर की पटरी पर ग्राम मेवाजट से हिरनपुरा तक 4 कि0मी0 सड़क निर्माण की मांग करता हूँ।]

विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित भूमि को आवासीय घोषित किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[महोदय, सादर, अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत स्थित बन्धवापुरम कालोनी (जमीन आराजी न0-959, 960, 937, 956, 980, 978, 976/1, 977/1, 972/1, 969/2 मौजा शिवपुर उर्फ रसूलपुर तप्पा 96, परगना कंतित, तहसील सदर, जिला-मिर्जापुर), जोकि एक रिहायशी कालोनी है, में भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रशासन द्वारा अस्वीकार किये जा रहे हैं। उक्त कालोनी के अन्तर्गत

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कतिपय मकान पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित हैं, परन्तु वर्तमान में विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त जमीन को ग्रीन सिटी पार्क हेतु प्रस्तावित कहकर आवेदन अस्वीकार कर दिये जा रहे हैं।

यह भी अवगत कराना है कि यह एक रिहायशी क्षेत्र है और इस के आस-पास कई आवसीय भवन बने हुए हैं तथा इस क्षेत्र को आवासीय करने से आस-पास के सैकड़ों लोग बेघर होने से बच जाएंगे।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्रीन सिटी हेतु प्रस्तावित जमीन की जाँच कराते हुए उक्त स्थापित आवासीय कालोनी को आवासीय भूमि घोषित कर सैकड़ों लोगों का विस्थापन रोका जाए।]

उत्तर प्रदेश के रेसलर कोच को सम्मान राशि दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन भैया-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय एवं लोक हित की सूचना को संज्ञान में लाकर त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूँ।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के रेसलर के दो कोचों श्री जगमिन्दर सिंह (मुजफ्फरनगर) एवं श्री राजीव तोमर (बागपत) भारतीय कुश्ती टीम के साथ रियो ओलम्पिक-2022 में भाग लेने गये थे जहां देश के दो पहलवानों श्री बजरंग पूनिया एवं रवि दहिया ने ब्राँज एवं सिल्वर पदक जीते।

मान्यवर, उ0प्र0 सरकार ने अन्य खेलों के कोचों को सम्मानित नगद राशि प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया, परन्तु अभी तक कुश्ती के उक्त दोनों कोचों को सम्मानित राशि नहीं दी।

अतः मैं सदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कुश्ती के उक्त दोनों कोचों को भी नगद इनाम राशि देकर सम्मानित करें ताकि उनका मनोबल बढ़े व भविष्य में वे अपने राज्य एवं देश की ओर अधिक गौरवान्वित करने में अधिक योगदान दे सकें]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट में आबादी हेतु भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के चिनहट स्थित उतरधौना के अन्तर्गत भूमि गाटा संख्या-272, जो कि आबादी हेतु आरक्षित है तथा जिस पर लगभग 50 वर्षों से आबादी निवास कर रही है, को भूमि से बेदखल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्व संहिता की धारा-67ए के अनुसार भी वर्णित भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को बेदखल नहीं किया जा सकता है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट स्थित उतरधौना में भूमि गाटा संख्या-272 को आबादी हेतु आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[महोदय, मुरादाबाद जनपद के तहसील बिलारी में समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन विधायक श्री मौहम्मद इरफान द्वारा मण्डी समिति बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया था। मण्डी समिति बनाने की सपा सरकार द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही मण्डी समिति की स्थापना रुक गई। मण्डी समिति की जगह मौजूद होने के बाद भी अभी तक मण्डी समिति की स्थापना नहीं हो पायी है। मण्डी समिति की स्थापना को लेकर कई बार पैरवी भी की जा चुकी है, परन्तु अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। बिलारी तहसील के लगभग 400 गांवों के किसान दूर-दराज जाकर अपनी फसलों को बेचते हैं, अगर बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना हो जाती है, तो किसानों को अपनी फसलों के बेचने के लिये दूर- दराज नहीं जाना पड़ेगा। अतः बिलारी में मण्डी समिति की स्थापना कराया जाना जनहित में होना आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में मण्डी समिति बनाये जाने मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावाँ के ग्राम मैड़ा-भरतपुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समर पाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-नौगावां सादात, जनपद अमरोहा में रतनपुरा से ग्राम मैड़ा-भरतपुर तक कच्चे रास्ते को पक्का बनाने की व्यवस्था कराई जाय। उक्त सड़क दो विधान सभा क्षेत्र व दो तहसीलों को भी जोड़ती है। अभी तक कच्चे व झाड़

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुण्डो से घिरा रास्ता है, जिससे बीसों गावों का आवागमन है, जो कि बाधित है। उसको पक्का कराया जाय, जिसकी लम्बाई लगभग कि0मी0 में है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय पर सदन के समस्त नियमों को निलम्बित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी, ग्राम मलिकपुर से नगला जौहरी मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-91, फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम मलिकपुर से नगला जौहरी, ग्राम बाकन्दा तक नव निर्माण कार्य जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। यह मार्ग कच्चा, दगड़ा तथा क्षतिग्रस्त स्थिति में है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

ओम साईं मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, ओम साईं मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल/हजार्ड प्रशिक्षण संस्थान, ए-041, सेक्टर-69 ट्रान्सपोर्ट नगर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में संचालित है, वर्ष 2001 में इसे अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया गया तथा वर्ष 2012 में संचालक ने हजार्ड वाहन प्रशिक्षण का पृष्ठांकन कराया। शासन के दिनांक 27-04-2023 के आदेशानुसार दिनांक 26-10-2023 से पूर्व संचालित सभी प्रशिक्षण संस्थान, नवीन मानक प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायें अन्यथा उक्त तिथि से उनकी मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

इसी क्रम में पहले से संचालित 580 प्रशिक्षण संस्थानों ने मानक प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कराया। अतः उनकी मान्यता समाप्त कर दी गयी, किन्तु उक्त संस्थान का निरस्तीकरण अब तक नहीं किया गया। इसी तरह संचालक की डिग्री संदेहास्पद है और सरकार के आदेश के बाद भी कोविड के दौरान उक्त संस्थान के बन्द नहीं होने के बावजूद भी संचालक श्री अनिल शर्मा के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसी तरह नोएडा विकास प्राधिकरण की सीमा के अन्दर निर्मित होने के बावजूद भी प्राधिकरण के नियमों के अनुरूप भवन नहीं निर्मित किया गया, किन्तु इस सन्दर्भ में भी कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है। इसी प्रकार ऑनलाइन प्रशिक्षण और अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षुओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण व प्रमाण-पत्र भी संदेह के घेरे में है। तमाम अनियमिततायें उक्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जा रही हैं, किन्तु संस्थान के विरुद्ध कोई

कार्यवाही न होने से जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का प्रमाण-पत्र पर शंसय जाता है, वहीं उक्त प्रशिक्षण संस्थान पर भी प्रश्न चिह्न उठता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्रवाई की माँग करती हूँ।]

श्री अध्यक्ष-

जो लोग अभी अनुपस्थित थे वह हमें बता देंगे तो हम उनकी सूचना ले लेंगे।

[12:31] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-300 की सूचना लेते हैं। आज दिनांक 08 फरवरी, 2024 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचनाएं प्राप्त हुयीं।

पहली सूचना मा0 सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय की बजट सत्र के उपवेशन की संख्या बढ़ाये जाने तथा विभागवार बजट लिये जाने के सम्बन्ध में है।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि के फ्री-होल्ड प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना पर अध्यक्ष के निदेश

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना मा0 सदस्य श्री अरमान खान की उत्तर प्रदेश में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि की फ्री-होल्ड प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

मा0 वर्मा जी, आप कृपया बैठिये। आपका संरक्षण चाहिये। आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप एक प्रबोधन कार्यक्रम करायें और मा0 सदस्यों को यह बतायें कि नियम-300 क्या होता है, क्योंकि आप ही सबसे योग्य व्यक्ति हैं और मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी का हम सभी सम्मान करते हैं। वह इस विधान सभा के मा0 अध्यक्ष रहे हैं, उनका बहुत सम्मान है। आप मा0 सदस्य को बताईये कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमि की फ्री-होल्ड प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाये जाने का विषय नियम-300 के अन्तर्गत कैसे आ सकता है ? अगर आप मा0 सदस्य को थोड़ा-सा बतायेंगे तो मुझे सुविधा होगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप नोटिस नहीं लेते हैं।

***श्री लालजी वर्मा-**

मा0 अध्यक्ष जी, नियम समिति जो आपके द्वारा स्थापित है। कल हम लोगों ने समिति का गठन से सम्बन्धित जो विषय उठाया था वह तो पूरी तरह से आता है, लेकिन आपने उसे अग्राह्य कर दिया तो उसी तरह से इस पर भी सुनकर इसे भी अग्राह्य कर दीजिये, लेकिन अनुरोध है कि इस पर भी सुन लीजिये, ताकि बात आ जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, उसका जवाब आ गया था, वह सुनने लायक तो था, लेकिन यह सुनने लायक कैसे है, आप यह बताइये ? कोई भी मा0 सदस्य हो, अगर उनको जानकारी नहीं है, मैं एक पॉजिटिव नोड में कह रहा हूँ कि जिन दिनों विधान सभा चलती है, पीछे कियॉस्क लगाये गये हैं, उसमें सभी नियमों का पूरा डिटेल है। जिस भी नियम में आपने सूचना लगायी है, उस नियम को अगर आप क्लिक कर देंगे तो उस नियम का पूरा डिटेल आ जायेगा। उसमें भी मैंने अप-टू-डेट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वह प्रयोग की है। इसलिये मेरा आग्रह है कि सूचना लगाने के समय अगर आप उसको देख लेंगे तो उचित रहेगा। दूसरी बात यह है कि मा0 मनोज पाण्डेय जी ने भी जो सूचना दी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा केवल इतना आग्रह है कि बात आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

विषय यह है कि फिर मैं नियम-300 के अन्तर्गत हर गली की नाली, खड़न्जा सुनने लगूँगा, तो फिर वही सुनूँगा। अगर बात यही आनी है कि नियम-300 के अन्तर्गत मैं किसी की बात सुन लूँ तो सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के नाली, खड़न्जा, राजस्व सब लगा देंगे, तो फिर मैं सब सुन लूँगा, जिसके बाद नियम-300 में सारा दिन निकल जाएगा। आप इस बात को सोचें कि विधान सभा का समय इसके लिए नहीं है, मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूँ ताकि आगे से सब लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है, इसलिए इसको आग्राह्य करते हैं। क्योंकि वह नए सदस्य हैं, इसलिए मैं कह उनको रहा था, लेकिन सुना आपको रहा था।

बजट सत्र के उपवेशन की संख्या बढ़ाये जाने तथा विभागवार बजट लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी सूचना पूरी तरह से मेंटेनेबुल है।

श्री अध्यक्ष-

कैसे मेंटेनेबुल है ? इसमें विधान सभा की कार्यवाही कैसे बाधित होती है, इसमें क्या है आप बतायें?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप दो मिनट का मौका दे दें तो हम नियमावली को ही पढ़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप नियमावली पढ़िए।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय के द्वारा कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप नियमावली पढ़िए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमें नियमावली कंठस्थ है।

श्री अध्यक्ष-

आपको कंठस्थ है, लेकिन हमें नहीं है, इसलिए मैं नियमावली निकाल लेता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आप हमारी नोटिस भी निकाल लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी नोटिस नहीं, मैं नियमावली निकाल रहा हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आप नोटिस और नियमावली दोनों निकाल लें।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमावाली छोड़िए, नियम-300 की सूचना पढ़िए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमने नियम-300 पर जो नोटिस दी है, वह इस बात के लिए है कि जो बजट इस हाउस में प्रस्तुत हुआ है, उसमें हमने निवेदन किया है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन महत्वपूर्ण विभागों पर कटौती प्रस्ताव पर चर्चा करा ली जाए। मैं समझता हूँ कि आपसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हम आपके बताये हुए रास्ते पर चलेंगे। आपने सदैव यह मांग की है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन पर अलग से चर्चा करायी जाए। इसके दृष्टांत और परम्परायें आपके पास हैं, यही निवेदन मैंने आपसे किया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने निवेदन किया और मैंने सुना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नियम-300 में आता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, जब मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था तब आपने पढ़ा नहीं, अब मैं आपको कह नहीं रहा हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमें तो कंठस्थ है इसलिए हम ऐसे ही बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, आप पढ़ के बता रहे हैं और ये ऐसे ही बता रहे हैं। यह भी एक गम्भीर बात है कि मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी, कह रहे हैं कि वर्मा जी, तो पढ़ कर बता रहे हैं लेकिन मुझे नियमावली याद है। इसका मतलब है कि आपको याद नहीं है। वह अपने आपको आपसे ज्यादा विद्वान बता रहे हैं यह भी समझिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जो आपने बोला है इस पर आपने कार्य-मंत्रणा की समिति में चर्चा की है और कार्य-मंत्रणा की समिति में यह कहा गया कि विभागवार चर्चा होगी, तो फिर आप यह विषय यहां पर क्यों लाए ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, कार्य-मंत्रणा में तो बहुत चीजे तय होती हैं लेकिन यहां पर नहीं तय हुई है।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर नहीं तय होती है, जो बिजनेस होता है वह कार्य-मंत्रणा समिति में तय होता है, यहां पर नहीं तय होता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, लेकिन हम नियम-300 तो यहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपको मालूम है कि वह आ रहा है तो आप अपना नाम लिखवाने के लिए यदि यह सब कर रहे हैं तो फिर नाम लिख गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह विधायकों और विपक्ष के लिए है और नियमावली में भी है इसीलिए निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष

मद संख्या-2 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार नियम-301 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की अट्ठारहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र, 2023 (दिनांक 28-11-2023 से दिनांक 01-12-2023 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार नियम-301 के अन्तर्गत ग्राहय सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण इस सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट†

ऊर्जा, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन ऊर्जा निगम लिमिटेड की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा वर्ष 2019-20 कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का अट्ठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21†

ऊर्जा, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का अट्ठारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 को कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 व 6 में कुछ नहीं है। मद संख्या-7 को बाद में लेंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

---

† छापी नहीं गई।

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 फरवरी, 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 08 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को विचार एवं पारण करा लिया जाये।

2-दिनांक 09 फरवरी, 2024 को भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, को विचार एवं पारण करा लिया जाये।

3-दिनांक 09 फरवरी, 2024 को निधन के निदेश।

4-दिनांक 09 फरवरी, 2024 को नियम-103 के चर्चाधीन प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा।

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी से सहमत हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य कोई नहीं है।

[12:36] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 2 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जायेगा। श्री अतुल प्रधान एवं श्री पंकज कुमार मलिक जी की सूचना प्रदेश में किसानों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। माननीय कृषि मंत्री जी से उन्होंने हाउस में निवेदन किया है कि उसको कल लेंगे। एक सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री कमाल अख्तर, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री आशु मलिक की राज्य वित्त आयोग द्वारा नए सर्वे कराकर स्थानीय निकायों, नगर निगम चूंकि इसमें संशोधन, सुबह यह ग्राह्य नहीं थी तो माननीय मनोज कुमार पाण्डेय जी द्वारा दूसरी सूचना दे दी गयी जिसमें नगर निगम और स्थानीय नगरीय निकाय के बारे में धन आवंटित के विषयक को सुनने के लिए है। कौन बोलेगा ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, दो लोग बोलेंगे। पहले कमाल अख्तर साहब बोलेंगे।

श्री कमाल अख्तर-

माननीय अध्यक्ष, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने लोक महत्व के इस मामले को जो 80 हजार चुने हुए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों के हनन से सम्बन्धित है। उस मामले को उठाने का मुझे मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग से विकास के लिए जो धन आवंटन किया जाता है। उसका आधार आबादी है। आबादी के आधार पर 2011 की जनगणना जब हुई तो उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 थी। उसी आधार पर सभी संस्थायें ग्राम सभाओं के लिए, ब्लाक के लिए, जिला पंचायत के लिए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के लिए पांचवे राज्य वित्त आयोग से धन आवंटन के लिए सबको धन दिया जा रहा है। आज 13 साल बाद जबकि आबादी बढ़कर 30 प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है तो इतना जरूर हुआ है कि 2020-21 में जो राज्य वित्त आयोग का मिलने वाला पैसा था वह निकायों या संस्थाओं से कम तो कर दिया गया। आज आबादी लगभग 23 करोड़ 15 लाख 2 हजार 578 है। जो सरकार ने सर्वे कराये हैं उसके हिसाब से। इस आबादी के सापेक्ष आज तक राज्य वित्त आयोग का पैसा इन संस्थाओं के लिए नहीं बढ़ाया गया। यहां तक सरकार ने लगातार पैसा घटाया है। पैसे घटाने के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग के अन्दर जो पैसा मिलता है उससे विकास का काम होता है। तनख्वाहें देना होता है। त्रिस्तरीय पंचायत या जो चुनाव कराये जाते हैं फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है।

यह आटोनॉमस बाडी है, इसलिये ग्राम प्रधान और चेयरमैन को यह अधिकार दिये गये थे कि वह अपने स्तर से काम करा सकें। आज यह हो रहा है कि सरकार ने राज्य वित्त आयोग के पैसे से पंचायत सहायक लगा दिये हैं, अच्छी बात है पंचायत सहायक लगाने चाहिये, लेकिन हर ग्राम सभा से उनको जो 7000 रुपये वेतन दिया जा रहा है उसके लिए सरकार को बजट के अन्दर प्राविधान करना चाहिये था। जब सरकार नौकरियाँ देने की बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है तो इनके लिए सरकार को अलग से बजट में व्यवस्था भी करनी चाहिये थी। आपने शौचालयों में सफाई कर्मचारी लगाये लेकिन उसकी तनख्वाह भी राज्य वित्त आयोग के खातों से जा रही है। गौशाला के अन्दर भूसे की व्यवस्था भी राज्य वित्त आयोग के पैसे से की जा रही है, आप जल सखी लगाने जा रहे हैं उसका भुगतान भी राज्य वित्त आयोग से करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं, ग्राम प्रधानों के मानदेय का भुगतान भी राज्य वित्त आयोग से कर रहे हैं और इसमें सरकार बजट से धनराशि नहीं दे रही है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के अन्दर कहा और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आपके पास बजट है और आपने बेसिक शिक्षा विभाग के

स्कूलों को बजट दिया। ग्राम प्रधान और चेयरमैन के पास अधिकार होते थे और वह शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते थे लेकिन आपने उनको भी हटा दिया।

राज्य वित्त आयोग में जितना भी विकास का पैसा है वह सारा का सारा पैसा आपकी पार्टी की योजनाओं के अन्दर अधिकारियों के बल पर खर्च कराने का काम किया जा रहा है। आजादी के बाद ऐसा कहीं नहीं हुआ कि अधिकारी टेण्ट और सोफे लगाकर राज्य वित्त आयोग के पैसे से भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और अधिकारी बैठकर इस पैसे से पार्टी की सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार गांव के अन्दर कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष को अधिकार दिये गये थे लेकिन आज उन अधिकारों का हनन हो रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर वर्ष 2021 में छठें वित्त आयोग की जो कमेटी बननी थी वह चुनाव की वजह से नहीं बनी और उसे पेण्डिंग कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इतनी सारी चीजें ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों पर थोपकर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज चुने हुए जनप्रतिनिधि पूरी तरह से त्रस्त हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पर चर्चा कराई जाये और आबादी के हिसाब से इसे बढ़ाया जाये ताकि विकास हो सके। कई जगहों पर तो ऐसा है कि जितना पैसा मिलता है उतनी तो तनख्वाह चली जाती है और वहां पर विकास के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार सभी जनप्रतिनिधियों के साथ भेद-भाव कर रही है। मैं मांग करता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय और यह विरोध का कोई विषय नहीं है। राज्य वित्त आयोग से सम्बन्धित टी0एन0 धर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में तीन चीजें ली गई थी। पहली, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्रफल, दूसरी वहां की जनसंख्या और तीसरी टी0एन0 धर साहब ने अनुशंसा की थी कि गांव या वार्डो की स्थितियाँ। इनके आधार पर राज्य वित्त आयोग ने यह सिफारिश राज्य सरकार को दी थी। हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम टाउन एरिया और नगर पालिका उनमें समय-समय पर विभिन्न सरकारों में सीमा विस्तार हुआ। सीमा विस्तार हो गया और उनमें क्षेत्र बढ़ा दिये गये, लेकिन राज्य वित्त आयोग से तुलनात्मक रूप से सिफारिश नहीं की गई कि इसके डेवलपमेण्ट के लिए और कितना पैसा देना चाहिये।

मान्यवर, राज्य वित्त आयोग के सम्बन्ध में 19 शासनादेश हुये। सारे शासनादेशों में एक जैसी बात कही गयी है कि राज्य वित्त के पैसे से पहले यह निकाय कर्मचारियों का वेतन, फण्ड, ग्रेच्युटी का भुगतान करेंगे, इसके भुगतान के बाद जो शेष धनराशि बचेगी उस धनराशि में भी केटेगरी तय की गयी कि आप इसको ड्रेनेज में प्राथमिकता देंगे, आप इसको लाइटनिंग

पर प्राथमिकता देंगे, इस तरीके के शासनादेश हुये हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा नगरपालिकायें और लगभग 500 टाउन एरिया हैं। उनमें अगर सर्वे कराया जाये तो उत्तर प्रदेश के लगभग 50 प्रतिशत टाउन एरिया ऐसे हैं जिनमें जो राज्य वित्त से पैसा जा रहा है वह उनकी सैलरी से भी कम है या कहीं पर इस तरह से जा रहा है कि वह उनकी सैलरी का ही हो पाता है। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, जिसके 12 अनुच्छेद रहे हैं, कई राज्यों ने उसको काफी लागू कर दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी पूरे लागू नहीं हैं। उसमें इन संस्थाओं को एक मिनी गवर्नमेंट के रूप में परिकल्पना की गयी है, भारत के संविधान में 243 टी0बी0 में यह है कि यह अपनी खुद की सरकारें होंगी और इनको विभिन्न विभागों का अनुरक्षण और देख-रेख करना है। यह सच्चाई है जो हमारे साथी श्री कमाल अख्तर जी ने कहा है कि जब एक लोकल बाडी गवर्नमेंट के रूप में भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में उसकी चर्चा की गयी है। उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप यह काम करेंगे आपकी यह प्राथमिकता होगी। आप पहले स्कूल की रंगाई करायेंगे, टाइल लगवायेंगे, पंखा लगवायेंगे, गौशाला के लिए आप करेंगे, बाउंड्री बनवायेंगे, टीन शेड बनवायेंगे, चारे का पैसा आप देंगे तो मान्यवर, जो वार्ड के अन्दर या गाँव के अन्दर जो डेवलपमेंट वर्क है जो उनकी प्राथमिकता है जिसके लिये वह चुनकर आये हैं, जो ग्राम पंचायत एक्ट में या नगर पालिका एक्ट में उनके बारे में चर्चा की गयी है उससे वह दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है। यह इस चीज का विषय नहीं है कि हम विरोध करने के लिए उठे हैं, यह विषय है कि जो उत्तर प्रदेश के चुने हुये प्रधान हैं वह आज अपने गाँव का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो पार्षद, मेम्बर या चेयरमैन हैं वह जिस चीज के लिए चुने गये हैं वह कार्य वह नहीं कर पा रहे हैं। यह भारत के 73वें, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार उनकी शक्तियाँ छीनी जा रही हैं, अतिक्रमित की जा रही हैं। अगर शासन से निर्देश दे दिये जायेंगे कि आपको यही कार्य उसमें करना है तो उनकी प्राथमिता जो बोर्ड ने तय किया है क्योंकि बोर्ड तय करता है कि नाली कहाँ बनवाना है, नाला कहाँ बनवाना है, कहाँ हमको पहले प्राथमिता देना है तो वह बोर्ड से ऊपर हो गया है। शासन ने कह दिया कि नहीं, आपको यही काम करना है। मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इस पर सरकार विचार करे और विचार करके एक समिति बनाये और पुनः राज्य वित्त की एक कमेटी किसी सुयोग्य व्यक्ति की अध्यक्षता में बनाकर एक नयी अनुशंसा ले और जो नगर पंचायतों, लोकल बाडी में और ग्राम पंचायतों में जो अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है इस पर रोक लगायी जाये उनके पैसे को गौशाला, स्कूल या तमाम जगहों पर रोककर जहाँ के लिए वह चुनकर आये हैं जो भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में कल्पना की गयी है उसको पूरा कराया जाये। मान्यवर, यह हमारा निवेदन है। महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं इसमें चर्चा की मांग करता हूँ और हमारे नगरीय क्षेत्र से ही चुनकर आये श्री रविदास मेहरोत्रा जी के लिए भी निवेदन करता हूँ कि दो मिनट इनको भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले आपने क्यों नहीं निवेदन किया।

***श्री रविदास मेहरोत्रा-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अभी बोलने का अवसर नहीं दिया है। अभी तो मै पाण्डेय जी से पूछ रहा हूँ कि उन्होंने पहले दो नाम लिये आपका नाम क्यों नहीं लिया।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, यह मेरी नोटिस है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो बात आप लोगों ने की है उससे मैं अलग बात कह रहा हूँ। मान्यवर, पूरे प्रदेश की बात आपने सुन ली है। मान्यवर, मै केवल लखनऊ नगर निगम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो राज्य वित्त आयोग है उसमें 13 साल पहले आबादी के आधार पर धन का आवंटन होता है। 13 वर्ष के अन्दर लखनऊ की आबादी दोगुना से अधिक हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन रेशियो वही है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, जो लखनऊ के चारों तरफ गाँव हैं वह लखनऊ नगर निगम में मिल गये हैं। अब नगर निगम के पास सफाई कर्मचारी नहीं हैं।

मान्यवर, नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं है क्योंकि उनके पास तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। जो लोग नाले की सफाई करते हैं वही कहते हैं कि राज्य वित्त आयोग से पैसे का आवंटन बढ़ नहीं रहा है। 13 साल में एक पैसे का भी आवंटन नहीं बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष-

यानि पैसे का आवंटन बढ़ा है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि बहुत गम्भीर बात है। सफाई कर्मचारियों के पास ठेले तक की व्यवस्था नही है, सफाई कर्मचारी के पास नाला साफ करने का भी सामान नहीं है, सीवर लाईन की सफाई करने वालों के पास सामान नहीं है क्योंकि धन का आवंटन नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा नगर निगम के अन्दर कहीं पर भी कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। मैं नगर निगम का पदेन सदस्य हूँ। जब मैं मीटिंग में जाता हूँ तो वह हर बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कहते है कि विधान सभा के अन्दर राज्य वित्त आयोग के पैसे का आवंटन बढ़ाने का काम किया जाए। आपने बजट पेश किया और आपने बजट में कहा कि स्कूल के अन्दर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसी पैसे से स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, उसी पैसे से लोगों को तनख्वाह मिल रही है।

श्री अध्यक्ष-

वह 15वें वित्त आयोग से बन रही है, राज्य वित्त आयोग से नही बन रही है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बहुत गम्भीर विषय है, सदन की कार्यवाही रोककर दो घण्टे की चर्चा कराई जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, 13 साल से जनगणना नहीं हुई है।

(सदस्य, श्री मौहम्मद फहीम इरफान के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री इरफान जी आपका क्या विषय है?

***श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मान्यवर, इसमें मेरा नाम है। मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप घड़ी देखकर एक मिनट में अपनी बात कह लीजिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, ग्राम प्रधानों के साथ बड़ी दिक्कत यह हो रही है क्योंकि.....

श्री अध्यक्ष-

मैने पहले ही नगरीय क्षेत्र के लिए बोल दिया था।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने को कमाल अख्तर जी, मनोज पाण्डेय जी एवं मेहरोत्रा जी से सम्बद्ध करते हुए एक गुजारिश करना चाहूँगा कि वर्ष 2011 की आबादी के हिसाब से जो राज्य वित्त आयोग की धनराशि आवंटित की गयी थी वह 13 वर्ष बाद भी उतनी ही है।

श्री अध्यक्ष-

उतनी ही नहीं है उसी रेशियो से बढ़ी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, थोड़ी सी बढ़ी है। मेरा कहना है कि ग्राम प्रधानों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ ज्यादती हो रही है। ग्राम प्रधान गांव का अपने आपमें बहुत बड़ा ओहदा होता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने ग्रामीण क्षेत्र की एक्सेप्ट ही नहीं की है। मैंने पहले ही नगरीय क्षेत्र के लिए बोल दिया था।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, उन जनप्रतिनिधियों से कहा जाता है कि आप अपने गांव में नाला बनवाइए, नगरीय क्षेत्र में सड़क बनवाइए लेकिन उनके पास उतना धन नहीं हो पाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चाहे गौशाला का मामला हो या बेसिक शिक्षा का मामला हो या सोलर का मामला हो, उनके लिए अलग से धन आवंटित होना चाहिए क्योंकि ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों को धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उनको ज्यादा-से-ज्यादा धन आवंटित कराया जाए जिससे उन्हें गांवों एवं नगरीय क्षेत्र में विकास करने का मौका मिल सके और सभी कार्य रोककर इस पर चर्चा कराने का काम किया जाए।

नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने जो विषय उठाया राज्य वित्त आयोग के द्वारा फाइनेसिंग होती है। मैं प्रमुख रूप से नगरीय क्षेत्र की बात करूँगा। जैसा कि कहा गया है कि 5वां राज्य वित्त आयोग वर्ष 2015 में बना था और उसने वर्ष 2018 में अपनी संस्तुति दी। उस संस्तुति के आधार पर जो कर का विभाज्य पूल होता है उसका 12.5 प्रतिशत अंश ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के लिए मिलता है। नगरीय निकायों को 60 प्रतिशत एवं ग्रामीण निकायों को 40 प्रतिशत दिया जाता है। 7.5 प्रतिशत नगरीय निकायों एवं 5 प्रतिशत ग्रामीण निकायों के पास जाता है। सदन में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की बात की गयी है, वह सही है कि वर्ष 2011 के आधार पर ही यह सारा मामला चल रहा है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में जनंसख्या का भारांक 90 प्रतिशत है और क्षेत्रफल का भारांक 10 प्रतिशत है। यह बात सच है कि वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है लेकिन इस बात को माननीय सदस्य को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो सबकी बढ़ेगी। अगर टैक्स का पूल उतना ही है तो जो शेयर या प्रतिशत है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूँ। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि नई एक्सरसाईज नहीं होनी चाहिए। नई एक्सरसाईज करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी ने छठें वित्त आयोग की रचना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पिछले जनवरी में उसकी कार्यवाही भी हो गयी है लेकिन अब इस दिशा में कुछ मा0 सदस्यों ने जो बात कही उसके बारे में कुछ स्पष्टता कर देना सबकी जानकारी के लिए भी

आवश्यक है और उन बातों को सदन में स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है। जैसे कहा गया कि लगातार एस0एफ0सी0 का पैसा घट रहा है। मा0 कमाल अख्तर ने जो कहा वह बात सत्य नहीं है। मैं चार साल का फीगर देना चाहूंगा वर्ष 2020-21 में एस0एफ0सी0 का आवंटन 8 हजार 525 करोड़ रुपया था, वर्ष 2021-22 में बढ़कर 9900 करोड़ हुआ और वर्ष 2022-23 में बढ़कर 10 हजार 800 करोड़ हुआ और वर्ष 2023-24 में उससे भी बढ़कर 12 हजार 600 करोड़ हुआ है। पहली बात तो आपकी यह जानकारी ठीक नहीं है कि वित्त आयोग का पैसा लगातार घट रहा है। जो कहा गया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य ने जो घटने की बात कही है उनका तात्पर्य है कि जब कार्य भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ेगा तो पैसा उतना ही है, लेकिन जब भौगोलिक क्षेत्र बढ़ गया तो वह बजट पर ही तो आएगा। यही मा0 सदस्य ने कहा है और इसको विपक्ष का न मानिए, इसको यह मानिए कि उत्तर प्रदेश के नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिए एक अच्छी योजना लाने जा रहे हैं या उस पर विचार करने जा रहे हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मैं खाली स्पष्टता कर रहा हूं, आप सबकी जानकारी में रहे यह आवश्यक भी है। दूसरी बात यह कही गयी कि तमाम विकास की योजनाएं चाहे गौशाला की बात हो, चाहे विस्तारित क्षेत्रों के विकास की बात हो तमाम योजनाओं का पैसा भी एस0एफ0सी0 से खर्च किया जाता है, मैं पुनः इसकी स्पष्टता करना चाहता हूँ कि जो नव-विस्तारित क्षेत्र हैं या नव रचित नगर पंचायतें हैं, आप सबके ध्यान में होगा कि पिछले साल के बजट में मा0 वित्त मंत्री जी की कृपा से एक नयी योजना सी0एम0एन0एस0वाई0 शुरू की गयी उसके लिए पिछले साल भी व्यवस्था की गयी थी, इस साल भी की गयी है। उसी प्रकार गौशाला के व्यवस्थापन के लिए भी अलग से बजट का प्रॉविजन है, एस0एफ0सी0 से उसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। कहीं इमरजेंसी आ जाये तो वह बात अलग है लेकिन गौशालाओं के लिए भी योजना है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे पिछड़े हुए निकाय हैं, छोटे निकाय हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, आकांक्षी निकायों के लिए भी नयी योजना शुरू की गयी है। जो इस राज्य में पहले कभी हुआ वह मा0 वित्त मंत्री व मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से नगरीय क्षेत्रों को जो विशेष योजनाएं मिली हैं उसका भी जिक्र कर दूं। मैं यह जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कार्य किसी भी मा0 सदस्य का हो तो आप प्रस्ताव भेजें उसको एस0एफ0सी0 से लिंक करके चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। इन सारी बातों के लिए अलग योजनाएं हैं, मैं खाली पढ़ देना चाहता हूँ कि वंदन योजना है, अगर धार्मिक स्थानों का विकास करना है तो उसके लिए पिछले अनुपूरक बजट और इस बार रेग्युलर बजट में इस योजना का प्रावधान किया गया है। इससे हम धार्मिक स्थानों एवं ऐतिहासिक स्थानों का सुन्दरीकरण कर सकते हैं। उसी प्रकार

पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि नगरीय क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए अलग से नगरीय क्षेत्र की कोई योजना हो।

मा0 वित्त मंत्री का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उन्होंने इसे समझा और सी0एम0 ग्रिड्स नाम से एक नयी योजना लेकर हम लोग आये हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टार्म वाटर ड्रैनेज योजना का नगरीय क्षेत्रों में प्रावधान करके बजट दिया। उसकी भी मा0 वित्त मंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से एक अलग से योजना बनी है। इतना ही नहीं, जो इनमें से भी परिभाषा में न आते हों, चाहे ऑडिटोरियम बनाना हो, चाहे प्रदर्शनी के लिए जगह बनानी हो या ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, लोक-उपयोगी काम, सामूहिक काम यदि नगर निकायों में करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निकायों में अलग से हेड खोलकर बजट में प्राविजन किया गया है। जैसा मैंने कहा इन्डस्ट्रियल एक्जिविशन सेण्टर, एक्जिविशन ग्राउण्ड बनाने के लिए या ऑडिटोरियम बनाने के लिए तो इन सारे कार्यों के लिए अलग-अलग योजनाएँ बजट में प्रस्तावित हैं, बजट में अप्रूव्ड हैं। आप में से किसी को भी ऐसा कोई काम कराना हो तो उसको एस0एफ0सी0 से चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विधायक, श्री रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ की विशेष बात की तो लखनऊ भी नव विस्तारित एक नगर निगम है, आपको मालूम है और उसके भी विस्तारित क्षेत्रों के लिए जहाँ-जहाँ भी विस्तारित क्षेत्र हैं, उन सब के लिए नगर सृजन योजना में से हम लोग पैसा दे रहे हैं और मैं चूँकि विद्युत मंत्री भी हूँ तो इन निकायों के लिए खास मेहरबानी करके माननीय वित्त मंत्री जी ने हमको एलाऊ किया कि हम अपने विभाग की अगर कहीं बचत हो तो इसमें सी0एम0एन0एस0वाई में जो पैसा है, उसके अतिरिक्त भी पैसा लगा करके हमने विद्युत विभाग से सम्बन्धित जो आधारभूत संरचना के कार्य थे, उसको भी हमने इन नव विस्तारित निकायों में और सभी निकायों में कराया है। तो कुल मिला करके बजट की कोई समस्या नहीं है। मैं एक और जानकारी दे करके अपनी बात पूरी करूँगा। 2016-17 में हमारे विभाग का जो बजट 6 हजार, 7 हजार करोड़ हुआ करता था, वह पिछले साल लगभग 04 गुना बढ़ करके 2023-24 में 28,779 करोड़ का हुआ है तो न तो एस0एफ0सी0 का पैसा घटा है, न ही हमारे नार्मल बजट का पैसा घटा है, दोनों में ही वृद्धि हुई है और जैसा मैंने कहा पिछले 10 सालों में लगभग 04 गुना की वृद्धि हुई है। अनेक कामों के लिए अलग-अलग योजनाएँ, जितना हम लोगों की समझ में आता है, प्रस्तावित करते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी की कृपा से मिल जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से मिल जाता है और अच्छी बात यह है, अगर आपकी चिन्ता कुछ हद तक सही भी मानी जाय तो छठवें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बहुत विस्तार से उत्तर आ गया है। नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत जितना काम हो रहा है और जितना बजट दिया जा रहा है, वह बहुत ज्यादा दिया जा रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, आप पता करा लीजिए, ग्राम पंचायतों को कितनी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

देखिए ग्राम पंचायतों का उत्तर यह नहीं देंगे। मेरा निवेदन आप सुन लीजिए, आपने कई विभागों के लिए एक साथ नोटिस दिया था। ग्राम और शहर अलग-अलग होते हैं। मैं आपकी नोटिस नहीं ले रहा था, क्योंकि दो विभागों के लिए एक नोटिस नहीं आ सकती है, यह बात आपको पता है। लेकिन आपके निवेदन पर कि हम केवल नगरीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे, उस पर मैंने आपकी नोटिस स्वीकार की थी। उस पर माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं और पूरी तरीके से जो योजनाएँ इन्होंने बनायी हैं, वह हम सब लोगों को मालूम हैं। तो अनावश्यक अब इसमें बात करने का औचित्य नहीं है। मैंने इस पर माननीय मनोज पाण्डेय जी को सुना, माननीय कमाल अख्तर साहब को सुना, माननीय रविदास मेहरोत्रा जी को सुना, माननीय इरफान जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

हमारी नियम-56 की सूचना पर माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, यह संविधान का उल्लंघन है। इसके विरोध में हम 01 मिनट के लिए सदन से बहिर्गमन करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट के लिए क्यों कर रहे हो, एक मिनट तो जाने-आने में लग जाता है।

(समाजवादी पार्टी के कतिपय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

एक सूचना श्री अनिल प्रधान की है जो ध्यानाकर्षण के लिए है। अनिल प्रधान जी आप एक मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं दो सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। जो मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना योजना है, उसकी तीन शर्तें हैं, या तो मृतक के नाम जमीन हो, उसमें तो लोगों को मुआवजा मिल जाता है। उसमें जो दूसरी शर्त है, अगर किसी का बेटा खत्म हो गया और वह अपनी माता या पिता के नाम की जमीन पर कृषि कार्य करता

था तो उसमें लेखपाल का प्रमाण-पत्र लगता है। लेखपाल उसमें प्रमाण-पत्र नहीं लगाता है, बहुत ज्यादा शोषण करता है। तीसरी शर्त जो है, बटाईदार का प्रमाण-पत्र लगना है। इन दोनों में लेखपाल बहुत परेशान करते हैं, रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा एक और सुझाव है, जो सर्प-दंश वाले मामले हैं, जिसमें सर्प काट लेता है, उसमें बिसरा रिपोर्ट नहीं आती। पहले डाक्टर लिख देता था, लेकिन अभी जो नया शासनादेश जारी हुआ है, मेरा इसमें यही निवेदन है कि जो भी बिसरा रिपोर्ट सर्प दंश के मामले की प्रिजर्व है, उनकी हर हाल में जाँच करायी जाय।

मेरा यह निवेदन है कि उसमें कुछ आदेश हो जाए कि लेखपाल लिखने लगे और जो बिसरा रिपोर्ट है वह हर हाल में आ जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो विषय मा0 सदस्य ने उठाया है, क्योंकि सांप काटने पर बिसरा रिपोर्ट की आवश्यकता होती है और बिसरा रिपोर्ट आने में काफी समय भी लग जाता है। मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार के इशूज हैं, मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

[01:06] उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 का अननुमोदन का संकल्प

***श्री सचिन यादव-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय सातवां संशोधन अध्यादेश वर्ष 2024 के अनुमोदन के लिए मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक तरफ हम लोग निजी विश्वविद्यालय इस प्रदेश में बनाते चले जा रहे हैं, निजी विश्वविद्यालय बन रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उसके जो रिपल इफेक्ट है, उसके बनने के बाद आस-पास की जो उससे रिलेटेड चीजें हैं उस पर कैसा इफेक्ट होता है उसको सदन के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि जब यह अध्यादेश लाया गया तो उसके जो निजी विश्वविद्यालय के रिपल इफेक्ट्स होंगे उसका असर किसी दूसरी चीजों पर कैसा पड़ेगा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और एक तरफ निजी विश्वविद्यालय बना-बना के लम्बी लाईन की कतार लगा दी जा रही है। निजी विश्वविद्यालय जहां बन रहे हैं उसके आस-पास आप पता कर लेंगे तो 200 से 250 छोटे कालेज होते हैं, उन कालेज में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, उसके आस-पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं, अगर आप आगरा क्षेत्र की बात करेंगे, मेरठ क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हैं, यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। आप देखेंगे कि बी0ए0, बी0एस0सी0 में जहां पर उस यूनिवर्सिटी में छात्र 30 हजार, 35 हजार हुआ करते थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और पढ़ा करते थे, वह आज पांच-छः हजार रह गए हैं, उनका रेवन्यू बढ़ता जा रहा है और पब्लिक यूनिवर्सिटी को चलाना मुश्किल हो रहा है और जो स्मॉल कॉलेज हैं एक निजी विश्वविद्यालय के आस-पास 200 से 250 कॉलेज होते हैं, वह सब इफेक्ट हो रहे हैं, वह सभी खत्म होने के कागार पर हैं और ताला लगने के कागार पर हैं।

निजी विश्वविद्यालयों की अगर क्वालिटी बेहतर हो तो भी उससे समझौता किया जा सकता है, लेकिन निजी विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं, पी0एच0डी0 की डिग्री बांट रहें, किसी भी कोर्स की डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं और अगर हम निजी विश्वविद्यालयों का अध्यादेश लाते हैं और उनको पास करने का काम करते हैं। कोई भी निजी विश्वविद्यालय रिजर्वेशन के हिसाब से टीचर्स को नहीं रख रहा है और जो भी नौकरियां रखी जा रही हैं, वह रिजर्वेशन के विपरीत रखी जा रही हैं। हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, टोटल आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है और कर्मचारियों के आरक्षण से और टीचर्स के आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा है और ज्यादातर निजी विश्वविद्यालयों में प्रॉपर टीचर्स भी नहीं हैं, संख्या जितनी होनी चाहिए यू0जी0सी0 के मानक के हिसाब वह भी नहीं है तो आप टीचर्स रखने का मानक चेक नहीं कर रहे हैं, आरक्षण वहां का चेक नहीं कर रहे हैं, एग्जाम होते हैं या नहीं होते वह चेक नहीं कर रहे और अपनी पब्लिक यूनीवर्सिटी को बचाने का काम नहीं कर रहे और उनकी बच्चों की संख्या गिरती जा रही है और उस पर आप काम नहीं करना चाह रहे। छोटे कालेज जिसको लोगों ने अपनी कमाई से बनाया वह खत्म हो रहे हैं उस पर आप ध्यान नहीं देना चाहते तो सरकार की क्या मजबूरी है कि निजी विश्वविद्यलायों को बढ़ाने पर अकेला एकतरफा काम कर रही है, आस-पास की चीजों को नहीं देख रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि निजी विश्वविद्यालय संशोधन के साथ इसको प्रवर समिति को दिया जाए और वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज को भी कैसे इम्प्रूव किया जाए उसको भी साथ में लाएं, छोटे कालेज को कैसे सरकार से मदद मिले उसको भी ध्यान में रखें, आरक्षण टीचर्स को लेकर और कर्मचारियों को लेकर कैसे मेनटेन हों निजी विश्वविद्यालयों पर उस पर भी ध्यान रखें। डिग्री बांटने का काम न हो, बच्चों को सचमुच पढ़ाने का काम हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो इस पर भी ध्यान रखें और तब यह बिल लेकर आया जाए, यही मेरा अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा भी इसमें संशोधन का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, आपका भी है। अभी मद संख्या-11 पर प्रश्न आ रहा है उसके बाद मद संख्या-12 पर मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे तब आपका मद संख्या-12 में संशोधन का प्रस्ताव आएगा। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2024 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

उच्च शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाए।

मा0 अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए और उसको विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया था, आज भी चल रहा है। उसमें संशोधन मात्र इतना है कि एस0के0एस0 इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु मूल अधिनियम के अनुसूची-दो में संशोधन हेतु यह प्रस्ताव लाया गया है। यानि इससे पहले अनुसूची दो में क्रमांक-37 तक था अब नवस्थापित विश्वविद्यालय के लिए क्रमांक संख्या बढ़ाकर क्रमांक-38 पर प्रस्ताव है कि एस0के0एस0 इण्टरनेशनल विश्व विद्यालय, मथुरा उ0प्र0 को जोड़ दिया जाये। जिसकी प्रायोजक संस्था ब्रजवासी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन मथुरा है। अब यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 कहा जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी, शिक्षा व चिकित्सा दोनों मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है यानि पढ़ाई और दवाई। चिकित्सा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए उसके विकास के लिए होती है और शिक्षा व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए, मानसिक मजबूती के लिए और उसके मानस को स्वस्थ रखने के लिए होती है। पिछली सरकारों में इसकी चिन्ता की यह स्थिति थी कि इस राज्य में 18 मण्डल हैं उसके एक तिहाई यानि 6 मण्डलों में राजकीय विश्वविद्यालय तक नहीं थे। यह स्थिति थी इनकी चिन्ता की। चिकित्सा भी इनकी निगाह में उपेक्षित थी, जबकि शिक्षा रोजगार सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को संस्कार सिखाती है। शिक्षा व्यक्ति को नवाचार सिखाती है और शिक्षा व्यक्ति को सुसंस्कृत व्यवहार सिखाती है और अशिक्षा व्यक्ति यानि मनुष्य को जानवर बनाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की उपेक्षा इनके समय में होती थी आज हमारी सरकार ने यानि योगी जी की सरकार ने शिक्षा को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बनाने का अपना संकल्प पूरा किया है। अपने राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करना जैसा अभी इंजीनियर साहब बता रहे थे जो उसके दूसरे पहलू को देखते थे। वास्तव में यदि उत्तर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाना है, देश-विदेश के छात्रों को यहाँ आमंत्रित करके पढ़ाना है या रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हैं, यहाँ की शिक्षा का जो स्तर दिख रहा है उसे बढ़ाना है तो प्रतिस्पर्धा लानी पड़ेगी राजकीय विश्वविद्यालय भी खोलने पड़ेंगे और निजी विश्वविद्यालय भी खोलने पड़ेगें। जैसा मैने बताया कि लगभग 6 मण्डलों में इनके समय राजकीय विश्वविद्यालय तक नहीं थे। हमारी योगी जी की सरकार ने उनके कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं और प्रगति पर हैं। 6 मण्डलों में जिसमें आजमगढ़ में राजा

सुहेलदेव जी के नाम पर, अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी देवी, देवीपाटन में माँ पाटेश्वरी देवी, मिर्जापुर में माँ विन्ध्यवासिनी देवी और मुरादाबाद का नाम मुरादाबाद राजकीय विश्वविद्यालय, मुरादाबाद है।

इसी तरह निजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में लगभग 26 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के संस्थानों को एल0ओ0आई0 या एल0ओ0पी0 दिये गये हैं। यह हमारे योगी जी की वह चिन्ता है कि अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुँचे, उसको उसका लाभ मिले। प्रदेश शिक्षा का हब बने। 26 विश्वविद्यालयों को एल0ओ0आई0 मिल चुकी है, जिनमें से 11 को एल0ओ0पी0 भी मिल चुकी है। इस तरह से मानव जीवन के विकास के लिए यह प्रयास हो रहा है। यह प्रसार की बात कर रहा हूँ। अब शिक्षा का स्तर सुधारने की बात करता हूँ। अपने योगी जी की सरकार से पहले नैक की रैंकिंग में एक भी विश्वविद्यालय इस प्रदेश में भी नहीं था। आज नैक ग्रेडिंग में 5 सरकारी विश्वविद्यालयों को नैक रैंकिंग में ऐ डबल प्लस ग्रेडिंग करना एक उपलब्धि माना जाना चाहिए। 5 सरकारी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस ग्रेडिंग को ले चुके हैं। 6 निजी विश्वविद्यालय नैक रैंकिंग में ए प्लस श्रेणी में आ चुके हैं। 4 निजी विश्वविद्यालय ए श्रेणी में आ चुके हैं और यू0जी0सी0 की ग्रेडिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय नम्बर वन ग्रेडिंग में है। इस तरह यू0पी0 पूरे देश में सबसे अधिक ग्रेडिंग वाला प्रदेश बन चुका है। शिक्षा का यहाँ स्तर बढ़ रहा है और उसी क्रम में आज का प्रस्ताव आया है। शिक्षा मानव जीवन के लिए होती है, अगर कोई विश्वविद्यालय खुलता है तो उसमें सभी वह संवैधानिक मान्यताएं पूरी होती हैं। प्रवेश में जो आरक्षण है, नौकरियों में जो आरक्षण है, शैक्षिक से अलग जो नौकरियां होती हैं, उनमें जो आरक्षण है, वह सब दिया जाता है। सबका विकास इससे होता है। बड़े अफसोस की बात है कि कल नेता प्रतिपक्ष यह कह रहे थे कि ए प्लस, ए डबल प्लस हो गयी तो क्या हुआ? उनको एक ही रट थी कि पी0डी0ए0 नहीं हुआ। इनका जवाब जो मैं यहां से देना चाहता हूँ, वह उन तक पहुँच जायेगा कि हमारे जो अपने सरकार के विश्वविद्यालय हैं, इसमें 37 नियुक्तियां सरकार करती है जिसमें 19 ओ0बी0सी0 या एस0सी0 श्रेणी के हैं और 26 निजी विश्वविद्यालय जो खुल रहे हैं, उनमें जो संचालक हैं, उसमें 11 ओ0बी0सी0 और एक मुस्लिम है। इसलिए ग्रेडिंग को और उसके प्रसार को, विस्तार को और उसके स्तर को भी जातिगत भावना से देखना निश्चित रूप से एक अच्छी सोच नहीं माना चाहिए। 6 राजकीय विश्वविद्यालय जिनके नाम मैंने अभी पढ़े हैं, उसमें 4 तो स्थानीय आस्थाओं के प्रतीक पौराणिक जो हमारी मान्यताएं हैं, उनके नाम पर हैं और 2 जो ओ0बी0सी0 से सम्बन्धित हैं, एक शहजादा मुरादनगर के नाम पर उन लोगों के नामकरण पर हैं। इसलिए इन बातों को शिक्षा के बढ़ते स्तर को पूरी शिक्षा को जो सबके लिए होती है, जो एक आदमी को इंसान बनाती है, उसको जातिगत दृष्टि से देखना एक छोटी सोच ही माना जायेगा। राजनीति में यह बातें करते रहिये, शिक्षा पर रहम करिये इसलिये मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं इसमें मा0 मोना जी को बुलाऊँगा लेकिन मेरा एक निवेदन है कि यह बिल हम सब लोगों के पास हो क्योंकि जिस समय इन बिल पर चर्चा होती है तो प्रायः यह मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं और बिना पढ़े-लिखे पास हो जाता है तो मैंने यह व्यवस्था पहली बार दी थी कि मैं हाउस ओपन करूँगा जिससे जो भी उस पर बोलना चाहते हैं, वह बोलें लेकिन मेरा एक निवेदन है कि पहले वह बिल को पढ़ें।

श्री लालजी वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, वह बिल हमारे पास आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास 100 परसेण्ट वह बिल आया होगा। तो आप बोलेंगे क्या, जब बिल आया ही नहीं और आपने पढ़ा ही नहीं।

***श्री लालजी वर्मा–**

माननीय अध्यक्ष जी, हमने पिछली बार उठाया था कि जैसे सारे परिपत्र हम लोगों को भेजे जाते हैं, उसी तरह से बिल भी अगर हम लोगों को समय से मिल जाया करें।

श्री अध्यक्ष–

100 परसेण्ट भेज दिये गये हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि 100 परसेण्ट घर पर नहीं भेजा गया।

श्री अध्यक्ष–

तो आप बोलेंगे क्या, आपने बिल पढ़ा ही नहीं है।

श्री अतुल प्रधान–

मान्यवर, निजी विश्वविद्यालय पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष–

निजी विश्वविद्यालय पर नहीं, बिल पर बोलना है। आप मेरी बात सुनिये। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने बिल पढ़ा नहीं, आप कह रहे है कि आया ही नहीं है। आप हाथ खड़ा करके बोलेंगे क्या, जब आपने पढ़ा ही नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि कार्यालय पर गया होगा, हम नहीं कह रहे कि वहाँ नहीं गया होगा।

श्री अध्यक्ष-

कार्यालय पर गया होगा तो आपको कार्यालय पर चेक करना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया था कि जिस तरह से अन्य परिपत्र हम लोगों के घर भिजवाये जाते हैं। अगर उसी तरह से बिल भी भिजवा दिये जायें तो हम लोगों को ज्यादा आसान हो जायेगा। कार्यालय में थोक में भेज दिया जाता है, यह बात सही है। जैसे पहले पिजन-होल में रहता था तो हम अपना निजी निकाल लेते थे। मैंने पिछली बार आपसे आग्रह किया था और आपने सहमति भी दिया था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा। मेरा भी निवेदन सुन लीजिए। देखिये, मैं बिल के ऊपर एक परपजफुल डिबेट कराना चाहता हूँ। यह डिबेट्स कभी भी हुई नहीं हैं। डिबेट कराने का यह मकसद है कि यहाँ पर डिबेट हो, अगर कोई बिल आता है और सरकार बिल को प्रेषित करती है तो पूरा हाउस ओपेन है, इधर से भी लोग उसके पक्ष में बोल सकते हैं और इधर से भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिये कि बिल पढ़ा ही नहीं और संशोधन आ गया। संशोधन आया, इसका मतलब बिल पढ़ा गया होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जिसने संशोधन दिया, उसने पढ़ा ही होगा।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मंत्री जी ने इसके बारे में बता दिया, उसके आधार पर तो बोल ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसके आधार पर हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी एक माननीय सदस्य से पूछा कि क्या आप बोलेंगे, आपने पढ़ा ? उन्होंने कहा कि पढ़ा नहीं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो उस पर बोला है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने जिस विषय के ऊपर बोला है। मैं सब लोगों को बता दूँ कि जिस समय मैं डिबेट कराना चाहता हूँ तो मैने कहा कि मैं एक परपजफुल, पॉजिटिव डिबेट कराना चाहता हूँ। विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित इश्यू है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बोलना है। शायद

पहले डिबेट इसीलिए नहीं कराई जाती होगी कि कुछ भी बोल लो। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। यह जो बिल है, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से सम्बन्धित, जो उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 है, वह 2019 अधिनियमित किया गया था, तो वह बिल है, उसमें आगे कुछ अंश जोड़ दिये जाते हैं, जिसमें निजी विश्वविद्यालय अर्थात् एस0के0एस0 इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश को उसके साथ में जोड़ना है। निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के ऊपर पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है, जब यह 2019 में बिल आया था। मंत्री जी, यह सही है ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में यह बिल आया था, उसमें 37 के बाद 38वाँ, एस0के0एस0 इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय जोड़ना है। इसमें कौन सा प्रवर समिति को भेजने की बात है?

श्री अध्यक्ष-

अब मुझे बताने दीजिए। अधिनियम के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अधिनियम पहले 2019 में प्रख्यापित हो चुका है। उसमें बीच में यह जो कालेज है, एस0के0एस0 इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना हेतु उपबन्ध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया, इतना ही है। मैंने इसलिए इसको यहाँ पर बताया है कि जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, केवल इसी बात के ऊपर बोलें, जो बिल आया है, विश्वविद्यालयों के ऊपर चर्चा करने का इश्यू नहीं है। अभी मैंने जो बोला, उसके ऊपर बोलना चाहते हैं तो बोलें।

माननीय श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद एक एजुकेशनिस्ट परिवार से आती हूँ। लम्बे समय तक और लगभग 22 कालेजेस का संचालन मेरे परिवार द्वारा किया गया है, इण्टर कालेज से ले करके डिग्री कालेज और इंजीनियरिंग कालेज तक। मैं शिक्षा के महत्व को पूरी तरह समझती हूँ और मानती हूँ, मान्यवर, विद्यालय हमारे लिए शिक्षा का मन्दिर है, जहाँ सरस्वती स्वयं विराजमान रहती हैं। शिक्षा का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर उत्तर प्रदेश में क्योंकि यह सबसे युवा प्रदेश है जहाँ पर आज भी 50 प्रतिशत की आबादी युवा है। अगर हमें इस देश को, प्रदेश को आगे ले जाना है तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मैं आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपने 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। यह 28वें निजी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव आज इस सदन में रखा गया। केवल आश्य यह है, इसमें क्यों मैंने अपना संशोधन रखा है। निजी विश्वद्यिालय आज की तारीख में अनियंत्रित हो चुके हैं। हमारे जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि निजी विश्वविद्यालयों में मनमानी फीस ली जाती है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि मनमानी नियुक्तियाँ की जाती हैं। यू0जी0सी0 मानकों की अवहेलना करके नियुक्तियाँ की जाती है। जो यूनिवर्सिटी चाहती है वह पाठ्यक्रम रखती है, उनके मनमाने नियम होते हैं।

पिछली बार जब निजी विश्वविद्यालय का प्रकरण आया था तो मैंने इसी सदन में उस बात को उठाया था। निजी विश्वविद्यालय में एक बच्चे को इंसेफेलाइटिस की बीमारी हो गयी थी, वह बच्चा कालेज नहीं जा पाया, उसने अपने सारे डाक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में जमा किये, इग्जेम्प्शन मांगा, उस बच्चे का फाइनल ईयर था, उन्होंने अपने निजी नियमों को देखते हुये उस बच्चे को एग्जाम देने की परमिशन नहीं दी। उस बच्चे का एक साल बरबाद हो गया। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि निजी विश्वविद्यालय हो या सरकारी विश्वविद्यालय हो, सरकारी विश्वविद्यालय में बच्चे को बहुत सारी सुविधायें मिलती हैं, बहुत सारी स्कीम हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने फ्री शिक्षा और बहुत सारी छात्रवृत्ति की योजनायें हैं, उससे तो अच्छादित होते हैं, पर निजी विश्वविद्यालय में जब फीस देता है, जो हजारों और लाखों की संख्या में होती है। उस बच्चे का माँ बाप उसकी फीस कैसे देता होगा। वह बच्चा चाहे लॉ की डिग्री पढ़ना चाह रहा हो, इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहा हो, डाक्टर बनना चाह रहा हो जहाँ लाख और करोड़ की संख्या में फीस निर्धारित होती है, तो वह गरीब माँ बाप फीस कैसे देता होगा। बहुत से लोग कर्जा ले करके उस फीस को देते हैं, गाँव में किसान जमीन बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसकी फीस जमा करता है। सरकारी विश्वविद्यालय में यह नहीं है। मान्यवर, मेरा आश्य कहने का इतना है कि अगर जिस तरह से सरकारी विद्यालयों का आप कहीं-न-कहीं उनकी ग्रेडिंग करते हैं, नैक की ग्रेडिंग होती है, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय की नैक की ग्रेडिंग हुयी, इसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देती हूँ। सरकार का जिस तरह से सरकारी विश्वविद्यालय पर नियंत्रण है, क्या वही नियंत्रण प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर कर रही है। स्पष्ट बात है कि सरकार का किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर न ही उनके ऊपर कोई ग्रेडिंग करने का अधिकार है और न ही कोई इण्टरवेंशन करने का अधिकार है। वह अनियंत्रित हो करके पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वह बच्चे के भविष्य के बारे में क्या निर्णय लेते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह बच्चे के भविष्य को सकारात्मक या अंधकार में धकेलना चाहते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनायें। आप उनका नियन्त्रण सरकार के पास रखें ताकि वह मनमानी न फीस ले सकें और न नियम बना सकें। वह भी उसी तरह से काम करें क्योंकि उनमें भी वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो सरकारी

विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वही बच्चे तो प्राईवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उन्हीं परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये भेद-भाव क्यों। सरकारी यूनिवर्सिटी पर तो नियन्त्रण है लेकिन प्राईवेट यूनिवर्सिटी में कोई नियन्त्रण नहीं है तो सरकार को सबसे पहले एक प्रभावशाली कमेटी बनानी चाहिए जो इन प्राईवेट कालेजेज पर फीस को लेकर, उनके नियमों को लेकर उनमें हो रही नियुक्ति को लेकर नियन्त्रण के लिए कमेटी बनानी चाहिए। जब प्राईवेट और गवर्नमेण्ट यूनिवर्सिटी में बराबरी होगी तो इसका लाभ सभी को मिल सकेगा, इसलिए मैं इस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मोना जी, आप बहुत विद्वान सदस्य हैं और आपने जितनी भी बातें कही वह बहुत ही पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक बातें कहीं, जिसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर हम प्राईवेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो इण्टरनेशनल लेविल पर चाहे वह हावर्ड हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, वह ज्यादातर प्राईवेट यूनिवर्सिटीज ही हैं। जो अभी आपने बताया कि आपके पास 15-20 इन्स्टीट्यूशन्स हैं तो वह भी तो सारे प्राईवेट हैं। इस प्रकार से कहना कि प्राईवेट यूनिवर्सिटीज के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, यह कहना उचित नहीं होगा। अगर गवर्नमेण्ट की यूनिवर्सिटीज सारे के सारे केटर कर सकती होतीं तो यह पहले से हो चुका होता। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो यहां पर मा0 लालजी वर्मा द्वारा कहा गया कि घर पर बंटवा दिया जाय। मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन पुरःस्थापित होता है, उस दिन आपके घरों में आपके एजेण्डे के साथ गया है, यह बात मैंने जानकारी करके बतायी है। जिस दिन बिल पुरःस्थापित होता है, 6 तारीख को पुरःस्थापित हुआ था और उसी दिन भेजा गया था ताकि आपको अध्ययन का टाइम मिल जाय। आगे से हम यह भी कह देंगे कि जिस दिन पारण के लिए आये उस दिन जाये, लेकिन ऐसा होने पर आप लोग ही कहेंगे कि आज ही मिला तो पढ़ेंगे कैसे। दोनों अलग-अलग विषय होते हैं, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि तत्काल बिल आ जाता है उसके लिए समय हमारे पास नहीं होता है तो उन परिस्थितियों में तो इसको करते हैं और अपरिहार्य करना पड़ता है। लेकिन इस बिल को 6 तारीख को सभी माननीय सदस्यों के पास भेज दिया गया था इसीलिए यह कहना उचित नहीं है कि बिल की कापी नहीं दी गई, बिल की कापी सभी लोगों को दी गई थी। अब मेरा निवेदन है कि जो मथुरा इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय की बात हुई है तो यह वहां पर क्यों जोड़ा जाय और क्यों न जोड़ा जाय, इस पर कोई बात करना चाहता है तो हाउस ओपेन है, खुला भाषण देने के लिए हाउस ओपेन नहीं है।

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, सभी सरकारों ने खोले हैं तो उनमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यह तो बताना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह आप पूछिये, इससे असहमति नहीं है।

श्री कमाल अख्तर-

यह जो इंटरनेशनल स्कूल मथुरा वाला है तो क्या उसमें भी वही होगा जो और निजी विश्वविद्यालयों या निजी मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सरकार प्राईवेट यूनिवर्सिटीज खोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उस पर कहीं न कहीं सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

है, वह मा0 मंत्री जी बतायेंगे।

श्री कमाल अख्तर-

वह मनमानी फीस लेते हैं और कहते हैं कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बस को आपको लेना पड़ेगा, हॉस्टल को आपको लेना पड़ेगा, मेरा कहना है कि ऐसा करके क्या हम शिक्षा का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालय खोलेंगे उतना ही ज्यादा फायदा जनता को होगा।

श्री अध्यक्ष-

जब बिल आया था तो उस पर आपने यह बात बोली थी।

***श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, जो बातें बोली है क्योंकि निजी विश्वविद्यालय का जिक है। शिक्षा और स्वास्थ्य हर घर से जुड़ा विषय है क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा भी चाहता है और स्वास्थ्य भी। तो इसमें जब निजीकरण के शब्द का इस्तेमाल होता है, तो हार्वर्ड का जिक्र किया, आप और भी यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, तो उनमें और यहां का जो काम करने का तरीका है, इनके और उनके काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। महोदय आपके माध्यम से हम सब इतना निवेदन करना चाहते हैं कि जो निजी विश्वविद्यालय बन रहे हैं उसे सरकार अपने नियंत्रण में रखे और कैसे रख सकती है सरकार, विश्वविद्यालयों में गवर्नमेंट से आपके वित्त नियंत्रक और रजिस्ट्रार नियुक्त होते हैं, कोई भी सरकार की बात होगी, या जो भी विषय होगा, या सरकार की जो भी आज्ञा होगी तो उस रूल को लागू कराने के लिए वहां पर रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक होते हैं। लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाईए, जितने भी पॉलीटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं आप किसी भी विश्वविद्यालय में सिफारिश करते होंगे जैसे किसी की अटेंडेंस शार्ट रह गयी या कोई एक या दो दिन नहीं जा पाया या कोई बीमार पड़ गया या कोई अन्य कारण है तो वहां पर किसी का कोई नियंत्रण थोड़े ही है। अगर जिले के कलेक्टर महोदय भी यह कहें किसी निजी विश्वविद्यालय के व्यक्ति को कि यह चीज आप गलत कर रहे हैं, तो वह कहेंगे कि इस चीज को आप सरकार को बताइए, तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम जब शिक्षा के स्तर पर बात करते हैं, तो आपने कहा कि 27 विश्वविद्यालय पूर्व में बने हैं और 28 वां विश्वविद्यालय मथुरा में बनने जा रहा है। क्योंकि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मेरठ में महोदय आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय है और अभी वर्तमान में एक विश्वविद्यालय बना है, सुभारती विश्वविद्यालय है आप महोदय किसी भी विश्वविद्यालय के बारे में पता कर लीजिए, मा0 मंत्री जी मेरठ में भी गए थे हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, हमने वहां के वाइस चांसलर से पूछा कि जो यहां पर नियुक्ति होनी है, जो यहां पर पद रिक्त पड़े हैं, इन पर आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? वह बोले की हमने शासन को मांग भेज रखी है, पर अभी शासन से परमिशन नहीं दी जा रही है, वह नहीं कर सकते। यहां तक कि जो फीस लेकर बच्चों से जैसे हमारे यहां मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी है, उस कृषि यूनिवर्सिटी में सरकार मात्र 70 लाख रुपये मुहैय्या कराती है, वहां के बच्चों से एक्सट्रा फीस वसूल कर, उस यूनिवर्सिटी का खर्च चलाया जा रहा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पता कीजिए, मा0 मुख्य मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों राजकीय कालेज और राजकीय महिला कालेज खोले जा रहे हैं। हमारे मेरठ क्षेत्र में इस समय 10-15 ऐसे कालेज हैं, जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आप कराने जा रहे हैं। 5-5, 7-7 साल से उनकी बिल्डिंग बनी खड़ी है, लेकिन वहां पर आपका स्टाफ नहीं पहुंच रहा है और एक तरफ वहां पर आप निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। निजी विश्वविद्यालयों में जिस तरह बी0सी0ए0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, एम0 टेक, बी0टेक0 इस तरह के कोर्स चलते हैं लेकिन उनकी फीस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पर शिक्षा की क्या गुणवत्ता होगी, किस तरह के टीचर वहां पर रखे जाएंगे इसका कोई मानक आपके पास नहीं है और जितना आप शिक्षा और स्वाथ्य को नीचे की तरफ धकेलते जाएंगे, उतने ही गरीब, किसान, मजदूर, शोषित वंचितों का हक मारा जाता रहेगा। आज तक करीबन 50 से 60 प्रतिशत जहां नए नौजवानों की भीड़ है, लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों की तरफ जाते हैं तो वह यह भी दिमाग में रखते हैं कि किस तरह से वहां पर हमें शिक्षा सस्ती मिल जाए। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि निजी विश्वविद्यालय को यह प्रवर समिति को भेजिए हालांकि हम तो यह चाहते हैं कि यह बने ही ना लेकिन अगर बने तो सरकारी बने और अगर फिर भी आपकी हठधर्मी है और बनाना ही चाहते हैं तो सरकार की तरफ से वहां पर रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक नियुक्त हों, जिससे अनाप-सनाप तरीके से वहां पर काम न हो काम सरकारी नियंत्रण में हो। आप किसी भी विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप का पता कर लीजिए, स्कॉलरशिप के हिसाब से लोगों को, बच्चों को रखा जा रहा है, वहां पर पढ़ाई होती नहीं सिर्फ नाम इनरोल हो जाता है, नाम का दाखिला हो जाता है और स्कॉलरशिप सरकार से उठा ली जाती है। अगर यह स्कॉलरशिप न आए तो यह निजी वश्वविद्यालय चल नहीं पाएंगे। आप यह पता कर लीजिए, यह चीज मैं अपने मेरठ की बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद अतुल जी।

हम सबको मालूम है कि जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, ये भी ऑटोनॉमस बॉडी होते हैं, उसका एक बोर्ड होता है, वह उसको तय करता है। सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे मा0 सदस्य जो नये आये हैं, उनको इस बात की जानकारी हो। मैं जो चाहता हूँ कि विधान सभा को उस लेवल के ऊपर ले जाऊँ, जहाँ ये सारी चर्चा हो, तो उसके निमित्त मैं ये सारी की सारी बातें बोल रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपके सामने ये जो टैबलेट लगा हुआ है, इसमें जैसा बोला है कि 6 फरवरी, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, तो 18वीं विधान सभा में सबसे ऊपर जाएंगे, तो उसमें प्रथम सत्र 2024 में आज की तारीख लिखी हुई है। आप उस डेट को दबाएंगे, तो उसमें 6 फरवरी, 2024 दिखेगी, उसमें यह बिल आया होगा। वह आप सबके डिवाइस पर उपलब्ध है।

मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय मैं यह कह रहा हूँ कि हम पेपरलेस हैं, तो उस समय सारी की सारी चीजें इसमें हैं। जो भी मा0 सदस्य आज यहाँ पर बैठे हैं, अगर वह उसको देखना चाहते हैं, जिस डेट में आया था, उस डेट को आप दबाएंगे, तो उस डेट में पूरा एजेण्डा आ जायेगा और जो बिल पुरः स्थापित हुआ था, वह आ जायेगा। हम सब लोग अपने आपको अपडेटेड करें, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। क्योंकि धीरे-धीरे मैं इस बात के लिए प्रयास करूंगा कि जिसको हमने पेपरलेस कहा है, धीरे-धीरे इस हाइब्रिड सिस्टम को विद्ड्रॉ करेंगे, धीरे-धीरे हम कागजों को विद्ड्रॉ करेंगे। विद्ड्रॉ करने के पहले ये सारी बातें यहाँ पर आनी आवश्यक है, इस निमित्त मैं इन सब बातों को आपको बता रहा हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य श्री समरपाल सिंह जी की बात को आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य समरपाल जी, इसी के ऊपर आप बोलिए, चूँकि इतना डिबेट हुआ है, इसलिए इसी विषय के ऊपर बोलिए।

श्री समरपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपको और मा0 खन्ना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे मण्डल में विश्वविद्यालय इन्होंने बनवाया, लेकिन अभी वैसे ही है। आप जो बता रहे थे, वहाँ पूरा का पूरा विश्वविद्यालय चल सकता है। एम0बी0ए0 का ऑफिस नये ऑफिस में शिफ्ट हो गया।

श्री अध्यक्ष-

आप बिल के ऊपर बोलिए। विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। वह इसका विषय नहीं है। इसके लिए अनुमति नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 संक्षिप्त नाम और कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची-2 में क्रम-संख्या-37 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम संख्या 37 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम-संख्या बढ़ा दी जायेगी :-

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
38	एस0 के0 एस0 इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश	बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, एस0के0एस0 इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या सन् 2003

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[01:45] लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन में वृद्धि के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य रविदास मेहरोत्रा जी, आप व्यवस्था पर क्या बताना चाह रहे थे?

***श्री रविदास मेहरोत्रा-**

मा0 अध्यक्ष जी। मैं लोकतंत्र सेनानी हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रु0 20000/-

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। लोकतंत्र सेनानी को पेंशन दी है या नहीं, कितनी दी है, इससे व्यवस्था का क्या मतलब है?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, हमारी सुन लीजिए। हम 02 मिनट में अपनी बात कह देंगे। विधान परिषद् के सभापति श्री मानवेन्द्र सिंह जी ने सरकार को ये निर्देश दिया है।

श्री अध्यक्ष-

वह विधान परिषद् के सभापति हैं, उनको पूरा अधिकार है। वह स्वयं कांस्टीट्यूशन अथॉरिटी हैं, वह कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वर्ष 2024 के आय-व्यय पर चर्चा। मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, इनकी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, तो सुनने की बात कहाँ है ?

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, ये लोकतंत्र सेनानी है। आप पीठ से कह दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पीठ से क्या कह दें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को क्या मिल रहा है? मा0 श्री ओम प्रकाश जी, आप यहाँ अधिष्ठाता के रूप में क्या बताएंगे? व्यवस्था में प्रश्न उठाने की बात कर रहे हैं और लोकतंत्र सेनानियों के बारे में बोल रहे हैं, तो आप क्या व्यवस्था देंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, उनको तो आप जानते ही हैं। मा0 श्री सुधाकर सिंह जी हैं। ये सबसे कम उम्र में लोकतंत्र सेनानी बने थे, जब ये 18 वर्ष के भी नहीं थे, तब स्वतंत्रता सेनानी बने थे।

श्री अध्यक्ष-

तो यह व्यवस्था में कहां आता है? ये तो अव्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, ये अव्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ये पहलवान लोग हैं, कृपया इनकी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री सुधाकर जी।

श्री सुधाकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, लोकतंत्र सेनानियों को वर्ष 2017 से रु0 20000/-सम्मान राशि दी जा रही है। वर्ष 2017 से 2024 आ गया, लेकिन 7 साल में उनकी सम्मान राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की राशि में वृद्धि हुई है या नहीं, यह हमारा विषय नहीं है, सरकार का विषय है।

(श्री रविदास मेहरोत्रा के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

मा0 मेहरोत्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको लोक सभा का टिकट मिल गया है। मैं अगर माईक बन्द करने के लिए बोलूँगा, तो कितना खराब मैसेज आपके क्षेत्र में जायेगा। आप बैठिए। मा0 सुधाकर जी, आप व्यवस्था बताइए।

श्री सुधाकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन के अन्दर में केवल 5 लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस समय विधान सभा की कार्यवाही में कहां व्यवस्था व्यवधानित हो रही है?

श्री सुधाकर सिंह-

मान्यवर, आप सुन लें। आप भी उसके अंग है। हमारा जो बजट पेश हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

अभी जब बजट पर चर्चा कराएंगे, तो आप बोलिएगा।

श्री सुधाकर सिंह-

मान्यवर, निवेदन है कि जो विधान परिषद् के मा0 सभापति ने व्यवस्था दिया है, उच्च सदन ने व्यवस्था दिया है।

बजट चर्चा पर मा0 सदस्यों/मा0 मंत्रिगण हेतु समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

अब हम बजट के ऊपर चर्चा प्रारम्भ करते हैं। मद संख्या-141 कल बजट के ऊपर चर्चा जिस समय प्रारम्भ की थी, तो श्री ओम प्रकाश जी खड़े हुए थे, तो अध्यक्ष पीठ के द्वारा निर्देश दिया गया था कि चर्चा जारी रहेगी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि प्रायः इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि सदस्यों को पार्टी की रेशियो के हिसाब से समय दिया जाता है, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा पूरा समय दिया गया। कल 103 सदस्यों ने जिस समय बोला, तो उसमें लगभग 47-48 सदस्य हमारे विपक्ष से भी बोले थे। जो 2:1 के रेशियों का सिस्टम था, उसके हिसाब से भी 1:3 होना चाहिए, लेकिन लगभग बराबर थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं सबको बराबर का अवसर देता हूँ। हम 7 मिनट बोलने के लिए निर्धारित करते हैं। सभी मा0 सदस्य 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। अगर मैं अध्यक्ष पीठ पर नहीं हूँगा, तो जो अधिष्ठाता यहाँ पर बैठेंगे, तो 7 मिनट बाद या तो उनको रोक देंगे या उनका माईक बंद करा के दूसरे को बुलवा देंगे, ताकि अधिक से अधिक मा0 सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो पहले बोलना शुरू करे, उसको थोड़ा ज्यादा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

जो पहले बोलना शुरू करेंगे, उनको हम 10 मिनट का समय देते हैं। मा0 वर्मा जी की बात को हम काट नहीं सकते हैं। वर्मा जी, आपकी अनुपस्थिति में हमने बिल वाली बात बता दिया था कि आप में बिल आया कि नहीं। आप सदन में तत्समय नहीं थे। उसको मैंने डिटेल में बता दिया है, आप पूछ लीजिएगा। जो कापी की बात थी, वह पूरी बात बता दी थी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोग उतने टेक्निकल नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तो सीखिए ना। बाकी हर मामले में आप टेक्निकल हैं। टेक्निकल्टी के नाते अगर पूछा जाए, तो पूरा हाउस ये कहेगा कि श्री लालजी वर्मा जी हर मामले में टेक्निकल है (सदन में

हँसी)। जहाँ पर टेक्निकल होने की जरूरत है, वहाँ पर नहीं हैं, बाकी सभी मामलों में टेक्निकल हैं।

श्री ओम प्रकाश-

अध्यक्ष जी, आप भी कम टेक्निकल नहीं है। कल आपका टेक्निक हम देखे, इसलिए हमको लगा कि लालजी वर्मा के उस्ताद आप ही हैं।

आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री नितिन अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर कोई मा0 मंत्रीगण बजट पर बोलना चाहते हैं, तो उनको भी 10 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगर कोई मा0 मंत्रीगण बजट पर बोलेंगे, तो उनको भी 10 मिनट का समय दिया जायेगा।

***श्री इकबाल महमूद-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई नाम आपके पास तक न पहुंचा हो तो आपके अन्दर स्वयं इतनी शक्तियां है कि आप स्वयं ही उसको बुला लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि यह अधिकार अध्यक्ष पीठ को प्राप्त है। वह किसी को भी बुला लें, लेकिन उसमें जो एक व्यवस्था चली आ रही है कि हमारे सारे माननीय मुख्य सचेतक अपने विधायकों की एक सूची देते हैं, उस सूची और क्रम के हिसाब से बुलाना व्यवस्थित रहेगा।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप अपनी तरफ से मेरा नाम ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हां, यह हो सकता है।

[01:50] वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

***श्री ओम प्रकाश-**

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल भी आपने मौका दिया, लेकिन कल माहौल इस तरह का नहीं था। कल मा0 नेता सदन एवं मा0 नेता विरोधी दल को बोलना था। मैं 2024-25 के बजट की कटौती पर अपनी बात रखता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी पूरे सदन और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बजट नाम का नहीं काम का होना चाहिए। यह बजट केवल नाम का बजट है और इस बजट की किताब में काम की बात नहीं है तो इस बजट का इसका कोई मतलब नहीं है। यह बजट कहीं न कहीं निराशाजनक, उदासीन और किसी मतलब का नहीं रह जाता है। यह उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का दिल है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान की राजनीति की दिशा तय करता है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा यह निवेदन है कि कोई भी सदस्य जिसका नाम सूची में है या नहीं है, वह अध्यक्ष पीठ पर आकर नहीं पूछेगा। अपने-अपने मुख्य सचेतक से पूछें कि उसका नाम कहां पर है। अध्यक्ष पीठ पर आकर लोगों ने नाम पूछना शुरू कर दिया तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं, इसीलिए वह अपने मुख्य सचेतक से ही पूछ लें।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट नाम का नहीं काम का होना चाहिए। अभी लास्ट फरवरी, मार्च चल रहा है, उस बजट को देखने के बाद जो आय-व्यय में खर्च हुआ है, वह बहुत निराशाजनक, उदासीन है। मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ का बजट है। यह सही है कि जब भी बजट रखा गया है वह बजट हमेशा पिछले बजट से बढ़कर होता है, लेकिन यह सरकार का एक जुमला है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मा0 वित्त मंत्री जी आपके बाद भी....

(इसी मध्य 01 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

जो बजट रखेगा वह कहीं न कहीं आपसे अधिक बढ़ाकर ही रखेगा। यह एक व्यवस्था का अंग है, लेकिन मैं एक सुझाव के रूप में आपसे कहूंगा कि आपने जो बजट रखा है उसको देख लें और जो पिछला बजट 2023-24 का है उसमें भी आप देखेंगे। उस बजट को देखने के बाद यह लगेगा कि हमने जो बजट पेश किया था, उसमें कितना खर्च हुआ है। हम स्वास्थ्य विभाग को ही ले लें। मैं पूर्वांचल से आता हूँ। जहां गरीब इलाके के लोग रहते हैं, जहां जनसंख्या बहुत अधिक है। जहां सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व व दबाव है। मैं बनारस से पढ़ा-लिखा हूं, जानता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की रोज नियुक्ति हो रही है और जितनी नियुक्ति की बात नहीं हो रही है, उससे अधिक लोग सरकारी अस्पताल छोड़कर जाने का काम कर रहे हैं। कल मैंने जब बजट पढ़ा तो पता चला कि अयोध्या और बनारस में 2 मेडिकल कालेज की स्थापना कर रहे हैं। बार-बार मा0 नेता सदन भी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हम

भी मान लेते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यह तो तय होना चाहिए कि यह इंजन कौन सा चल रहा है, ऊपर वाला चल रहा है, नीचे वाला चल रहा है या दोनों नहीं चल रहे हैं। इंजन बेशक है, लेकिन चल कौन सा रहा है? यदि अयोध्या में बहुत धूमधाम से सब काम हो रहा है तो कहीं न कहीं पूर्वांचल में एम्स की कमी है।

मान्यवर, एम्स की कैटेगरी का बनारस जहां से देश के प्रधान मंत्री का चयन होता है और अयोध्या जहां पूरे बजट में टोटल अयोध्या का ही गुणगान हुआ है। अयोध्या में क्यों नहीं एम्स बन सकता है। जब आप श्री राम जी को बैठाने की बात कर सकते हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अयोध्या में एम्स की स्थापना क्यों नही हो सकती है। जब हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं तो क्या यह ऊपर वाला इंजन फेल है। मेडिकल कालेज की जो स्थापना हो रही है उस स्थापना को देख लीजिए और मैं यह कह सकता हूँ कि मेडिकल विभाग का यह हालत है अभी आप बजट देख लीजिए मा0 वित्त मंत्री जी तिरसठ प्रतिशत, अड़तालीस प्रतिशत अभी तक फरवरी में खर्च और मैं यह कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में सूरदास आँख का ऑपरेशन कर रहे हैं फूटना तय है और अगर बच जायें तो दिल्ली वाले या लखनऊ वाले की मेहरबानी है। बिहार बॉर्डर से सटा हुआ मेरा क्षेत्र है। कम से कम सात-आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और पांच पर डॉक्टर नहीं है। फार्मसिस्ट चला रहा है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री जी से बात होगी तो पूछा जाएगा कुछ तो बोलेंगे कुछ। उनको समझ में ही नहीं आता है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं कि साहित्यिक मंत्री है। उस पर वित्त मंत्री जी भी मजे लेते हैं। आप बजट तो पेश कर देते हैं लेकिन मैंने पढ़ा कि मा0 वित्त मंत्री जी 24 जून 2014 को मैंने बजट पढ़ा और मैंने महसूस किया कि जब आदमी इधर रहता है तो कितना अच्छा बोलता है और वहां जाने के बाद कैसे बदल जाता है। मैंने देखा कि मौसम भी बदलने में समय लगाता है और एक इंसान इतना तेज बदलता है। मैंने पढ़ा मा0 वित्त मंत्री जी जब यहां बैठते थे तो इतना सुंदर बोलते थे कि लगता था कि अगर वित्त मंत्री जी के हाथ में आएगा तो सब कुछ राम राज्य हो जाएगा। लेकिन जब देखने के बाद बजट आपने कहा आप पी0डब्लू0डी0 के बारे में पता कर लीजिए, सात साल से खाली गड्ढा मुक्त हो रहा है जो पिछली सरकार में बनाने की बात की है उससे पहले भी तो सरकार बनाई है उसमें कौन गड्ढा आप कह रहे हैं कि पी0डब्लू0डी0 में राज्य मंत्री जी बैठे है। भाई हो छोटे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। विधायक हैं सब विधायक हैं चाहे इधर का विधायक हो या चाहे उधर का विधायक हो। यह आपके भी मंत्री हैं और मेरे भी मंत्री है। यह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं हम लोग भी दो साल से देख रहे हैं दो महीना कम है आप बता दो इधर एक भी कोई विधायक बता दे कि नयी कोई स्वीकृति कार्य योजना के बाद भी कोई स्वीकृति हुई तो बता दो।

***वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो काम की बात करना हो वह बता दीजिए हम सुनकर चले जायें। आपके तीन मिनट रह गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं मा0 मंत्री जी की चिन्ता से अपने को सम्बद्ध करता हूँ तीन ही मिनट हैं आप अपनी बात कह दीजिए। देखिए पीठ का निर्देश है।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, मैं काम की बात ही कर रहा हूँ मैं यह बातें कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य का और पी0डब्लू0डी0 का। आप सिंचाई विभाग देख लीजिए। सिंचाई विभाग में निर्माण कार्य में अड़तीस प्रतिशत खर्च हुआ। मैं यह बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की यह किताब है यह तय करती है कि सरकार की क्या मंशा है, क्या मकसद है। कार्य क्या करना चाह रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय पी0डब्लू0डी0 से आप भी जुड़े रहे हैं। अब त्वरित में 24 सौ करोड़ रुपया है। एक भी कोई विधायक इधर का बता दें, उधर की भी बात कर रहे हैं ऐसा नही है कि हम उधर की बात नहीं करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया कर के एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, कई बार ऊपर से व्यवधान हुआ है अगर दस मिनट कहा गया है तो दस मिनट होने तो दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 ओम प्रकाश जी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार की हालत डायनासोर की तरह है। डायनासोर एक जानवर था जो बहुत मजबूत था। वह जिस इलाके में जाता था वह पूरा इलाका साफ हो जाता था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि डायनासोर ही खत्म हो गये। इस सरकार की भी हालत यही है। यह अपने को डायनासोर मान रही है। इनके पास इतनी ताकत है, लेकिन इनको यह आभास ही नहीं है कि सरकार की उम्र पाँच साल की होती है। मैं भी 35 साल से देख रहा हूँ, पता नहीं कितने मुख्य मंत्री आये, आते-जाते भी देखा है, शक्ल-सूरत भी देखी है, बनते और बिगड़ते भी देखा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सरकार यह नहीं तय करती है कि लाल है कि पीला है कि हरा है। सरकार महसूस कराती है कि सरकार जनता की है और मैं जनता का हूँ, लेकिन यह सरकार कहीं से भी महसूस नहीं करा रही है।

कल ऊर्जा मंत्री कह रहे थे कि राम जी आयेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि राम जी नहीं आयेंगे। उन्होंने कहा कि सब पाप धुल जायेंगे। हमने कहा कि 7 साल वाला पाप धुलेगा कि 10 साल वाला धुलेगा। राम जी के आने के बाद आपका कौन-सा पाप धुल रहा है? आप बता नहीं रहे है। मान्यवर, यहाँ पर वित्त मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आप मुझे थोड़ा संरक्षण दीजिये। मा0 वित्त मंत्री जी चले गये। पर्यावरण के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया तथा भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यावरण को लेकर चिन्तित है, लेकिन पर्यावरण विभाग में फरवरी तक मात्र 14 परसेंट पैसा खर्च हुआ है और मात्र डेढ़ महीना बचा है और डेढ़ महीना बाद वह पैसा भी खत्म हो जायेगा। इसलिये मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद, बड़े मंथन-चिन्तन के बाद इस बजट का प्रावधान किया गया होगा, लेकिन अभी मा0 वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि पिछली सरकार में पर कैपिटा इनकम 52 हजार थी और हमारी सरकार में 83 हजार हो गयी, जिस पर अभी हमारी मा0 विधायिका जी कह रही थीं कि आप पिछली सरकार से तुलना क्यों कर रहे हैं, दुनिया में तरक्की के जो रास्ते तय हो रहे हैं, तो आप बताईये कि दुनिया में क्या है और हमारे यहाँ क्या है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आपकी बात आ गयी है, धन्यवाद। मा0 पंकज सिंह जी।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा। अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं किसानों, किसानी और गाँव से जुड़ा रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 ओम प्रकाश जी, मेरा आपसे आग्रह है कि सभी मा0 सदस्यों को बोलना है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं तो मैं उसी भाव से कह रहा हूँ कि आप अब कृपया समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाये। यह केवल मुँह से कहने से नहीं होगा, इसके लिये कोई न कोई कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। मैं एक बार फिर से सभी मा0 सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि अभी मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी ने हम सबके सामने हम सबके लिये ही एक व्यवस्था दी है तो आप सभी उसका पालन करने की कृपा करें। मा0 पंकज सिंह जी।

***श्री पंकज सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष के मा0 वक्ता को बोलने के लिये 10 मिनट का समय मिला था तो क्या मुझे भी 10 मिनट मिलेंगे अथवा 7 मिनट ही मिलेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पंकज सिंह जी, आप बोलना प्रारम्भ करें।

श्री पंकज सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो 2024-25 का जो बजट हमारे मा0 वित्त मंत्री जी और सरकार ने पेश किया है, इस ऐतिहासिक बजट के लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और मा0 वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह बजट सही मायने में विकास और विरासत दोनों की बात करता हुआ बजट है और सच में यह अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक बजट है। ऐतिहासिक इसलिये कि अयोध्या में भगवान श्रीरामचन्द्र जी की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद, उनके विराजमान होने के बाद उसी उत्तर प्रदेश में पेश किया गया यह पहला बजट है।

मान्यवर, और दूसरा इसलिए क्योंकि यह बजट अपने आप में 7 लाख करोड़ से भी बड़े आकार का है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा रखा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि यह बजट अपने आप में ऐतिहासिक है और हम सब सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब लोग साक्षी बन पा रहे हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजी में एक यूटोपिया शब्द है और इसके बारे में कहा जाता है कि यूटोपिया अपने आप में एक ऐसी स्थिति है, अपने आप में एक ऐसा संसार है जो अपेक्षित तो है, जो होना तो चाहिए लेकिन पश्चिमी देशों में यह कहते है कि ऐसा संसार सिर्फ कल्पना में हो सकता है, स्वप्न में हो सकता है लेकिन सच्चाई में या धरातल पर यह उपस्थित नहीं है। लेकिन हमारी परम्परा में, हमारी देश की संस्कृति में, स्वप्न में या सिर्फ ऐसे ही हवा में यह बाते नहीं कही गयी हैं, यह यूटोपिया वाली स्थिति वर्षों पुरानी है और रामराज्य के रूप में वह स्थिति हमारी संस्कृति में, हमारे देश में विराजमान रही है। जहां पर आर्थिक सम्पन्नता भी थी, आदर्श भी था, न्याय भी था। कहीं भी किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं था। इस प्रकार यह पहले से हमारे यहां विराजमान था। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह आस्था, अन्त्योदय और एक मजबूत अर्थव्यवस्था को समर्पित करने वाला, उस पर केन्द्रित बजट है और भगवान श्रीराम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चन्द्र जी को समर्पित लोक मंगल का यह बजट है, जो सही मायने में इस प्रदेश के सभी वर्गों को छूता है और सबके साथ न्याय करता है। इस बजट में हर चीज का ध्यान रखा गया है। प्रदेश का कोई भी कोना, कोई भी वर्ग इस बजट से छूटा नहीं है। इस बजट की यही खासियत है। जैसा विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि यह बजट सही मायने में सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है। यह बजट आकार में कितना बड़ा है यह बात सही है कि सिर्फ यही बजट की खूबी नहीं हो सकती है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस बजट की भी मात्र यही खूबी नहीं है कि यह आकार में बड़ा है बल्कि सच में इस बजट की खूबी यह है कि यह बजट, जैसा हमारे दीन दयाल जी ने कहा कि हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था का केन्द्र मानव होना चाहिए, ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ हैं वहां जब तक आशा और पुरूषार्थ का संदेश हम सब लोग न पहुँचा दें तब तक राष्ट्र के चौतन्य को जागृत नहीं कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा का केन्द्र आराध्य और उपास्य, हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण और उपलब्धियों का मापदण्ड वह मानव होना चाहिए जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्राही है। ऐसा दीनदयाल जी ने कहा था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बजट में सही मायने में मानव को केन्द्र में रखकर और गांव, गरीब, किसानों पर ध्यान रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। सबके साथ न्याय करने वाला यह बजट आदरणीय वित्त मंत्री जी ने रखा है।

जब 2017-18 में यह बजट रखा गया था तो मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उस बजट को हम लोगों ने अन्नदाता को समर्पित किया था और यह बजट जो कि 2024-25 का रखा गया है इसे हम लोग दाता और विधाता, हमारे भगवान श्रीराम चन्द्र जी को समर्पित किया गया है। इस प्रकार बजट को अन्नदाता से लेकर विधाता तक समर्पित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामराज्य के आदर्शो पर आधारित हमारा यह बजट हर वर्ग के कल्याण की बात रखता है। मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा बतायी गयीं हमारी 4 जातियाँ जो महिला, युवा, गरीब और किसान के उत्थान की नींव है उनके लिए यह बजट रखा गया है। मैं कल देख रहा था और आज भी कुछ सदस्यों को सुन हरा था, यह हमेशा पी0डी0ए0 की चिन्ता करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया, यह बताया कि हमारी सोच में ही यह चीज है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अछूता न रहे। सबके साथ न्याय हो यह चिन्ता रहती है। लेकिन विपक्ष की चिन्ता यह नहीं रहती है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े। खासतौर से समाजवादी पार्टी की बल्कि उनकी चिन्ता बार-बार वोट बैंक को कंट्रोल में रखने की होती है और सिर्फ वोट बैंक का ही संदेश देने की कोशिश की जाती है।

मैं मानता हूँ कि यह बजट, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर इकॉनामी बनाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका संकल्प है 5 ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर इकॉनामी का, उसको हासिल करने में निश्चित रूप से सबसे अग्रणी भूमिका

अगर किसी भी राज्य की होगी तो हमारे उत्तर प्रदेश की होगी। चूंकि समय कम है मैं अपने आपको संक्षेप में कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन पर भी बहुत जोर दिया गया है। सच में इसमें अपार सम्भावनायें हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब यह चीजें उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हुईं हैं अपने सनातन धर्म की स्थापना के लिए, सांस्कृतिक और आध्यत्मिक प्रतीक चिह्नों को स्थापित एवं उसको संरक्षित रखने की जब से कोशिश प्रारम्भ हुई है तब से ही यह उत्तर प्रदेश जो भगवान श्री राम की धरती भगवान श्री कृष्ण की धरती है। अगर 2022 में पर्यटकों की संख्या देखें तो लगभग 22 करोड़ की थी 2023 में 37 करोड़ और 2024 में यह अनुमान है कि 50 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक इस उत्तर प्रदेश में आयेंगे। स्वाभाविक रूप से उसका असर हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा, रोजगार सृजन होंगे। यह स्वाभाविक रूप से होगा। जब चुनाव आते हैं तो सरकारें खास तौर पर लोक-लुभावन बजट पेश किया करती हैं। लेकिन इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ कि नई योजनाओं के लिए लगभग 25 हजार करोड़ तो दिया ही है। साथ-साथ में जो जारी योजनायें हैं जो योजनायें चल रहीं हैं उसके लिए लगभग 90 प्रतिशत का बजट उस पर ही केन्द्रित किया है। सही मायने मे इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस साहस के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस ईमानदार प्रयास के लिए अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बजट में ऐरो सिटी से लेकर एयर पोर्ट तक की व्यवस्था है। सड़कों तक के लिए फण्ड दिया गया है। खास बात यह है कि यहां पर सामाजिक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए ऐसा माहौल बनाने के लिए भी फण्ड की व्यवस्था की गयी है। मैंने कहा कि अपने यहां पर विरासत को कैसे बचाना है, बढ़ाना है इसकी चिन्ता भी की गयी है। बहुत सारे विषय है मैं उन सब पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बहुत पहले 2016-17 की जी0डी0पी0 देखें तो 12.50 लाख करोड़ थी आज 25 लाख करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय लगभग दो गुनी हो गयी है। कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। और मैं मानता हूँ कि यह 5.1 का जो लक्ष्य है यह पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश और देश का विकास करना है तो जब तक हम गांव-गलियारों को नहीं जोड़ेगे तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। अन्त में चूंकि समय हो गया है। मैं बस समाप्त करूंगा। मैं लगातार देखता हूँ कि भगवान श्रीरामचन्द्र जी के अस्तित्व पर भी विपक्ष प्रश्न चिह्न खड़ा करता है। अभी भी जब संकल्प रखा गया, प्रस्ताव रखा गया तो उस पर भी कई लोगों ने विपक्ष से उसके लिए हाथ उठाया। मैं एक बात विपक्ष से कहना चाहता हूं, सलाह भी देना चाहता हूँ और आगाह भी करना चाहता हूँ क्योंकि यह कहा गया है कि 'धर्म एवं हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोवधीत।' मारा गया धर्म ही अपने मारने वालों को मार देता है, समाप्त कर देता है। जब धर्म की रक्षा की जाती है तो वही धर्म अपने रक्षकों की रक्षा भी करता है। इसीलिए धर्म पर, अच्छे कर्म पर प्रश्न चिह्न मत लगाइये। वर्ना किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा और विपक्ष

हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

आबकारी व मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2024-2025 का जो बजट प्रस्तुत किया उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 736000 करोड़ रुपये के इस विशाल बजट को उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित किया है और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है और संकल्पित है उसमें यह बजट एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा। अधिष्ठाता महोदय, सरकारें विपक्ष की भी रहीं और हमारी भी सरकारें चल रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई भी सरकार जब आती है तो प्रदेश में विकास न हो यह सोचकर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। जो भी सरकार बैठती है वह यह सोचकर काम करती है कि प्रदेश में विकास हो, लेकिन सरकार की मंशा क्या है और सरकार कितनी गति से उस विकास को प्रदेश में लागू कर रही है यह देखने वाली बात होती है। आज मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से लगभग 07 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रही है। हमारी सरकार ने जितनी तेजी से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है और जो अन्तिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके पालन-पोषण के लिए और उसे समृद्ध बनाने के लिए जो योजनायें चलाई हैं, मैं समझता हूँ कि इतिहास में कभी भी उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी के साथ विकास का काम नहीं हुआ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं इसलिये देना चाहता हूँ कि आज देश की जी0डी0पी0 में उत्तर प्रदेश का अगर मैं हिस्सा बोलूँ तो वह करीब 9.2 परसेण्ट है जो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नम्बर पर है।

आज हम पूरे देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। यह आदरणीय योगी जी की प्रतिबद्धता है और यह हमारी सरकार के कार्यक्रमों के कारण है। आज मैं अगर ग्रास सोशल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में यह करीब 2499000 करोड़ की है जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 5.8 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ बढ़ी है। हमारी इकोनामी में तीन मेन सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर है, मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। अगर मैं तीनों सेक्टर्स की बात करूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 10 प्रतिशत की ग्रोथ लेकर आगे बढ़े हैं, अगर मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो हम पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत की ग्रोथ लेकर आगे बढ़े हैं और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो हम 12 प्रतिशत की ग्रोथ लेकर आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि हम आज रेवन्यू सरप्लस स्टेट हैं। हम बहुत वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू में डेफिसिट रहता है। हम लगातार केन्द्र के सामने हाथ फैलाते हैं कि हमें योजनाओं के लिए पैसा दे दीजिये, हमें पैसे की कमी है, लेकिन आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में चल रही

सरकार में उत्तर प्रदेश पूरे देश में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनकर आगे बढ़ा है जिससे हमारे पास अपनी इकोनामी और योजनाओं को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि इकोनामी में दो तरीके के मेन एक्सपेंडिचर होते हैं एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम लोग सेलरी, पेंशन, ब्याज सब्सिडी, ग्राण्ट देते हैं। पिछले साल के मुकाबले हमने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को 17 प्रतिशत बढ़ाया है। पिछले साल जो इसमें बजट प्राविधान था वह 454771 करोड़ रुपये का था और इस साल के बजट में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 532655 करोड़ रुपये रखा है। विपक्ष कहता है कि आपका बजट डेफिसेट का बजट है, मेरी व्यक्तिगत सोच है जो अगर बजट डेफिसिट होता है तो उसका मतलब होता है कि प्रदेश तरक्की कर रहा है क्योंकि हम इकोनामी में ज्यादा पैसा लगाते हैं और हम अपने कैपिटल एसेट्स को ज्यादा डेवलप करते हैं। कैपिलेट एसेट्स को डेवलप करने के लिए हम रोड बनायेंगे, ब्रिज बनायेंगे और तमाम सारे डेवलपमेण्ट करेंगे। वर्ष 2023-24 में सरकार ने इस मद में 146177 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया था लेकिन इस बजट में हमने इसमें 154747 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है जो पिछले साल की तुलना में 6 परसेण्ट अधिक है।

मान्यवर, मैं आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी की बात सुन रहा था। वह बार-बार एक ही चीज कहते हैं और विपक्ष के कई भाषणों में कहा गया कि सरकार बजट नहीं खर्च कर पा रही है। अगर आप बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना बड़ा बजट क्यों ला रहे हैं। आपके विभागों में तमाम बजट पेंडिंग पड़ा हुआ है और खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो क्या जरूरत है। आज मैं उनको यह भी आईना दिखाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आंकड़े लायें हैं। मैं उत्तर प्रदेश ट्रेजरी का आंकड़ा लाया हूँ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो यह बार-बार आरोप लगाते हैं कि बजट नहीं खर्च पा रहे हैं तो इतना बड़ा बजट लाने का आपका मतलब क्या है। मैं कुछ ही सेक्टर की बात करूंगा उससे अंदाजा हो जायेगा कि अभी फरवरी तक डेढ़ महीने का समय बाकी है कितना प्रतिशत बजट हम लोगों ने खर्च किया है। अगर मैं आवास विभाग की बात करूं, पिछले साल 4 हजार 806 करोड़ रुपये एलोकेट हुये थे हमने अभी तक फरवरी में 4 हजार 337 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है जो हमारे अलाटमेंट का 90.25 प्रतिशत है, अभी डेढ़ महीने का वक्त बाकी है। अगर मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं, 45 हजार 155.71 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ था और हमने अभी तक 43 हजार 994.13 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है जो एलोकेशन का 97.43 प्रतिशत है अभी डेढ़ महीने का समय बाकी है। अगर मैं ग्राम्य विकास विभाग की बात करूं तो 16 हजार 285.27 करोड़ रुपये एलोकेट हुआ था और हमने 15 हजार 835.43 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है जो 97.24 प्रतिशत है। खाद रसद विभाग में 11 हजार 429.18 करोड़ एलोकेशन था और 10 हजार 319.63 करोड़ रुपये हमने खर्च कर दिया है जो 90.29 प्रतिशत है। ऐसे ही

बहुत सारे विभाग हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो हम करीब-करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा एलोकेटेड बजट को खर्च कर चुके हैं। अगर मैं सेक्टरवाइज बात करूं तो एजूकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एण्ड कल्चर की बात करूं तो 2023-24 में जो एलोकेशन था 64 हजार 766 करोड़ रुपये का था, इस साल हमने जो खर्च करने का बजटेड किया है वह 01 लाख 03 हजार 35 करोड़ रुपये किया है। जो पिछले साल से 55 प्रतिशत ज्यादा है। ऐसे ही हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में 40 हजार 999 के अगेन्स्ट 42 हजार 744 करोड़ रुपये का बजट है जो चार प्रतिशत अधिक है। गृह विभाग की बात करूं तो 28 हजार 867 करोड़ के सापेक्ष 37 हजार 398 करोड़ का बजट है जो पिछले साल से 30 प्रतिशत से ज्यादा है। ऊर्जा विभाग की बात होती है। ऊर्जा विभाग में 2022-23 में 53 हजार 814 करोड़ का था इस वर्ष हमने 64 हजार 359.63 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का बजटेड किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। गन्ना विकास में पिछले वर्ष 1559.88 करोड़ था और इस साल 2117.67 करोड़ है जो 40 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी के साथ-साथ पर्यटन विभाग, पिछले साल 1104 करोड़ था, 1785 करोड़ इस साल है। जो 60 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि है। यह चीजें दर्शाती हैं कि सरकार जो योजनायें बनाती है जो बजट एलोकेट करती है जो विभागों को बजट देती है उसके बाद उस बजट को कैसे इस्तेमाल करना है कैसे उसका एलोकेशन करना है हम उसको बेहतर तरीके से करते हैं। मैंने अभी रेवेन्यू सरप्लस की बात आपके सामने की थी। उसका भी कुछ आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज हम कैसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुये हैं। कुछ पैरामीटर्स हैं जहाँ पर रेवेन्यू आता है, जी0एस0टी0 है, एक्साईज, वैट, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रेवेन्यू आता है और लैन्ड रेवेन्यू और टैक्स एण्ड ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी पर हमें जो रेवेन्यू मिलता है उससे प्रदेश सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू आता है। मैं जी0एस0टी0 की बात करूं तो 2023-24 में 77 हजार 224 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट किया था कि इतना रेवेन्यू आयेगा। आज हमारा इस साल का बजटेड है एक लाख 514 करोड़, जो कि 30 प्रतिशत अधिक इस्टीमेट किया है और हमने यह टारगेट फिक्स किया है। मान्यवर, स्टेट एक्साईज, क्योंकि मेरे पास एक्साईज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी आप संक्षिप्त कर दीजिए।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा क्योंकि मैं आंकड़ों के माध्यम से बात कर रहा हूँ और इससे लोगों को सीखने का मौका भी मिलेगा। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं वर्ष 2012 की बात करूँ तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का 14 हजार करोड़ रुपये का एक्साईज रेवन्यू आता था। आज मुझे यह बताने में खुशी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 चल रहा है। हमारा प्रोजेक्शन है कि हम

50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचें। जो पिछला वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है उसमें एक्साईज डिपार्टमेंट ने 41 हजार 250 करोड़ रुपये का रेवन्यू दिया था। इतनी लम्बी ग्रोथ एक्साईज डिपार्टमेंट में मिली है। हमने बहुत सारे लीकेजेज को प्लग किया है। आज एथेनॉल का प्रोडेक्शन देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, शीरे का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है और एक्साईज रेवन्यू पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आ रहा है। यह हमारी प्रतिबद्धता है। हमने पिछले साल के मुकाबले 18 प्रतिशत वैट में ग्रोथ ली है। ऐसे ही हमने पिछले साल के मुकाबले टैक्सेज ऑन व्हीकल्स में 50 प्रतिशत की ग्रोथ की है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी अब आप समाप्त कीजिए क्योंकि सभी मा0 सदस्य समय की ओर देखते हैं और फिर हमारी तरफ इशारा करते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश जी को कम-से-कम बीस बार टोक दिया।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, आदरणीय योगी जी की सरकार जो समाज में अन्तिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको समृद्ध करना, उसको आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार इसी संकल्प के साथ कार्य कर रही है। आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय कुमार शर्मा-

मान्यवर, मै आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस बार के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इस बार का बजट 7 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का एक बहुत ही अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक बजट है। वर्ष 2016 में जब विपक्ष का आखिरी बजट आया था वह 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये का था। 3 लाख 46 हजार करोड़ रुपये से लेकर पिछले सात वर्षों में दोगुने से भी ज्यादा की राशि का बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण किसी प्रदेश में नहीं, अगर किसी देश में इतनी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई हो, ऐसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऐसे बजट के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को कोटि-कोटि बधाई देता हूँ। विपक्ष की तरफ से 5 ट्रिलियन डॉलर एवं 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी को लेकर जुमले कसे जाते हैं। वर्ष 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी का संकल्प लिया था तो उस समय देश में सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी थी और पिछले वर्ष में हमारे देश की इकोनामी 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी हो गयी है। हम 70 साल में सिर्फ 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी पर पहुंचे थे और हमने सिर्फ 10 वर्षों में उसको

दोगुना कर दिया है। आज हमारा देश उससे कारण दुनिया में 5वें नम्बर की इकोनामी बना है। उत्तर प्रदेश उससे पीछे नहीं है। हमारा जी0डी0पी0 वर्ष 2016 में 13 लाख करोड़ था और इस समय जी0डी0पी0 26 लाख करोड़ है। हमने भी दोगुने का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। यह इसी तरह की चर्चा करते रह जायेंगे और कब यह देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी बन जायेगा और कब यह प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी देकर प्रदेश की प्रगति में अपना हाथ बटायेगा, यह इनको पता भी नहीं चलेगा। यह सब हुआ कैसे। हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक श्लोक है कि-

'अलब्ध लब्धार्था लब्ध परिक्षणी,

रक्षित विवर्धनी, वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च।'

अर्थात् जो खजाने में पैसा नहीं प्राप्त होता, उसको प्राप्त करना, प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना और जो संरक्षित धन है उसको समानता के आधार पर हर व्यक्ति तक पहुंचाना, यह राजा का कर्म होता है।

हमारी सरकार ने हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इसको पूरे मन से लागू किया है और उसी का परिणाम यह निकला है कि प्रदेश के जिन लोगों के पास जनता का हक होता था, जनता के टैक्स का पैसा होता था उसको उनके हलक से बाहर निकाला है तब यह बजट 03 लाख 46 हजार करोड़ से बढ़कर आज 07 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। ये कैसे हुआ ? ये पी0डी0ए0 की बात करते हैं, पी0डी0ए0 क्या है ? हमारा भी पी0डी0ए0 है, ये जिस पी0डी0ए0 की बात करते हैं उससे तो इनका लेना-देना ही नहीं है। इनके तो 'पी' का मतलब है परिवार, इनके 'डी' का मतलब है दोस्त और दलाल और इनके 'ए' का मतलब तो सिर्फ रामपुर तक सिमटकर रह जाता है। हमारे पी0डी0ए0 की बात करते हैं, आइए, मैं गांव में इनको दिखाता हूं आकर देखें कि उज्ज्वला योजना का लाभ किस पी0डी0ए0 को मिल रहा है। अखिलेश यादव जी अपने इस कवच से निकलकर आकर देखें कि आज निःशुल्क राशन का लाभ किस पी0डी0ए0 को मिल रहा है, आकर देखें किसको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आज किसको जल जीवन मिशन का लाभ मिल रहा है। यह ऐसे ही नहीं हुआ है। इन लोगों ने तो कभी प्रदेश की जनता की चिन्ता नहीं की। एक दोहा कबीरदास जी का है,

कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक।

बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक।।

यह वही तो प्रदेश है, वही जनता है, वैसे ही जनता सरकार बनाती थी। हर पांच साल बाद जनता को सरकार बदलने की चिन्ता होने लगती थी पर कभी इन्होंने उस जनता की चिन्ता नहीं की। बस इनको उस समय ओक भरकर घी पीने का काम करना होता था। इन्होंने जनता के बारे में कभी भी नहीं सोचा। उस बर्तन के छेद को बंद करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। इनका जो पी0डी0ए0 है

उस तक राशन नहीं पहुंच रहा है लेकिन हमारे पी0डी0ए0 तक तो पहुंच रहा है। जो इनका पी0डी0ए0 है उसकी ऊपर की कमाई बंद हो गयी है इसलिए सब के सब परेशान हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अभी हमारे आबकारी मंत्री जी बैठे थे। वर्ष 2017 तक 12 हजार करोड़ रुपये की आमद होती थी, आज हमारी 58 हजार करोड़ रुपये की आमद होती है। इनके बीच में पांच गुना राशि बढ़ी है वह पहले किसके पास जाती थी ? इनके किसी 'पी' के पास जाती थी, वह 'पी' इस दुनिया में नहीं है लेकिन जनता का हक उसी 'पी' के पास पहुंचाया करते थे। ये उनका पी0डी0ए0 है। आज स्टाम्प में 11 हजार करोड़ से लेकर प्रदेश की आमदनी 36 हजार करोड़ रुपये हो गयी है। आज परिवहन में आमदनी 05 हजार करोड़ से बढ़कर 14 हजार करोड़ रुपये हो गयी है। आज खनन में 05 गुना राजस्व प्राप्त हो रहा है। यह उसी का परिणाम है कि विकास की इतनी सारी योजनाएं आज इस प्रदेश में चल रही हैं। महोदय, ये लोग बार-बार इंवेस्टर्स समिट की बात करते हैं, इस बार इंवेस्टर्स समिट तक 37 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आये थे। इंवेस्टर्स समिट के खत्म होने के बाद 04 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आये थे जिनके लिए न कोई रोड शो हुआ, न कोई मार्केटिंग हुई। ये जो उद्योगपति हैं उनका इस प्रदेश पर विश्वास है, इसकी कानून-व्यवस्था पर विश्वास है, यहां की नीतियों पर विश्वास है कि इंवेस्टर्स समिट के बाद भी 04 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव आ रहे हैं। इतना तो इनके समय में पूरे प्रदेश का बजट भी नहीं होता था। आज इस प्रदेश में सबकी आस्था बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश ने 24 पॉलिसीज को परिवर्तित किया है उसके कारण उद्योगपति हमारी तरफ आ रहे हैं। आज सिंगल विंडो है। इनके लिए नोएडा एक रियल स्टेट का जरिया होता था, वहां दलालों द्वारा प्लाट खरीदे जाते थे। आप सर्वे करा लीजिए पिछले 20 वर्षों में किसी उद्योगपति को बिना प्रीमियम के प्लाट नहीं मिला होगा। हमारी सरकार नोएडा के साथ-साथ बुंदेलखण्ड को भी डेवलेपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, समय बहुत कम है, मैं अपने क्षेत्र की भी दो-तीन मांगे रखना चाहता हूँ। मैं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं वित्त मंत्री जी को इतना सुंदर बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। महोदय, हमने अपने क्षेत्र की दो सड़कें बाबू स्व0 कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मार्ग और एक गंगा-यमुना मार्ग जिसे हमने और आदरणीय जेवर के विधायक जी ने दिया है जिसमें हम अनूप शहर को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ना चाहते हैं, उन दोनों की स्वीकृति हो जाये तो बहुत अच्छा होगा। हमारी चीनी मिल 50 साल पुरानी है लेकिन प्रदेश में सबसे अच्छा काम कर रही है उसकी भी क्षमता अगर दोगुनी हो जाये तो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा। मेरे क्षेत्र में गंगा जी पर एक पीपे का पुल है जिसको पक्का बनाना बहुत आवश्यक है उसके लिए भी अनुरोध करता हूँ एक सूती मिल बहुत दिनों से बन्द पड़ी हुई है, उसकी जगह एक मिनी इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलेप हो तो उससे क्षेत्र और जनपद को बहुत लाभ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे वित्त मंत्री जी

को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें। अब माननीय श्री प्रसन्न कुमार जी। आप अपनी बात 07 मिनट में समाप्त करें।

***श्री प्रसन्न कुमार-**

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, सरकार एक तरफ अमृतकाल की बात करती है और जब बजट पेश होता है, तब पता चलता है कि बजट में किसानों के लिए कोई भी सुविधा का कार्य नहीं किया गया है। युवाओं के लिए कोई भी ऐसा कार्य बजट में दिखायी नहीं देता, जिससे युवा अपनी नाराजगी दूर कर सके। महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी योजना इस बजट में नहीं है, जिससे महिलाएँ अपनी रसोई के खर्चे को कम कर सकें। मान्यवर, मैं किसान की बात करूँ और खासकर मैं गन्ने की बेल्ट से आता हूँ। बजट में बताया गया, लिखा गया कि पहली सरकार के मुकाबले हमने इतना ज्यादा पेमेण्ट किया है, लेकिन उसे मकड़जाल में उलझाया गया, यह नहीं बताया गया कि आज से 07 साल पहले जो गन्ने का बुवाई का क्षेत्र था, वह अब डेढ़ गुना बढ़ चुका है, यानी केवल मकड़जाल में उलझाना है। जब किसान गन्ना ज्यादा देगा तो उसका पेमेण्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरी बात, भाव मात्र बढ़ाया गया, जबकि महँगाई बढ़ी है। लानत है ऐसी सरकार पर जो किसान के फेवर की बात करती है और जब फर्टीलाइजर की बात आती है, यूरिया की बात आती है, आज मैं माननीय कृषि मंत्री को सुन रहा था कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। यूरिया का कट्टा जिसमें 50 किलो खाद आती थी, भाव तो वही रखा, कट्टे का दाम तो वही है, लेकिन 10 किलो यूरिया साफ, तो यह किसानों के साथ धोखा हो गया। दूसरी किसान की आय होती है, पशुपालन से। आज कोई भी किसान पशुपालन नहीं करना चाहता क्योंकि वह उद्योग बिल्कुल खत्म हो चुका है। तीसरा नम्बर आता है, बिजली के कनेक्शन का। बजट में एक डॉर्क जोन पर छूट दी गयी है और यह कहा गया कि हम किसानों का फायदा कर रहे है। किसानों का फायदा तो तब होना था, जब कोई नया कनेक्शन किसान को मिले और उस पर जो एस्टिमेट बनता है, उसकी छूट दी जाय। आज किसान की स्थिति क्या है, वह गरीब से गरीब होता जा रहा है, लेकिन जब वह विभाग में बिजली का कनेक्शन लेने जाता है, तब एक खम्भे का लगभग उसे 01 लाख रुपया देना पड़ता है। यदि 04 खम्भे की उसकी लाइन है तो उसका 7-8 लाख रुपये का बिल बनता है। यदि किसान को छूट देनी थी तो उस एस्टिमेट की छूट देनी थी। हँसी आती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 05 साल पहले 06 हजार रुपये एक साल की थी। आज हर चीज का दाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ा हुआ है, लेकिन किसान सम्मान निधि वही झुनझुना, 02 हजार रुपये का। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की भी चर्चा मैं करना चाहूँगा। आज स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, हर जिले में डाक्टरों की कमी है और कहीं-कहीं तो 70 परसेण्ट की कमी है।

मैं दूर-दराज के जिले शामली से आता हूँ जिसकी अगर फिजिकल स्थिति मानचित्र में देखें तो उसकी दिल्ली से दूरी लगभग सौ किलोमीटर है, मेरठ से दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, यदि वहां कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी अगर एक्सीडेंट से पीड़ित हो जाता है तो वहां ऐसी सुविधा नहीं है कि उसका इलाज शामली में हो सकें। शामली में एक ट्रॉमा सेण्टर की मांग मैंने मा0 स्वास्थ्य मंत्री से की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन वह फाईल आज तक कागजों में रहती फिर रही है, उस फाईल का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और यदि उसमें व्यक्ति को 15 मिनट के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए तो वह ठीक हो सकता था। मान्यवर, आज हृदय रोग से सबसे ज्यादा व्यक्ति मर रहे हैं, अभी हमने एक आंकड़ा पढ़ा था हापुड़ जिले का जिसमें एक ही दिन में पांच हृदय रोग से व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और शामली जिले में भी हर दिन दो या तीन युवा व्यक्ति ज्यादातर हृदय रोग से पीड़ित हैं, जो मर रहे हैं। सरकार ने बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि गौ संरक्षण के लिए सरकार बड़ा ध्यान दे रही है, गौशाला खोली हुई है, लेकिन उनका एक गाय का खर्चा 30 रुपये था उसे बढ़ाकर 32 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक फण्ड बनाया गया था जो फण्ड निधि होती है, जो गांव की निधि होती है उसमें से काटना था 32 परसेण्ट तो कुछ गांवों में जो प्रधान थे उन्होंने वह 32 परसेण्ट खर्च कर दिया, लेकिन आज तक उन्हें 32 परसेण्ट का पैसा नहीं मिला और आज गांवों की ऐसी स्थिति है कि जो फण्ड यहां से जा रहा है उसकी 60 परसेण्ट की कटौती टोटल हुई है, उसमें उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं हो रही है। अब मैं अंत में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उन्हें भी रखना चाहता हूँ और मांग करता हूँ जैसे कि हमारी कल्लरपुर नहर है, उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो उसमें कृपया पानी छोड़ा जाए और अंत में मैं अपनी बात को बंद करने से पहले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को याद करना चाहता हूं, वह किसान के कण-कण में हैं, हमारी आत्मा में हैं और हम उनके अनुयायी लोग हैं और जो दूसरी साईड के लोग बैठते हैं, वह भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मान्यवर, आपने हमें बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने के लिए समय दिया। अभी मा0 सदस्य, मंत्री जी बजट पर विस्तार से इस तरह से बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से लगता है कि पूरा प्रदेश में चारों तरफ न कोई बेरोजगार है और न ही कोई विकास की कमी रह गई है। पिछला चुनाव याद होगा जिसमें वायदा किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, सस्ती बिजली देंगे, पिछड़े, कमजोरों

का उत्थान करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई कम कर देंगे जाने क्या-क्या वायदे किए गए थे। बजट देखा, न नौकरी की घोषणा, न महंगाई कम हुई, सब जुमले हैं और कुछ नहीं। अगर बजट के बारे में विस्तार से बात कर लें तो जिस वक्त इस सरकार ने वर्ष 2018-19 में पहला बजट रखा था 4 लाख 28 हजार 3 सौ 84 लाख रुपये का, लेकिन अगर देख लें तो लगभग 3 लाख 91 हजार 2 सौ 10 लाख ही पैसा खर्च हो पाया। अगर बजट रखने की ही बात है तो कितना ही बजट कागजों में लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि यह वर्ष 2018-2019 की ही बात है, वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और आज 2024-25 के बाद भी जो बजट रखा गया है 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ रुपये का रखा गया है, बहुत लम्बी-चौड़ी बातें हो रही कि यह सबसे बड़ा बजट है। यह पहले के बजट से 2.4 प्रतिशत ही बड़ा है इसमें 17 हजार 423 करोड़ रुपये ही इसमें अधिक है लेकिन खर्च किस तरह से होगा इसका उदाहरण मैंने वर्ष 2016-17 के बजट से अभी दे दिया है।

चाहे आप इन्वेस्टर्स समिट की बात कर लें या ओ0डी0ओ0पी0 की बात कर लें या बेरोजगारी की ही बात कर लें आज स्थिति यह है कि अगर इन्वेस्टर्स समिट की बात कर लें तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में न तो जमीन बची है, और न ही मेरे ख्याल से कोई बेरोजगार बचा है सबको रोजगार मिल गया है और जमीन बिल्कुल कहीं खाली नहीं रही है। किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश के अंदर। सही बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर वर्ष 2018 के बाद से जो इन्वेस्टर्स समिट की बात लगातार हो रही है उसमें न तो कोई उद्योगपति और न ही इस तरह से कोई बड़े पैमाने पर उद्योग दिखायी दिया है लेकिन यह बात सही है कि यदि कहीं कोई उद्योग उत्तर प्रदेश में लग रहा है तो सारे अधिकारी वहाँ उन कारखानों में दौड़े फिर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि रहने के लिए कोई कमरा बनाया हो तो उसका एम0ओ0यू0 भी हमको लिखकर दे दीजिए। इतना तो विकास जनरली हुआ है इसके अलावा तो मुझे कहीं विकास नजर नहीं आता है। यदि ओ0डी0ओ0पी0 में हमारे अपने मण्डल की स्थिति ही देख लें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, रामपुर का चाकू, मैं कहूँगा सम्भल का हड्डी का और हमारे यहाँ ढ़ोलक को ओ0डी0ओ0पी0 में 'वन डिस्ट्रिक, वन प्रोडक्ट' में लिया गया था। उसके तहत यदि एक रुपया भी कहीं पर जारी किया गया हो या उस पर कोई काम किया हो इस योजना के तहत तो हमें बतायें। यह क्या है, क्या इस तरह से ही सरकार समाज के लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है, ये बातें छोड़िए आपको जमीन पर काम करना पड़ेगा क्योंकि 'मंदिर को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखें है वह सब अपने पेट के निवालों को जानते हैं' इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

यदि आप अल्पसंख्यकों की बात कर लें तो बजट में उनका कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर पेपरलेस बजट की बात तो हुई है लेकिन मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पेपरलेस तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ लेकिन यह बजट अल्पसंख्यक लेस जरूर हो गया है। देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वर्ष 2023-24

का बजट ले लें तो 1882 करोड़ रुपये का बजट अल्पसंख्यकों के लिए था और इस साल घटकर 220 करोड़ रह गया है यह है आपकी प्रगति और ये है आपका सबका साथ सबका विकास 25000 से अधिक मदरसों से सम्बन्धित योजना के अन्दर शिक्षकों को जो राज्यांश मिलना था वह भी बंद कर दिया। शिक्षक भर्ती अभी तक बंद पड़ी है। कई विद्यालय भी बंद होने की कगार पर पड़े हैं कोई सुनने वाला नहीं है। यह सब इन्वेस्टर्स समिट से सम्बन्धित बिन्दुओं के विषय में मैंने आपसे अभी कहा ही है, अब खेल की बात कर लें। अभी मा0 मंत्री जी से सुबह बात हो रही थी। बहुत लम्बी बातें कर रहे थे मा0 मंत्री जी। कहीं न कहीं पैदा होने के बाद यदि हम हमारी नस्लों को सही और स्वस्थ चाहते हैं तो खेल का कहीं न कहीं किसी प्लेग्राउण्ड में जाकर प्रशिक्षण ले लें और कहीं न कहीं वहाँ मैदान में व्यायाम कर लें और यह कहीं भी सम्भव हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर केवल एक कोच है और इसका बजट कितना है 120 करोड़ रुपये। स्टेडियम बहुत लम्बे चौड़े बनाने की बात कर रहे हैं कि हम यह स्टेडियम बनाएंगे, हम वह स्टेडियम बनाएंगे। लेकिन बजट मात्र 120 करोड़ रुपये है। कितने स्टेडियम बनायेंगे ? आपके पास कोच है नहीं, कह रहे है कि जो जिला क्रीडा अधिकारी है, वह कमीशन से आता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, समाप्त करें।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं तो अभी शुरू ही हुआ हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसमें बड़ी विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा कि पीठ का निर्देश आप मानें अपनी बात संक्षिप्त कर खत्म करें।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, सामने जितने मा0 सदस्यों ने बोला है, मैं कम से कम उससे ज्यादा देर बोलूँगा। सीनियरिटी, जूनियरिटी के आधार पर देख लें मेरा अधिकार बनता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने अपने आप ही पीठ पर से व्यवस्था दी है, तो वह व्यवस्था सब पर लागू होती है।

श्री अधिष्ठाता-

वह व्यवस्था सब पर ही लागू होगी, आप कृपया समाप्त करें।

श्री महबूब अली-

आपने बात की है कि हां हम कि हम स्टेडियम बनायेंगे, मैंने अभी कहा था कि मोहम्मद शमी मेरी विधान सभा क्षेत्र से आता है। मुख्य मंत्री जी ने एलान किया परन्तु स्टेडियम नहीं बना। एक स्टेडियम वहां तत्काल बन जाना चाहिए, उन्हीं के अपने गांव के अन्दर जगह

भी पड़ी है। वहां तो पॉलिटिकल कालेज चल रहा था, जो बनाया हमारी सरकार ने था परन्तु आज तक वह कालेज नहीं चल पाया। मैं चाहूंगा कि अमरोहा के अन्दर लगातार एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर मेडिकल कालेज की बात करें तो कोई मेडिकल कालेज नहीं बना है। वहां के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 38 करोड़ रुपया हमने लगाया था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय महबूब अली जी, अब समाप्त करें।

श्री महबूब अली-

मैं इस पूरे बजट का विरोध करता हूँ और बजट की धनराशि काटकर एक रुपये कर दी जाये। 'कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए'।

श्री अधिष्ठाता-

मैं एक बार फिर सभी मा0 सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि पीठ के निर्देश को मेरा व्यक्तिगत निर्देश न मानें। अब यह बात मैं बड़ी प्रार्थना से कह रहा हूँ कि अगर हमारी बात 7 मिनट, साढ़े 7 मिनट तक पूरी हो जाये, अन्यथा की स्थिति में माइक बन्द करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्र कश्यप जी।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसी से सम्बन्धित व्यवस्था है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अभी आप बीच में डिस्टर्ब न करें। कश्यप जी, आप अपनी बात रखें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नरेन्द्र कश्यप-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट भाषण 2024-25 के समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूँ। यह बजट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के मा0 वित्त मंत्री जी के माध्यम से सदन में प्रस्तुत हुआ और बजट की प्रस्तुति के उपरांत प्रदेश भर के गरीब, पिछड़े, दलित, कमजोर, दुकानदार, किसान बहुत लोगों से बात हुई और बजट के सापेक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। मान्यवर, मुझे हर्ष के साथ यह बात आपके माध्यम से सदन में कहनी है कि इस बजट की प्रशंसा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। मा0 वित्त मंत्री जी ने पूरा दिल खोलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के सिद्धांत को धरातल पर उतारने के लिए 7 लाख 36 हजार करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि का बजट पेश करके अपनी पार्टी के मूल भाव को पूरा करने का सार्थक प्रयास इस बजट के माध्यम से हुआ है।

महोदय, हमारी सरकार के बजट के पीछे लक्ष्य उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है। वर्ष 2017 के पहले की व्यवस्था पर मैं कोई बड़ी बात आपके बीच नहीं करूँगा, प्रदेश जानता है।

लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की समृद्धि में, उत्तर प्रदेश की खुशहाली में, नौजवानों के चेहरे की रौनक से स्पष्ट हो रहा है कि लगातार हमारी सरकार ने अपने सार्थक प्रयासों से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। आपके बीच कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ, 'हम निकल पड़े हैं, प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके, जिद है कि सूर्य उगाना है, अमर से ऊँचा जाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है।'

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

महोदय, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी तेजी के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा भले ही किसी को यह इवेंट लगे, लेकिन दुनिया इस बात को स्वीकारती है कि जिन रामभक्तों ने रामलला की प्रतिष्ठा के लिए 500 सालों का अथक प्रयास किया था, आज विश्व पटल पर कहीं न कहीं उनके मनोभाव पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। मुझे एक दोहा याद आता है, 'रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जायं पर वचन न जाई।' महोदय, हमारी सरकार का हर संकल्प, हमारी पार्टी का हर संकल्प धीरे-धीरे देश में पूरा होता हुआ, देश और प्रदेश की जनता देख रही है। मान्यवर, रामराज्य की परिकल्पना का सबसे बड़ा मूल यही था कि जो कहा जाये, उसे धरातल पर करने का प्रयास हो। 6 करोड़ प्रदेशवासी गरीबी की रेखा से ऊपर निकले हैं, क्या यह उपलब्धि नहीं है ?

महोदय, उत्तर प्रदेश के नौजवान रोजगार के साथ जुड़कर अपने आपको सुखद स्थिति में पा रहे हैं, क्या यह सरकार की उपलब्धि नहीं है ? महोदय, मैं अपनी बात को अपने विभाग की परिधि में केन्द्रित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में देना चाहता हूँ। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में सेवा करने का दायित्व मुझे मेरी सरकार ने दिया है। देश की बात करें या प्रदेश की बात करें। यह पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी 1955 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 52 प्रतिशत है। सम्भवतः आज वह आबादी बढ़ी होगी लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाये है, उन कदमों की सराहना ओ0बी0सी0 समाज के हर घर में हो रही हैं। महोदय, मुझे आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना है कि इस 2024-25 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने ओ0बी0सी0 समाज की गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान की राशि को 150 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ करने का फैसला लिया ताकि गरीब ओ0बी0सी0 समाज की बच्चियों की शादी में हम सहयोग कर सकें। ओ0बी0सी0 समाज के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिये, सी0सी0सी0 और ओ-लेवल की योजना हेतु इस बजट में हमारी सरकार ने 23 करोड़ की राशि को बढ़ाते हुए 35 करोड़ करने का फैसला लिया, जिससे आज हमारे ओ0बी0सी0 समाज के बच्चों में कहीं न

कहीं उत्साह का वातावरण है। 22 करोड़ की धनराशि इसी बजट में पिछड़े समाज के बच्चों के छात्रावास के निर्माण के लिए भी हमारी सरकार ने रखा है।

मान्यवर, ताकि गरीब बच्चे शहरों में जा करके निःशुल्क छात्रावास में रह कर, अपने बौद्धिक जीवन को आगे बढ़ा सकें। मान्यवर, एक बात कहते हुये मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में कदाचित, सम्भवतः ऐसा कभी नहीं हुआ कि शत-प्रतिशत ओ0बी0सी0 समाज के बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप प्राप्त हुयी हो। आज मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि इस बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में ओ0बी0सी0 समाज के सभी छात्र-छात्राओं को 100 प्रतिशत वजीफे का प्रबन्ध करते हुये, 2 हजार 475 करोड़ की व्यवस्था की है। हम इस साल इस सुखद स्थिति में होंगे कि हम उत्तर प्रदेश के हर पात्र ओ0बी0सी0 छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और छात्र प्रतिपूर्ति देने में सफल होंगे। डबल इंजन की सरकार आज देश और दुनिया में मोदी और योगी का कायल वैसे ही नहीं है बल्कि डबल इंजन की सरकार ने देश और दुनिया में बहुत कुछ करके दिखाया है। मैं अपनी बात को केन्द्र बिन्दु में ओ0बी0सी0 को लेते हुये बात करना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की पहली सरकार है, 70 सालों के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सरकार ने भारतवर्ष में ओ0बी0सी0.....

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, अब संक्षिप्त करें।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मान्यवर, मेरा समय अभी थोड़ा-सा बचा हुआ है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओ0बी0सी0 समाज के ओ0बी0सी0 कमीशन को 70 सालों के बाद किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया है। 27 प्रतिशत रिजर्वेशन नीट की परीक्षा में, जिसके माध्यम से ओ0बी0सी0 के बच्चे एम0बी0बी0एस0, एम0डी0, एम0एस0 बनेंगे। 27 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया है जिसमें 4400 बच्चे हमारे पहले साल में डाक्टर बनने के लिए तैयार हो गये हैं। केन्द्रीय विद्यालयों, सैनिक विद्यालयों में 27 प्रतिशत रिजर्वेशन देश में पहली बार लागू हुआ तो मोदी जी की सरकार में लागू हुआ है। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुये यह कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार ने देश में चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, उत्तर प्रदेश में, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, हमारी सरकार ने इनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुये जो काम किये हैं उसकी प्रसंशा आज प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है। निश्चित मत भी है कि जिस पार्टी के साथ यह 52-55 प्रतिशत लोग ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो 400 की बात छोड़िये अगर 450 के पार करना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने समय से अपनी बात पूरी की है।

श्री धीरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं पीठ और सदन को धन्यवाद अर्पित करते हुये कहना चाहूंगा कि मुझे इस बजट के समर्थन का भाषण करने का मौका इस सम्मानित सदन में मिल रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्ता है कि आज वो लोग किसानों की, दलितों की और पिछड़ों की चिन्ता कर रहे हैं, जिनके समय में किसानों पर लाठियाँ बरसाई जाती थीं। भट्ठा पारसौल मेरी विधान सभा क्षेत्र में ही है। मेरा जिला गौतमबुद्धनगर है, जहाँ किसानों की जमीनों को लूट कर अपनी तिजोरियाँ भरने का काम किया जाता था। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि वह लोग चिन्ता कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लागू किया है। वह रिपोर्ट वर्षों से धूल फांक रही थी, सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ इस देश के किसानों को गुमराह करने का काम किया लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने के पश्चात नरेन्द्र मोदी जी ने सबसे पहले किसानों के हितों के लिए उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को निकलवाया। और उसे लागू करने के लिए उस दिशा में काम किया जिससे आज हम देख रहे हैं कि किसानों के हितों की अनेकों ऐसी योजनाएं भारत सरकार भी बना रही है और हमारे बजट में भी उसके लिए प्रावधान किये गये हैं, किसानों की उन्नति के लिए। मुझे इतिहास का वह दौर भी याद आ रहा है जब नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया के लोग शोध करने के लिए आते थे और यहां पर सांस्कृतिक वैभव देख कर उसके बारे में लिखा करते थे। आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज श्री राम की नगरी अयोध्या अपने गौरवशाली अतीत को पुनः स्थापित करने की ओर अग्रसर है जहां भगवान श्री राम के चरित्र के पहलू और आदर्श जिसमें हमारे भारत की संस्कृति के मूल तत्व दया और करुणा विद्यमान है। यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी पहचान बनाने जा रहा है जहां अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ-साथ उन असंख्य नौजवानों के भविष्य की योजनाओं को साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है जो आज तक किन्हीं सरकारों ने नहीं किया।

योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास की वह गाथा लिखने की ओर अग्रसर है जहां गरीब किसानों, बेरोजगारों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण की योजनाएं है और बजट में उनके लिए बहुत सारी ऐसी धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के वह दबे, कुचले और पिछड़े वर्ग लाभान्वित होंगे जिनका सपना पं0 दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था। आज अगर हम खेलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो खेल नीति बनायी गयी है वह उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है जो ग्रामीण अंचल से आते हैं। उनको सुविधाएं देने के लिए अनेकों इनाम की घोषणाएं की गई हैं और उनके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। पैरा ओलम्पिक में पुरस्कार पाने वाले लोगों के

लिए पहली बार इस सरकार ने योजना बनायी और उन्हें इनाम दिये जाने का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया गया तो यह कोई छोटी बात नहीं है। लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से हम अपने उत्तर प्रदेश के उन लोगों को मौका दे रहे हैं, ऐसी नीतियां बनायी जा रही हैं जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी आगे आकर इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर) के माध्यम से उन ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में वह व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे डिजिटल माध्यम से वहां स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जा सके। तो यह योगी आदित्यनाथ जी का करिश्माई नेतृत्व ही है जिसकी वजह से आज इन सारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। चूंकि मैं सरकार पक्ष का विधायक हूँ इसलिए मेरी यह भी जिम्मेदारी है कि मैं जनता की समस्याओं को भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाऊं।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा जनपद गौतमबुद्धनगर जो इस प्रदेश के ग्रोथ का इंजन बनने जा रहा है और मेरी विधान सभा क्षेत्र इस प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। आज मैंने देखा कि किसानों की समस्याएं हैं और किसान आन्दोलनरत हैं तो मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन किसानों ने आगे आकर अपनी जमीन को इस प्रदेश के विकास के लिए दिया है उन किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए राज्य स्तर पर एक ऐसे मंत्री और विधायकों के समूह का गठन किया जाय जो वहां बैठ कर किसानों की समस्याओं का समाधान करें। जो अभी तक फायदा नहीं ले पाये हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन कर उनकी समस्याओं को सुलझाया जाय। और मैं यह भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आज गौतबुद्धनगर जनपद की बहुत जरूरत बन गया है, बेहतर प्लानिंग के साथ उस पब्लिक ट्रान्सपोर्ट को लागू किया जाए और साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, वह इसी सत्र में सदन में लाया जाए, जिससे होने वाली दुर्घटनाएं को रोका जा सके। मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री जी के उस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ और एक ऐसा बजट प्रदेश को दिया है जो सबका साथ और सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक)-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय बजट भाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के पक्ष में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। महोदय यह जो बजट है यह समावेशी है, ऐसा बजट कभी आया नहीं था। मैं पहली बार कुशीनगर से विधायक चुनकर आया हूं, इस बजट में आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये दिया है, इसके लिए कुशीनगर की जनता की तरफ से आदरणीय योगी जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को व आदरणीय वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में फिलहाल इनवेस्टर समिट की कई बैठकें हुई, जी 20 की कई बैठकें हुई। कानून व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो यहां पर जो गुण्डागर्दी चलती थी, आज वह गुण्डे चोर उचक्के या तो जेल के अन्दर हैं या फिर प्रदेश छोड़कर के दूसरे प्रदेश में शरण लिये हुए हैं। जहां तक शिक्षा की बात है प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प किया गया है, मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी राजकीय इण्टर कालेज है, वहां शौचालय, बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। जहां तक स्वास्थ्य की बात की जाए तो हमारे यहां पर भी एक मेडिकल कालेज बनकर तैयार हो गया है, इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत आभार। जहां तक बिजली की बात है गांव में हम लोगों को कम से कम 20 घण्टे बिजली मिल रही है, शहर में 24 घण्टे तक बिजली मिल रही है, इसके लिए भी आभार। संत महापुरुषों का सम्मान करना यह मा0 योगी जी व मा0 मोदी जी ने बताया है। जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से परिषद् का गठन किया गया है, संत श्री रविदास जी की जंयती पूरे देश में धूम-धाम से मनायी गयी, कुछ रविदास जी के आदर्शो पर चलने का प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे कि रविदास जी ने कहा है कि-

''ऐसा चाहूँ राज में सबको मिले अन्न, छोटे बड़े और सबसे रविदास रहे प्रसन्न''

हर घर नल के तहत गांव में टंकी बनाई गयी, शहरों गावों में मुफ्त आवास दिया गया, मेरी विधान सभा क्षेत्र में पुलों और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वानाथ का कॉरिडोर हो, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का धार्मिक केन्द्र भी है, वहां पर भी मा0 योगी जी की सरकार ने विकास की बहुत सारी व्यवस्थाएं दी है। अभी हमारे यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी 2021 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्य मंत्री जी के द्वारा सफल संचालन हुआ, एक फ्लाईट चल रही है और मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि दो-तीन फ्लाईट और बढ़ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी, 2024 को लगभग 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामजी का बाल विग्रह, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मा0 मोदी जी की जो सोच है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसमें अयोध्या का राम मन्दिर महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा जो कहा जाता है कि नार्थ पोल और साउथ पोल तो साउथ पोल से मुझे लग रहा है कि नार्थ पोल में मोदी जी और योगी जी ने सिद्ध कर दिया है जो कहा जाता था कि तिरूपति बाला जी हैं। अब सबसे ज्यादा पर्यटक अयोध्या में आयेंगे। मैं अपने यहां की कुछ मांग भी रखना चाहता हूँ। हमारे यहां एक कुबेर स्थान बड़ी बाजार है। वह नगर पंचायत बनने के सारे मानकों को पूरा करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग

करता हूँ कि वहां नगर पंचायत बनाने का प्रयास किया जाए। आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

आपने समय-सीमा के अन्दर अपनी बात पूरी की है, इसके लिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समाजवादी पार्टी, विधान मण्डल दल के नेता श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा रखे गये बजट के प्रस्ताव पर जो उन्होंने सुझाव दिया है, उसका समर्थन करता हूँ। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही बड़ा बजट है, जिसको यह सरकार पूरे प्रदेश में वाहवाही लेने का काम कर रही है। 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ से अधिक का बजट सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। हम लोग गांव, खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र टांडा है। जो पूरे देश में टांडा टेरीकाट के नाम से विख्यात है। वहां टेरीकाट कपड़े का बहुत बड़ा एक मार्केट है। पूरी दुनिया में टांडा टेरीकाट की सप्लाई होती है और मुझे लगता है कि विदेशों से बहुत धन आता है। मेरे पास कोई डाटा तो नहीं है कि कितना धन आता होगा, लेकिन कपड़े का एक्सपोर्ट होने से निश्चित रूप से सरकार को खजाने में कुछ न कुछ रकम प्राप्त होती होगी। इस बजट में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कहीं पर भी एक रुपये का बजट निश्चित नहीं किया गया है, उलटे कपड़ा उद्योग तहस-नहस हो रहा है, जो टांडा की पहचान है। टांडा टेरीकाट इस देश की पहचान है, उसको मिटाने के लिए बिजली की दर को जो पहले 65 रुपये प्रति पावर लूम थी, अब बढ़ाकर 400 रुपये प्रति पावर लूम कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस बजट में जब एक जनपद एक प्रोडक्ट की बात की गयी है तो अम्बेडकर नगर जनपद का प्रोडक्ट टांडा टेरीकाट है, उसके लिए सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत दुःख और खेद है कि सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। न पावर लूम की विद्युत दरों में छूट देने का कोई प्राविधान किया गया है न कोई मार्केट हब बनाने की बात की गयी, जिससे उनकी मार्केटिंग को बढ़ाया जा सके।

(इसी मध्य 03 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनोज कुमार पाण्डेय पीठासीन हुए)

मान्यवर, इसके द्वारा टांडा के व्यापारियों का जो वह तरक्की कर रहे थे उसको रोकने का काम सरकार कर रही हैं। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिनके ऊपर जी0एस0टी0 के टैक्स से उनकी लागत काफी बढ़ गई है। बिजली के दाम चार गुना बढ़ गये हैं, यूरिया में दस रुपये कम करके दस किलो की कमी कर दी गई है, डी0ए0पी0 के दाम में 2014 से 2024 में दो गुने के अंतर है। जबकि पैदावार में कोई इजाफा नही हुआ है चार सौ से पांच सौ रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि सात वर्षो में अभी तक सरकार ने किया है। जबकि

सरकार ने चुनाव से पहले किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए अपने घोषणा पत्र में भी कहा था और यह कहा था कि हम सरकार में आने पर तीन सौ यूनिट तक के बिजली के बिल को फ्री करेंगे। इसको भी नही किया और दूसरा गांव, खेत खलिहान के लोग शिक्षित न होने पायें इसके लिए सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी कर दिया है। जिसके तहत अब जहां पर प्राथमिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल बनेंगे वहां तीस फीट चौड़ी सड़क का होना अनिवार्य है। जो गांव, गरीब, खेत खलिहान परिवार के बच्चों के शिक्षा में बहुत बड़ा बाधक है, अम्बेडकरनगर में 42 विद्यालय हैं, जिनको इस मानक की वजह से मान्यता नहीं मिल रही है। टांडा में एक शादी का मंडप बन रहा था उसको भी इस सरकार ने बंद कर दिया। मेरे दहियावार गांव में जो थिरुआ नाला है उस पर एक पुल का निर्माण का प्रस्ताव पी0डब्लू0डी0 की तरफ से प्रस्तावित है और उसको भी मंजूरी नही दी गई। बेरोजगारों के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं है। घाघरा नदी में जो लगातार कटान हो रही है महरीपुर से लेकर के केवटला तक के लिए मैंने मांग किया था माननीय मुख्य मंत्री जी से पर्सनल मिल कर मांग किया था कि महरीपुर से केवटला तक बांध बनाया जाये जिससे किसानों की फसलों को डूबने से बचाया जा सके। इसके बारे में भी बजट में कोई व्यवस्था नही है। हमारे यहां महादेवा घाट है टांडा विधान सभा क्षेत्र में जिस पर पचासों लाशें प्रत्येक दिन जलती हैं। उस घाट के सौंदर्यीकरण के लिए भी मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से मुलाकात की थी लेकिन कोई व्यवस्था बजट में नहीं हो पाई। हमारे यहां पर एक सीमेंट फैक्ट्री है उससे इतना प्रदूषण है कि आस-पास के लोगों का रहना दूभर है। किसान यूनियन के लोग टांडा हाई-वे पर लगभग दो महीने से धरना दे रहे है। शिक्षक जहां पर पूरी तरीके से अवमुक्त किये जा चुके हैं। उन विद्यालयों में पढ़ाने वाला कोई नही है।

श्री अधिष्ठाता-

आदरणीय वर्मा जी अब आप समाप्त करिए।

श्री राम मूर्ति वर्मा-

मान्यवर, मैं श्री ओम प्रकाश सिंह के बजट संशोधन प्रस्ताव को जो उन्होंने कहा है कि बजट निराशजनक है, अनुपयोगी है, इस बजट को शून्य कर दिया जाये उसका समर्थन करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रकाश द्विवेदी। श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' जी।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे 2024-25 बजट कटौती पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले चन्द लाईनें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

'दमन की बात करते हो, अमन की बात कर लो तुम।
किसी बिछड़े मुसाफिर से मिलन की बात कर लो तुम।
जमीं पर आज बैठे हैं, दिखा देंगे तम्हे एक दिन।
हमीं से है वतन जिन्दा, वतन की बात कर लो तुम।'

मा0 अधिष्ठाता महोदय, लगातार हर वित्तीय वर्ष में बढ़ते हुये बजट से, पेपरलेस और माइनॉरिटीलेस बजट से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पिछले वित्तीय वर्ष का बजट समाप्त नहीं होता, क्योंकि आँकड़ों में लम्बी-चौड़ी वाहवाही लूटने की जो आदत सरकार को हो गयी है, उस आदत को कायम रखते हुये 07 लाख 36 हजार करोड़ से भी ज्यादा लम्बे-चौड़े बजट को पेश किया गया, मगर मैं उन बेरोजगारों के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार लोग हर साल सरकार की नीतियों, बजट और उनके दावों का इंतजार करके अपनी पढ़ाई, अपने परिश्रम को पाने के लिये सरकार के संकल्प पत्र को पढ़कर इस उम्मीद से बजट को देखते हैं कि अबकी हमको रोजगार मिलेगा, अबकी मेरा इलाज होगा। ऐसे लोगों को मुँह चिढ़ाने वाले इस बजट की हम सब निंदा करते हैं। हम यह देखते हैं कि जब कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आता है। अभी-अभी यहाँ आने से पहले एक कैंसर का पेशेन्ट अपनी छोटी-सी बच्ची को लेकर मेरे पास आया था और वह मुँह से बोल नहीं पा रहा था। उस बच्ची ने कहा कि मेरे पापा के इलाज के लिये मुझे पैसा चाहिये। मैंने कहा कि बेटा, मैं मुख्य मंत्री जी से तुम्हे पैसा दिला दूँगा। वह बोली कि मुख्य मंत्री जी से मैं पाँच लाख रुपये ले आयी हूँ। मैंने बोला कि कहाँ से लायी हों तो वह बोली की महराजपुर के विधायक मा0 महाना जी के ऑफिस से मुझको पाँच लाख रुपये मिल गये हैं। मैंने कहा कि फिर गयी तो उसने कहा कि मैं फिर गयी तो उन्होंने कहा कि बेटा अब इससे आगे नहीं मिलेगा। सरकार की इतनी ही व्यवस्था है। इससे आगे क्या उसको मौत मिलेगी ? इससे आगे क्या ऐसे बीमार को मौत मिलेगी ? इलाज के अभाव में न जाने कितने बीमार ऐसे हैं जो अगर विधायक के पास आते हैं और अगर उसके पास विधायक निधि है तो विधायक अपनी निधि से तो पैसा दे देता है और उसकी जेब में जो रूपया है वह भी दे देता है, वह यहाँ बताने की बात नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि हम वायदा करते हैं कि किसी बीमार को बीमारी से मरने नहीं देंगे, उसको इलाज से वंचित नहीं होने देंगे। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान बहुत बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के लिये जब हमारे पास कोई मरीज आता है और कहता है कि विधायक जी, हमारे पेशेन्ट को भर्ती होना है, हैलट से रेफर किया गया है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास पी0आर0ओ0 साहब का एक नम्बर है। डायरेक्टर के पी0आर0ओ0 को मैं फोन करूँगा तो वह तुम्हे सम्मान पूरा देगा, लेकिन भर्ती होने की उम्मीद कोई नहीं होगी और यह सामने वाले विधायक भी आजमा कर देख लें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हृदय रोग अर्थात कॉर्डियोलॉजी का बहुत बड़ा अस्पताल है और

पूरे प्रदेश से और न जाने कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं। हमारी सरकार के समय आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने 2013 में एक अधिनियम के तहत् पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को यह प्रिविलेज दिया था कि कोई भी अपनी चिट्ठी लिख देगा तो उसके इलाज के लिये डेढ़ लाख तक के छल्ले मुफ्त डाल दिये जायेंगे। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब हम लोगों के पास कोई आता है तो इस अस्पताल की भूमिका क्या होती है, जरा सुन लीजिये और सरकार को बता दीजियेगा।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो हम पर्चा लिखते हैं, पर्चा लिखकर जब भेजते हैं तो वह दलालों के पास पहुँच जाता है और कहा जाता है कि सरकारी छल्ला अगर पड़ेगा तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। हमारे पास जब वह व्यक्ति वापस आता है या उसका फोन आता है तो मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए और आप हमें ऐसे तमाम मरीजों के पर्चे को वॉट्सऐप कर दिया कीजिए। उसके बावजूद यह दलाली प्रथा लगातार बनी रहती है। न जाने कितने लोग इस भय के डर से, इधर-उधर से अपनी सामान गिरवी रखकर पैसा लाते है। हमारे कार्यालय का एक आदमी पर्चे लिखकर दुनिया को देता था लेकिन जब उसके पिता को इलाज की जरूरत पड़ी तो उसने अपने बाप के इलाज के लिए अपनी माँ के और अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर 2 लाख 80 हजार रुपये दिये। उसका कहना था कि मुझे डर लग रहा है कि यह लोग कहीं गलत छल्ला न डाल दें। ऐसा वातावरण बनाकर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह तो मालूम हो गया कि विश्वास तो टूट गया, गरीबों का विश्वास भी टूट गया और उन लोगों का विश्वास भी टूट गया जिनको यह उम्मीद थी कि हम सरकार के पैसे से इलाज करा लेंगे। प्रयास की जहां तक बात आई, हम विपक्ष में बैठे हैं, हम यह प्रयास करते हैं कि सरकार को आईना दिखायें और जहां चूक हो रही है वहां आप अच्छा काम कर लें। लेकिन सरकार के लोग जय श्रीराम के नारे लगाने लगते हैं तब मुझको यह याद आती है कि.....

'देखो ओ दिवानों तुम ये काम न करो राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो'।

अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भगवान राम को याद करने लगते है और यहां तो यह वोट पाने के लिए भगवान का नाम याद करते हैं। लेकिन धरातल पर क्या होता है क्या आपको पता है ? अगर बुर्का पहने कोई बहन सड़क पर जा रही होती है, दाढ़ी बढ़ाये कोई भाई सड़क पर जा रहा होता है, बोलने दीजिएगा, सुन लीजिए उसकी साख और शिनाख्त को देखकर आप लोग तो वोट के लिए यह सब बाते करते हैं लेकिन वह लोग समझते हैं कि यह लोग सही हैं, वोट के बाद आप हमसे गले मिलते हैं, आप लोग तो कहते हैं कि यह हमारी सरकार की विचारधारा है क्योंकि हमें वोट बटोरना है। उस बहन से कहते हैं। कि कोई बहन नकाब पहन कर न आओ और उस भाई से कहते हैं कि दाढ़ी लगाकर और टोपी पहन कर तुम नहीं चल

सकते। अब उस हिन्दुस्तान की कल्पना होने लगी है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का जो प्रियम्बल था उससे हम बहुत दूर चले गये हैं, हम दूर क्यों चले जा रहे हैं ? आप विकास करो, आप जिस तरह भी वोट ला रहें हैं लाओ, जब ले आओ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास करो। तब तुम्हारी यह बात पूरी होगी। वोट की विचारधारा कुछ भी हो, हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन जब विकास की विचारधारा हो तो सबको साथ लेकर चलो।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मो0 हसन रूमी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट दे दीजिए मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप समय का ध्यान रखें, आपका माईक बंद कर दिया गया है, अब आपका लिखा नहीं जाएगा।

श्री प्रकाश द्विवेदी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट जो मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल निर्देशन पर सदन के पटल पर रखा गया है उसके समर्थन पर बोलने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। यह बजट बहुत खास है, खास इसलिए नहीं कि यह 7 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का बजट है। खास इसलिए है क्योंकि यह बजट राम युग का पहला बजट आया है। इस बजट में जहां पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए योजनाओं का समावेश है। विभागवार इस बात की चिन्ता की गयी है कि समाज में कहीं पर किसी भी व्यक्ति अथवा समाज के लिए कोई कमी न रह जाए। मान्यवर, मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र से आता हूँ। जहां पर 2017 के पहले पीने के पानी का संकट था और आवागमन का भी बड़ा संकट झेलना पड़ता था। 2017 के बाद बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे जिसको चित्रकूट से लेकर लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस-वे तक कनेक्ट किया गया। लगभग 7 जनपदों की कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली से जुड़ी। इसके अलावा हर घर पेय जल योजना। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि बुन्देलखण्ड के झांसी में बीडा का गठन कर औद्योगिक विकास के लिए, आवास, शिक्षा के लिए एक व्यवस्था की गयी तो नोएडा के तर्ज पर भी बुन्देलखण्ड के झांसी और आस-पास के जनपद डेवलेप होंगे। राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाला बजट है। बहुत सारे उधर के मित्र कह रहे थे, इलाज वाले भाईसाहब अभी कह रहे थे कि इलाज में 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था है। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2017 से लेकर आज तक का डाटा निकाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी

आदित्यनाथ जी की सरकार ने इलाज के लिए जितना पैसा दिया, बिना भेद-भाव दिया। जितना भाजपा के विधायकों को मिला है उतना ही विपक्ष के विधायकों को मिला है। क्योंकि उनका दिल और दिमाग राम-राम-राम-राम चिल्लाता है। कल तक आप लोग ही कहते थे कि राम लला हम आयेंगे, मन्दिर वहीं बनायेंगे, तारीख नहीं बतायेंगे। अब जब राम लला स्थापित हो गये हैं। बैठ गये है। विराजमान हो गये हैं। आप लोग अन्दर से भी चाहते थे कि आप लोग जायें लेकिन मजबूरी वोट बैंक की मजबूरी अपने बड़े नेताओं की क्योंकि उनका निर्देशन है कि नहीं जाना है। लेकिन आप कल्पना करिये कि उस दिन गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, किस तरह का हर्ष उल्लास का वातावरण था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी आखों में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय आसूं न आये हों। गली-गली भण्डारे हो रहे थे। राम नाम संकीर्तन हो रहा था। गांव-गांव मन्दिरों में भजन संकीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। यही तो राम राज्य है। एक ही पंगत पर बैठकर सभी समाज के लोग एक साथ प्रसाद पा रहे थे। कोई चीख-चीख कर थोड़ी हो रहा था।

राम-राज्य 'नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना।' इसको ध्यान में रखकर जब बजट बनाया गया। आज आप देख लें। एक-एक विभागवार हम चर्चा करें तो बुन्देलखण्ड में मैं सुन रहा था रमेश जी एक दिन कह रहे थे कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में चलिए। मैं भी इस सदन में दावा करता हूँ कि मेरी बांदा विधान सभा क्षेत्र में चलें। हर गांव एक दूसरे से कनेक्ट है, यह पिछले 5 सालों का डाटा है। आपका स्वागत है। आप आयें। रहना, खाना मुफ्त और घुमाऊँगा भी अपनी गाड़ी से। गांव-गांव की कनेक्टिविटी देख लीजिए। बिजली गांव-गांव, मजरे-मजरे, पुरवा-पुरवा पहली बार पहुंची। इसके अलावा सिंचाई के संसाधनों को अगर आप देख लें तो बाढ़ नियंत्रण के लिए मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 4 से 5 परियोजनायें हैं। अभी हाल ही में कनवारा में 12 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई है। माननीय सिचांई मंत्री जी को मैने धन्यवाद दिया कि बाढ़ से बचने के लिए बांध का इन्तजाम किया जाये। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि बुन्देलखण्ड में एक आपरेशन कायाकल्प चला। हम लोग बचपन में प्राइमरी विद्यालयों में देखते थे कि टाट-पट्टी पर बैठा करते थे। प्रथम चरण में उन विद्यालयों का कायाकल्प किया गया। टाइल्स लगाई गयीं। वहां पर बाथरूम की व्यवस्था की गयी। दूसरे चरण में बड़े व्यापक पैमाने में उन विद्यालयों में अब फर्नीचर की व्यवस्था यानी गरीब का बच्चा भी एक शानदार मॉडल स्कूल में जाकर पढ़ाई करने का काम करेगा। अन्त में अपनी विधान सभा क्षेत्र के लिए सरकार से मांग करता हूँ कि एक चीनी मिल की स्थापना की जाय, कताई मिल को विस्तारित किया जाय, बाँदा क्षेत्र के विद्युत लाइन को अण्डरग्राउण्ड किया जाय तथा दो पावर हाउस स्थापित किया जाय।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, उसी तरीके से हमारे चित्रकूट का भी विकास किया जाये क्योंकि हमारे भगवान राम साढ़े ग्यारह वर्षों से अधिक समय चित्रकूट धाम में रहे हैं। चित्रकूट धाम के मा0 विधायक जी सामने बैठे भी हैं,

अगर आप चित्रकूट के विकास को देखेंगे तो पायेंगे कि वहां पर हमारी सरकार में कितना अधिक विकास हुआ है, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, समय की बाध्यता है और मा0 अध्यक्ष जी का निर्देश आया है कि सात मिनट से ज्यादा कोई मा0 सदस्य नहीं बोलेगा। अब श्रीमती अंजुला सिंह माहौर जी बोलेंगी।

***श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-**

'सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी' उपस्थित सभी सदस्यों को राम राम। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद जो आपने लोक कल्याणकारी बजट जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और अन्त्योदय की मूल भावना और बीज मंत्र के साथ प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया है। यह शानदार बजट है इससे अच्छा और इससे उत्कृष्ट बजट कोई हो ही नहीं सकता। 'चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यहीं इल्जाम लग रहा है हम पर वेवफाई का, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का।' मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने यशस्वी योग्य वित्त मंत्री जी को जिन्होंने मा0 मुख्य मंत्री जी के सशक्त मार्गदर्शन में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों को ध्यान में रखकर राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने वाला, वर्ष 2024 की नींव को मजबूत करने वाला, समाज की उन्नति, प्रगति, तरक्की और भविष्य को तय करने वाला शानदार लोकहितकारी बजट प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से हम सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और ख्याति अर्जित करेंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ अपने मा0 विधान सभा अध्यक्ष श्रीमन् सतीश महाना जी को जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा को पूरे हिन्दुस्तान की आइडियल विधान सभा बनाया है। उनकी सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ। अयोध्या दर्शन के उनके निमंत्रण के लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जब महामहिम अभिभाषण कर रही थीं तब विपक्ष का आचरण बहुत निन्दनीय और आपत्तिजनक था। 'जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकी मति पहले हर लेही' विपक्ष के लोग नारे लगा रहे थे गो बैक, गो बैक, गो बैक' इस पर मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि 'सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तनु तीनि कर होत बेग ही नाश' मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो राम राज्य आ गया है अब यह जाने वाला नहीं है क्योंकि यह रुकने वाला है, ठहरने वाला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनता ने तो आपको कह दिया है गो बैक, गो बैक और साथ में यह भी कह दिया है कि कम से कम 50 सालों तक डोंट कम बैक। मैं अपने सभी विधायक भाई-बहनों का भी उत्साहवर्धन करती हूँ जिन्होंने सकारात्मक चर्चा इस सदन के अन्दर की है। सबसे बढ़कर मैं सराहना करना चाहती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ अपने धीर-गंभीर, योग्य, जनता पर सरल और अपराधियों पर कठोर आदरणीय मा0 मुख्य मंत्री जी की जिन्होंने मन्दिर निर्माण में महती और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न केवल मन्दिर निर्माण में वरन् वहां की व्यवस्था उच्च कोटि की हो। वहां सबको दर्शन करने और प्रसाद की व्यवस्था अतुलनीय है। देश दुनिया के सामने इससे बड़ा और अनुपम उदाहरण नहीं हो सकता है। अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ है। भव्य, नव्य और दिव्य स्वरूप में अवतरित अयोध्या धाम हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रस्थान बिन्दु है। हमारी जागृत चेतना का अलौकिक ज्योति कलश है, दृढ़ इच्छाशक्ति से बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। मन्दिर निर्माण करके असम्भव कार्य को भी सम्भव करके दिखाया गया है। कहते हैं कि 'कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों' कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असम्भव कार्य को सम्भव करके हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है।

कहते हैं कि लोग बुनियाद बनते हैं, लोग दीवारें बनते हैं, कंगूरे बनते हैं, शिखर बनते हैं। पर कलश बिरले ही बनते हैं और कलश योगी जी, मोदी जी बनते हैं। जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करें सब कोई। बिहारी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उस समय जब विपरीत सरकारें थीं पूरा माहौल अलग था। ऐसे माहौल के बीच में भारत की मूल परम्पराओं का पक्षधर बनकर खड़े होना यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वचन दिया था कि रामलला हम आयेंगे और मन्दिर वहीं बनायेंगे। कसम राम की खाते हैं मन्दिर वहीं बनायेंगे। वचन दिया था, कसम खायी थी। पूरे देश के सामने कसम खायी थी कि वहाँ मन्दिर बनेगा। कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आयी प्राण जाये पर वचन न जायी। इस अवधारणा को साकार करते हुये मंदिर का निर्माण हुआ है। यह भाजपा का मूल संस्कार है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और राष्ट्र तो बिना राम के हो ही नहीं सकता। कहते है राम हमारी मति, हमारी गति, हमारी भक्ति, हमारी आस्था है, राम हमारा कर्म, हमारा मर्म, हमारा धर्म है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्श कहाँ है और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। ऐसी अवधारणा को साकार करने वाले प्रभू पराक्रम प्रकाम हैं श्रीराम, गति, प्रगति, यति, विराम हैं श्रीराम, चित्तन, चिंतन को अतुल, असीम, अगम, प्रार्थना को प्रणाम है श्रीराम। भगवान श्रीराम का नाम स्मरण करने मात्र से कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। रामनाम मणि दीपधर जीह देह हरिद्वार और तुलसी भीतर बाहुरे जो चाहस उजियार। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा। भगवान श्रीराम के चरणों, रमन्ते इति रामा। जो सृष्टि में हैं, जो बृहमाण्ड में हैं, जिसके अन्दर रमी हुयी हैं वह राम है और राम आग नहीं है ऊर्जा हैं। राम विवाद नहीं हैं समाधान हैं। राम विजय नहीं हैं विनय हैं। राम सिर्फ हमारे नहीं हैं सबके हैं। सबमें राम और सबके राम। ऐसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट भये मैं जाना। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का शौर्य लौट आया है। सम्पूर्ण विश्व को राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होकर रहेगा। उसका प्रतीक उसका उदाहरण उसका सशक्त हस्ताक्षर राम

राज्य की संकल्पना को साकार करता है। यह भव्य रामलला का मंदिर है, हम सब राम राज्य के अन्दर हैं। कहते हैं कि दैहिक, दैविक भौतिक तापा रामराज्य काहू नहीं व्यापा। सब नर करहिं परस्पर प्रीति।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद मा0 सदस्य। इसके बाद मा0 सदस्य श्री बाबूलाल जी।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

अधिष्ठाता महोदय, एक मिनट।

श्री अधिष्ठाता-

एक मिनट नहीं, कुछ कहना हो आप कह दीजिए। समय का ध्यान रखिये। समय नहीं दिया जा सकता।

श्रीमती अंजुला सिंह माहौर-

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं।

(इसके बाद सदस्य, श्रीमती अंजुला सिंह माहौर जी बोलती रहीं लेकिन उनका माइक आफ हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

अब लिखा नहीं जायेगा। इनका माइक ऑफ कर दें।

श्री बाबूलाल-

बोलो श्री राजा रामचन्द्र जी की जय। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी मा0 विधायकों को राम-राम करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुये धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मुझे 1996 में निर्दलीय विधायक बनाकर विधान सभा में भेजने का काम किया। इसके बाद देश की जनता को प्रणाम करते हुये धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन में वोट देकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करते हुये धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने देश की जनता के लिए तमाम जनकल्याणकारी योजनायें बनाकर जनता को लाभान्वित कराने का काम किया। इसके बाद सबसे बड़ा कार्य हमारे आदरणीय मोदी जी ने और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी ने भगवान श्रीराम जी का भव्य मंदिर बनवाकर 22 जनवरी, 2024 को देश में ही नहीं पूरे विश्व को राममय बनाने का काम किया। पूरे विश्व में राम ही राम, हर जगह मंदिरों में, गलियों में और मोहल्लों में राम के नाम के तमाम कीर्तन किये जा रहे थे।

मान्यवर, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी महाराज जी का बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को आफिसों से निकालकर गांव-गांव तक भेजकर जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का काम किया है। यह पहला काम है। आज तक जितनी भी सरकारें आई लेकिन उनके द्वारा कभी भी अधिकारियों को आफिसों से गांवों में नही भेजा गया, जनता की समस्याओं को नहीं सुना गया। यह काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। उसके लिए सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्य मंत्री महाराज जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने गुण्डा एवं माफियाओं का खात्मा करते हुए प्रदेश को भयमुक्त वातावरण दिया और उ0प्र0 को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। हमारे सामने वाले भाई गो-बैक, गो-बैक की बात कर रहे थे। मैं बता दूं कि आप सभी लोग हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हम लोग किसान आदमी हैं। आज से 60-70 साल पहले बैलों द्वारा कुओं से पानी पुरखों द्वारा चर्स खींचा जाता था, तो किसान कहता था कि आये राम जी, गये राम जी। सभी लोग अपने दिन की शुरुआत राम के नाम से करते हैं। हमारे क्षेत्र में भले ही कोई विरोधी हो, वह राम-राम करके अभिवादन करता है। राम के बिना देश और दुनिया में एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। उस राम के लिए आप लोग गो-बैक, गो-बैक की बात कर रहे हो। महामहिम राज्यपाल के लिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हो सकता है कि मा0 अध्यक्ष जी मेरे शब्द को बाहर निकाल दें लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। आज हम और आप सभी लोग राम की बदौलत पैदा हुए हैं, उनके आशीर्वाद से फल-फूल रहे हैं। उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार ने पं0 दीनदयाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास से सरकार चल रही है।

आदरणीय विधान सभा अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा को अलौकिक, भव्य एवं सुन्दर बनाकर पूरे विश्व में विधान सभा का नाम रोशन करने का काम किया है। तमाम विदेशी प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को देखने के लिए आते रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी ने यह काम बहुत अच्छा किया है। आखिर में अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। मेरा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान से लगा हुआ है। 60-70 गांव ऐसे है जहां सिंचाई के पानी की दिक्कत है। किसी जमाने में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाई थी और पानी की कमी की वजह से फतेहपुर सीकरी को छोड़कर दूसरी जगह चले गये थे। मैंने कई बार सरकार से कहा भी है और आपके सामने विपक्ष के लोग मेजें थपथपा रहे थे, जब मैंने पिछले बजट में बोला था। जब इन 70 गांवों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारी जनता परेशान रहेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया और कहा कि हम इसको पूरा कराने का काम करेंगे। मड़ौली माइनर तथा जहांनपुर गूल माइनर को बढ़ाकर

किसानों की समस्याओं को हल किया जा सकता है। हमारे यहां पर पीने के पानी के लिए चम्बल से पानी की व्यवस्था कराई जाए। फतेहपुर सीकरी इलाके में कोई भी राजकीय कन्या डिग्री कालेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कन्याओं की पढ़ाई के लिए एक राजकीय कन्या डिग्री कालेज की स्थापना कराई जाए क्योंकि लड़कियां 50-50 किमी0 दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आगरा मण्डल एवं अलीगढ़ मण्डल में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में आलू के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए और आलू की सरकारी खरीद 1200 रुपये प्रति क्विंटल की जाए। और अन्त में एक बात जरूर कहूंगा हमारे ब्रज क्षेत्र का बंटवारा करके ब्रज प्रदेश बनवा दें इससे हमारी सब समस्याओं का समाधान हो जायेगा। एक बात और कहना चाहूंगा हमारी सरकार यहां उत्तरांचल लखवाड योजना सिंचाई के लिए लम्बित पड़ी है, उस योजना को लागू कराकर आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस के किसानों को लाभान्वित करने का काम करें। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने किसानों के लिए मरते दम तक लड़ाई लड़ने का काम किया, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी हो चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष को हो, चाहे किसी भी बिरादरी का आदमी हो, चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करता है। फतेहपुर सीकरी कस्बा में ए0डी0ए0 द्वारा बहुत दिक्क्त है और पुरातत्व के द्वारा बहुत शोषण किया जा रहा है उसमें महायोजना लागू करायी जाये जिससे वहां नक्शे पास हों और उसी आधार पर हमारे कस्बे का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मौके पर बोलने का समय दिया।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद बाबूलाल जी। सभी मा0 सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री संदीप सिंह-

धन्यवाद, मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज मैं मा0 ओम प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, यह विधान सभा जब से चली, इस विधान सभा में लोग जिस तरह से राम के आदर्शो के बहाने आर0एस0एस0 के एजेण्डे को लागू कराना चाहते हैं, जो विधान सभा गांव, गरीब, किसान और नौजवान के सम्मान के लिए बनाई गयी। जहां पर नौजवानों के सम्मान की चर्चा होनी चाहिए, बड़ी चालाकी से सरकार आर0एस0एस0 के एजेण्डे को जिस तरह से लागू करना चाहती हैं वह बहुत ही दुःखद है। सत्तापक्ष में बैठे कुछ हमारे शबरी परिवार के लोग भी हैं जिन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जैसे लोगों को शिक्षा नहीं ग्रहण करने दी गयी बल्कि पानी भी नहीं पीने दिया गया। यह वही देश है जहां पर बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर ने मेहनत करके शबरी की संतानों को सम्मान दिलाने का प्रयास किया था। मैं आज बड़ी

जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में राम राज्य की बात कही जाती है, कबीरदास का एक दोहा है, 'गुरू गोविन्द दोऊ खड़ें, काके लागू पायं। बलिहारी गुरू आपने, गोविन्द दीयो बताय।' लेकिन इस सरकार ने ओ0पी0एस0 (ओल्ड पेंशन) को आज तक स्वीकार नहीं किया। जिस गुरू के माध्यम से हमें ज्ञान हासिल होता है वे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आज तक सरकार को उसका ध्यान नहीं आया। हम जब शिक्षामित्रों का सवाल उठाते है तो सरकार कहती है कि इसमें मा0 न्यायालय का आदेश है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि न्यायालय ने मानदेय बढ़ाने से नहीं रोका है, अगर यह चाहें तो शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट में इन्तजाम कर सकते हैं लेकिन उस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया। ये जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन जातीय जनगणना हो जायेगी उस दिन जातियों को लड़ाकर इनको वोट लेने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि समतामूलक समाज बने, आप चाहते हो कि संविधान को लागू करने वाला प्रदेश बने, आप चाहते हो कि इस देश के अन्दर संवैधानिक व्यवस्था लागू हो तो आपको जातीय जनगणना कराकर संख्या के आधार पर सभी समाजों का हिस्सा उनको बराबर दे देना चाहिए वही असली समाजवाद है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत लम्बी-लम्बी बात ये लोग करते हैं और ऐसी बातें करते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आर0एस0एस0 का एजेण्डा है कि देश गरीब हो, गाँव गरीब हो, गाँव अशिक्षित हो, चूँकि इनको पता है कि गरीब और अशिक्षित व्यक्ति को गुलाम बनाना सरल है और आपका यह बजट बताता है कि आज ये देश को, प्रदेश को गरीबी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये अशिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिसका सीधा-साधा उदाहरण है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, आप किसानों के क्षेत्र में देख लें, इन्होंने उनके लिए कोई बजट का इन्तजाम नहीं किया। आज तीसरा बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। दो बजटों को हमने देखा है, दोनों बजटों में ये ऊर्जा के क्षेत्र में कहते हैं, आज तक गाँव के अन्दर किसी भी विधान सभा का कोई साथी नहीं बता सकता कि उनके यहाँ ट्राँसफार्मर की कोई क्षमता वृद्धि हुई हो। आज तक गाँव के अन्दर एक भी नयी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको अलग से बजट मिलता है, लेकिन हम सभी जितने विपक्ष के साथी हैं, अगर आप कहते हो, सबका साथ, सबका विकास तो हमारे भी क्षेत्र का विकास होना चाहिए, अगर आप इस बात की चर्चा करते हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चूँकि समय कम है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। ये 2025 के कुम्भ की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 का कुम्भ आदरणीय अखिलेश जी की सरकार में, हमारे नेता की सरकार में हुआ था। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो काम उन्होंने इलाहाबाद जनपद के अन्दर कराया है, वही हुआ है इस सरकार ने केवल कुम्भ के नाम पर बजट का बन्दरबाँट किया, आज तक कोई काम कराने का काम प्रयागराज में नहीं किया। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ। जब हम विधान सभा के अन्दर खड़े होते, एक घटना

याद आती है। जब-जब 27% रिजर्वेशन की बात होती है, जब-जब मण्डल की बात होती है, तब-तब सरकार की तरफ से कमण्डल की बात शुरू कर दी जाती है, क्योंकि मण्डल को दबाने का प्रयास किया जाता है। याद करते हुए मैं नेता जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि नेता जी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर सिर्फ 27 परसेण्ट आरक्षण सरकारी नौकरी में ही नहीं दिया। बल्कि शिक्षण संस्थानों में लागू करके गाँव के अन्दर पिछड़े नौजवानों के अन्दर शिक्षा में ताकत लाने का काम किया था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विकास की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ पिछली सरकार में पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री और उ0प्र0 सरकार के उप मुख्य मंत्री जब-जब चुनाव आता था तब-तब गंगा पर एक पुल बनाने की घोषणा करते थे, शिलान्यास करते थे और चुनाव बीत जाता है तो हमारे क्षेत्र के लोग उस पुल को ढूँढ़ते है, लेकिन वह पुल आज तक दिखायी नहीं पड़ा। मैं माँग करता हूँ कि जो पुल हमारे क्षेत्र के परानीपुर से खदाबाट को जोड़ने का काम करता है, उस को बनाने का कष्ट करें। हमारे यहाँ करछना विधान सभा क्षेत्र के साथी विधायक बैठे हैं, एक सड़क जो उनके क्षेत्र से निकल कर मेरे क्षेत्र से होती हुई, विन्ध्याचल को जाती है, मैं उसको स्टेट हाई-वे बनाने की माँग करता हूँ। इतना ही नहीं हमारे क्षेत्र के अन्दर तमाम धार्मिक स्थल हैं। मैं आपसे माँग करता हूँ कि उन धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल में रूप में चयनित करके उनका विकास करने का काम करें। मैं आपके माध्यम से एक और बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूँगा कि यह जो आर0एस0एस0 की मंशा है, देश को गरीब बनाने की, आर0एस0एस0 की मंशा है, आरक्षण को खत्म करने की, जिसका जीता-जागता उदाहरण वह 69000 शिक्षक है। अधिष्ठाता जी, मैं अपने आप को श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव से सम्बद्ध करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब श्री अभय सिंह जी।

***श्री अभय सिंह-**

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट की साधारण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम को नमन् करते हुए, मैं यह बताना चाहता हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि मैं उसी सूर्य वंश में पैदा हुआ हूँ, जिस सूर्य वंश में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम ने जन्म लिया था, अवतार लिया था। मैं सदन के माध्यम से मन्दिर निर्माण के पक्ष में जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया और सर्वसम्मति से दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस देश के करोड़ों लोगों को तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन करोड़ों लोगों को बहुत-बहुत बधाई और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपये की व्यवस्था किया और भव्य मंदिर का निर्माण किया, उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, जन-जन में राम हैं कण-कण में राम हैं और राम राज्य तभी आ सकता है जब आप गरीब की झोपड़ी में जाकर बैठेंगे, मजदूर और किसानों के दुख और दर्द को समझेंगे। जैसे मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम चौदह वर्ष वनवास में गए तो हिमवासी, गिरवासी और बनवासी सबके बीच में गए और जब लौटकर के चौदह साल बाद आए तो किस तरीके से चक्रवर्ती राजा बने और उनके राम राज्य की कल्पना और तुलना आज तक की जाती है, क्योंकि गांव, गरीब, मजदूर और किसान के बीच में रहे। मान्यवर, हम सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो यह बजट बना है बहुत ही लोक-लुभावन है, लेकिन इसमें वह सारी बातें नहीं है जो राम राज्य के बजट में होनी चाहिए, जो मजदूर के लिए होनी चाहिए, छात्र के लिए होनी चाहिए, किसान के लिए होनी चाहिए और नौजवान के लिए होनी चाहिए। हम सदन के माध्यम से क्योंकि सदन ऐसी जगह है, जहां पर हमें अपनी बातें बोलने का अवसर मिलता है और आज हम बोलकर के जाएंगे तो सैकड़ों साल के बाद भी लोग इसको सुनेंगे। हम क्षेत्र में जाते हैं, अपने बिरादरी के भोज में जाते हैं, वहां पर जाते हैं तो जानते हैं क्या चर्चा होती है, कहते है बहुत अच्छा होता, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया भगवान राम का मन्दिर बन गया, लेकिन हम लोगों को उपेक्षित किया गया, क्षत्रिय समाज को उपेक्षित किया गया, हमारे समाज का कोई भी आदमी आज ट्रस्ट में नहीं है इसलिए उनको बहुत दुख होता है और कष्ट होता है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पांच साल की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का मन्दिर बना। मैं भी अयोध्या से जनप्रतिनिधि हूँ और अयोध्या में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको आमंत्रित किया गया और सभी लोगों को बुलाया गया, हमारे दल के लोगों को भी बुलाया गया, लेकिन पता नहीं किस तरीके से वर्गीकरण किया गया कि हमें आमंत्रण भी नहीं दिया गया, हमसे पत्रकारों ने पूछा और कहा विधायक जी क्या हुआ आपको नहीं बुलाया गया तो हमने कहा कि जैसे हम लोग मां-बाप की सेवा करते हैं और उनसे आर्शीवाद लेते हैं, उसी तरीके से चाहे भगवान ....

(इसी मध्य 04 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पुनः पीठासीन हुए)

राम हों, चाहे माता सीता हों, चाहे हनुमान जी हों हम तो घर से निकलेंगे जाएंगे प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मान्यवर आम आदमी का उससे कोई मतलब नहीं कि आपका बजट 7 लाख 36 हजार करोड़ का है, पर कैपटा इनकम कितनी बढ़ जाएगी इससे उसको कोई मतलब नहीं है, आवश्यकता उसको है कि किस तरीके से मजदूर, किसान और आम आदमी की आय बढ़ेगी, किस तरीके से बजट, गरीब और मध्यम वर्ग में वितरित हो रहा है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम आपसे कहना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है इस बजट का लाभ गरीब आदमी को और मजदूर को और किसान को कैसे मिलेगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बड़ी रोडें बन जाएं, बड़े-बड़े पुल बन जाएं, लेकिन

अगर गांव का विकास, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो गांव वालों को कोई उससे फायदा नहीं होता है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया गांव के माध्यम से, जनेश्वर मिश्रा गांव के माध्यम से, गांव का विकास हो पाता, गांव के अन्दर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास हो पाता, जिससे गांव वालों को फायदा मिलता था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मान्यवर, अच्छा बजट वह है जिससे गांव और मजदूर के किसान की इनकम बढ़े न कि पूंजीपतियों की इनकम बढ़े। इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि गांव के मजदूर और किसान का बजट बड़े जिससे पूंजीपतियों को ही लाभ होने वाला है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इसके लिए बधाई देना चाहते है मा0 मुख्य मंत्री जी को उन्होंने ओ0डी0ओ0पी0 में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत जैसे जिले को छोड़कर अयोध्या जनपद का चयन किया ओ0डी0ओ0पी0 में गन्ने की खेती और गुड़ के लिए, लेकिन हम यह भी कहना चाहते हैं आपसे कि आज गन्ने के किसानों के बहुत बुरे हालात हैं।

पंजाब और हरियाणा में गन्ना किसानों को उनके फसल का मूल्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिल रहा है। इस बजट में उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का मूल्य ज्यादा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, हमें यह जानकर बहुत निराशा हुई, हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि आज गांव में रहने वालों के आर्थिक हालत बहुत गिरती जा रही है, वह अपने बच्चों को दिल्ली, इलाहाबाद और लखनऊ भेजकर के आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 तैयारी नहीं करा पा रहे हैं। हमारी सोच थी कि अगर आपने गांव के गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 तैयारी करने के लिए कोचिंगों में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की होती तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होता। हम आपसे कहना चाहते हैं गांव में आशा बहुएं होती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकत्री होती हैं, रसोईयां होते हैं इनके लिए इनका मानदेय बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि बजट को पढ़ करके बहुत निराशा हुई। हम आपसे यह कहना चाहते हैं मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ रही है, हमारे अयोध्या में बहुत बड़ा मेडिकल कालेज बना हुआ है, लेकिन हम प्रदेश की बात नहीं करते। सिर्फ अयोध्या की बात करते हैं कि जो मेडिकल कालेज बना है उसमें न किडनी का डाक्टर है, न हार्ट का डाक्टर है, न न्यूरो का डाक्टर है, और न कैंसर का डाक्टर है, बहुत बुरे हालात हैं वह सिर्फ एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र बनकर रह गया है। हमारा सदन के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध है कि उसमें विकास किया जाए, अच्छे-अच्छे डाक्टर भेजे जाएं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं। विकास बहुत हो रहा है। हम विकास के लिए आपको बधाई देना चाहेंगे।

पहले हमारा गांव था, छोटी सी रोड थी आगे से फोरलेन समाजवादी पार्टी ने बना दिया। हमारे गांव के पीछे से जो रोड आ रही है उसको आपने फोरलेन किया, उसके लिए भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी को जितनी रोडों के प्रस्ताव हम लोगों ने दिये थे उनको उन्होंने स्वीकृत कर दिया उसके लिए मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देना

चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ रोडों का प्रस्ताव बनकर आपके पास और आया है उसको भी स्वीकृत कर देंगे तो हम आपको डबल धन्यवाद देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं आज दलित और पिछड़े छात्रों की बड़ी दयनीय स्थिति है। 50 परसेन्ट से ज्यादा उनको शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल पा रही है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप उनको शुल्क प्रतिपूर्ति दिलवायें। एक बहुत जरूरी चीज है, सबके लिए आवश्यक है, चाहे इधर बैठे हों या चाहे उधर बैठे हों। इलाज के लिए आप सिर्फ 50 परसेन्ट देते हो। इसमें हमारा अनुरोध है कि आप प्राइवेट अस्पताल को भले पूरा पैसा न दें लेकिन जो सरकारी अस्पताल का इस्टीमेट जा रहा है उसको पूरा का पूरा दिलवाने का प्रयास करें। कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि गरीब का इलाज हो जाए क्योंकि वह पैसा नहीं दे पाता है। अगर 5 लाख का इस्टीमेट आया है और ढ़ाई लाख रुपया ही गया है तो बाकी ढाई लाख रुपया वह नहीं दे पाता है और वह पैसा आपका बाद में वापस चला जाता है हमारा अनुरोध है कि उसको आप पूरा-पूरा पैसा दिलाने का प्रयास करें जो सरकारी अस्पताल हैं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य होने हैं उसकी सूची हम मंत्री जी को दे देंगे उसको आप दिखवा लीजिएगा। जे0पी0एन0आई0सी0 मान्यवर, यह तो आप ही की बात है। उधर बहुत से लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं इधर तो कम ही होंगे उधर इस समय संख्या ज्यादा है। इतना बड़ा सेन्टर बना है कांग्रेस की दुदर्शा बताने के लिए कि इमरजेन्सी में उन्होंने क्या अत्याचार किया था, जे0पी0एन0आई0सी0 बनाने का काम करें और लोकतंत्र सेनानियों को भी भत्ता बहुत कम मिल रहा है। उनकी बहुत कम संख्या बची हुई है और वह ऐसे लोग हैं जो इमरजेन्सी में इस देश की क्या दुर्दशा हुई थी उसको अच्छे से बताने वाले लोग है। लोकतंत्र सेनानियों को भी यह जो 25000 की राशि दी जाती है उसको 30000 करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें बजट में बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा उत्तर प्रदेश को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ का शानदार बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, यह लोक कल्याणकारी बजट मा0 प्रधानमंत्री जी के 'सबका साथ सबका विकास' को चरितार्थ करता है। मा0 मुख्य मंत्री जी के उत्कृष्ट दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है यह बजट युवा, महिला और किसान को सशक्त और सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कानून व्यवस्था है कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता। कानून-व्यवस्था निरंतर पहले की तुलना में और बेहतर हो रही है। भगवान रामलला अयोध्या में

अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो गए हैं। अयोध्या के विकास के लिए एयरपोर्ट का विकास, नये सेतुओं का निर्माण, अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान का निर्माण आदि के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने विशेष तौर पर बजट का आवंटन किया है। मा0 मुख्य मंत्री जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में हमारी सरकार ने किसानों के हित में पिछले वित्तीय वर्ष में 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 831 करोड़ की क्षतिपूर्ति दी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खाते में 63 हजार करोड़ रुपये डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजे गये। 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। युवाओं के लिए प्रदेश के 117 विकास खण्डों में 124 ग्रामीण स्टेडियम और मल्टीपर्पज हाल का निर्माण कराया गया। 1 लाख से अधिक जोड़ों का विवाह मुख्य मंत्री सामूहिक योजना के अन्तर्गत किया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय कार्य हुआ है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या 4390 से बढ़ाकर 9078 की गयी है। मान्यवर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किये गये हैं। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से 1 लाख 61 हजार 962 व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता के रूप में 2765 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्तमान में प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कालेज संचालित हैं और 14 जिलों में निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 9 हजार 899 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी की अभूतपूर्व दूरदर्शिता से इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 2 हजार 57 करोड़ 76 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे व पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। सड़क एवं फ्लाईओवर के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु 13 हजार 931 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त सिंचाई, नदी में सुधार और कटाव निरोधक परियोजनाओं एवं मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 3720 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। जल जीवन मिशन हेतु 22 हजार करोड़ प्रस्तावित किया गया है। हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2400 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। 38 लाख 69 हजार गरीबों को आवास दिया जा चुका है। 17 लाख 65 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 35 हजार 236 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जा चुकी है। इस बजट में गरीबों को आवास देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी/ग्रामीण एवं मुख्य मंत्री आवास योजना के लिए 7 हजार 529 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा महाकुम्भ मेला में वर्ष 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। नगर विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों

हेतु कुल 14 हजार 723 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु 3400 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, गांव के विकास के लिए पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु कुल 23 हजार 506 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाओं के भरण-पोषण, निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह एवं छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु 13 हजार 912 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 2732 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। नारी शक्ति, शक्ति, गरीब भाई-बहन और किसानों के हितों पर केन्द्रित यह बजट निश्चित ही मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्यों को पूरा करने में उ0प्र0 अपना सर्वोत्तम योगदान प्रदान करेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। आज एक मेरे साथी कह रहे थे कि यह नाम का बजट है, न किसी काम का बजट है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह काम का बजट है और यह श्रीराम का बजट है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में अपने विकास की गंगा को बहायेगा। आने वाला समय हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अति उत्तम है और इस बजट द्वारा हम अपने विकसित भारत की कल्पना को पूरा करेंगे।

आज हमारा यह बजट गरीबों को समर्पित है और अंत तक उदय करने वाला बजट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के दो-तीन काम रखना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण समस्यायें इस प्रकार हैं। तहसील सिकन्दराराव में बस स्टैण्ड की अति आवश्यकता है, बस स्टैण्ड न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को चौराहे पर खड़े होकर घण्टों बसों का इंतजार करना पड़ता है। आये दिन जनता को जेबकटी एवं दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा मेरे यहाँ बस स्टैण्ड बनाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक हसायन के कानऊ सकरा मार्ग की दयनीय दशा है। बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा पुरदिल नगर की आबादी लगभग 15-16 हजार है, वहाँ कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इस नगर पंचायत में एक पी0एच0सी0 या सी0एच0सी का निर्माण कराया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, ब्लाक हसायन में एक 12वीं कक्षा तक कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कराया जाये। आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए अधिष्ठाता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय श्रीराम।

***श्री बाबूराम-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि वर्ष 2024-25 का 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का भारी भरकम आठवाँ बजट हमारी सरकार ने पेश किया। इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, नौजवानों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। माननीय अधिष्ठाता जी, आज मन अभिभूत होता है, प्रफुल्लित होता है, कृतज्ञ है कि पाँच सौ वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई है और सनातन का गौरव अब वापस आया है। हम सभी के लिए भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित की जाने वाली गरिमामयी, गौरवशाली, प्राण-प्रतिष्ठा एवं करोड़ों हिन्दुओं और सनातनियों की श्रद्धा का विश्वास, सर्वोच्च सम्मान का भाव लेकर दिनाँक 22 जनवरी, 2024 का दिन एक सुखद एहसास के साथ प्रारम्भ हुआ। यह बजट हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित है, यह जानकर मन आनन्द विभोर है। इसके अतिरिक्त इस बजट में हमारी माताओं-बहनों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे नौजवान साथियों का बहुत अधिक ध्यान रखा गया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री का हृदय से वन्दन, अभिनन्दन करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सारा देश-प्रदेश राममय है। मन्दिर के निर्माण के पश्चात् पुरातनकाल की अयोध्या, सरयू नगरी अत्याधुनिक रूप में विकसित हुई है, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, समस्त प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ प्रदेश का भव्य रेलवे स्टेशन, धर्म पथ का निर्माण एवं अयोध्यापुरी को विशेष पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने में हमारे युगपुरुष माननीय योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय जाता है। श्री राम मन्दिर का अभूतपूर्व निर्माण विश्वस्तरीय पर्यटन की सम्भावनाओं एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मूर्त रूप प्रदान करने की सुखद परिणति है। आगामी कुछ ही वर्षों में मथुरा एवं काशी, दोनों ही तीर्थ स्थानों पर महाराज जी के कुशल नेतृत्व में हम विजय पताका फहरायेंगे। हम सभी सनातन धर्म के उपासक आज अपने लिए गौरवशाली एवं विजय का अनुभव करते हैं। प्रदेश के विकास के संकल्प से सिद्धि तक अनेक विकास परियोजनाओं से महिलाओं, वृद्धों तथा सभी समुदाय के लोगों को लाभ मिला है।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना सबका साथ, सबका विकास करने वाली प्रदेश सरकार कठोर अनुशासन और आतताइयों का दमन करने वाली साबित हुई है। ऐसे युग पुरुष का नेतृत्व हम सभी के लिए वास्तव में अति महत्वपूर्ण एवं निर्णायक है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ समस्यायें मेरी विधान सभा क्षेत्र की हैं। पूरनपुर में को-ऑपरेटिव की सहकारी चीनी मिल जो 80 के दशक में लगी थी, उसके कलपुर्जे अत्यन्त खराब हो गये हैं। उनका नवीनीकरण कराया जाये जो किसानों के हित में बहुत प्रमुख

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। हमारा क्षेत्र और हमारी विधान सभा क्षेत्र रिजर्व टाइगर होने के कारण पास के गाँवों में टाइगर द्वारा लोगों को निवाला बनाया जाता है। इससे लोगों में आक्रोश रहता है तो उसमें तार फेन्सिंग करायी जाये। पूरनपुर एशिया का सबसे बड़ा ब्लाक है, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या-275 है, उसमें एक ब्लाक होने के कारण, शायद इतना बड़ा ब्लाक भारत में कोई नहीं होगा जो डेढ़ विधान सभा क्षेत्र में केवल एक ब्लाक है। वहाँ लोगों की मांग है कि माधौ टांडा जहाँ गोमती का उद्गम स्थल है, उस गाँव में ब्लाक बनाया जाये। पूरनपुर में माधौ टांडा क्रासिंग पर एक उपरिगामी पुल की आवश्यकता है। इसी के साथ आदरणीय मोदी जी और योगी जी के लिए इन चन्द पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 'आज आकाश में गंगा उतर आई है, राम आये हैं अवध में, तो बहार आई है।' जय हिन्द जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपने अपनी बात को समय से समाप्त किया इसके लिए धन्यवाद है।

***श्री जय कुमार सिंह जैकी-**

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के समर्थन में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में, मा0 मुख्य मंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया जी के अतुलनीय सहयोग से बनी सरकार द्वारा 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। जोकि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी के भव्य मन्दिर का अयोध्या में निर्माण होने से हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिला है। अयोध्या विश्व का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र बन गया है। यहाँ पर भारत और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिला है। हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास के नारे को चरितार्थ किया है, साथ ही हमारी नीतियाँ विशेष रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब के उत्थान को समर्पित हैं। हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए और जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को उत्तर प्रदेश में करने का जो लक्ष्य लिया है। जब इस लक्ष्य और उद्देश्य पर बात होती है तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश की आत्मा गांव और किसानों में बसती है। इसको ले करके अभी हाल ही में मोदी जी की गारण्टी का जो रथ चला उसके लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो हमारे विपक्ष के साथी इस बात को कह रहे कि गांव, गरीब और किसान का काम नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी-अपनी विधान सभा क्षेत्रों में एक बार गहन अध्ययन करना चाहिए और गांव के गरीबों के बीच में जाना चाहिए। मैं जनपद फतेहपुर से आता हूं, मेरी बिंदकी विधान सभा क्षेत्र है, मैं कुछ बोलने से पहले बिंदकी विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है। हम लोगों ने अभी हाल ही में इतनी कड़ाके की ठण्ड में विकसित भारत यात्रा के माध्यम से गांव के गरीबों में, चाहे गरीब का राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे गैस का चूल्हा या सिलेण्डर हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे निराश्रित महिला पेंशन, चाहे दिव्यांगों की पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कोई भी कल्याणकारी काम हो, गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं मिला जिसको सरकार की कोई न कोई सुविधा न मिली हो।

इस राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, अभी हाल में विपक्ष के साथी कह रहे थे, राम राज्य आयेगा, भगवान राम चौदह वर्ष वनवास में रहे, उन्होंने वनवासियों को देखा, गरीबों को देखा, शबरी के जूठे बेर खाये, उन्होंने पशु-पक्षियों सभी के लिए काम किया, उन्होंने कहा कि भगवान राम ने जो काम किया वह समाजवाद की स्थापना है, लेकिन असली समाजवाद की स्थापना योगी और मोदी जी कर रहे हैं कि कोई गरीब गांव में नहीं बच रहा, जिसको सरकार की सुविधाओं का लाभ न मिल रहा हो। इससे पहले 2014 और 2017 के पहले भी आजादी के इतने वर्ष हो गये थे, मुझे आज भी याद है कि लोग सांसदों के यहां टेलीफोन और गैस के कनेक्शन के लिए लाइन लगाते थे और उसका जुगाड़ करते थे। बड़े सम्बन्धों के आधार पर जब सांसद हाँ भरते थे तो कहते थे कि किसी से मत बताना कि हमने तुम्हें कूपन गैस का दिया है। आज लोगों को घर में गैस मिल रही है और त्यौहारों के समय में गरीब को दो सिलेण्डर फ्री मिल रहे हैं। लोग महँगाई की बात करते हैं कि गैस का सिलेण्डर महँगा हो गया, इसलिए गरीब अपनी गैस नहीं भरा पा रहा है। आज भी याद कीजिये देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति जब इस देश का प्रधानमंत्री हुआ तो उसने उन माताओं के दर्द को समझा। हर आदमी कहता है कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जिसके पास सर ढकने के लिए छत न हो, तन ढकने के लिए वस्त्र न हों, पैरों में जूते न हों, पेट भरने के लिए भोजन न हो तो बरसात के समय की लकड़ियां कभी सुरक्षित नहीं रख सकता, जिसके पास आवास न हो। ऐसी परिस्थितियों में कोई माँ अपने बेटे को भूखा नहीं सुला सकती है, कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बेटे को भूखा सुला दे। ऐसी स्थितियों में जब वह फुंकनी से फूंक करके गीली लकड़ियों से खाना बनाती थी तो कितना धुआं उसके पेट में जाता था और कितना आँखों में जाता था। डॉक्टर कहते हैं कि एक सिगरेट पीने से इतनी जिन्दगी कम होती है तो उनकी कितनी जिन्दगी कम होती होगी, उन्हें कितनी दिक्कत होती थी। 12 हजार का शौचालय हो सकता है, 12 हजार रुपया कम हो सकता है, यह प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसे

इज्जतघर के रूप में बना करके तमाम घटनाओं को रोकने का काम हुआ है। अभी विपक्ष के साथी कह रहे थे, दल की प्राथमिकताएं होती हैं, जो जिस दल से चुनकर आता है उस दल का एजेण्डा होता है, उस एजेण्डे के आधार पर लोग सदन में बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों से जब लॉबी में बात होती है तो वह कहते हैं कि यह वास्तविकता है। गरीब आदमी जब अस्पताल में जाता था। तो जब नर्सिंग होम में बिल बनता था, तो इस गम्भीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपये बनता था, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पैसे के अभाव के कारण अपने पिता को बेटा अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर वापस लाता था और नीली-पीली गोली दे करके एक आश्वासन और ग्लूकोज की बोतल अपने घर में लगवा करके जीवन और मौत का इंतजार करता था, यह वही बेटा समझ सकता है, जो आर्थिक अभाव के कारण अपने पिता का इलाज नहीं करा सकता। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब आयुषमान कार्ड दिया तो उसके घर में एक सपना आया, आज कोई बेटा अस्पताल से अपने पिता को इलाज के अभाव के कारण नहीं लाता। मेरी बिंदकी विधान सभा क्षेत्र है और मैं चाहता हूँ और मैंने पिछले सदन में भी कहा था कि जो हमारे यहां पर पुराना मुगल रोड है उसको पण्डित गयादीन दुबे के नाम से कर दिया जाए। हमारे यहां क्षेत्र में बामन इंगली है, उस बामन इंगली में अंग्रेजों ने 52 लोगों को 30 दिन तक अन्तिम संस्कार नहीं करने दिया था और उसी तरह से उनकी डेड बॉडी नीम के पेड़ पर लटकी रही थी और 30 दिन बाद हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अन्तिम संस्कार करने दिया था, उनको जिस रास्ते से गंगा के तट पर लेकर गए थे, उसका नाम जोगासिंह अटरिया के नाम से कर दिया जाए। अब समय हो गया है, मैं धन्यवाद देता हूँ।

***श्री प्रदीप कुमार यादव-**

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अभी बहुत लम्बा-चौड़ा बजट सरकार ने पेश किया अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को खेद है कि इस बजट में बेरोजगार युवा, महिलाएं, किसान व गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया गया है। यह बजट लोक लुभावना है और जब यहां हम सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बात सुनते हैं तो सामने से कभी ट्रिलियन की बात करते हैं, कभी मिलियन की बात करते हैं, कभी संस्कृत में दोहा सुनाते हैं ऐसा लगता नहीं है कि यह लोग विकास की कोई बात करें। हम लोग जब कक्षा 7 में पढ़ते थे तो हमने एक संस्कृत में छोटी सी कहावत पढ़ी थी उसमें एक गांव का व्यक्ति और विद्वान पंडित जी थे और विद्वान वक्ता ने कहा कि हमारा तुम्हारा शास्त्र हो जाए, तो गांव का जो व्यक्ति है उसने कहा ठीक है, तो विद्वान संस्कृत में लगे रहे, लगातार बोलते रहे और वहां जानवर चराने वालों के हाथ में फैसला था, तब उस व्यक्ति ने यह कहा कि-

'काला कम्बल अग्नि चक, वीवत मटका भरिये पठ'

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानि पीपल पेड़ की छाया हो, काला कम्बल बिछा हो, पानी से भरा घड़ा हो और वहां पर भोजन करें तो कितना अच्छा हो। तब उन जानवर चराने वालों ने कहा कि यह लगातार विद्वान अपने को बताता है, फू-फू करके मेरे कानों मे शोर मचाता रहा, लेकिन असली विद्वान यह है, इसने मेरे मन की बात कही, तो ऐसे ही हम कहना चाहते हैं कि इस बजट में गरीबों और किसानों की मदद होती तो सबसे बड़ा काम होता। इसमें कहा गया है कि 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बने, महोदय हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो क्रेडिट कार्ड बनते हैं आज भी वहां पर बिचौलिये और बैंक के कर्मचारी मिलकर बनवाते हैं। उस व्यक्ति का उतना फायदा नहीं होता है, जितना ज्यादा रुपया उसका कमीशन में लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां पर क्रेडिट कार्ड किसान के बनते हैं, उसमें पारदर्शिता अपनाई जाए। बहुत जगह ऐसा हुआ कि किसान की फोटो ले ली गई, उसकी फर्जी फोटो लगाकर उसके नाम से धन निकाल लिया गया, लेकिन किसान के पास जब आर0सी0 आई तब उसे पता चला, तो कम से कम इन चीजों में सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

मा0 अधिष्ठाता जी, ये सीमान्त किसान महिला-पुरुष को रु0 3000/-प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से देते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। इसकी आबादी लगभग 25-26 करोड़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस राशि को और बढ़ा दिया जाए। निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के बारे में कहना चाहते हैं कि आज भी जो गरीब लोग हैं, वह चाहते हैं कि हमारा इलाज फ्री में हो जाए। जब वह गुहार लगाते हैं, तो मा0 मुख्य मंत्री राहत कोष से या विधायक कोष से 40 प्रतिशत पैसा स्वीकृत किया जाता है। अगर उसका 10 लाख का इस्टीमेट बना, तो चार लाख स्वीकृत हो गये, लेकिन वह गरीब आदमी शेष 6 लाख नहीं वहन कर सकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कम से कम गरीब व्यक्ति को गम्भीर इलाज में, गम्भीर बीमारी में पूरा पैसा दे दिया जाए। उसका फ्री में इलाज होना चाहिए।

मा0 अधिष्ठाता जी, प्रदेश में निःशुल्क 75 जनपदों में डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, लेकिन आज भी जब गरीब आदमी डायलिसिस कराने जाता है, तो कहीं मशीन खराब बता दी जाती है, तो कहीं रजिस्ट्रेशन का बहाना लिया जाता है, तो कहीं डाक्टर न होने का बहाना लिया जाता है, लेकिन गरीब आदमी का डायलिसिस फ्री में नहीं हो रहा है। इस बजट में हमने देखा कि सैफई मेडिकल कालेज को कुछ नहीं दिया गया, जबकि सैफई का अस्पताल हर गरीब के लिए, हर व्यक्ति, हर जाति, हर वर्ग, सबका साथ, सबका विकास के साथ वहाँ इलाज होता था। कानपुर, आगरा तक के मरीज सैफई मेडिकल कालेज में इलाज कराने आते थे, लेकिन आज सैफई की स्थिति यह है कि वहाँ डायलिसिस भी नहीं हो पा रहा है।

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने कहा आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने जारी किया। हम भी कहते हैं कि अच्छी योजना है। गरीब का इलाज होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों पर आयुष्मान कार्ड है, वे जब इलाज कराने जाते हैं, तो उनके कार्ड पर इलाज नहीं होता है और प्राइवेट अस्पताल जहाँ आयुष्मान कार्ड से इलाज होता था, उन लोगों ने भी बन्द कर दिया है। डा0 बहाना ये लेते हैं कि हमने इसलिए बन्द कर दिया कि हमारा पुराना भुगतान नहीं हो रहा है। आदमी कार्ड लिए लिए घूम रहा है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो रहा है। मा0 अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि वह आयुष्मान कार्ड जिन-जिन लोगों पर है, उन गरीब लोगों का इलाज सरकार द्वारा कराया जाय।

मा0 अधिष्ठाता जी, सरकारी नलकूप, सिंचाई मुफ्त, यह सरकार के बजट में है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो नलकूप लगे हैं और जिनके खेत में लगे हैं, अगर वह नलकूप खराब हो गये, तो उसका मोटर खेत वाला ठीक कराता है। जब खेत वाला ठीक कराता है, तब वह उस सरकारी नलकूप से सिंचाई का पैसा लेकर काम कराता है। हम इसलिए अनुरोध करते हैं कि मा0 नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि जिस दिन हिन्दुस्तान में किसान खुशहाल हो जायेगा, उस दिन हिन्दुस्तान अपने आप खुशहाल हो जायेगा, ये उनका नारा था। मा0 अधिष्ठाता जी, त्वरित विकास योजना में 2400 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है और 2520 करोड़ विधायकों की क्षेत्र विकास निधि है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप अपनी बात को समाप्त करिए।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, हम अभी समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन वह 2400 करोड़ और 2500 करोड़ लगभग बराबर है। प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रुपये विधायक निधि मिलती है, लेकिन त्वरित विकास निधि हम लोगों को नहीं मिली। कहा जाता है कि जब वहाँ पर कमीशन पहुँच जायेगा, तब मिलेगा। विपक्ष के किसी विधायक को त्वरित विकास में पैसा नहीं मिला। आपसे अनुरोध है कि इसमें पारदर्शिता बरती जाए।

मा0 अधिष्ठाता जी, गेहूँ-धान की खरीद में किसान की लूट होती है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शुरू में ही कांटे लग जाने चाहिए। गौ-रक्षक केन्द्र जितने हैं, वहाँ जाकर देख लें, गायों की स्थिति बहुत खराब है। आखिरी में एक शब्द आपसे कहते हैं कि मा0 अधिष्ठाता जी हमारे विधान सभा क्षेत्र में दिवियापुर नहर के पुल से मल्हौसी नहर पुल तक पटरी का चौड़ीकरण करा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये रोड चलती है। इसमें कहीं टोल टैक्स नहीं लगता है। दिवियापुर का जो पुल है, उस स्थान को जरूर चौड़ा कर दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री देवेन्द्र सिंह लोधी-**

'बोलिये श्री रामचन्द्र की जय।' माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह रामराज्य वाला बजट है। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर बिना किसी भेद-भाव के 'सबका साथ, सबका विकास' और सबका विश्वास कायम करने वाला यह बजट है। इस बजट में जहां एक ओर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी वहीं महिला, युवा, व्यापारी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, उजड़े, पिछड़े, दबे-कुचले और अधिकारों से वंचित हर वर्ग के लोगों के लिए यह कल्याणकारी बजट है। यह बजट अन्नदाता किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां का किसान 24 घण्टे अपने खेतों में काम करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पहाड़ और पर्वतों से टकराकर अपने खून को पसीने में बदलकर साग-सब्जी, अन्न पैदा करता है और उस अन्न से पूरे देश का भरण-पोषण होता है, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमसे पीछे की सरकारें रही थीं, उनमें वह किसानों का शोषण करते थे। उन्होंने किसानों की बद से बदतर स्थिति बना दी थी। मैं अपने मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों को समर्पित यह बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने डार्क जोन में निजी कूपों के कनेक्शन देने के लिए जो प्रतिबन्ध था, उसे हटाकर लाखों किसानों को सीधा फायदा पहुंचाया है। पेराई सत्र 2023-24 में गन्ना किसानों को 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों को सीधा लाभ दिया है। मैं उनको हार्दिक बधाई भी दूंगा कि उन्होंने किसानों को समर्पित बजट पेश करके बाबूजी कल्याण सिंह जी के सपने को साकार किया है। बाबूजी कहा करते थे कि किसान उठेगा तो गांव उठेगा और गांव उठेगा तो देश उठेगा। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो बाबूजी की कर्मभूमि थी। वह राम के ऐसे परम भक्त थे कि अगर सतयुग में राम के लिए भरत ने सत्ता को लात मारी थी तो कलयुग में परमपूज्य बाबूजी ने राम मन्दिर निर्माण के लिए सत्ता को लात मार दी थी और जो राम जन्मभूमि पर कलंक लगा था, उसे सदा-सदा के लिए मिटा दिया था। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने बुलन्दशहर की एक सभा में कहा था कि आज जो यह राम मन्दिर का भव्य निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जहां भी बाबूजी कल्याण सिंह होंगे, उनकी आत्मा बहुत आनन्दित होती होगी। मैं आपके माध्यम से एक मांग करना चाहता हूँ कि अयोध्या में परम्पूज्नीय बाबूजी की मूर्ति की स्थापना की जाए। उन्होंने सदैव देश की सेवा की है और उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां गरीबों का इलाज हो सके। 70 किमी0 की दूरी पर एक अस्पताल की स्थापना की जाए। लखादु मोड़ से वशीघाट तक की रोड जर्जर है, वहां पर 10 हजार व्हीकल चलते हैं, उसका चौड़ीकरण कराने की मांग रखता हूँ। मेरे सामने जो विपक्षीगण बैठे हैं, उनसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको राजा सिकन्दर से भी सीख लेनी चाहिए। राजा सिकन्दर ने जीवित काल में यह कहा था कि- 'आई एम गॉड, गॉड इज नथिंग' और जब उसका अन्तिम समय आया तो उसके पीछे भी राम नाम सत्य है के नारे लगाये गये थे। जब विपक्षीगणों का अन्तिम समय आयेगा तब इनके पीछे भी राम नाम सत्य है के ही नारे लगेंगे, इसलिए भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी कन्या डिग्री कालेज नहीं है। कन्या डिग्री कालेज का निर्माण होना जरूरी है और यहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी प्रॉब्लम रही है जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं एक मेडिकल कालेज की मांग करता हूँ। अधिक न कहते हुए समय के अन्दर ही मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। जय हिन्द जय भारत।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 श्री प्रदीप शुक्ला जी अब आप बोलिए।

श्री प्रदीप शुक्ला-

मान्यवर, आपने हमें 2024 2025 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो पांच सौ वर्षों की तपस्या थी प्रभु श्रीराम अपने दिव्य घर में आये इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री पूज्य महाराज जी का अपनी विधान सभा क्षेत्र की तरफ से हृदय से अभिनन्दन और वन्दन करता हूँ। जब चौदह वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्रीराम लंका पर विजय कर के अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी उसी तरह 2017 में जब पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो अयोध्या में दीप जलाकर उस त्रेतायुग को कलयुग में उतारने का काम पूज्य महाराज जी के द्वारा किया गया। आज जो बजट हमारे पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और हमारे यशस्वी वित्त मंत्री ने पेश किया है। यह बजट देश के सभी प्रदेश के जितने हमारे नवयुवक हैं हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, जो दीनदयाल जी का सपना था कि अन्तिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी उसका लाभ ले, वह आज प्रदर्शित हो रहा है, हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के पूरे गांव-गांव में विकसित भारत यात्रा जो मोदी की गारण्टी वाली गाड़ी चली है देश में आजादी के बाद पहली बार गांव-गांव जाकर सभी विभागों को बैठाकर गांव में जिन्होंने योजनाओं का लाभ पाया है, जो नहीं पाया है वह अपना रजिस्ट्रेशन कराये और उसका लाभ पाये। यह देश में प्रदेश में पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति जब दस वर्ष कार्य करता है जब उत्तर प्रदेश की सरकार में सात साल जो व्यक्ति कार्य करता है वह जाकर गांव में लागों से संवाद करता है कि बताओ योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला पूरे प्रदेश के लोग गांव-गांव महिलाएं आ करके

कहीं कि मुझे योजना का लाभ मिला है। आज विकास के क्रम में हमारा सहजनवा विधान सभा क्षेत्र है गोरखपुर का जो एक औद्योगिक क्षेत्र है आज पूज्य महाराज की कृपा से पूरे विधान सभा क्षेत्र की एक-एक रोड चमचमाती हुई रोड बनकर तैयार है। कोई ऐसा मुख्य मार्ग नहीं है जो पूरे विधान सभा क्षेत्र में खराब हों या उजड़ा हुआ हो। आज औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते 1989 में इसकी स्थापना हुई और 2017 सत्ताइस साल तक केवल औद्योगिक क्षेत्र का नाम रहा। वहां कोई उद्यमी जाता नहीं था सपा और बसपा की सरकार में केवल माफियाओं के नाते वहां बड़े-बड़े उद्यमी नहीं जाते थे। उद्योग नहीं लगाते थे उनसे महीना वसूला जाएगा उनको लूटा जाएगा और जो बची दो-चार-पांच कम्पनियां थी उसका बँटवारा कर लेते थे।

आज 2017 के बाद उस गीडा में नोएडा के तर्ज पर विकास हो रहा है आज बड़ी-बड़ी कम्पनियां वहां पर आ रही हैं जो अपने उद्योग लगा रहे हैं। आज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में लाखों लोग वहां रोजगार पा रहे हैं। आज हमारे पूर्वान्चल के जो नौजवान हैं उनको बाहर नही पलायन करना पड़ रहा है, आज उस विधान सभा क्षेत्र में पचास हजार लोग ऐसे हैं जो बाहर से आकर के दूसरे प्रदेशों से आकर के वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पूर्वान्चल के लोगों को दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़ता है आज जो पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में यह अब विकास हुआ है। जो यह विकास के क्रम में आज हर गरीब को पांच लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में पांच करोड़ से अधिक परिवारों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ पाया है मुझे वह भी दिन याद है 2017 के पहले जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था तो लोग साहूकारों से 25 हजार, 50 हजार कर्ज लेकर अपने परिवार का इलाज कराते थे और जब कर्ज नहीं भर पाते थे तो उनको अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था। मातायें-बहनें अपना जेवर गिरवी रखती थीं, लेकिन वर्ष 2017 के बाद आज पूज्य महराज जी की सरकार में किसी गरीब को खेत गिरवी नहीं रखना है, माता-बहनों को अपना जेवर नहीं गिरवी रखना है। पाँच लाख का कार्ड बना करके सभी गरीब लोगों को दिया जा रहा है। विकास के क्रम में आज पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। आज हम मन्दिरों का भी निर्माण कर रहे हैं। वे क्रान्तिकारी जो देश की आजादी के लिये शहीद हुये, उनकी स्थली का भी हम निर्माण कर रहे हैं। आज चौतरफा विकास चल रहा है। लोग हिन्दू-मुसलमान की बात करतें हैं। आप गोरखपुर आईये। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे क्रान्तिकारी थे, उनको जेल में फांसी दी गयी थी। वर्ष 2017 के पहले वह स्थली बन्द रहती थी, लेकिन पूज्य महराज जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद उसको पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया गया ताकि लोग वहाँ जायें, दर्शन करें और देखें कि जिन्होंने आजादी के लिये अपनी जान गँवायी है, उनके सबसे करीबी मित्र अशफाक उल्ला खाँ के नाम से वहाँ पर चिड़ियाघर बनाया गया है ताकि गोरखपुर में पं0 राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खाँ की वह जोड़ी बनी रहे।

आज विकास के क्रम में पूज्य महराज जी के द्वारा सहजनवा विधान सभा क्षेत्र में चारो तरफ से फोर लेन का जो निर्माण कराया गया है, गीडा का आज जो विकास हुआ है,

बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ आ रही हैं और वह बड़े-बड़े उद्योग लगा रही हैं जिससे कहीं न कहीं सहजनवा विधान सभा क्षेत्र में बाजार को लेकर, रोजगार को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर जो सुधार हो रहा है, उसके लिये मैं पूज्य महराज जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। आज सहजनवा में लोग आ रहे हैं। जो हमारा एन0एच0-27 रोड है, उसके दोनों तरफ गीडा बसा हुआ है, ट्रांसपोर्ट नगर भी वहीं पर है। मेरा केवल एक आग्रह है कि कालेसर से लेकर जीरो प्वाइंट सहजनवा भीटी रावत तक ओवरब्रिज बनाया जाये, क्योंकि गीडा का जो विकास हुआ है, वहाँ पर जो पब्लिक बढ़ी है, गाड़ियाँ बढ़ी हैं, उनको आने-जाने में दिक्कत हो रही है। कहीं न कहीं जब लोग बढ़े हैं तो बाजार में भीड़ बढ़ी है और क्रॉस करने में जो हमारी 100 मीटर की दूरी है उसको पार करने में 10 किलोमीटर लग रहा है। इसलिये ओवरब्रिज बनाया जाये, यह मेरा आपसे आग्रह है और हमारे क्षेत्र में एक कटका गाँव है वहाँ पर एक कटका पुल है। उस पुल का निर्माण कराया जाये और गोरखपुर से खजनी रोड पर अगर आप जायेंगे तो नगवाँ से खजनी तक दोनो किनारों पर नाली का निर्माण कराया जाये, वहाँ पर रोड बनकर तैयार है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य श्री मोहन वर्मा जी।

श्री मोहन वर्मा-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण को जय श्रीराम करता हूँ। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश के मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा 07 लाख 36 हजार करोड़ से भी अधिक का जो अब तक का सबसे बड़ा बजट रखा गया है उस बजट में प्रदेश के किसान, मजदूर, महिलाओं, नौजवान साथियों का ध्यान रखा गया है। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे दवाई का क्षेत्र हो, चाहे सड़क-स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे नौजवानों के रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे बिजली-पानी की व्यवस्था हो, चाहे पर्यटन के विकास की व्यवस्था हो, इस बजट में सभी कुछ देखने को मिला है। यह बजट पूर्व बजट से लगभग 46 हजार करोड़ अधिक का बजट है।

मान्यवर, वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकारें चलती थीं वह गुण्डों और माफियाओं की सरकारें चलती थीं। पहले बीमारू प्रदेश में यह प्रदेश गिना जाता था। आज मुझे गर्व होता है कि ऐसे प्रदेश के मुखिया मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 से लगातार सरकार चल रही है। विपक्ष के साथियों को नजर उठाकर देख लेना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? अभी माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा था विपक्ष के साथी कह रहे थे कि महिलाओं की सरकार नहीं चलेगी, नौजवानों की सरकार नहीं चलेगी, गरीबों की सरकार नहीं चलेगी। इनको तो गुण्डों और माफियाओं की सरकार की जरूरत है। जहां तक विकास की बात है मैं कुशीनगर जनपद से आता हूँ जो कि बिहार के

बार्डर से लगा हुआ है। मेरी विधान सभा क्षेत्र जनपद कुशीनगर में हांटा है। अभी विपक्ष के साथी पी0डी0ए0 की बात कर रहे थे। मैं उनको बता दूँ कि पी0डी0ए0 तो भारतीय जनता पार्टी में निहित है जिसका मै जीता-जागता उदाहरण हूँ। मैं स्वर्णकार समाज से आता हूँ। आजादी के बाद पहली बार मेरे समाज के लोगों को भरतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे यहां पहुँचाया है। मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का नमन-वन्दन करता हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इतने बड़े सदन में मुझे भेजने का काम किया है, पी0डी0ए0 तो यहां पर दिखाई दे रहा है। जो बिन्द, मल्लाह, गोड़, चौहान, चौरसिया समस्त लोगों को लेकर चलने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पी0डी0ए0 तो यहां देखने को मिल रहा है। हमारा पहली बार इस सदन में आना हुआ है, हम सोच रहे थे कि सदन में चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या मिला? यहां पर विपक्ष के साथियों को भी धैर्य का परिचय देना चाहिए। क्योंकि एक समय मेरी भी पार्टी के लोग विपक्ष में रहते थे। अभी कुछ साथी दवा के बारे में बोल रहे थे।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपनी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 700 लोगों को लगभग 10 करोड़ रुपया मा0 मुख्य मंत्री राहत कोष से दिलवाने का कार्य किया है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। आपको बुराई करनी है तो आप करते रहिए। क्योंकि तुलसी दास जी का एक दोहा है कि 'बरषत हरषत सब लखै करषत लखै न कोई। तुलसी प्रजा-सुभाग तें भूप भानु सम होइ।' क्योंकि देश का राजा यदि कर वसूलता है और उसका सही उपयोग श्री राम जन्म भूमि पर भव्य राम लला की मूर्ति बनाने में लगता है, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरीडोर बनने का कार्य होता है। मथुरा में श्री कृष्ण स्थान विकसित होने का कार्य होता है तो इनको कष्ट होता है। यह कष्ट इनको इसलिए होता है, क्योंकि इनके समय में कर लिया जाता था, लेकिन सैफई में नंगा नाच कराया जाता था, जो व्यक्ति नंगा नाच देखता था, नर्तकी नचाता था, एक्का मागंता था उस व्यक्ति को रामलीला एवं कृष्णलीला से क्या मतलब है ? मैं बताना चाहता हूँ कि इस बजट में मेरे जिले को भी बहुत कुछ मिला है। अभी कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपया मिला है। जो कुशीनगर जनपद कभी बीमारू जिले में गिना जाता था, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं था आज वहां पर अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अण्डा बनके तैयार हुआ है। वहां से उड़ान शुरू हो गयी है। इतना ही नहीं अभी एक महीने पहले हम लोगों का विकसित भारत के तहत् गांव-गांव जाना हुआ। गांव के लोग चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान हों उन लोगों ने कहा कि यह पहली ऐसी सरकार है जो हम लोगों के बीच आकर पूछती है कि कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। जिस योजना का लाभ नहीं मिल रहा होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सहित लगभग 17 विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उन लोगों को लाभ पहुँचाने का काम कर रहे थे। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी विधान सभा क्षेत्र की विकास की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। क्योंकि इस सत्र में मेरी हांटा तहसील को बस अण्डे की

स्वीकृति मिली है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में राज्य योजना में 48 करोड़ रुपये के लागत की सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली। इसी के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हेतिमपुर में मुक्ति धाम बनकर तैयार है और संचालित भी है। वहां आने-जाने का मुख्य रास्ता नहीं है। वहां रास्ता बनवाने का कार्य करें। हाटा विधान सभा क्षेत्र में अहिरौली थाना जो नगर पंचायत के सारे मानकों को पूरा करता है। आपके यहां पत्रावली आई हुई है केवल कैबिनेट में पास कराना है। उसको पास कराने की कृपा करें। इसी के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः आप सबका अभिनन्दन, वन्दन करते हुए इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूँ। वन्दे मातरम्। जय श्री राम।

***श्री अशरफ अली खान-**

धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट 2024-25 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं बजट पर बोलने से पहले एक बात यहां सदन में रखना चाहता हूँ।अभी पिछले माह जनवरी में हमारी केन्द्र सरकार ने दो-दो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी एवं लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिये हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमे बड़ी खुशी है कि केन्द्र सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। आज मैं सदन से सरकार से यह चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से केन्द्र सरकार को जाये जिसमें यह मांग की जाये कि हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाये। यह हम सब लोगों की मांग है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं। उन्होंने किसानों, गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए अपना पूरा जीवन लगाया है। मैं समझता हूँ कि वे भारत रत्न के हकदार हैं। मैं बजट पर आते हुए कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 लाख 36 हजार करोड़ का बजट लिया है जिसमें शिक्षा के ऊपर 76 हजार 35 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर सरकार द्वारा शिक्षा का पूरा बजट खर्च किया जाये। अफसोस तब होता है जब एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत जो हमारे राजकीय इण्टर कालेज थे। जिनकी आधारशिला 8-9 साल पहले रखी गयी थी। वे आज तक न बनकर तैयार हुए हैं न उनमें शिक्षण कार्य शुरू हुआ है। क्योंकि 8-9 साल पहले के इस्टीमेट हैं। उस पैसे में वह काम पूरा नहीं हो पा रहा है। 65 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 35 प्रतिशत राज्य सरकार का पैसा होता है। मेरा सरकार से निवेदन है, यह दरख्वास्त है कि अविलम्ब उनको पूरा कराने का काम किया जाये। ऐसे तीन राजकीय इण्टर कालेज मेरी थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। बलठेडी में, हसनपुर लुहारी मे, भासावीपट्टी में हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वे बनकर पूरे हों और उनमें शिक्षण कार्य पूरा हो सके। ऐसे ही न जाने कितने आई0टी0आई0 हैं। सोन्ता रसूलपुर का आई0टी0आई0 2014 से बनकर तैयार है। बिल्डिंग कम्पलीट है। मगर यह नहीं पता कि उसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षण कार्य क्यों नहीं शुरू हो पाया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 22 हजार करोड़ रुपया 2024-25 के बजट में रखा गया है। मगर जब हम गांव में जाते हैं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में 119 गांव हैं। कोई गांव नहीं है जहां सड़क की दोबारा मरम्मत की गयी हो। हर सदन में सवाल लगते हैं, हर सत्र में सवाल लगते हैं। मगर वहां देखने में यह आता है जो गांव में नई-नई सड़के थीं। नई-नई सी0सी0 रोड बिछीं थी। बड़ा अफसोस होता है जब हम जाकर उनको देखते हैं कि किस तरीके से उनकी कटिंग हुई है और उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक ज़ल जीवन मिशन पूरा होना है, लेकिन इसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। जब तक वह पूरा हो तब तक के लिए मेरी मांग है पहले जैसे प्रत्येक विधायक को 200 नल दिये जाते थे उसी प्रकार से सभी विधायकों को नल दिये जाये। हम विधायकों के पास बहुत बड़ी संख्या में लोग नल मांगने के लिए आते हैं और गर्मी का मौसम भी आने वाला है। सब जगह टंकी से हर घर नल की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। गांव से बाहर कई एरिया ऐसे होते हैं जैसे कहीं बस स्टाप है, कहीं श्मशान है, कहीं कब्रिस्तान है तो वहां तक पाइप लाइन से पानी नहीं पहुँचा सकते इस लिहाज से विधायकों को 200 नल जो पहले से दिये जाते थे वह दोबारा से दिये जाने की व्यवस्था की जाये। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं गन्ना की समस्या पर कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में 46 लाख गन्ना किसान हैं और हमारे नेता माननीय अजीत सिंह जी जब उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने मिल की दूरी 40 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दी थी और वह इसीलिये की थी कि क्योंकि हमारा किसान परेशान रहता था। मिलें कम थी, सेण्टर ज्यादा लगते थे, ट्रांसपोर्टेशन की सही तरीके से सुविधा नहीं थी, किसान का गन्ना नहीं पहुँच पाता था, तो उस समय मिलें बढ़ाई गई थीं और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14-15 मिलों को लाइसेंस दिये गये थे। उत्तर प्रदेश सरकार का इतना भारी-भरकम बजट है और अभी भी 4000 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का मिलों पर बकाया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम पांच-छह हजार करोड़ का कोई ऐसा कोष बनाया जाये जिससे कि उन किसानों का पेमेण्ट हो सके जिनका पेमेण्ट नहीं हो पा रहा है। बाद में सरकार वह धनराशि मिलों से वसूल कर ले। यह बहुत जरूरी विषय है। मैं नगर विकास विभाग की बात करता हूँ। सरकार ने नगर विकास विभाग के लिए 25698 करोड़ रुपये का आवंटन रखा है। आप देखें कि 10 स्मार्ट सिटी को केन्द्र सरकार ने 20000 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में नगर निगम, नगर पालिका परिषद् और नगर पंचायतें हैं। राज्य वित्त आयोग से जो पैसा मिलता है उसमें तनख्वाहें भी सही तरीके से नहीं दी जा रही हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस मद में धनराशि में अधिक बढ़ोत्तरी की जाये। अब मैं अपने क्षेत्र की दो-तीन समस्यायें रखकर अपनी बात समाप्त करूँगा। हमारे यहां शामली में कलेक्ट्रेट चौराहा है वहां पर दुर्घटनायें होती रहती हैं इसलिये वहां पर पुल बनना बहुत जरूरी है। हमारे यहां भैसवाल शामली रोड है उस पर भी पुल बनना बहुत

जरूरी है। शामली गढ़ी गुप्ता मार्ग है उस पर पुल बनना जरूरी है। टपराना क्रासिंग है इस पर भी पुल बनना जरूर है, क्योंकि यहां पर बहुत दुर्घटनायें होती हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका दिल से गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया।

***श्री रफीक अंसारी-**

'मेरी तकदीर के मालिक, मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हिस्से पर हिन्दुस्तान लिख देना, कहीं राम लिख देना कहीं रहमान लिख देना।' मा0 अधिष्ठाता जी, आजादी के बाद जब यह मुल्क आजाद हुआ और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ। हम अपनी मर्जी से यहां पर रहे। सबकी च्वाइस थी कि किस को पाकिस्तान जाना है और किस को यहां रहना है। हमने अपनी मर्जी से हिन्दुस्तान को चुना। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहर लाल नेहरू और गाँधी जी ने कहा था कि ऐ हिन्दुस्तान के मुसलमानों, आप इस वतन को छोड़कर मत जाइये। आपके अब्बा जो कब्रिस्तान में दफन हैं वह बारावफात को आवाज देंगे कि कहाँ जा रहे छोड़कर, मस्जिदों की मीनारें आवाज देंगी कि कहाँ जा रहे हो छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद सिर पर पोटलियाँ बांधकर हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन ईमानदारी से और इन्साफ के साथ हम अपने हिन्दुस्तान में कायम रहे और इसलिए कायम रहे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बँटवारा हुआ और कराची से लेकर देवबंद तक हिन्दू और मुसलमानों को फांसी पर लटकाने का काम अंग्रेजों ने किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बराबर के हक पर हिन्दू और मुसलमान शहीद हुये तो आज मुसलमानों को सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही है। क्यों इनका हक मारा जा रहा है, क्यों इनके साथ नाइन्साफी की जा रही है क्यों उन पर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने क्या बिगाड़ा है, क्या हमारा यही कसूर है कि हमने हिन्दुस्तान को चुना। आज हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है। आज मुसलमान दहशत और खौफ के माहौल में जी रहा है। जब बेटा घर से निकलता है तो उसकी माँ शाम को इन्तजार करती है कि मेरा बेटा हिफाजत से है या नहीं वह दरवाजे पर खड़े होकर दुआयें मांगती है कि हे अल्लाह मेरे बेटे को सही-सलामत घर भेज देना। आज हम इस मुल्क में रहकर हिफाजत से नहीं हैं। इस मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। लेकिन आज बजट में देख लीजिए, बजट में माइनॉरिटी के लिए क्या रखा है, मदरसों के लिए क्या रखा है, मस्जिद के लिए क्या रखा है। मा0 अध्यक्ष जी, आज क्यों नाइन्साफी हो रही है हमने क्या बिगाड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि गाँधी जी अब आकर देख लो अपना हिन्दुस्तान, कैसे-कैसे आपके चेले हो गये बेईमान। आज गाँधी जी ऊपर से सब देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर क्या हो रहा है। राम-राम कर रहे हैं। राम तो सबके हैं। किसने कहा कि राम उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हैं। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, भगवान सबके हैं और सबका एक है, सबका नाम है अल्लाह, भगवान सब अपनी-अपनी जुबान से पुकार रहे हैं अल्लाह और भगवान। मैं पूछना चाहता हूँ कि सांस रुकती है तो आपके बीच में कौन आता है। लेकिन अल्लाह और भगवान सबके एक है, लेकिन तुम लोगों ने हमें बाँट दिया। राजनीति के लिए, अब 2024 का चुनाव आया है, पूरे देश के अन्दर राम-राम, अरे, हम भी तो अल्लाह वाले हैं हम भी तुम्हारे हैं, हम किसके हैं। लेकिन हमें बाँट रहे हो तुम। हमें काट रहे हो तुम। हमें मिटा रहे हो तुम। हम मिटने वाले नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, पीठ की ओर बात करें।

श्री रफीक अंसारी-

दो-चार चाहे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली फ्री देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली सबसे महंगी है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अन्दर है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज बिजली के नाम पर कितनी लूट हो रही है। छापे मारे जा रहे हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि के बाद बुनकर समाज का नम्बर आता है। आज बच्चा जब पैदा होता है तो बुनकर समाज के कपड़े की जरूरत पड़ती है और जब आदमी मरता है तो कफन की जरूरत पड़ती है जो बुनकर तैयार करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बजट के अन्दर क्यों बुनकर का नाम नहीं है। क्यों बुनकर को गायब कर दिया गया। गांधी जी को भी कपड़ा पहनाने का काम बुनकर ने ही किया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2006 में मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लेट रेट पर बिजली देने का काम किया और नई जिन्दगी देने का काम बुनकरों के लिए किया। 65 रुपये और 130 रुपये में बुनकर को लाइट देने का काम किया। आज इस सरकार ने 65 रुपये के 400 रुपये और 130 रुपये के 800 कर दिये। यह कैसा इन्साफ है। कृषि के बाद बुनकर समाज का नम्बर है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने बुनकर का खून चूसकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश और देश-दुनिया के अन्दर बुनकर ने बनारसी साड़ी का नाम रोशन किया है बनारस, जहाँ से इस देश के प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़ा, यह उनको भी हराने का काम पूरा कर रहे हैं।

मान्यवर, बनारस के अन्दर भारी तादाद में बुनकर समाज रहता है। बनारस, मऊ एवं टांडा के अन्दर बुनकर समाज रहता है। अगर बुनकर समाज नहीं बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी नहीं बढ़ेगा और अगर उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी तो बुनकर की तरक्की होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि 'अब थकन पांव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ ये कहता है कि चलते रहिये।' उत्तर प्रदेश के अन्दर बुनकर समाज को मिटाने का काम किया गया है। हमारा

मुकाबला गुजरात एवं महाराष्ट्र से है क्योंकि वहां पर धागा सस्ता है और उत्तर प्रदेश में धागा महंगा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यह लोग बुनकर समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। बिजली की कीमत को क्यों नहीं घटा रहे हैं। पूरे देश के सभी राज्य के अन्दर बिजली की कीमत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। मेरे यहां पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज हैं, जहां पर 2000 लड़कियां पढ़ती हैं और वह सभी माइनॉरिटी की लड़कियां हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 12 ही अध्यापक नियुक्त हैं। इनका 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ' का नारा कहां है ? जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं होंगे, सरकार के स्कूल में अध्यापक नहीं होंगे तो फिर बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ कहां से हो पायेगा। मैं सिर्फ एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

'हम हक के सौदाई हैं, बातिल को मिटा डालेंगे,
हमने जिस दौर को चाहा है, बदल डाला है,
जिस दौर को चाहेंगे, बदल डालेंगे।'

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा-

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर धन्यवाद देने के लिए समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सदन में जो बजट पेश हुआ है वह एक ऐतिहासिक बजट है। जिसमें प्रदेश के उन्नति एवं विकास का और देश में प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं एवं नौजवानों का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है। यह सर्वस्पर्शी और सर्वहिताय वाला बजट है। इस बजट में हर क्षेत्र में विकास की परिकल्पना की गयी है। देश को मोदी जी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया गया है। उसमें हमारी योगी सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि उस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी में उत्तर प्रदेश से 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी देंगे और हम लोग यह जरूर करेंगे क्योंकि यह योगी की सरकार है। आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट पेश किया है और योगी सरकार जो कहती है वह करती है। हम वर्ष 2017 के पहले कल्पना करें तो उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश था, अपराधियों का बोलबाला था। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सुशासन है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है। हमारे प्रभु श्रीराम 5 शताब्दियों तक टेण्ट में विराजमान थे। हम लोग उसके साक्षी बने है कि उनके लिए भव्य मन्दिर बनाकर प्राण-प्रतिष्ठा करने का कार्य हुआ है। हम लोगों के लिए यह गौरव का क्षण है कि हम लोगों के समय में, हम लोग कहा करते थे कि 'रामलला हम आयेंगे और मन्दिर वहीं बनायेंगे' और हमने करके दिखाया है। इसके हम लोग गवाह और साक्षी बने। उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में एक उभरता हुए प्रदेश है, अग्रणी

प्रदेश है, सुशासन का प्रदेश है। यहां पर महिलाओं, बच्चों, गरीबों, किसानों का हर वर्ग का ख्याल रखा जाता है। यह जो बजट पेश हुआ यह बजट पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का आइना है। इसमें हर बात का ख्याल रखा गया है। मैं वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट के समर्थन में बोल रहा हूँ। देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप में मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि आने वाले वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनायेंगे, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में रामराज्य की संकल्पना, जो हम लोगों के मन में है, उस रामराज्य की संकल्पना को पूरा करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का बजट है। विकास एवं विरासत का बजट है। आशा और पुरूषार्थ का बजट है। हर वर्ग के विश्वास का बजट है और उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने वाला बजट है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ वह फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र है, वह बिहार की सीमा से सटी है, वहां पर जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की निर्वाण स्थली है।

मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूँ कि फाजिलनगर का नाम जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में पावापुरी उसका नाम हुआ करता था, उसका नाम पुनः पावापुरी करने का काम किया जाये। इससे वहां के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड हब की बात चल रही थी, उसके लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें थोड़ी गति लाई जाये। हमारी विधान सभा क्षेत्र में सुमही बुजुर्ग ग्राम सभा में बिजली की समस्या के समुचित समाधान के लिए एक 33 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना आवश्यक है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है उस क्षेत्र तुर्कपट्टी महुंअवा ग्राम सभा में घनी आबादी है और नगर पंचायत के सारे मानकों को पूरी करता है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाये। हमारी विधान सभा में एक खनुआ नाला है जो दो विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर और पथरदेवां को जोड़ता है। यह फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर जनपद में है, पथरदेवा देवरिया जनपद में है, उसके बीच में यदि पुल की स्थापना अगर होती है तो निश्चित रूप में आवागमन की सुविधा आसान हो जायेगी। पुल तो वहां पर है, लेकिन पतला पुल है उसका चौड़ा किया जाना आवश्यक है। हमारा क्षेत्र जो है वहां केले, हल्दी, ड्रैगन फूट, स्ट्राबेरी की खेती के लिए काफी सम्भावना है...

श्री अधिष्ठाता-

अपने एक-दो प्वाइंट रखकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा-

उसकी उचित मार्केटिंग के लिए व्यवस्था की मांग करता हूँ। ज्यादा कुछ न कहते हुए, बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री अंकुर तिवारी-**

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अधिष्ठाता जी, आज आपने बजट 2024-25 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया यह बजट रामराज्य की और विकास की अवधारणा वाले शानदार बजट की तरफ है। माननीय अधिष्ठाता जी, जन-जन के आराध्य प्रभु श्रीराम लगभग 500 वर्षों के बाद आज अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। मान्यवर, हम अपनी विधान सभा क्षेत्र (313), खलीलाबाद की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति में उन्होंने जो यह प्राण-प्रतिष्ठा की, आज पूरी दुनिया में आस्था का एक जन-सैलाब उमड़ रहा है। मान्यवर, भारत देश के प्रत्येक प्रदेश के श्रद्धालु, रामभक्त अयोध्या पहुँच रहे हैं। मान्यवर, ऐसा लग रहा है कि आज सभी सड़कें अयोध्या की ओर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी रेल और जहाज अयोध्या के लिए चल रहे हैं। मान्यवर, आज आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा-वृन्दावन में आज जो ताँता भक्तों का लगा है, वह इससे परिलक्षित हो रहा है। मान्यवर, देश का पसंदीदा पर्यटक स्थल आज अयोध्या-धाम बन चुका है और हमारी सरकार आस्था, धर्म के साथ-साथ विकास के नए मानक को भी छू रही है। मान्यवर, शबरी माता के नाम से रसोई घर का आरम्भ हो चुका है और निषादराज के नाम से रैन बसेरा का वहाँ निर्माण हो चुका है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह है असली पी0डी0ए0 और पी0डी0ए0 जो हमारे विपक्ष के लोगों का, सपा का पी0डी0ए0 है, मैं वह बताना चाहता हूँ, पी0डी0ए0 उन्होंने परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बनाया है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा धर्म का कार्य, विकास का कार्य, जनहित का कार्य किया जा रहा है और तभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो भरोसा आज उन्होंने जताया है, कल विधान सभा में उन्होंने कहा कि 'हमने वचन निभाया है, मन्दिर वहीं बनाया है।' मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमारे एक सदन के साथी कह रहे थे, उन्होंने आर0एस0एस0 के बारे में कुछ टिप्पणी की। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने आर0एस0एस0 के बारे में जो बोला है-'आधी गगरी छलकत जाय', यह स्थिति है। आर0एस0एस0 के बारे में उनको और जानना चाहिए। मान्यवर, आर0एस0एस0 वह है कि करीब 02 लाख से ज्यादा विद्यालय आज भारत में आर0एस0एस0 ने बनाये हैं, जिसमें गरीब बच्चे, सर्वसमाज के बच्चे पढ़ रहे हैं और आज आर0एस0एस0 की स्थिति यह है कि आर0एस0एस0 व्यक्ति निर्माण, भारत के निर्माण के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य कर रहा है और किसी एक व्यक्तिगत जाति, धर्म के लिए खाली काम नहीं कर रहा है, राष्ट्र-निर्माण के लिए आर0एस0एस0 काम कर रहा है। मान्यवर, मैं इस बजट की तरफ कहना चाहूँगा कि यह बजट रामराज्य का, आस्था का, विकास का और सबके सपनों का बजट है। विकास और सपनों के साथ-साथ यह बजट किसानों का है, महिलाओं का है, नौजवानों का है, बालिकाओं के सम्मान का है और यह बजट, बजट की शुरुआत से ले करके, बजट के मध्य और अन्त तक प्रभु श्रीराम का बजट है। यह बजट आत्म-निर्भरता, अर्थ-व्यवस्था और अन्त्योदय तक की व्यवस्था का बजट है। मान्यवर, 2016-17 में जब बजट आया था तो उसकी तुलना में आज जीडीपी लगभग दोगुनी हो चुकी है, छठवीं अर्थ-व्यवस्था से आज दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू के मामले में भी आज हमारी सरकार सरप्लस है और यह बजट अब तक का सबसे शानदार बजट है और सबसे शानदार बात यह है कि अब युवाओं की परेशानी, युवाओं की पीड़ा को इस बजट में समझा गया है और युवाओं को 05 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। अगर कोई युवा काम करना चाहता है तो पांच लाख रुपये ऋण मुक्त ब्याज उसको मिल सकता है। यह बजट महिलाओं, बुजुर्गों और सब के हित का बजट है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बजट राम राज्य के विकास का है, यह बजट गौरव का है और यह बजट युवाओं का है।

विशेष रूप से अभी एक साथी सदन में कबीरदास का दोहा पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान्यवर, मैं कबीर की धरती से ही विधायक चुन करके आया हूँ और मगहर हमारी ही विधान सभा क्षेत्र में है। मान्यवर, इस सदन को उन्होंने कबीर के दोहे से कुछ बताया पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 'लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट।' मान्यवर, कारण यह है कि राम नाम का अभी समय है, राम नाम का नाम ले लो और नहीं तो जब प्राण छूट जाएगा तो राम नाम का नाम नहीं ले पाओगे। मान्यवर, अभी हमारे सदन के कुछ साथी कह रहे थे कि यह सरकार सर्व समाज की सरकार नहीं है। मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि जब कभी वह चाहें वह हमारे विधान सभा में आएं, भोजन, रात्रि विश्राम की व्यवस्था हम करते हैं, आने-जाने की व्यवस्था हम करते हैं और मगहर में आ करके देखें सौ करोड़ रुपये की मगहर में जो हिन्दू-मुस्लिम एकता का विश्व का सबसे बड़ा स्थान है, मगहर में सौ करोड़ रुपये की एकाडमी बनवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, सौ करोड़ रुपये से ऊपर की व्यवस्था किया है। मैं मान्यवर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। हमारे यहां मगहर में एक कताई मिल है, कताई मिल की बहुत सारी जमीनें खाली हैं जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बगल में हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे जनपद में भी कोई एक बड़ी इण्डस्ट्री आए जो हमारे जिले का विकास करे, युवाओं को रोजगार दे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कहता हूँ जय श्री राम।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। परम् आदरणीय मा0 मुख्य मंत्री जी साथ में यहां पर उपस्थित सभी मा0 मंत्रीगण, सदस्यगण आप सभी को अभिवादन, नमन, वन्दन। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जिस प्रदेश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अनेक सिद्ध महात्माओं ने और सन्तों ने जन्म लिया और जिस धरती को भगवान शिव की जटाओं में जहाँ समाहित किया, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पावन नदियों का जहाँ संगम है जहां पर मां आदि शक्ति के अनेक शक्ति पीठ हैं, सही अर्थों में पर्यटन और अध्यात्मिक दृष्टि से यह भारत का केन्द्र बिन्दु है। आज जो, हमारे भारतीय समाज का गौरव अयोध्या में भगवान श्री राम का मन्दिर सदियों के संघर्ष के बाद यह अवसर बना है कि भगवान राम एक बार फिर से अयोध्या में प्रतिष्ठित हुए हैं और उनके दिव्य, नव्य और भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ है। आम चर्चा में लोग कहते हैं कि यदि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी न होते और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी न होते, तो आज करोड़ों भारतीयों के जीवन का यह गौरव सम्भव नहीं हो पाता। इसके लिए मैं अपने दल (निर्बल इण्डियन शोषित हमारा अपना दल) की तरफ से और उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके इसी प्रकार के गौरवशाली भविष्य की कामना करता हूँ।

उपस्थित सज्जनों, आप सभी इस बात के लिए सहमत होंगे कि जिस भगवान राम का जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में हर समय महत्व है और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने अपने अन्तिम क्षणों में भी 'हे राम' कहकर अपने प्राण छोड़े थे, ऐसे प्रभु श्रीराम जो भारत के जन-जन की आत्मा में बसे हुए हैं उनके विरुद्ध यदि कोई बात होती है तो अत्यन्त ही निन्दनीय है और आज पूरी दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है तथा भारतीयों की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है उसमें कहीं न कहीं अयोध्या के विकास, अयोध्या के उत्कर्ष और भगवान श्री राम के मन्दिर का निर्माण और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमारे कुछ साथी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और मैंने यह महसूस किया कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो विकास आज चल रहा है, जिस प्रकार से सर्वांगीण विकास इस प्रदेश में हो रहा है, वर्ष 2017 के पहले इस प्रदेश में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आदरणीय मोदी जी ने निरन्तर इस देश और इस प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किया उसके बारे में आप सभी जानते हैं। आज इस देश का हर गरीब, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो वह आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूरी तरीके से सन्तुष्ट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है। उस संकल्प की यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में वह वाहन पहुँचा जिसमें मा0 प्रधानमंत्री जी का संदेश

था और हम सबको अवसर मिला कि हम उस वंचित समाज के लोगों को एक बार फिर से मुख्यधारा में जोड़ने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प है उसको लेकर घर-घर, गाँव-गाँव तक जायें। हमने वह सब काम किया। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के बारे में लोग टिप्पणियां करते हैं कि एक जाति विशेष, सम्प्रदाय विशेष के साथ उनका शत्रुता का नाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश का हर नागरिक, हमने गाँव-गाँव जाकर देखा है प्रदेश का हर नागरिक आदरणीय मुख्य मंत्री जी की योजनाओं से पूरी तरीके से लाभ पा रहा है और मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद दूँगा उन्होंने ऐसे समाज को जो कि दिव्यांग समाज था, जिनको कोई नहीं पूछने वाला, ऐसे दिव्यांग भाई-बहनों को उन्होंने विशेष रूप से मुख्य मंत्री आवास देकर उनके पुनर्वास का काम किया और यह भी कि हमारे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे जो कई घंटे का समय वहाँ पर बिताते थे उनके लिए भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हॉट कुक्ड मील देने की योजना बनाई। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ विशेष विषय को लेकर आपके सामने रखना चाहूँगा।

श्री अधिष्ठाता-

एक-दो प्वाइंट हों तो सीधे-सीधे बोल दीजिए। कोई मुख्य बिन्दु हों तो उन्हें रख दें।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल, जो सन्तकबीरनगर का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका कहलाता था, लेकिन पिछले सात वर्षों में आदरणीय मुख्य मंत्री जी के प्रयत्नों से वहाँ काफी विकास के कार्य हुए हैं। मैं आज आपके माध्यम से सदन में यह माँग करता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के युवाओं के खेल प्रोत्साहन के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, राप्ती नदी में बाढ़ के कारण अनेक गाँव बार-बार नष्ट होते हैं, उनकी सुरक्षा के उपाय किए जायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कृपया सीधे-सीधे संक्षिप्त में बता दें।

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ कि बेलौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जाये और बेलौली में राप्ती के तट पर एक पक्का घाट का निर्माण कराया जाये और वहाँ पर चोरमा रेगुलेटर को भी दिखवा लिया जाय। वहाँ और सड़कों का निर्माण कराया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीय सदस्य श्री नफीस अहमद जी बोलें।

***श्री नफीस अहमद-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया और अपनी बात को अपने सीनियर विधायक, आदरणीय ओम प्रकाश जी से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। जब प्रदेश में बजट आता है तो पूरे प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद और आस रहती है कि हमारा बजट आ रहा है। इस बजट से हमारे घरों में खुशहाली आने का काम होगा, किसान, नौजवान बुनकर सभी बहुत उम्मीद और आस लगाये बैठे रहते हैं। जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर वर्ष ये कहते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा बजट आया है। लेकिन जमीन पर देख लें तो हालात अभी भी वैसे ही हैं। इस बार जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया, 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख का और इस बजट को पेश करते वक्त उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं। लेकिन अगर उठाकर देख लें तो इस बजट से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, बुनकरों को बहुत मायूसी हुई है। यहाँ के जो 90 प्रतिशत पी0डी0ए0 के लोग हैं, इस बजट से निराश हुए हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले साल इन्होंने बजट पास किया, अगर देखा जाये तो सूचना विभाग का बजट इन्होंने पूरा खर्च किया क्योंकि यह सरकार प्रचार-प्रसार में, अपने नाम में ज्यादा विश्वास करती है। वहीं पर दूसरी तरफ देख लें तो क्षेत्रों के अन्दर गड्ढा मुक्ति के नाम पर सड़कें गड्ढा मुक्त कराई जा रही हैं, लेकिन आपको आज भी सड़कें गड्ढा युक्त मिलेंगी।

यहाँ का नौजवान बहुत उम्मीद लगाये हुए था। यह सरकार बार-बार यह कहती है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन अफसोस तो तब होता है कि यह सरकार हमारे नौजवानों को मौत के मुँह में ढकेलने का काम करती है। हमारे नौजवान आज इजराइल जाने के लिए, रोजगार के लिए लाइन लगाये हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से और तमाम प्रदेशों से लोग रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज हमारे प्रदेश के अन्दर नौकरियाँ नहीं हैं, रोजगार नहीं है और यहाँ का गरीब आदमी अपने बच्चे को जान के जोखिम में डालकर इजराइल भेजने का काम करने जा रहा है और साथ ही साथ हमारा किसान जो यह आस लगाये हुए था कि उसकी आय दोगुनी हो जायेगी, लेकिन मान्यवर, आज तक उनकी आय दोगुनी नहीं हुई और किसान परेशान है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बड़ी तादाद में हमारे गन्ना किसान हैं। गन्ना किसानों का भुगतान सही समय पर नहीं होता। इस बार उम्मीद थी कि गन्ना किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा देने का काम किया गया है। मैं तो कहूँगा, किसी ने कहा था, 'कहां तो यह तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं है एक शहर के लिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, दूसरी तरफ मा0 प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम बड़े-बड़े नेता यह कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप बतायें कि यह सबका साथ है कि बड़ी खूबसूरती से अल्पसंख्यक विभाग का बजट ही खत्म कर दिया गया, उसमें कहीं ऐसी कोई चीज नहीं प्रस्तावित की गयी। इतनी बड़ी आबादी के छात्र नौजवानों की छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ 220 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं। मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उनकी शिक्षा, उनके रोजगार पर जोर देना होगा, लेकिन बजट में कहीं इस तरीके का प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ उनकी शिक्षा के अच्छे इन्तजाम, तालीम के इन्तजाम करने के लिए जो पहले से पैसे मिलते थे उसको भी इस सरकार ने खत्म करने का काम किया है। साथ-ही-साथ आज के हालात में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप राम राज की कल्पना करना चाहते हैं तो राम के राज में कोई भी आदमी परेशान हाल है, तो राम राज की सही कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि राम के राज में सभी को उनका हक मिलना चाहिए और कहीं-न-कहीं अल्पसंख्यकों की आबादी के साथ नाइन्साफी हो रही है, उनकी हकतलफी की जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अस्पतालों में चले जायें, वहाँ बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर बिचौलिये काम कर रहे हैं, डाक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कालेज है वहाँ पर हम जाते हैं या किसी पेसेंट को भेजते हैं तो वहाँ पर न किडनी का इलाज हो पा रहा है, न कैंसर का इलाज हो पा रहा है, लगातार मांग करने में, पिछले कार्यकाल में जब मैंने कहा था तो मा0 मंत्री जी ने वायदा किया था कि आजमगढ़ के मेडिकल कालेज में यह सारी सुविधायें उपलब्ध करा दी जायेंगी जो अभी तक नहीं हो पायी हैं। मेरी गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार सरकार से मांग करता आ रहा हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में तहसील बना दिया जाये। मेरा इलाका बाढ़ग्रस्त है वहाँ पर एक 100 बेड का सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल बना दिया जाये। एक महिला डिग्री कालेज गोपालपुर में बना दिया जाये। मेरी विधान सभा क्षेत्र में जो लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में पिछड़े इलाके में रहते हैं वहाँ पर एक चिकनहवा ढाला है उसके पुल के निर्माण के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। वहीं हमारे यहाँ एक महाजी सिंगवारा का पुरवा है, बिल चला गया लेकिन कनेक्शन मिला, मीटर लग गया करेंट नहीं आया, मांग करने पर आज तक विद्युतीकरण का काम नहीं हुआ। कन्धरापुर बाजार के पीछे शाहपुर बाजार में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। बनकट जैगहा मार्ग के चौड़ीकरण अवशेष कार्य को पूर्ण करा दिया जाये। मान्यवर, हम सब लोग यह उम्मीद करते हैं कि सरकार कोई सौतेला व्यवहार न करे। यहीं पर मा0 नेता सदन ने कहा था कि सभी विधायकों को बराबर त्वरित योजना से लाभ पहुंचाया जायेगा, लेकिन जब हमारी फाइल गयी तो हमारी फाइलों को वापस कर दिया गया। यह राम राज नहीं है, अगर राम राज लाना होगा तो सबको बराबर का अधिकार देना होगा। जय समाजवाद, धन्यवाद।

***श्री श्रीकान्त कटियार-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट सत्र के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इतने अच्छे प्रस्तुत बजट पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बजट 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख का है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बजट इतना विराट है, उत्कृष्ट है, जो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सबका साथ सबका विकास के साथ विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने वाला यह बजट है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र से दूसरी बार निर्वाचित हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ऐतिहासिक विजय के साथ बांगरमऊ की ईश्वर रूपी जनता ने मुझे दोबारा यहां भेजने का काम किया है इसके लिए मैं बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र की जनता का अभिनन्दन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहले कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख देता हूं, बांगरमऊ औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है वहां के जाम के समाधान के लिए एक रिंग रोड की आवश्यकता है, मैं उसे बनाये जाने की मांग सरकार से करता हूँ। महाराजा सातन पासी, माननीय मुख्य मंत्री जी बांगरमऊ गये थे तो वहां की रोड उनके नाम से देने का काम किया था, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वहां पर एक सुनैना देवी का मन्दिर है उसके जीर्णोद्धार के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ।

अधिष्ठाता महोदय, फतेहपुर चौरासी ब्लॉक में एक सड़क जो जीटी रोड को जोड़ती है, कानपुर को जोड़ती है, उसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन बीच में गंगा नदी होने के कारण एक पुल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनवाया है, उसकी दोगुनी दरें हो जाएं तो बाढ़ आने पर वहां आवागमन की सुविधा मिलेगी। मेरी विधान सभा क्षेत्र के बगल में सफीपुर विधान सभा क्षेत्र पड़ती है, वहां कटरी क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र तो है, लेकिन वहां दो ही गाड़ी हैं, यदि दो और बढ़ जाएं तो नागरिकों को सुविधा मिलेगी। अपने यहां गंगाकटरी में मैं एक राजकीय महाविद्यालय की मांग करता हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी, अभी बहुत चर्चा हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी व लोकप्रिय यशस्वी मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 22 जनवरी, 2024 को जो अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा हुई उससे देश के आम जनमानस, लोक आस्था, लोक भावना और सनातन धर्म का गौरव पांच सौ वर्षों के बाद आज फलीभूत हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दो-तीन दिन से देख रहा हूँ कि इधर भी चौपाई पढ़ी जा रही है। रघुकुल रीति सदा चलि आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अरे आपने क्या किया है, आपने तो सरकार से कारसेवकों को मरवाने का काम किया था मगर हमने बाबू जी के नेतृत्व में सरकार को त्यागने का काम किया है, विरासत को सबसे ऊपर उठाकर रखा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत विषय हैं, जो कहे जा सकते हैं, अभी विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से तमाम बातें आयी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। वह बातें आ रही हैं, कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से पाओगे। ये सारे जो आपके वचन हैं इन्हें 22-25 करोड़ की जनता सुन रही है। इस देश की व्यवस्था पर माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की 2017 के बाद की सरकार की व्यवस्था पर उंगली उठाने का काम करते हैं। बिजली के बिल की बात करते हैं, आपके समय में तो बिजली का अता-पता नहीं था, बिजली की तो बात छोड़ो, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांव, गरीब, छप्पर तक में बिजली देने का काम किया है, गांव, मजरे तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। पीडीए, पीडीए, जाति, जाति चिल्लाई जा रही है, जनहित का काम जाति से नहीं होता है, गांव का एक छप्पर भी सर्वसमाज से उठाया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, किसान, गरीब को केन्द्रित किया है। उन केन्द्रों में सभी वर्गों के सम्मान की सुरक्षा के लिए सभी को समृद्धशाली के लिए पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा जो अन्त्योदय है, उस विचारधारा को और सबके चेहरे पर खुशी आए, खुशियों वाला बजट यह आया है। जब हम 2017 का उत्तर प्रदेश और उससे पहले का उत्तर प्रदेश देखते हैं, अभी हम लोगों को इस विकसित संकल्प यात्रा में जाना हुआ, लोगों के भरोसे की गाड़ी, विश्वास की गाड़ी, लोगों की एक-एक समस्या को महोदय यह पहली बार हुआ है कि सरकार गरीबों के द्वार तक पहुंची है। इससे पहले कोई सरकार नहीं पहुंची, पहले सरकार ऑफिस में पहुंच जाती थी या कभी आरती की थाली लेकर देख लिया, मगर काम नहीं हुआ। इन 7 वर्ष में मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वार पर है, वर्ष 2017 से ले करके गांव में आवास से लेकर बिजली पहुंचाने का काम यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने किया है। हमें बोलने का अवसर आपने दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस विधान सभा भवन में बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपको और अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता को कोटि-कोटि बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के सफल प्रयास से मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट मन खोलकर बनाया है, उन्होंने इस बजट में 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट अब तक का बनाया है। इस बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी ने किसान, महिला, गरीब, युवा, मजदूर सबको ध्यान रखते हुए बनाया है। बजट सर्वव्यापी, सर्वग्राही, समाज उपयोगी है। जैसा कहा जाता है कि-

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्यभवेत्।'

यह सभी समाज जन का बजट है, यह बहुत बड़ा बजट है। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लगता है कि वित्त मंत्री जी ने मन खोल करके दिल खोल करके इस बजट को बनाया है। इस बजट में सभी जन का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है, गरीबों की पढ़ाई-लिखाई का ध्यान रखा गया है। इस बजट में

प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक कमिश्नरी में राज्य सरकार का विश्वविद्यालय एवं शिक्षा क्षेत्र में सभी का ध्यान रखते हुए माँ विंध्यवासिनी धाम, मण्डल में विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में 51.20 करोड़ का धन दे करके व स्वीकृत करके, विश्वविद्यालय को उच्चीकृत करने व पढ़ने के लिए बनाया गया है। अस्पतालों का ध्यान दिया गया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भर्ती कराने के लिए बहुत बड़ी लाइन लग जाती थी, मरीजों को कई दिनों तक इन्तजार करना पड़ता था। लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कालेज की स्थापना करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना से गरीब परिवारों को लाभ हो रहा है, उससे आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में जीवन ऊंचा बड़ रहा है। जबसे प्रधानमंत्री जी, मा0 मुख्य मंत्री जी आए हैं। तब से गरीबों के जीवन खिल गये हैं। इससे पहले क्या होता था कि दबंग लोग उनकी जमीनों को कब्जा कर लेते थे। वे जो फसल उगाते थे, उनके फसल को चरा लेते थे, लेकिन आज मुख्य मंत्री जी के आने पर सारे लोगों की नसें ढीली हो गयी हैं। सभी लोग समरसता के मार्ग पर चल रहे हैं। माफिया सब डर गये हैं। हब हमारी बहनें साइकिल या बस द्वारा स्कूलों में जा करके सुगमता से पढ़ रही हैं। इससे पहले क्या होता था कि हमारी बहनें जब पढ़ने जाती थीं, तो हमारे अभिभावकों के हृदय पर सांप घूमा करते थे कि हमारी बहन-बेटी तो पढ़ने चली गयी, आयेंगी कैसे ? आज वह सब शरारत और गुण्डागर्दी समाप्त हो गयी है। एक दम अमन-चैन का राज शुरू हो गया है।

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं अपने क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र चन्दौली जनपद की वनवासी क्षेत्रों से विलांग करती है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 50 प्रतिशत वनवासी क्षेत्र है और 50 प्रतिशत में कृषक हैं, तो हमारे चकिया विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1978 में राजकीय महाविद्यालय सावित्री बाई फुले स्नातकोत्तर महाविद्यालय चालू हुआ। आज तक हमारे चकिया महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग नहीं है। मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ पर विज्ञान वर्ग की मान्यता देकर कक्षाएं प्रारम्भ की जाएं। दूसरा, हमारे चकिया तहसील में एक भी राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है, वहाँ पर एक राजकीय कन्या बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में वर्षाकाल में तो पानी रहता है, क्योंकि बांध बना करके नदियों से सिंचाई की जाती है, लेकिन दो बार से सूखा काल में अकाल पड़ जाता है। हमारे क्षेत्र के लोग सूखे से जूझ रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा कि सोनभद्र और चन्दौली जिला सटा हुआ है। सोनभद्र नगवां बांध का मरम्मत कर दिया जाए और सोन नदी में लिफ्ट कैनाल लगा करके नगवां बांध को भर करके नौगढ़ के लिए नगवां बांध से सिंचाई करने के लिए नहर है। उस नहर का विस्तारीकरण करके, वहाँ से पानी ला करके नौगढ़ तहसील में हमारे विधान सभा क्षेत्र चकिया के भरदुआ नामक स्थान के बाईं तरफ से नहर चन्द्रावती नदी के पास गई है, उसमें मिला करके चन्द्रप्रभा बांध में पानी पहुँचाने का काम कर दिया जाए, तो हमारे यहाँ

के किसानों का जीवन धन्य हो जायेगा, सुखी हो जायेगा, सम्पन्न हो जाएंगे। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय श्री राम।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद। मा0 श्री विपुल दूबे जी (अनुपस्थित)

***श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 08 फरवरी के दिन मुझे बजट पर बोलने का अवसर मिला है। 08 फरवरी इस सदन की बड़ी नेता और मेरी दादी मां डॉ0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेई जी की जयन्ती का दिवस होता है। वह इस सदन में रहते हुए बहुत से विभागों की मंत्री रही हैं। आज उनको प्रेरणा के रूप में याद करते हुए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। कुम्भ क्षेत्र का मैं विधायक हूँ और ढाई हजार करोड़ रुपये की सौगात कुम्भ में सरकार ने दी है, पिछले साल भी हजारों करोड़ रुपये की सौगात सरकार ने दी थी। मुझे लगता है कि जैसे ओलम्पिक में कोई शहर, कोई सूबा पूरा बदल जाता है वैसे ही प्रयागराज पूरी तरीके से बदल जाएगा। जब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई 1857 की गदर में संघर्ष कर रहे थे, उस समय से अंग्रेजों ने प्रयागराज को रेलवे के एक मुख्य जंक्शन के रूप में डेवलप करना शुरू किया था तब से लगभग 175 साल हो गये हैं। हमारे क्षेत्र में ढेर सारी रेलवे क्रॉसिंग्स थीं, जो खत्म नहीं हो रही थीं, लेकिन इस बड़े कुम्भ के बजट की वजह से उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक सारी रेलवे क्रॉसिंग्स को हम लोग खत्म कर देंगे और पहली विधान सभा क्षेत्र प्रयागराज मण्डल में उत्तरी विधान सभा क्षेत्र होने जा रही है, जिसमें एक भी रेलवे की क्रॉसिंग नहीं रह जायेंगी। इसके साथ-साथ और भी बहुत ढेर सारे काम हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है तो केन्द्र और प्रदेश के बीच में जुगलबन्दी भी देखने को मिल रही है जैसे कि एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का विकास केन्द्र सरकार और एविएशन मिनिस्ट्री करा रही है और उसका सम्पर्क मार्ग, उसके लिए डेडिकेटेड फ्लाईओवर देने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। यह ऐसा फ्लाईओवर होने जा रहा है, आपने सुना होगा कि रेलवे फाटक के ऊपर से आर0ओ0बी0 बनते हैं, लेकिन यह आर0ओ0बी0 पूरे सूबेदारगंज स्टेशन के ऊपर से बनाया जा रहा है। इसके अलावा एनीबेसेन्ट में केन्द्र सरकार अगर अण्डरपास दिया तो बगल में आई0आर0टी0 पर प्रदेश सरकार ने ओवरपास दिया है। इस तरीके से हम लोग एक-एक करके सारी रेलवे क्रॉसिंग्स को समाप्त कर रहे है। मैं आपको बता दूं सिंचाई विभाग के लोग कहते थे कि प्रयागराज में गंगाजी पर घाट नहीं बनाये जा सकते हैं, केवल यमुना जी पर घाट बनाये जा सकते हैं, क्योंकि गंगाजी डायरेक्शन बदलती हैं, लेकिन हम लोगों ने तर्क के साथ संघर्ष किया और मुझे खुशी है कि पहली बार गंगाजी पर घाट बनाये जा रहे हैं जैसे कि दशाश्वमेध घाट, जो प्रयागराज का प्रमुख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घाट है, जिससे कांवड़ यात्रा में लोग जल लेते है। रसूलाबाद घाट जिसका विस्तारीकरण हो रहा है। मेरा बड़ा प्रिय छुहारा हनुमान मन्दिर है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ। छुहारा हनुमान मन्दिर तेलियरगंज, जोंधवल क्षेत्र का एक मुख्य मन्दिर है, वहां पर एक नया घाट बनाया जा रहा है। कोस्टल रोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह मुम्बई में है। ट्रांस हार्बर ब्रिज का नाम सुना होगा, वह भी मुम्बई में है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि केवल मुम्बई में ही नहीं आपके प्रयागराज में भी कोस्टल रोड कुम्भ में बन रही है, जिससे हम लोग पूरे शहर को नदी के किनारे से कवर करते हुए शहर में एक नयी रोड बना रहे हैं जो तेलियरगंज, सलोरी, छोटा बघाड़ा होते हुए कुम्भ क्षेत्र में जाएगी। जैसे ट्रांस हार्बर ब्रिज भारत के बड़े ब्रिजों में से एक है वैसे ही 6 लेन का पुल लखनऊ मार्ग को ममफोर्डगंज क्षेत्र से कनेक्ट करने के लिए एन0एच0ए0आई0 बनाने का काम कर रही है। मैं उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस विधान सभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिवक्ता और जज रहते हैं, क्योंकि वह देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्र है। मेरी रगों में अधिवक्ताओं का खून है। मेरी दादी भी एक बैरिस्टर की बिटिया थीं और मेरे नाना जस्टिस एम0एन0 शुक्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे। मैं कह सकता हूँ कि मैं अधिवक्ताओं का भी प्रतिनिधि हूँ और इस उच्च सदन में वकीलों की भी वकालत करता हूँ, इसीलिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि 100 करोड़ रुपये की धनराशि लॉ यूनिवर्सिटी के लिए दी गयी है और मुझे इसका भी गर्व है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी झलवा में बन रही है, उसको हाई कोर्ट से कनेक्ट करने वाला चौफटका का ब्रिज है। चौफटका के पास जो महिला ग्राम ब्रिज बन रहा है, उसको बनवाने में मेरा भी संघर्ष रहा है। आर्मी के साथ मैंने भी निगोशिएट करने का काम किया है।

(इसी मध्य 06 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनोज कुमार पाण्डेय पुनः पीठासीन हुए)

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मान्यवर, साथ में अधिवक्ता कल्याण निधि में दो सौ से पांच सौ करोड़ करना और यूपी अधिवक्ता सामाजिक निधि में अगर किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो डेढ़ लाख की जगह पांच लाख मिलने का भी मैं सराहना करता हूँ। इसी के साथ मैं अब पूरे प्रदेश के फिगर में बस दो लाइन कहना चाहूंगा कि हमारा जो बजट है वह दिखा रहा है कि लगातार हमारा रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है। हर फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन फिजिकल डेफिसिट मेंटेन है अगर रेवेन्यू सरप्लस है और फिजिकल डेफिसिट मेंटेन है, इसका मतलब कि पैसे को कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य में इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो पिछले साल हम लोगों ने एक लाख छियासी करोड़ का कैपिटल आउटले किया था, हमारे एक्सपेंडीचर में जो साठ प्रतिशत का इजाफा था इतने हाई बेस पर होने के बावजूद भी हम लोग इस बार भी छह प्रतिशत ज्यादा एक लाख चौवन हजार करोड़ का एक्सपेंडीचर करने जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ हम लोगों ने प्रदेश का कर्जा लगातार कम किया है, अभी बहुत कुछ करना है, मैं

इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत लम्बा रास्ता तय करना है। मैं बस इन शब्दों के साथ अपनी बात को अन्त करूंगा कि रोबर्ट फ्रॉस्ट मशहूर कवि हैं उनके शब्दों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि ''दि वुड्स आर लवली डार्क एण्ड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एण्ड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एण्ड माइल्स, टूगो बिफोर आई स्लीप''।

श्री जै किशन साहू-

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्यय पर मुझे बात रखने के लिए बोला गया है मैं श्री ओम प्रकाश जी की बातों पर बल देते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भगवान श्री राम का 22 जनवरी को मंदिर भव्य उद्घाटन हुआ, लेकिन मैं एक बात उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का गुरुकुल गाजीपुर है। भगवान विश्वामित्र और भगवान परशुराम गाजीपुर में पैदा हुए हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाये। दूसरी बात यह है कि बड़ा धन यहां वहां खर्च हुआ इससे हृदय प्रसन्न है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि माननीय पूर्व रेल राज्य मंत्री ने गाजीपुर में पुल की आधारशिला रखी। रेलवे और रोड दोनों को मिला कर ब्रिज रखा था। वह पुल तो एक लाइन बन गया तथा पूर्ण रूप से अभी तक बना नहीं दूसरी रेल लाइन भी नहीं बनी और हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए उद्घाटन भी कर दिया जाये। मैं इस सदन के माध्यम से मा0 प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि गाजीपुर की यह अहम समस्या है, इसलिए गंगा नदी पर सैदपुर ब्रिज भी बन्द किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गाजीपुर आवागमन के लिए बिहार से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर ब्रिज बन रहा है, उसका तत्काल निर्माण कराया जाये। मेरी एक मांग है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। चोचकपुर ग्राम सभा में एक सौ बत्तीस का सर्वे हुआ जो ग्राम सभा की जमीन है वह जमीन ग्राम सभा देने के लिए तैयार है, प्राइवेट जमीन होती तो विधायक जाकर जनहित में दिलवाता, लेकिन वह वन विभाग की शेष जमीन है, सरकार की जमीन सरकार के दूसरे मद में जाएगी क्या अड़चन है। मेरा व्यक्तिगत तौर से आग्रह है गाजीपुर की जनता की तरफ से, चोचकपुर एक सौ बत्तीस के लिए वन विभाग से वार्ता कर वह जमीन एक सौ बत्तीस को दिलवाने की कृपा करें। इसलिए उससे नंदगंज, चोचकपुर, करंडा, मैनपुर, सइतापट्टी, पहाड़पुर छः पॉवर हाउस जुड़ जाएंगे, और उससे गाजीपुर विधान सभा के दक्षिणी क्षेत्र की व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। लोगों ने एक डाटा दिया है कि 18 घण्टा 9.00 मिनट ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति की गयी है। मा0 मंत्री जी, आपका बहुत आशीर्वाद है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में 09 घण्टे से ज्यादा विद्युत आपूर्ति नहीं की गयी है तथा मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि शहर में विद्युत की स्थिति बहुत खराब है। शहर में 03 पावरहाउस मांगे गये थे, लेकिन आपने 02 पावरहाउस सर्वे के लिये भेज दिया। नगर पालिका की सरकारी जमीन तथा अफीम फैक्ट्री के पास जमीन है। यदि उस जमीन को देखकर

तुरन्त पावर हाउस नहीं बनाया जायेगा, तो आने वाले दिनों में सरकार बदलती रहेगी, विधायक बदलते रहेंगे, लेकिन शहर को विद्युत व्यवस्था हेतु बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार विचार करने का कष्ट करे।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चन्दौली जिला और गाजीपुर जिला जोड़ने के लिये चोचकपुर में गंगा नदी पर जहाँ पर पीपा पुल बना हुआ है, वहाँ पर एक स्थायी पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि उस पुल को बनवाने का कार्य किया जाये। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूँगा कि नंदगंज में चीनी मिल बरसों से बन्द पड़ी है। मा0 मंत्री जी भी हमारे जनपद के हैं। मैं चाहूँगा कि या तो चीनी मिल को चालू करवा दिया जाये, अन्यथा उसको इण्डस्ट्रियल इस्टेट घोषित करवा दिया जाये, वह इसलिये कि वह जमीन अनुपयोगी पड़ी हुयी है। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार मा0 मंत्री जी और आपसे भी निवेदन कर चुका हूँ। गाजीपुर, नंदगंज, चोचकपुर, हरिहरपुर, सिरगिथा, आदर्श बाजार, महराजगंज, इन पाँच-छः मार्केट में नाले की अति आवश्यकता है, लेकिन आज तक कोई बना नहीं है, जबकि जी0एस0टी0 और व्यापार कर में सबसे ज्यादा राजस्व कर जनपद की इन्ही मार्केट्स से आता है। इसको व्यवस्थित करने के लिये यहाँ नाला बनाया जाना अति आवश्यक है। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि सादियाबाद-नंदगंज रोड की अत्यधिक दुर्दशा है, उसका उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया जाये। नंदगंज, महराजगंज, पहाड़पुर से लगाकर जखनिया तहसील तक के क्षेत्रों में आर्सेनिक जल है। इस विषय को मैं जिला कमेटी तथा जिले की काफी मीटिंग्स में उठा चुका हूँ, लेकिन अब तक उस जल की जाँच नहीं हुयी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द उसकी जाँच करवा कर अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गाजीपुर स्टेडियम मा0 अखिलेश जी ने बनवाने का काम किया था। उसकी बाउण्ड्री हो गयी, लेकिन वहाँ पर संसाधनों का अभाव है। मेरा खासतौर से आपसे निवेदन है कि वह स्टेडियम काफी धनराशि से बना है, इसलिये उस स्टेडियम में समुचित व्यवस्था करवायी जाये।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें। इसके बाद मा0 सदस्य मौहम्मद फहीम जी बोलेंगे।

श्री जै किशन साहू-

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरा एक और निवेदन गोंड और खरवार जाति के लोगों के विषय में है। डी0एम0 कहते हैं, मा0 मंत्री जी कहते हैं, आप लोग कहते हैं और मा0 सदन भी कहता है। आखिर इस शासन-प्रशासन में कितना बड़ा अधिकारी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री जै किशन साहू-

मान्यवर, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूँ कि 'कमल तुम्हारा दिन, कुमुदनी-यामिनी तुम्हारी है। कोई निराश न होवे, सबकी समान बारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इसी मध्य सदस्य श्रीमती विजमा यादव जी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य विजमा जी आप कुछ कहना चाहती हैं।

श्री राजीव गुम्बर-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पीठ की तरफ से 3 और 1 की व्यवस्था की गयी थी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, 3 और 2 की व्यवस्था की गयी थी।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है सत्ता पक्ष से और उनके सहयोगी दल जो हैं वह मिलाकर 3 विपक्ष से 2 और एक बार छोड़कर उसमें लोक दल लिया जाएगा। श्रीमती विजमा यादव जी आप कुछ कह रही थीं।

***श्रीमती विजमा यादव-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक व्यक्तिगत बात विधान सभा में कहना चाहती हूँ। मेरे जनपद प्रयागराज के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र से जहां से मैं चुनकर आई हूँ वहां पर एक गांव कटेहरी पड़ता है जहां पर महिलाओं को आने-जाने, किसानों को खेत तक पहुँचने एवं उनके निकलने के लिए 10 किलोमीटर तक घूम कर आना पड़ता है। वहां पर दोनों तरफ से रोड बनी हुई है, लेकिन आने-जाने के लिए पुल नहीं बना है, जिससे आने-जाने में अत्यधिक परेशानी होती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि वहां पर पुल का निर्माण करा दिया जाए। मा0 बिजली मंत्री जी बैठे हैं, मेरे क्षेत्र में ऐसे गांव हैं जहां पर कहीं पर बल्लियाँ लगी हैं, कहीं बांस लगाया गया है वहां पर अभी तक खम्भा नहीं पहुँचा है। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो जनता कहती है कि हम लोगों ने आपको विधायक बनाया है, लेकिन अभी तक यहां पर खम्भा नहीं लगा है। अभी वहां पर एक घटना भी घटित हो गयी थी एक किसान का बेटा खम्भे पर चढ़कर लाइन जोड़ रहा था जिसकी दुर्घटना के कारण मृत्यु भी हो गयी। गांवों में 18 घंटा 20 घंटा बिजली देने की बात कही गयी है, लेकिन मुश्किल से 10 घंटा, 8 घंटा बिजली पहुँच रही है। जो रोडें हैं, बिजली है, पानी है जो किसान की जरूरत की चीजें हैं वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन तक नहीं पहुँच रही हैं। सरकार सामने कहती है, कागज पर कहती है, लेकिन गांवों में काम नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, हम लोग चीफ, एक्सीयन, ए0सी0, एस0डी0ओ0 के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बस विधायक जी बनने वाला है। जैसे ही ट्रांसफार्मर लगता है दूसरे दिन फिर जल जाता है। मैं कहना चाहती हूँ कि नदी पर अगर वह पुल बन जाएगा तो कम से कम 50 गांव का विकास हो जाएगा, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

विजमा जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और पहली बार बोली हैं, धन्यवाद।

***श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर अपने विचार रखने का जो मौका दिया सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद करता हूँ उसके बाद इस भाषण के विरोध में विचार रखने वाले समस्त साथी विधायकों के विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ। मेरे विचार से यह बजट भाषण सरकार की उपलब्धि विहीन एक और वर्ष के लेखे-जोखे का रंग-बिरंगे शब्दों से सजाये गये रंगीन लिफाफे जैसा है। सरकार अपने दावों और वायदों की हकीकत को जमीन पर सच साबित करने में नाकाम रही है। सरकार ने बहुत ही महारथ से छोटी उपलब्धियों को बड़ा करके दिखाने और नाकामियों को छिपाने का सात्विक प्रयास किया है। प्रदेश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बेहाल स्वास्थ्य सेवायें, भ्रष्टाचार, पुलिस का अत्याचार, धर्म, जाति आधारित भेद और हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, शिक्षा की बदहाली, टूटी सड़कों, गांव के प्रवेश मार्गों पर जलभराव और गम्भीर अपराधों में बढ़त से त्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पंचायत सहायक, केयर टेकर, मनरेगा कर्मी, शिक्षा अनुदेशक, शिक्षामित्र, आशा, आंगनबाड़ी, ए0एन0एम0, उर्दू टीचर, वित्त विहीन कालेज शिक्षक, होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवान, चौकीदार आदि मासिक एवं दैनिक मानदेय कर्मी अपनी बदहाली से मायूस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह देश यह प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब का एक गहवारा है जिसमें हम सब लोग मिलजुलकर रहते हैं और यहां की तहजीब और यहां की एकता ईमानदारी आपस में ऐसी है जैसे एक परिवार। इसमें हम लोगों में, क्योंकि हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और कुछ लोग गीता पढ़ते हैं। क्योंकि धर्म हम लोगों को आगे बढ़ाने का पैमाना है कि हम सब लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं। गीता हो या कुरान सभी आसमानी किताबे हैं। उसी को फॉलो करके हम सब लोग आगे बढ़ते हैं।

कुरान में लिखा है 'बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम, अतिउल्लाह वा अति ओ आर रसूल वा उली एल अमरी मिंकुम' मोहब्बत करो ए ईमान वालो इबादत करो अल्लाह की और उनकी जो तुममे हुकूमत वाले हैं। जिनकी हुकूमत हैं उनको फॉलो करना। चाहे गीता हो या कुरान हो यही सिखाता है। हर मजहब सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत का पैगाम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो, अमन की बात करो, खुलूस की बात करो, एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ दो, एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ो। मैं यही कही कहना चाहूंगा 'ए आबरू ए गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा' 'मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।' कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जहां पर एक लाख से ज्यादा मुस्लिम भाई और ढाई लाख से ज्यादा हिन्दू भाई हैं। मैं वहां से जीत कर आता हूँ जहां पर बेरनी का शिव मन्दिर है। वह ऐसा शिव मन्दिर है जो 13वीं सदी का मन्दिर है और महादेव का बड़ा प्रतीक है। उसका आकार हर साल बदलता रहता है। वह अपने आप में ऐसी जगह है जो आस्था का बड़ा केन्द्र है। वहां लोग जाते हैं। मैं चाहूंगा बजट में ऐसे धार्मिक स्थल का हर हाल में प्राविधान होना चाहिए। वह पर्यटक स्थल घोषित है, उसे धन आवंटित होना चाहिए। इसी तरह से तिसाबे की दरगाह है वह भी आस्था का केन्द्र है। वहां हिन्दू-मुस्लिम सब जाते हैं। उसे भी धन आवंटित होना चाहिए। हमारे यहां सैनी, शाक्य, मौर्य समाज है, आज-कल सनफ्लावर की खेती हमारे यहां बहुत ज्यादा होती है, उसके प्लांट का प्राविधान इस बजट में नहीं है, वह होना चाहिए। हमारे यहां गाजर की खेती किसान करते हैं। गाजर का बड़ा उत्पादन होता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का कोई प्राविधान हमारे बजट में नहीं है।

सरकारी अस्पताल का विस्तार हमारे वालिद मोहतरम हाजी मो0 इरफान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमारे मुख्य मंत्री थे तब 30 बेड का महिलाओं का अस्पताल बनवाया था। उसमें सुविधाओं की कमी है। आज-कल वहां पर हैपिटाईटस सी के इन्जेक्शन और महिलाओं के लिए इक्विपमेन्ट्स की कमी है, अल्ट्रासाउण्ड की कमी है। हम चाहते हैं कि हमारी विधान सभा में अस्पतालों के लिए इस बजट में प्राविधान होना चाहिए। हमारे यहां सूत कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। बहुत बुनकर समाज रहता है। तमाम लोग सूत कारोबार से जुड़े हुए हैं। अभी तक कोई सूत डिपो नहीं बना, उसका भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है। हमारी विधान सभा में सर्राफा बाजार भी बहुत बड़ा है। उसके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थायें होनी चाहिए जिससे उनका साहूकारा और बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहां गन्ना समिति की सोसाईटी की जमीन है वहां पर एक काम्पलेक्स बनना चाहिए जो सब्जी वाले हैं, बाजार वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं। बड़ी परेशानी होती है। वहां अगर कोई व्यवस्था हो जायेगी तो गरीबों का उद्धार हो जायेगा। प्रधानमंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनायें हैं, लेकिन वहां के लिए गमादेवा का मन्दिर है। मन्दिरों के जीर्णोद्धार करने के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां लकड़ी का बड़ा कारोबार है। तमाम सैफी समाज लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। पीतल नगरी एक्सपोर्ट हब है। लकड़ी के कारोबार के लिए भी लकड़ी के एक्सपोर्ट के लिए किसी तरह का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। हमारे यहां तेल का भी बड़ा कारोबार है। तेल के कारोबार में स्पेलर और इस तरीके की व्यवस्थायें हैं पर इस बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। भट्ठे का कारोबार बहुत बड़ा है। माननीय

मंत्री जी बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सब्सिडी आपने और क्षेत्र में दी है। भट्ठे वालों को भी सब्सिडी देने का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। हमारी विधान सभा हो या पूरे प्रदेश में हो अम्बेडकर पार्क के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव है, पर कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। मैं खासतौर से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां मण्डी समिति बिल्कुल तैयार है। बजट जारी हो चुका है, पिछली सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम में हमारे वालिद हाजी इरफान साहब जब विधायक थे तो बजट भी जारी हो गया था, पैसा भी जारी हो गया। लेकिन अब तक मण्डी समिति की स्थापना हमारी विधान सभा में नहीं हो सकी है। सोण्डारा से रीड का जो रास्ता है उसके चौड़ीकरण के लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसका कोई प्राविधान बजट में नहीं किया गया है। बड़ी के चौराहे से डारनी के चौड़ीकरण का प्रस्ताव इस बजट में नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बिलारी में नगर निकाय के लिए लभगग 22 से 23 करोड़ रुपये मन्जूर हुआ है। वहां टेण्डिरिंग हो चुकी है। टेण्डर निकल चुका है, लेकिन अभी तक ठेकेदार वहां काम नहीं कर रहा है। न बन्च केबिल बदल रहा न ट्रान्सफार्मर चेन्ज कर रहा है। मेरी माननीय मंत्री जी से गुजारिश है क्योंकि मौके पर मौजूद हैं उसको दिखवा लें। आपने 28 करोड़ रुपये बिलारी को दिये हैं। जिस तरीके से समाजवादी सरकार में जनेश्वर मिश्र और लोहिया ग्राम के नाम से सैचुरेट गांव किये जाते थे। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के उन गांव को ले लिया जाये जहां पर ज्यादा वोट इन लोगों को मिले हैं और कम वोट हमे मिले हैं। तो वे भी हमारी विधान सभा के। अटल बिहारी जी के नाम पर या किसी भी महापुरुष के नाम पर जनेश्वर मिश्र जी की तरह, लोहिया जी की तरह ऐसे गांव को धन आवंटित कर दिया जाये जिससे कम से कम उन गांव में विकास का कार्य हो सके। जिससे कम से कम हमारे क्षेत्र के गांवों में विकास के कार्य हो सकें। बिलारी में 70 बीघे में जोर का तालाब बहुत बड़ा तालाब है अगर उसका जीर्णोद्धार हो जाये तो बिलारी में जल निकासी की व्यवस्थायें ठीक हो जायेंगी। बिलारी में एक खेल स्टेडियम की बेइन्तहा आवश्यकता है। हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल स्टेडियम का भी कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बजट में हमारे यहां किसी डिग्री कालेज का प्राविधान नहीं किया गया है, जो बनना चाहिये। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी विधान सभा को एक अटल आवासीय विद्यालय मिला है। हमारे यहां अटल आवासीय विद्यालय की जो रोड है उसे बनाने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया। कृपया आप समाप्त करें।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मैं इस अल्फाज के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि 'सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज और शब में उलझकर न रह जाये

कि तेरे जमानों मका और भी हैं।' मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खास तौर से अपनी बिलारी विधान सभा के हिन्दू और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे यहां जहां कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहीं ग्यारहवीं शरीफ की फातिहा भी होती है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य का माइक बन्द किया जाये और लिखा नहीं जायेगा। माननीय मंत्री जी श्री सतीश चन्द्र शर्मा कृपया आप बोलिये।

खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री सतीश चन्द्र शर्मा)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में आपने मुझे बोलने का समय प्रदान किया जिसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत आभार और अभिनन्दन ज्ञापित करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के जीवन को सुखद एवं गरिमापूर्ण बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस हेतु इतिहास के सबसे बड़े बजट, जो आस्था, अन्त्योदय विकास एवं प्रभु श्री राम को समर्पित है मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा और समर्थन करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, 500 वर्ष की प्रतीक्षा के उपरान्त भगवान रामलला गगनचुम्बी राम मन्दिर में प्रतिष्ठित हुये हैं। इस हेतु मैं मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से बहुत-बहुत आभार और अभिनन्दन ज्ञापित करना चाहता हूँ। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अयोध्या अद्भुत है और अयोध्या की नीति और पराक्रम अविस्मरणीय है। दिनांक 22 जनवरी, 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरान्त रामलला सरकार के प्रथम दर्शन के उपरान्त करोड़ों आँखों में जो अश्रु धारा बह रही थी उसको समझना मुश्किल है कि किस प्रकार से लोग इस अवसर को देखने के लिए पांच सदी से प्रतीक्षा कर रहे थे और उसके उपरान्त यह अवसर आया। इस हेतु मैं पुनः मा0 प्रधानमंत्री जी और मा0 मुख्य मंत्री जी का हृदय से बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूँ। मैं अभिनन्दन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने अयोध्या के अन्दर लगभग 100 से अधिक बार अयोध्या पहुँचकर वहां की विकास योजनाओं को निरन्तर जमीनी स्तर पर देखने का काम किया है। यही कारण है कि आज चाहे अयोध्या के अन्दर महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो, चाहे अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे राजा दशरथ मेडिकल कालेज की बात हो, चाहे बाराबंकी-अयोध्या रेलवे लाइन के दोहरीकरण की बात हो, चाहे रामपथ जन्मभूमि पथ की बात हो और चाहे वहां के घाटों और कुण्डों के सौन्दर्यीकरण की बात हो, आज 31000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनायें मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में वहां पर या तो जमीन पर पहुँच

चुकी हैं या फिर उनको चलाने का काम हो रहा है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विकास और कानून व्यवस्था के लिए बेहतरीन काम किया है। वर्ष 2012-2017 के बीच में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर अराजकता, अपराध और अपराधियों का बोलबाला था और बन्दूक और सन्दूक की नोक पर जिले के माफिया जिलों की सरकारें चलाने का काम करते थे। आज उस संगठित माफिया को खत्म करने का काम प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में संस्कृति और विरासत का भी संरक्षण हो रहा है। आज जो हमारे धार्मिक केन्द्र हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है और उसे जमीन पर पहुँचाने का काम कर रही है। चाहे बाबा विश्वनाथ को सजाने की बात हो, चाहे विन्ध्याचल माई को सजाने की बात हो, चाहे नैमिषारण्य को सजाने की बात हो, चाहे प्रदेश के अन्दर सभी विधान सभाओं में एक-एक धार्मिक स्थान का सौन्दर्यीकरण करने का काम हमारी सरकार कर रही है।

आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, खेल, युवा, संस्कृति, धर्मार्थ, सिंचाई, ग्राम्य विकास, सड़क, सेतु, ऊर्जा के क्षेत्र में निरन्तर बजट में वृद्धि करके जो जनोपयोगी योजनायें हैं उनको लागू करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आज पूरे प्रदेश को मालूम है कि जब बिजली पहुंचने की बात होती थी तो गाँव में मात्र 4-6 घण्टे बिजली मिलती थी और 6 हफ्ते के साथ एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात में मिलती थी। लेकिन आज मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में गाँव में 18 घण्टे बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है। अभी एक मा0 सदस्य कह रही थीं कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हमको सिफारिश करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 मंत्री जी के नेतृत्व में आज ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद 48 घण्टे के अन्दर बदलने की व्यवस्था की गयी है, जबकि पहले ट्रांसफार्मर फुंकने के बाद चन्दा लगता था आज उस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाने का काम मा0 प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। अपने संकल्प-पत्र के वायदे के अनुसार हमारी सरकार एक करोड़ 75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को आज होली और दीपावली में निशुल्क गैस रिफिल सिलेण्डर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। किसानों को चाहे गेहूँ, मक्का या धान हो की खरीदारी क्रय केन्द्रों के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। भुगतान की प्रक्रिया को हमारी सरकार ने तेज और पारदर्शी बनाने का काम किया है। अभी हमारी सरकार ने मा0 मुख्य मंत्री जी के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि ई-पॉस जो मशीने हैं उनको इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन के साथ जोड़ने का काम किया है। जिससे आने वाले समय में प्रदेश में जितने भी लाभार्थी हैं उनके साथ कोई नाइन्साफी नहीं होगी। इसके साथ ही आज हमारी सरकार प्रदेश में अन्नपूर्णा स्टोरों का निर्माण भी कर रही है। प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री जी के प्रयासों का ही यह असर है कि आज

उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है और विकसित एवं नये भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज कराने का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। मान्यवर, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार लोकहित को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये कार्य कर रही है। प्रभु श्रीराम लला की पावन धरती उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये अपना समर्थन ज्ञापित करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय सिया राम।

***श्री राजीव गुम्बर-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का जिन्होंने 22 तारीख को प्रभु श्रीराम जी के भव्य मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वित्त मंत्री जी का और मा0 मुख्य मंत्री योगी जी का और बजट के काम में लगे हुये समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट को बनाकर इस विधान सभा में प्रस्तुत करने का काम किया है। वह बजट जो किसानों के हित का है, युवाओं को रोजगार देने वाला है, प्रदेश में उद्योग को विकसित करने वाला है, प्रदेश विकास की गंगा चाहे वह सड़क के रूप में हो चाहे अन्य रूप में हो उस बजट के माध्यम से उस विकास की गंगा को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मैं आदरणीय योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था को बहुत उत्तम बनाते हुये जो हमारा प्रदेश एक उजड़ा हुआ प्रदेश, गुण्डागर्दी का प्रदेश, गुण्डों का प्रदेश कहलाता था आज एक विकासशील प्रदेश, एक उत्तम प्रदेश बनाया है उसके लिए आदरणीय योगी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वह प्रदेश जिसके अन्दर गुण्डे, माफिया उद्योगपतियों से चौथ वसूली करते थे, जिससे यहाँ का उद्योग विस्थापित हो रहा था। आज मा0 योगी जी के संरक्षण के अन्दर आज उत्तर प्रदेश में केवल प्रदेश के लोग ही नहीं, देश के लोग ही नहीं विदेश के लोग भी उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं।

मान्यवर, मैं अपने सामने के बन्धुओं को याद दिलाना चाहता हूँ (जो वर्ष 2017 तक सत्ता में थे) कि भरत ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रभु श्रीराम ने कहा था कि 'कहब सँदेसु भरत के आएँ। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ।' प्रभु श्रीराम ने कहा था कि मैं संदेश भेज रहा हूँ कि राजपद पा जाने पर नीति न छोड़ें, मन, क्रम और वचन से प्रजा का पालन करें। प्रजा का पालन क्या होता है कि सबको समान रूप से देखा जाए, सबका साथ, सबका विकास किया जाए। जो आज मोदी जी और योगी जी की नीति पर चल रहा है। मैं सामने बैठे बन्धुओं को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी सरकार के अन्दर कुछ जिलों को ही बिजली मिलती थी, कुछ जिलों का ही विकास होता था, कुछ जिलों की ही सड़कें बनती थीं। आज इस बजट में पूरे प्रदेश के अन्दर एक समान विकास कार्य हो रहा है। हमारी सरकार ने सड़कें बनाने के लिए बजट में प्राविधान किया है। योगी जी ने राजधर्म का पालन करते हुए सभी क्षेत्रों में समान रूप से सेवा को संकल्प मानते हुए राजमार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है तथा राज्य सड़क निधि से भी लगभग 6500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। आज फ्लाईओवर व रेल उपरिगामी सेतु बनाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपये और ग्रामीण सेतु बनाने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट के अन्दर किया गया है। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलते हुए मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, आज योगी जी की सरकार उस नीति पर चल रही है। आज प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और मुझे आज बताते हुए गर्व हो रहा है कि 65 जिलों के अन्दर सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं जिससे आम जनता, गरीब जनता जो इलाज के लिए तड़पती थी, आज उसे इलाज मिल रहा है। प्रत्येक मेडिकल कालेज कार्य करने लगे हैं। आज नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 कर दी गयी है। आज प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के अन्दर हेल्थ वेलनेस सेण्टर बनाये गये हैं। मेरी विधान सभा के अन्दर 34 हेल्थ वेलनेस सेण्टर बनाये गये हैं जिन्हें मोहल्ला क्लीनिक का नाम दिया जाए। इन हेल्थ वेलनेस सेण्टर पर कालोनियों के लोग इलाज कराते हैं जिससे उन्हें जिला अस्पताल में जाकर धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से 61 हजार से ज्यादा गरीब लोगों को इलाज के लिए पैसा मिलने का काम हुआ है। आज चिकित्सा क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ प्रत्येक जिले को चिकित्सा के लिए बजट में प्राविधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भी, जहां पहले प्रदेश से उद्योग पलायन करते थे।

आज यहां पर बाहर से आने वाले उद्योगों को रेड कॉरपेट देकर उद्योग लगाने के लिए बुलाया जा रहा है। पहले यहां से उद्योग क्यों विस्थापित होते थे, क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिलती थी, उनका शोषण होता था। आज 24 घण्टे उद्योगों को बिजली सप्लाई करके, अवैध वसूली को रोककर उद्योगों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। एक समय था जब गरीब व्यक्ति को स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, उनका स्वास्थ्य खराब होता था। आज हर घर नल की योजना के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। मैं सहारनपुर जिले से आता हूँ और पहले इस जिले की बहुत बुरी हालत थी। मां शाकुम्भरी देवी के दर्शन करने के लिए सड़क नहीं मिलती थी। सरकार ने वहां पर बहुत अच्छी सड़क बनाई है और मां शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय का निर्माण कराकर सहारनपुर के आस-पास के जिलों के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। आज सहारनपुर में तेजी से विकास हुआ है। बड़े-बड़े हाई-वे बने हैं, सरसवां में एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मात्र 2-3 महीने के अन्दर एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में लोगों को सहारनपुर बदला हुआ नजर आता है। मलिन बस्तियों का

विकास हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में कुछ काम बाकी है। मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार इन कार्यों को पूरा करेगी। सहारनपुर को होजरी का क्लस्टर बनाया जायेगा। नयी इंटीग्रेटेड आधुनिक टाउनशिप विकसित होगी, नया औद्योगिक पार्क विकसित कराया जाये और सहारनपुर में हम लोगों की बस अड्डे की लगातार मांग है, मैं विश्वास करता हूँ कि सरकार उस मांग को भी पूरा करेगी। इनर रिंग रोड बनाकर शहर का बहुत बड़ा विकास हो रहा है, शहर में जाम की स्थिति से निपटने के लिए इनर रिंग रोड बनाई जाये और आउटर रिंग रोड का भी निर्माण कराया जाये। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूं, इतना लोक-लुभावन बजट, इतना लोक-कल्याणकारी बजट इससे पहले कभी नहीं आया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरोज कुरील-

मैं उन सभी महापुरुषों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक लड़ाई लड़ी और अपना दल (एस) के संस्थापक स्व0 डा0 सोनेलाल पटेल जी जिन्होंने दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 दीदी अनुप्रिया पटेल जी को और इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम करते हुए अपना दल (एस) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भैया आशीष पटेल जी को प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी घाटमपुर की समर्पित जनता को भी हृदय से प्रणाम करती हूँ। मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी विधान सभा बनाई और अधिष्ठाता महोदय जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मा0 वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रेषित बजट पर बोलने का सुअवसर दिया। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछला बजट 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख का था और बजट में कई योजनायें प्रदेश में सम्मिलित करायी गयी थीं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने व्यापार को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया था। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने ग्लोबल समिट जी -20 का भव्य रूप से आयोजन किया था। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि यदि व्यापार और व्यापारी विकसित एवं विकासशील होंगे तो देश और प्रदेश का चौमुखी विकास सम्भव होगा। इसी सच को आगे बढाने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्लोबल समिट का सफल आयोजन कराया था। मा0 मुख्य मंत्री जी का जीरो टॉलरेन्स नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश में व्यापारी बेखौफ होकर व्यापार को कर पा रहा है। इसी का नतीजा है कि अबकी बार वर्ष 2024-25 का बजट 07 लाख 36 हजार 437 करोड़ 41 लाख का किया गया, क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा विगत वर्ष में 40 लाख करोड़ से अधिकम इन्वेस्ट प्रस्ताव दिये। आपका ध्यान भारतीय सनातन संस्कृति की ओर ले जाना चाहूंगी जिस तरह से अयोध्या नगरी में 22 जनवरी, 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ यह हमारे देश के प्रधानमंत्री

जी और मा0 मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है, जिसका उद्घोष सम्पूर्ण विश्व में है। आज पूरा विश्व राममय है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण-प्रतिष्ठा करके मा0 मुख्य मंत्री जी ने सनातन की प्रेरणा को जन-जन में बढ़ा दी है, जिस तरह से हमारी नीतियां उन सभी वर्गों के लिए जिससे युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान और गरीब वर्ग भी आता है, उनके लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है। मा0 प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गयी कई योजनाओं से आज सम्पूर्ण भारत का एक-एक पात्र लाभार्थी लाभान्वित हो रहा है। सम्पूर्ण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफल आयोजन गांव के निचले छोर पर खड़े गांव, गरीब व पात्र लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमारा उत्तर प्रदेश आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में कई प्रचण्ड ऊंचाइयों को छू रहा है। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ और महिलाओं के उत्थान के लिए बजट में बहुत सारी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे निराश्रित महिला पेंशन, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों के लिए चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। गरीब असहाय लोगों के लिए मा0 मुख्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था की गयी। पारदर्शिता पूर्ण ढंग से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जमीनी स्तर पर हमारी सरकार द्वारा आवास उपलब्ध कराये गये एवं समाज के कई वर्षों से आवास योजना से वंचित रहे पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले बंजारा समाज एवं मछुआ समाज के लिए मछुआ आवास, बंजारा आवास की व्यवस्था की गयी, जिसके लिये मैं मा0 मुख्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

यह बजट उ0प्र0 को उत्तम प्रदेश बनाने में सफल साबित होगा। सम्मानित सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूँगी। मेरी घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का जाल मेरे प्रस्ताव पर किया गया, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री, लोक निर्माण को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर्यटन के क्षेत्र में हमारी विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर में कई मन्दिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराया गया। मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के प्राचीन मन्दिरों को सजाने एवं संवारने पर ध्यान दिया और आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। मैं ऊर्जा विभाग के मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे घाटमपुर में बहुत सारे कार्य कराये। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी, जिन्होंने घाटमपुर के लिए बहुत सारा योगदान दिया। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर की मुख्य समस्या जल निकासी है, जिसको दूर करना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, रामसारी में बन्द चीनी मिल की खाली पड़ी जमीन में डिफेन्स कॉरिडोर या अन्य उद्योग लगाने की अत्यधिक आवश्यकता है। जिससे हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे और बेरोजगारी भविष्य में दूर होगी।

घाटमपुर कस्बे में भोगनीपुर रोड से चौडगरा हाई-वे रोड के किनारे ब्लाक के सामने खाली पड़ी जमीन लगभग साढ़े ग्यारह बीघे जो कि खेल विभाग के नाम अभी हाल ही में दर्ज करायी गयी है, जिस पर जिला स्तरीय स्टेडियम बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। चूँकि क्षेत्रीय युवाओं को अपने खेल की प्रतिभा को निखारने के लिये लगभग 80 किमी0 कानपुर नगर एवं 60 किमी0 हमीरपुर बुन्देलखण्ड की सीमा पर जाना पड़ता है तथा घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सामुदायिक केन्द्र व बारातशाला के निर्माण एवं भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के पार्कों की बाउण्ड्रीवाल, गेट व छतरी एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु धन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आशा करती हूँ कि घाटमपुर की प्रमुख समस्याओं का निदान प्राथमिकता पर कराया जायेगा। मान्यवर, प्रदेश में पान की खेती को बढ़ावा देते हुए, पान की खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाय। इसके साथ ही मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगी :-

'त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिये,
राम ने खोया बहुत प्रभु श्रीराम बनने के लिये।''

माननीय अधिष्ठाता जी, आपको धन्यवाद देते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्रीराम, जय अपना दल (एस)।

श्री अधिष्ठाता-

अब डॉ0 अजय कुमार जी बोलें।

डॉ0 अजय कुमार-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की साधारण चर्चा पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, इस भारी-भरकम बजट में गरीब, किसान और युवाओं के लिए कोई खास नहीं है। इन वर्गों के लिए अभी और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कृषि, स्वास्थ्य तथा गन्ना पर अधिक बजट आवंटन की आवश्यकता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, जिसकी 62 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह गन्ने का क्षेत्र है और मुझे यह कहते हुए, सदन को बताते हुए दुःख है कि मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई मिलों ने अभी तक पिछले वर्ष का भुगतान भी नहीं किया और इस वर्ष जो पिछले महीने गन्ना मूल्य बढ़ाया गया, वह मात्र 20 रुपये था। मान्यवर, जो एम0एस0पी0 होनी चाहिए, वह फसलों की लागत के हिसाब से उसका डेढ़ गुना होना चाहिए और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पिछले वर्ष 311 रुपये एक कुन्तल गन्ना पैदा करने में लागत आयी। इसका मतलब यह हुआ कि इस वर्ष जो गन्ने का दाम होना चाहिए था, वह करीब साढ़े चार सौ रुपये कुन्तल तय होना चाहिए था। लेकिन बढ़ाया गया 20 रूपये। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि किसानों को कम से कम 30 रुपये प्रति कुन्तल की दर से बोनस दिया जाय और आज हम सभी जान रहे

हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोल्हू आज जो हमारे सरकारी रेट हैं, उससे ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान कर रहे हैं।

मान्यवर, कृषि शोध और कृषि शिक्षा पर और गन्ना पर बजट बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सहकारी रमाला चीनी मिल में एथेनाल ब्राण्ड लगाए जाने की सख्त आवश्यकता है, जिससे न केवल मिल की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि गन्ना किसानों के भुगतान में भी मदद मिलेगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और तो और पेट्रोल में जो एथेनाल मिलाया जाता है और इसके मिलाने से जो हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा पेट्रोल आयात करने में खर्च करते हैं उसकी भी बचत होगी। मान्यवर, एथेनाल को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में नेशनल हाई-वे दिल्ली-सहारनपुर से लेकर सड़क मार्ग स्ट्रेट हाई-वे बड़ौत मार्ग को जोड़ने वाला एक रिजवाड़ा नहर है उसकी पटरी पर पिछले लम्बे समय से एक सड़क जलमार्ग की जनता द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन खेद है कि उस पर अब तक समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे दिल्ली-सहारनपुर रोड से बड़ौत मार्ग को जोड़ने वाले रिजवाड़ा रजवाहे की पटरी पर सड़क निर्माण कराया जाए। मान्यवर, बड़ौत नगर जो बागपत जनपद का सबसे बड़ा नगर है, उसमें सौ बेड के अस्पताल की नितांत आवश्यकता है, जिससे ढ़ाई से तीन लाख की आबादी लाभान्वित होगी। पूर्वी यमुना नहर की पुनर्स्थापना कराई जाए, पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर शामली बागपत गाजियाबाद की लाईफ लाईन है, जिससे उन जनपदों में सिंचाई होती है, लेकिन खेद है कि बहुत अधिक सिल्ट जमा हो जाने के कारण हमारी इस नहर की सिंचन क्षमता बहुत बिगड़ती जा रही है इसलिए पूर्वी यमुना नहर की पुनर्स्थापना शीघ्र कराई जाए। मेरे क्षेत्र में गन्ने की बहुत सड़के हैं और उनकी स्थिति बहुत खराब है। मेरा अनुरोध है कि गन्ना स्वामित्व वाली सड़कें जैसे नयनल से डांगमोली, सबगा से बड़ौत सम्पर्क मार्ग, बुढ़ाना रोड से मांगरौली, चिड़चिडा रोड से हिडन की ओर जाने वाला सम्पर्क मार्ग, चिड़चिडा से इण्टर कालेज कमाला रोड से हजूरा बाग रवि का दूसरा भाग, रमाला से सेण्टीमार्ग का प्रथम भाग, अंगदपुर आर्य समाज मन्दिर से बड़ौत मार्ग, मलिकपुर छपरौली रोड से पश्चिम घाट घास की पटरी पर निर्माण शीघ्र कराया जाए। इसी तरीके से कण्डेरा से बामलौली से सम्पर्क मार्ग की स्थिति भी बहुत दयनीय है, उसके निर्माण के लिए भी निश्चित, सुनिश्चत कार्यवाही होनी चाहिए। अन्त में मेरे विधान सभा क्षेत्र के टैना गांव में पी0एच0सी0 की बहुत सख्त आवश्यकता है। मान्यवर, यह गांव शुरू हरियाणा से मिलता हुआ है और यमुना के किनारे बसा हुआ है और दस से पन्द्रह हजार की आबादी वाला गांव है, उसमें पी0एच0सी0 की सख्त आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, यह जो सरकार की तरफ से भारी-भरकम बजट 7 लाख 36 हजार करोड़ से ऊपर का दिया गया है, यह बजट दिशाविहीन है,

अधिकारियों द्वारा बनाया गया मकड़जाल है एवं झूठ का पुलिंदा है और यह मुंगरी लाल के हसीन सपने जैसा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जहां पर देश के अन्य राज्यों में कृषि पर साढ़े पांच परसेण्ट आवंटन बजट का है, वहीं उत्तर प्रदेश में ढाई से तीन परसेण्ट है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा बजट अगर कृषि का बढ़ता तो सरकार के पास व्यवस्था होती, जो कृषि में उपकरण हैं, जो खेती किसानी में लगते हैं उसके दाम कम करने में मदद मिलती। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि उपकरणों पर सरकार बड़े पैमाने पर जी0एस0टी0 ले रही है। जैसे ट्रैक्टर पांच से दस लाख का मिलता है कम्बाइंड पच्चीस लाख का मिलता है। थ्रेसर एक लाख का मिलता है, भूसा मशीन साढ़े तीन लाख की मिलती है, लेजर लैण्ड लेवलर ढाई लाख का, डिस प्लाऊ 40000 का, मिट्टी लोडर 3 लाख का आदि। मान्यवर, इस तरह 44 लाख से ऊपर के उपकरण कृषि में एक किसान के लगते हैं और सरकार जी0एस0टी0 के रूप में 7 लाख 54 हजार रुपये लेती है और मान्यवर, इतना ही नहीं कृषि के उत्पादन के बाद जो पराली नष्ट करने के उपकरण जिस पर भारत सरकार भी चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और हम भी चिंतित हैं। जैसे सुपरसीडर, पैडीस्ट्रॉचापर और मल्चर पर मान्यवर, इसकी लागत 07 लाख है और इस पर जी0एस0टी0 लेते हैं 84000 तो की कीमत हो जाती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि सरप्लस रेवेन्यू इनके पास है तो मैं सरकार से माँग करता हूँ कि यदि बजट में प्राविधान नहीं कर पाये हैं या ये केन्द्र सरकार से इस पर जी0एस0टी0 नहीं कम करा पा रहे हैं तो तब तक कम से कम इन पर सब्सिडी देकर किसानों की लागत कम करने का काम करें।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मान्यवर, स्थिति यह है कि अमेरिका में 95 प्रतिशत कृषि में मशीनीकरण की दर है, ब्राजील में 75 परसेन्ट है, चीन में 57 परसेन्ट है और हिन्दुस्तान में यह मात्र 40 से 45 परसेन्ट है इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि सब्सिडी देकर यह जी0एस0टी0 को कम करें जिससे किसानों की लागत कम हो। मान्यवर, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ना मूल्य पर मा0 गन्ना मंत्री जी लगातार बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मैंने रिकार्ड भुगतान किया है। मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, कभी नहीं कहते कि भुगतान न करने का रिकार्ड है। मैं कहना चाहता हूँ दावे के साथ मा0 मंत्री जी से वह यहाँ पर नहीं है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जनपद में वॉल्टरगंज मिल है जो कि 2017-2018 से बन्द है और उस पर किसानों का 50 करोड़ का बकाया है लेकिन सरकार अभी तक भुगतान करने पर गम्भीर नहीं है। इसी तरीके से मान्यवर, आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अठदमा शुगर मिल है उस पर भी 40 करोड़ का बकाया है जिसका की भुगतान नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, शिक्षा के मामले में मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2016-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सामान्य और अनुसूचित समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए 2633 करोड़ रुपये का प्राविधान था और आज की तारीख में 25 परसेन्ट बच्चों की संख्या बढ़ गई और आज 24-25 के बजट में मात्र 1882 करोड़ का प्राविधान है बजट उठाकर आप देख लें।

संख्या बढ़ी है और बजट घट गया है और वहीं पिछड़े समाज की स्थिति भी है। जहाँ डेढ़ करोड़ बच्चे पढ़ते हैं बजट में मात्र 2475 करोड़ का इनके पास इंतजाम है। एक बच्चे पर यदि आप निकाल लें तो मात्र 13000 रुपये आता है और आप से कह दूँ मान्यवर, आई0टी0आई0 का छात्र हो उसकी 16000 से 25000 तक की फीस है, कोई डिप्लोमा का छात्र हो तो उसकी 54000 की फीस है और यदि कोई डिग्री का छात्र है तो मान्यवर, उसकी 74000 से साढ़े तीन-चार लाख तक की फीस है तो मान्यवर, कैसे छात्र पढ़ सकते हैं। मान्यवर, यह सरकार गरीबों को शिक्षा से बाधित कर रही है और इतना ही नहीं जब पिछली सरकार थी तब पिछड़े समाज के व अनुसूचित समाज के बच्चे अपने कोटे से ऊपर पढ़ते थे। शून्य पर प्रवेश था, लोगों को फीस मिलती थी, प्रतिपूर्ति मिलती थी आज अनुसूचित समाज की 22.5 प्रतिशत के स्थान पर 7 से 9 परसेन्ट बच्चों के पढ़ने की स्थिति हो पा रही है, पिछड़ा समाज की स्थिति भी खराब है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार जो रामराज्य की बात करती है। यह बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। इसी पर चार लाइन मान्यवर, कहना चाहूँगा कि शिक्षा से वंचित कर बड़े-बड़े जहाज इत्मीनान से डुबोये जा रहे हैं। स्कूल कालेज बन्द कर लोग मेलों, रैलियों में बुलाये जा रहे हैं। समूह, सखी, श्रमिक बनाकर लोग गुमराह किये जा रहे हैं। हे आदमी, तू लेता रहे मुफ्त का अनाज व चंद पैसे के आनंद का सफर तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार की व्यवस्था है।

मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी किसानों का दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया था आज 7 वर्ष बीत गया, वह बढ़ा नहीं है, यह कम से कम 10 लाख किया जाना चाहिए। मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत में बड़ी-बड़ी बातें लोग करते हैं कि हमने 5 लाख प्रति व्यक्ति इलाज के लिये रुपया दे दिया है। इन्होंने यह भी कह दिया कि 6 से जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक होगी उसी को देंगे। मान्यवर, क्या 6 से कम वाले गरीब नहीं हैं। गरीब 6 से कम वाले भी हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम दो, हमारे दो। हम दो हमारे दो तो चार होंगे न, यदि आप उनको नहीं दे रहे हैं तो दे किसको रहे हैं। यह भी धोखाधड़ी है यदि सबको देना चाहेंगे तो कम से कम 10 करोड़ से अधिक उससे लाभान्वित हो जाएंगे। यह कम से कम होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों को उठाना चाहूँगा हमारे यहाँ जो जो अमरौली जुमाली अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं हैं, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट के बल पर चल रहा है। मान्यवर, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मान्यवर, अपनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों के बारे में आपसे कहूँगा, दाउदपट्टी से तेलियाडीह मार्ग बनाया जाना जरूरी है, जिसकी 01 किमी0 लम्बाई है। सगरा-हरिहरपुर, चौसार मार्ग, साढ़े तीन किमी0 का बनाया जाना जरूरी है। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि हनुमानगंज-सुरवार मार्ग से बड़ी बनकटिया मार्ग को बनाया जाना जरूरी है। दुद्राक्ष से सोनबरसा मार्ग बनाया जाना जरूरी है। एल0डी0 मार्ग से विशुनपुरवा से हनुमानगंज दानोकइया मार्ग जो संतकबीरनगर को जोड़ता है, ओ0डी0आर0 में उसे बनाया जाना जरूरी है। मान्यवर, कुवानो नदी पर भैसहियाँ घाट, पगारे घाट, बालकघाट पर पुल बनाया

जाना जरूरी है। मान्यवर, पर्सोहिया और छपिया जो आमी नदी पर हैं, वहाँ पुल बनाया जाना जरूरी है। मान्यवर, आपसे कहना चाहूँगा कि तुरकोलिया, अमरेडीहा से नौवडिहवा तक मार्ग बनाया जाना जरूरी है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मथुरापुर दुसलवा मार्ग का निर्माण भी जरूरी है। गरथा ड्रेन की खुदाई नहीं हुई है, उसको भी किया जाना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, अंत में आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह बजट किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, अनुसूचित-पिछड़ा विरोधी है, मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है, अधिकारियों द्वारा बनाया गया मकड़जाल, झूठ का पुलिन्दा है। मान्यवर, मैं माननीय ओम प्रकाश जी के द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री सुरेश कुमार-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2024-25 के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह बजट 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ से अधिक का है। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं देख रहा हूँ, लगातार विपक्ष के लोग, सपा के लोग, राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं और राम मंदिर के निमंत्रण का विरोध करते हैं।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

विरोध कोई नहीं करता है।

श्री सुरेश कुमार-

अध्यक्ष जी द्वारा दिये गये निमंत्रण का भी इन्होंने विरोध किया, लेकिन राम सबके हैं, सभी धर्मों के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है-

'जथा भूमि सब बीजमय, नखत निवास अकास।
रामनाम सब धरममय, जानत तुलसीदास।'

यानी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे सारी धरती बीजों से भरी पड़ी है और सारा आकाश नक्षत्रों से भरा पड़ा हुआ है, उसी तरह सारे धर्म रामनाम में समाये हुए हैं। देशभक्तों से ही देश की शान है, रामभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के वासी हैं, जिस देश का नाम हिन्दुस्तान है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र को अभी एक नई इण्डस्ट्रियल एरिया देने का काम किया है। यह 148 हेक्टेयर में बनेगी और 1 अरब 56 करोड़ रुपये किसानों को जो मुआवजा मिलना है, उसकी धनराशि भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृत कर दी है। मैं माननीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इन्हौना से सुकुल बाजार होते हुए रूदौली तक 18 किमी0 सड़क स्वीकृत कर दी है और राज्य मंत्री जी का भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वहाँ माँ कामाख्या धाम है, उसके विस्तार के लिए भी एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। एक नया कस्तूरबा विद्यालय भी हमारे शुकुलबाजार ब्लाक को दिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण माँगे हैं, उनकी मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ। एक नया थाना जामू ब्लाक में कृष्णनगर में बनाने की माँग करता हूँ। राजकीय बालिका इण्टर कालेज और डिग्री कॉलेज, बाजारशुकुल में बनाने की माँग करता हूँ। जगदीशपुर ब्लाक में राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज बनाने की माँग करता हूँ। जगदीशपुर एवं बाजारशुकुल को नगर पंचायत की बनाने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर ऐसी है कि वह तीन तहसीलों से लगती है। लेकिन एक भी तहसील हमारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर नहीं है। मैं जगदीशपुर तहसील बनाने की माँग करता हूँ। हलियापुर जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर जो पी0एच0सी0 है, उसको सी0एच0सी0 बनाने की माँग करता हूँ। हमारी सरकार गाँव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर, नौजवान सबके उत्थान के लिए काम करती है। 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया, 63 हजार करोड़ रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया। महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया। मान्यवर, वृद्धा पेंशन को 500 रुपये से बढ़ा कर 1 हजार रुपये किया। गरीबों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपये अनुदान देने का काम किया है। जनधन योजना के माध्यम से 9 करोड़ खाते खुलवाने का काम किया। हर जिले में डायलसिस की व्यवस्था करने का काम किया है जिससे हमारे अमेठी जिले को भी इसका लाभ मिला है। विपक्ष के लोग डाक्टर-डाक्टर की बात करते हैं लेकिन जब इनकी सरकार थी तब एम0बी0बी0एस0 की सीटें बढ़ाने का काम नहीं किया, हमारी सरकार ने निजी क्षेत्रों में 2550 से बढ़ा कर 5250 सीटें करने का काम किया, सरकारी क्षेत्र में 1890 से बढ़ा कर 3828 सीटें करने का काम किया है। कानून व्यवस्था हमारी सरकार की जिस तरह है यह जगजाहिर है किसी से छिपा नहीं है। टैबलेट, स्मार्ट फोन के लिए 4000 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देकर सबका सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। बिजली आपूर्ति शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी तरह रही है। पी0एम0 आवास आज गरीबों को मिल रहा है उससे गरीब खुशहाल है। उज्ज्वला योजना से आज लोग अच्छादित हो रहे हैं। बेसिक शिक्षा में सुधार किया गया है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का स्थान चमकाने का काम किया गया है। मैं विपक्ष के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ।

अगर ये लोग नदी के किनारे बस जाते,
तो लोग एक बूंद पानी के लिए तरस जाते।
ये तो कहो ऊपर वाले के आगे इनकी चलती नहीं,
नहीं तो बादल इन्हीं के खेत में बरस जाते।

मान्यवर, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, मैं मा0 प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 आडवानी जी को भारत रत्न मिला, इसके लिए भी मा0 प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, हम उदा देवी पासी को भारत रत्न देने की माँग करते हैं। 1857 में जनरल कालिन कैमवेल जिन्होंने लखनऊ को चारों तरफ से घेर लिया था और उदा देवी ने अपनी पिस्तौल से उन 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था मैं आपके माध्यम से भारत रत्न देने की मांग करता हूँ। मान्यवर, यह पी0डी0ए0, पी0डी0ए0 की बात करते हैं लेकिन पी0डी0ए0 का मतलब है, परिवार डेवलपमेंट अथार्टी, यह केवल अपने परिवार को डेवलप करना चाहते हैं, इनका पी0डी0ए0 का मतलब यही है। मान्यवर, मैं दो बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका भेजा। जब वहाँ से हनुमान जी लौट कर आये तो उन्होंने जब अपना वृतान्त सुनाना शुरू किया तो अन्त में उन्होंने कहा, प्रभु मुझसे एक गलती हो गयी है, मैं क्षमा चाहता हूँ तो प्रभु श्री राम ने कहा क्या गलती हो गयी है, उन्होंने कहा मैंने बगैर आपकी आज्ञा के सारी लंका को जला कर राख कर दिया है। उसी तरह यह जो राम सेना इधर बैठी है, स0पा0 के रावण रूपी राज को समाप्त करके 2024 में 80 की 80 जीतेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद सरोज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-2025 के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय योगी जी की सरकार के इस पुनीत ऐतिहासिक बजट से निःसन्देह उत्तर प्रदेश के हर वर्ग एवं हर क्षेत्र का विकास होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था में पहले से अब में काफी सुधार हुआ है लेकिन गांव में जो ट्रांसफारमर लगे हुए हैं आपने देखा होगा कि वह हमेशा ओवरलोड हुआ करते हैं, हम चाहते हैं कि ओवरलोड लगे हुए ट्रांसफारमरों की क्षमतावृद्धि करायी जाय। हम आपसे ये भी चाहते हैं कि जो विद्युत सब-स्टेशन बने हुए हैं उनकी भी क्षमता बढ़ाकर बड़ा सब-स्टेशन बनाया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों को बड़ी समस्या है, आवारा पशु किसानों के खेतों में बड़ी संख्या में झुन्ड बनाकर फसलों को खाये जा रहे हैं। सरकार की ओर से उनकी रोकथाम के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इनके कारण किसान रात-दिन खेतों की तकवाही करता है तब जाकर कहीं फसल को बचा पाता है। हम सरकार से चाहते हैं कि किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों की बेरीकेटिंग करने के लिए ब्याजमुक्त ऋण दिया जाय, जिससे किसान अपने खेतों की बेरीकेटिंग कराकर अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जल जीवन मिशन के तहत् जो गांव में पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है, उसमें जब ठेकेदार गांव में जाते हैं तो हमारी जो सड़कें और खड़ंजे लगे हुए हैं उनको खोदकर पाइप डालते हैं लेकिन सड़क जो पहले बनी रहती है उस तरह से बनाने का काम नहीं करते हैं जिससे गांव

वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, असाध्य रोगों की मुक्त चिकित्सा सुविधा के लिए प्रस्तावित आगामी बजट में 125 करोड़ रुपए की धनराशि कम है, इसे बढ़ाने का कष्ट करें जिससे असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को पूरा लाभ मिल सके। मौजूदा सरकार द्वारा प्रदेश में कई एक्सप्रेस-वे बनाये जा रहे हैं, इसी क्रम में हमारे क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे की परियोजना का कार्य चल रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे बनने से ग्रामीण सड़कें अत्यधिक लोड की ट्रकें चलने से खराब हो रही हैं, हम चाहते हैं कि गंगा एक्सप्रेस-वे बनने के बाद हमारी ग्रामीण सड़कों को भी बनाने का काम किया जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र बाबागंज, जनपद प्रतापगढ़ में निम्नलिखित सड़कें काफी खराब हैं जिससे आवागमन काफी दुरूह हो जाता है। ये सड़के हैं ताजपुर लरू केसरी का पुरवा विदासिन लाखीपुर-मनगढ़ वाया बल्ला पींग होते हुए अवसानगंज मार्ग, परियावां से लवाना मार्ग, सगरा बाबूगंज डेरवा-गलगली वाया गरीबपुर-रायपुर-काशीपुर डुबुकी होते हुए हरिहरपुर पीजेएल मार्ग, वाजिदपुर-झोकवारा मार्ग वाया कुसुवापुर-छाछामऊ होते हुए लालगंज-कालाकांकर मार्ग, बाघराय से राजापुर वाया कुशहा पटना नहर चौराहा-पूरे हरिकेश-बदगवाँ गिस्था होते हुए (लखपेड़ा) बिहार बाबागंज मार्ग एवं कन्हैयानगर से रामबन गमन मार्ग, ये काफी खराब सड़कें हैं, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि उपरोक्त सभी सड़कों का चौड़ीकरण और सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाय जिससे क्षेत्र वासियों को आने जाने में सुविधा मिल सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा बाजार में वर्ष 2007-08 में निर्माणाधीन था जो कि आधा-अधूरा बनकर पड़ा हुआ है। उसकी आधी-अधूरी बिल्डिंग में क्लॉस नहीं चलती है बल्कि आईटीआई छात्रों के एडमिशन एवं पढ़ाई का काम प्रतापगढ़ जनपद जिला मुख्यालय पर किया जाता है जो कि हमारी विधान सभा क्षेत्र से काफी दूर पड़ता है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो आधा-अधूरा आईटीआई कालेज बना हुआ है उसको पूरा कराया जाय ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे वहां पढ़ सकें। मेरी विधान सभा बाबागंज एवं बगल की विधान सभा क्षेत्र कुण्डा में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए हीरागंज रजबहा एवं मानिकपुर रजबहा मुख्य नहर है जिससे खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं आ पाता है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि उपरोक्त रजबहों का परियोजना बनाकर चौड़ीकरण कराया जाय जिससे किसानों को समय पर और पर्याप्त पानी मिल सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बेसिक शिक्षा के शिक्षकों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण 2023 में किया गया लेकिन भारांक प्रणाली में कुछ कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अध्यापक अपने गृह जनपद के आस-पास अभी तक नहीं आ पाये हैं, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए कोई ठोस नीति बनाकर अध्यापकों की समस्या का समाधान करे।

मा0 अधिष्ठाता महोदय हमारी विधान सभा क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई भी स्टेडियम क्षेत्र में नहीं है। जिस कारण से बच्चों को खेलने में असुविधा होती है, मैं सरकार से मांग

करता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र बाबागंज में एक स्टेडियम बनवाया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चों को खेलने का अवसर प्रदान हो सके। महोदय आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।'

***श्री शफीक अहमद अंसारी-**

मा0 अधिष्ठाता महोदय इस सम्मानित सदन में आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के समर्थन में मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में मा0 मुख्य मंत्री जी के एवं अपना दल सोनेलाल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहिन अनुप्रिया पटेल जी के अतुल्य सहयोग से बनी सरकार द्वारा 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। जोकि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में वेटिकन सिटी को मात देते हुए उत्तर प्रदेश को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश को दुनिया में प्रथम स्थान दिलाने का काम किया गया है। वेटिकन सिटी में लगभग 90 लाख लोग धार्मिक पर्यटन के लिए जाते हैं। वही अकेले वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद, लगभग 4 करोड़ लोग धार्मिक पर्यटन के लिए जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने के बाद से यह संख्या 10 करोड़ के ऊपर चली जाएगी और पर्यटन उद्योग को उत्तर प्रदेश के राजस्व में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण उद्योग बन जाएगा। महोदय 22 जनवरी, 2024 को सनातन संस्कृति के आदर्श और हम सबके प्रभु राम जन्म भूमि अयोध्या में विराजमान हो गए, इससे भारत के साथ-साथ पूरे विश्व ने आलौकिक अवसर का साक्षात किया, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी और मा0 योगी जी का कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं।

महोदय मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में काफी कुछ काम होने के लिए है। जैसे कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लाक है, 219 बी0डी0सी0 मेम्बर उस ब्लॉक में हैं और दो तहसीलों का एक ब्लॉक है। अगर वह एक टांडा ब्लॉक बन जाता है तो उससे क्षेत्र के लोगों की समस्या का काफी समाधान हो जाएगा। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र में दड़ियाल, टांडा, स्वार में डिग्री कालेज की बहुत आवश्यकता है। यदि इन तीनों जगह पर डिग्री कालेज बन जाता है तो लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र स्वार में मण्डी समिति की जगह नहीं है, वहां पर अगर मण्डी समिति की स्थापना हो जाती है तो बहुत लोगों को उसका लाभ मिलेगा। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मजबासी बिजली घर के सामने से खुशाहलपुर के मोड़ तक डामरीकरण हो जाता है, तो उससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। महोदय स्वार नगर पालिका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टांडा में रोडवेज बस अड्डा नहीं है, यह देश जबसे आजाद हुआ है वहां पर दो बार को छोड़कर के लोकल का कोई विधायक नहीं रहा है। मैं पहली बार अपना दल टिकट पर भाजपा एन0डी0ए0 गठबन्धन के रूप में चुनाव जीता हूं, चूंकि पिछड़ा इलाका है, वहां पर अगर यह काम हो जाते हैं तो बहुत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र 34 में मा0 योगी जी ने 144 करोड़ की लागत से स्वार बाजपुर की रोड का पैसा स्वीकृत किया है, यह बहुत बड़ा कार्य है। महोदय मेरी विधान सभा क्षेत्र उत्तराखण्ड से सटी हुई है। तथा पर्यटन स्थल क्षेत्र है। विगत 30 वर्षों से विपक्षी पार्टी के मा0 सदस्यगण द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य नहीं कराये गये हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहां पर जब-जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, तो जहाँ से मैं विधायक चुनकर आया हूँ, तो वह केन्द्र शासित प्रदेश हो जाता है। इसलिए हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि ये सब काम हमारे क्षेत्र में हो जाते हैं, तो वहाँ की जनता को काफी लाभ मिलेगा। आज बजट के समर्थन में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप का, विधान सभा के सभी मा0 सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री जय प्रकाश अचंल-

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारी भरकम बजट आम जनता को देने का वादा किया है। अगर उसको देखा जाए, तो हर तरह से जनता को छलने का वादा किया जा रहा है। आज मैं अपने नेता मा0 श्री ओम प्रकाश जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में नौजवानों के लिए बड़ा पिटारा खोलने का काम किया है। आज हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जनपद बलिया की तरफ ले जाना चाहते हैं। बलिया जनपद आज उद्योग विहीन जनपद है। वहाँ पहले दो ही उद्योग थे, एक चीनी मिल और दूसरा कताई मिल। चीनी मिल बन्द पड़ी है और कताई मिल भी बन्द पड़ा हुआ है। मैं चीनी मिल को पुनः चालू कराने की सरकार से अपील करता हूँ।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, गंगा और घाघरा नदी के बीच का तटवर्ती इलाका और बिहार प्रान्त से लगभग तीन तरफ से घिरा हुआ हमारा जनपद है। सरकार ने वादा किया था 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट'। आज किसी को पता नहीं है कि ये सरकार बलिया में कौन सा बड़ा उद्योग लगाने का वादा किया है? वह कब तक लग जायेगा, उसके लिए कितना बजट दिया गया है। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल जायेगा, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है? ऐसी हालत में अपने विधान सभा क्षेत्र बैरिया की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए बहुत वादा किया है, जबकि बलिया का 40 प्रतिशत हिस्सा आज भी बरसात के समय बाढ़ की त्रासदी से बेहाल हो जाता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया के गंगा घाघरा नदी की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में गंगा नदी की भीषण तबाही से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही दुबेछपरा रिंग बांध टूट गया था और मा0 मुख्य मंत्री जी उस बाढ़ के निरीक्षण में भी गये हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक उस रिंग बांध का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण लगभग पचासों हजार की आबादी जल मग्न हो जाती है, चाहे सुधरछपरा, केहरपुर, दुबेछपरा, उदईछपरा, गोपालपुर, भुआलछपरा, नौरंगा, बहुआरा, शिवपुर, सेमरिया, गड़ेरिया, जगदीशपुर, नरदरा व भुसौला आदि गाँव गंगा नदी से तबाह हो जाते हैं और रोक-थाम के लिए कोई उपाय नहीं हो पाता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी तरह से घाघरा नदी के गोपालनगर और सिवाल मठिया गाँव में घाघरा नदी से काफी कटान हुआ है। लगभग सैकड़ों घर घाघरा नदी में विलीन हो गये। वे लोग विस्थापित हो करके कहीं न कहीं बन्धे के किनारे शरण ले करके आज भी बसे हुए हैं। सरकार की तरफ से बार-बार पत्र लिखने के बाद, माँग करने के बाद तथा विधान सभा में प्रश्न लगाने के बाद भी न तो उन लोगों को बसाने का कोई इंतजाम किया गया, न ही उनके लिए बिजली का कोई इंतजाम किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि गंगा और घाघरा नदी के बाढ़ से विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा जमीन क्रय करके उन्हें बसाया जाए। प्रधानमंत्री व मुख्य मंत्री आवास से उन्हें सुसज्जित किया जाए। उन गाँवों में विद्युतीकरण की व्यवस्था करायी जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, रहा सवाल सड़कों का तो सरकार ने वायदा किया था कि हमारी सरकार दिसम्बर महीने तक गड्ढा मुक्त कर देगी। सरकार वायदा और घोषणा तो कर देती है, लेकिन आज सड़कों की हालत देखी जाए तो बहुत ही खराब है। बिहार प्रदेश से जुड़ा हमारा विधान सभा क्षेत्र है। दलन छपरा से लेकर खवासपुर की सड़क चलने योग्य नहीं है, वह बिहार बार्डर को जोड़ती है। दूसरी सड़क भगवानपुर से रामनगर की सड़क है, गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं हो पायी है। तीसरी सड़क सुरेमनपुर का मुख्य मार्ग है गोपाल नगर तक जाती है, उस सड़क की वही स्थिति है। रेवती भोपालपुर मार्ग भी गड्ढा युक्त है। दतहां नूरपुर मार्ग की भी वही स्थिति है। मानगढ़ बिन्द टोली होकर पंचायत भवन गोपाल नगर तक जाने वाली सड़क की वही स्थिति है। सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से लेकर उपाध्यायपुर चाई छपरा मार्ग की वही स्थिति है। दयाछपरा प्रसाद छपरा मार्ग, दयाछपरा बुधन चक मार्ग, दयाछपरा ढाला से जगदेवा पाण्डेयपुर मार्ग, मुरली छपरा से लालगंज तक की सड़क पूर्णतः टूट चुकी है, लेकिन सरकार की दृष्टि उन सड़कों की ओर नहीं गयी है, न ही उसके लिए कोई बजट की व्यवस्था की गयी है। ऐसे हालात में हम निवेदन करना चाहते हैं कि जब सरकार ने वायदा किया है कि हम सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करेंगे तो सरकार को उस पर धन देकर गड्ढा मुक्त करना चाहिए, लेकिन सिर्फ झूठे वायदे किये हैं। इसी तरीके से मा0 मुख्य मंत्री जी की ओर से घोषणा हुई थी कि मैं प्रदेश के समस्त विधायकों को 07 करोड़ निधि सड़कों के लिए देने का काम करूंगा, वह भी

एक छलावा रहा। रहा सवाल विद्युतीकरण का तो मा0 ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की थी कि हम गांवों को 18 घण्टे से अधिक बिजली, तहसील मुख्यालयों को 22 घण्टे और जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे बिजली देने का इंतजाम कर रहे हैं। आप सभी सम्मानित सदस्यगण हैं। आप लोग अपने-अपने क्षेत्र की हालत जानते होंगे कि किस तरीके से बिजली की व्यवस्था गांवों, नगर पंचायतों या जिला पंचायतों के लोगों को मिल रही है। अब तो लखनऊ में भी देखा जाए तो घण्टे-घण्टे बिजली कट रही है तो गांवों के लोगों की क्या हालत होगी? आए दिन बिजली की आंख मिचौली हो रही है। ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं, पोल टूट जाता है, तार टूटकर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं, लेकिन बिजली विभाग का कोई अधिकारी उन्हें मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मैं अपने क्षेत्र बैरिया के उन ग्रामीण अंचलों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकार ने अमृतकाल योजना के अन्तर्गत समस्त गांवों का विद्युतीकरण कराने के लिए वायदा किया था। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के चांददीयर के मौजा फिरंगी टोला, नई बस्ती, गोपालनगर आदि की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री राम अवतार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 2024-25 के अनुमानित बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं इस सदन को और नूरपुर विधान सभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है। मैं सबसे पहले अपनी विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद हरिद्वार रोड के किमी0-49 से अलादीनपुर के लिए एक रोड जाती है, जो अभी तक नहीं बनायी गयी है, उसमें दोनों तरफ बस्तियां हो गयी हैं, सड़क गहरी हो गयी हैं, पानी भरा रहता है। मेरे यहां विकास खण्ड बुढनपुर में एक कडूला नदी पड़ती है, गल्लाखेड़ी के पास 110 मी0 लम्बे पुल की बात पिछली बार भी मैंने सदन में रखी थी। मैं इस पुल और सड़क के सम्बन्ध में याचिका में, नियम-51 में, नियम-301 में लगा चुका हूं, स्वीकृत भी हो चुकी हैं, मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से मिला हूं, कई बार मा0 मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, लेकिन आज तक मेरी विधान सभा क्षेत्र में यह दोनों काम नहीं हुए हैं।

मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत राजा का ताजपुर है। जिसको नगर पंचायत घोषित करने के लिए मैने पिछली बार भी सदन में रखा था और इसके बाद इसके लिए मैं एक बार लिख चुका हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम हलदुआमाफी से एक सड़क काठ के लिए जाती है जो काठ की ओर से कडूला नदी के पुल तक पक्का बना है लेकिन कडुला नदी से लेकर रामपुर तक करीब तेरह सौ मीटर लम्बी वह रोड है वह अभी तक नही बनाई गई है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में सी0एच0सी0 है नूरपुर सी0एच0सी0 में डाक्टरों की तैनाती के लिये पिछली बार भी मैं बजट पर बोला था और मैंने सदन में भी यह निवेदन

किया था कि वहां पर चिकित्सकों की भी नियुक्ति कर दी जाये। लेकिन मेरे निवेदन के बाद आज तक एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति वहां पर नही की गई। जबकि वहां पर बहुत संख्या में डिलीवरी होती है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी राजकीय इण्टर कालेज छात्रों के लिए नहीं है और न ही छात्राओं के लिए है मै निवेदन करता हूँ कि बालक और बालिकाओं के लिए एक-एक इण्टर कालेज बनवाने का काम करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय काफी दूर पड़ता है तो मैं चाहता हूँ कि वहां पर एक अग्निशमन केन्द्र बनाया जाये। तदवा सहसपुर से मेवा जट कुमखिया मार्ग है जो जनपद अमरोहा को जोड़ने का काम करता है यह मार्ग काफी तंग है तो मेरा एक निवेदन है कि इस पर चौड़ीकरण करा जाये। मेरी विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में दो ब्लॉक पड़ते हैं।

(इसी मध्य 07 बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि दोनो ब्लॉक में एक-एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र ही नही बल्कि पूरे जनपद में पाल, धनगर जाति के लोग काफी संख्या में रहते हैं लेकिन आज तक पहले तो उनको सर्टिफिकेट जारी होते थे लेकिन वर्तमान में उस जाति के लोगों को धनगर प्रमाण-पत्र नही जारी होते हैं तो इस सदन के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी इन समस्याओं का समाधान कराया जाये। मैं जब इस सदन में आया था और इस सत्र में मुझे ऐसा लग गया कि जैसे सदन में हम लोकतंत्र के भवन में न आकर एक किसी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो गये हैं कि जहां दिन भर धार्मिक बातें होने का काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मठों में बैठकर पूजा-पाठ करना चाहिए था वह लोग राजनीति कर रहे हैं और जिन लोगों को राजनीति करना चाहिए था लोकतंत्र के हिसाब से वह धर्म की बाते करने का काम कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नौजवान इस सरकार की तरफ बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहा है। आज इस बजट में रोजगार के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नही की गई है। मैं चूंकि सैनी जाति से आता हूँ जब हम कभी भी अपना इतिहास देखते हैं तो यह माना जाता है कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, शत्रुघ्न के पुत्र हमारे वंश प्रवर्तक रहे हैं लेकिन आज यह महसूस होता है कि जैसे इसका नाम का टैग मार्क किसी और ने ले लिया है और यह खुशी की बात है कि 22 तारीख को भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है लेकिन भगवान श्रीराम निश्चित रूप से देख रहे होंगे कि इस प्रदेश में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, क्या हो रहा है महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। निश्चित रूप से वह मणिपुर की घटना भी देख रहे होंगे वह जुल्म ज्यादती भी देख रहे होंगे, वह थानों को भी देख रहे होंगे, वह तहसीलों को भी देख रहे होंगे कि कैसे उनके साथ जुल्म ज्यादती होने का काम कर रहे हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी यह नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास अगर सबका साथ और सबका विकास करना है तो निश्चित

रूप से यह जरूरी है कि जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना जब होगी तभी सबका साथ सबका विकास हो सकता है। नहीं तो सबका विकास नहीं हो सकता है। जो इतना भारी भरकम बजट रखा गया है उस बजट में निश्चित रूप से असंतुलन पैदा होगा गरीब और गरीब होगा और कुछ लोगों को मालदार होने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं इस बजट पर से अपने जो नेता हैं जो हमारे पार्टी के नेता हैं माननीय ओम प्रकाश जी उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ और निश्चित रूप से यह उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने समस्याएं रखी हैं मैंने याचिका के माध्यम से रखी, नियम-51 में रखी, नियम-301 में रखी लेकिन मेरा कोई कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। उधर के लोग यह कहते हैं कि हमारी चौदह किलोमीटर बन गई पंद्रह किलोमीटर बन गई लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक भी नयी सड़क पिछले दो साल में अभी नही स्वीकृत हुई आपके माध्यम से यह निवेदन है कि संतुलन बनाने का काम करें और नूरपुर विधान सभा की क्षेत्र की जनता आपकी तरफ देख रही है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आराधना जी, क्या आपकी पार्टी के मा0 सदस्य वीरेन्द्र चौधरी जी बोल चुके हैं ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, वह बोल चुके हैं।

(इसी मध्य सदस्य श्री समरपाल सिंह जी के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 समरपाल जी, आपका नम्बर अभी आयेगा। मा0 राजेश्वर सिंह जी, आप बोलना प्रारम्भ करें।

श्री राजेश्वर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आपकी सौम्यता, आपकी दृढ़ता, आपका संसदीय ज्ञान हम सबके लिये प्रेरणास्रोत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 22 जनवरी के भव्य प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये धन्यवाद देता हूँ। यह हमारी 5000 वर्ष की सनातन संस्कृति का एक स्वर्णिम क्षण था जिसके हम सब साक्षी बने हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने परम् श्रद्धेय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के लोकमंगल को समर्पित 07 लाख 36 हजार करोड़ का हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। आदरणीय सुरेश खन्ना जी की दूरदर्शी नीतियों के कारण तथा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के कारण आज उत्तर प्रदेश पिछले 05 वर्षों में अपने जी0एस0डी0पी0 को डबल कर चुका है।

आज हमारा जी0एस0डी0पी0 12 लाख करोड़ से 25 लाख करोड़ का हो चुका है। हमारा बजट जो 03 लाख 46 हजार करोड़ का हुआ करता था, आज वह 07 लाख 36 हजार करोड़ का हो चुका है। इस बजट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस बजट में 02 लाख 03 हजार करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्राविधान किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वह है जिससे आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजेश्वर जी, एक मिनट। जो हमारे नये मा0 सदस्य हैं अथवा जो लोग भी यहाँ पर बैठे है, मेरा उनसे निवेदन है कि मा0 सदस्य, राजेश्वर सिंह जी जो कह रहे हैं, उसको सुनें। विधान सभा में बैठने के बाद हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। बहुत सारे लोग अपने भाषण में केवल क्षेत्र की बातें करते हैं। मा0 सदस्य ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कही है तो उसकी तरफ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना क्या होता है। बजट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिये। मा0 राजेश्वर जी, सॉरी, मैंने आपका एक मिनट लिया। प्लीज, आप कन्टीन्यू करें।

श्री राजेश्वर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तथा आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी की यह दूरदर्शी नीतियाँ हैं कि उन्होंने 02 लाख 03 हजार करोड़ का प्राविधान कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिये किया है जिससे प्रदेश की आधारभूत संरचना का लगातार विकास हो रहा है। एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, हवाईअड्डे बन रहे हैं और सड़कों का जाल बिछ रहा है और सभी को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश ने 05 लाख 31 हजार करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है जो हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा है। महाराष्ट्र से ज्यादा हैं, कर्नाटक से ज्यादा है, आन्ध्र प्रदेश से ज्यादा है, तमिलनाडु से ज्यादा हैं। इसी कारण उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। नयी योजनाओं के लिये 24 हजार करोड़ का प्राविधान किया गया है। 74 हजार करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। बजट का फिजिकल डेफिसिट नियंत्रण में है। यह दिखाता है कि हमारा बजट कितना अच्छा है। सबेरे से वन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि वन ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। ऐसे ही लगता था कि हिन्दुस्तान की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी। हम किस गति से बढ़ रहे हैं इसकी किसी को कल्पना नहीं है। हिन्दुस्तान का पहला ट्रिलियन 60 साल में हुआ। दूसरा ट्रिलियन बनने में हमें 07 साल लगे। तीसरा ट्रिलियन बनने में हमें 05 साल लगे और अब हर 02 साल में हम 01 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। यह हमारे हिन्दुस्तान और हमारे प्रदेश की गति है। आज पूरा विश्व साढ़े तीन परसेंट की गति से बढ़ रहा है और हिन्दुस्तान 7 परसेंट के ग्रोथ रेट से लगातार आगे बढ़ रहा है। यह हमारी स्पीड है। इसके लिये मैं

आदरणीय खन्ना जी को, आदरणीय मुख्य मंत्री जी को तथा आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूँ कि यह उनका विजन ही है जिसके कारण हिन्दुस्तान आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे एयरोसिटी तथा स्टेट कैपिटल रीजन के प्रस्ताव पर विचार किया और उसको आगे ले गये। एयरोसिटी बनने से लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का फायदा होगा। एन0सी0आर0 की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनने से पूरे क्षेत्र का विकास होगा।

मान्यवर, मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो प्रस्ताव लम्बित चल रहे हैं जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कैम्पस जल्दी से सरोजनीनगर में स्थापित होगा और हमारा स्कूल ऑफ फॉरेन लैग्वेजेज का कैम्पस भी जल्दी ही स्थापित होगा। उनके आशीर्वाद से सरोजनीनगर में अब तक नेवल वॉर म्यूजियम स्थापित हो चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित हो चुका है और सरोजनीनगर हिन्दुस्तान के नक्शे पर आ रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बजट सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को बढ़ा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है। 50 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही है और 11 हजार 22 करोड़ का प्राविधान किया है। मैं इसके लिए आदरणीय खन्ना जी को बधाई देता हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मा0 अध्यक्ष महोदय, बिजली, पानी, सड़क तो आधारभूत संरचनाए हैं जो महत्वपूर्ण होती ही हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज का युवा है। उत्तर प्रदेश में 25 वर्ष की उम्र से कम हमारी 52 प्रतिशत आबादी है जिसमें लगभग 13 करोड़ युवा है। 166 देशों से ज्यादा आबादी के युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। उनके लिए आने वाले चैलेन्जेस से निपटने के लिए, आने वाले समय में सबसे बड़ा चैलेन्ज आर्टिफिशल इंटीलेजेंस का है। उससे निपटने के लिए कैसे डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए, जिसके लिए मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय खन्ना जी ने 4 हजार करोड़ का प्राविधान किया है कि युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट दिए जाएं, 500 करोड़ का प्राविधान डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करने के लिए किया गया है। 500 करोड़ से ज्यादा का प्राविधान स्मार्ट क्लासेज लगाने का किया गया है। यह सब इसलिए किया गया है ताकि युवा डिजिटली साक्षर बन सके। आज मा0 अध्यक्ष जी, साक्षरता के मायने बदल चुके हैं। जो व्यक्ति डिजिटली साक्षर नहीं है वह आगे कैसे रहेगा यह बड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि प्रिडक्शन्स है वर्ष 2045 तक ऐज ऑफ इंटीलेजेंस मशीन्स आ रही है। अभी हम देख रहे हैं कि इंटीलेजेंस मशीन्स ऐसी होंगी जो ह्यूमन बींइग्स को, हम लोगों को आउट परफॉर्म, आउट स्मार्ट करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता उसके लिए उत्तर प्रदेश में और हमारे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस बजट में उसके लिए प्राविधान किया गया है ताकि डिजिटल साक्षरता बढ़े, इसके लिए मैं आदरणीय खन्ना जी को बधाई देता हूँ। सरोजनीनगर में भी लगातार हम हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी सी0एस0आर0 फण्ड के माध्यम

से स्थापित करा रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम दे रहे हैं। मेरा प्रयास है कि बच्चे जितना ज्यादा डिजिटली साक्षर होंगे उतना ही ज्यादा आने वाले समय के लिए वह मजबूत होंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पुलिस का बजट बढ़ाया गया है। पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो 16 हजार करोड़ का पुलिस का बजट था, उसके बाद 37 हजार करोड़ हुआ और इस बार 39 हजार 500 करोड़ का बजट किया गया है। क्योंकि आदरणीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि किसी भी राज्य का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहां की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। लगातार पुलिस में भर्तियाँ की जा रही हैं। डेढ़ लाख से ज्यादा भर्तियाँ की गयीं, ढेड़ लाख से ज्यादा लोगों को प्रमोशन दिया गया है। पुलिस का मनोबल ऊँचा हुआ है जिसका परिणाम यह रहा कि 23 हजार से ज्यादा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें लिखे गये, 72 हजार से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया, 196 से ज्यादा शातिर अपराधी मुठभेड़ में मारे गये, 135 अरब की सम्पत्ति उनकी जब्त की गयी है और 910 लोगों पर रासुका लगाया गया है। तभी आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है और सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पुनः मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर बल देता हूँ, धन्यवाद।

***श्री सौरभ श्रीवास्तव-**

मा0 अध्यक्ष जी, इस ऐतिहासिक और अब तक के सबसे बड़े बजट के समर्थन में बोलने का अवसर देने के लिए आपका हृदय से आभार। प्रभु श्रीराम जी को समर्पित लोक कल्याण और रामराज की संकल्पना पर आधारित बजट प्रस्तुत करने के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद। आदरणीय, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास के आधार पर बना यह बजट प्रदेश को रामराज्य की ओर ले जाएगा। 'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज नहिं काहु व्यापा, नहि दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहि कोई अभूत न लक्षण हीना'। जिस तरह से रामराज्य में चिन्ता की जाती थी कि समाज में कोई दरिद्र न रहे, कोई रोगी, दुखी, गरीब न रहे, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, बिल्कुल वैसे ही इस बजट में प्रदेश की जनता की चिन्ता की गयी है। पिछले 7 वर्षों में प्रदेश की जी0डी0पी0 दो गुने से भी ज्यादा हो गयी है। सही मायने में यह प्रदेश के विकास के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता हुआ बजट है। 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख का यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया। एक सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी बजट है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे अन्नदाता। किसान भाइयों के सम्यक् विकास के लिए जहां विभिन्न योजनाओं द्वारा उन्हें सुविधायें दी जा रहीं हैं। बिजली नलकूप योजना, क्रेडिट कार्ड का वितरण, फसल बीमा, सिंचाई की सुविधा दूसरी तरफ किसान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्मान निधि, मासिक पेंशन योजना, गन्ना मूल्य भुगतान द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान भी किया जा रहा है। दुग्ध विकास योजना, पशु पालन, मत्स्य योजना के द्वारा कृषकों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाने की योजना पर भी ध्यान दिया गया है। कृषि की उत्पादन दर में वृद्धि हेतु कृषि शिक्षा अनुसंधान, कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना की जा रही है। राष्ट्र और चरित्र का निर्माण करती है हमारी मातृ शक्ति। देश की आधी आबादी जो हमेशा से उपेक्षित रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष ध्यान देने के कारण बजट में उनके लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। सुमंगला, उज्ज्वला, सामूहिक विवाह, महिला किसान सशक्तीकरण, निराश्रित महिला पेंशन, लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, महिलाओं के लिए बड़ी लाभकारी योजनायें हैं।

राष्ट्र का भविष्य युवा है। विश्व का सबसे युवा देश भारत, उसका सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश के इस बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं पर न केवल परिवार का भार रहता है अपितु देश की सामाजिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा का भार भी रहता है। युवाओं को रोजगार देने के लिए बुनियादी सिस्टम खड़ा करना पड़ता है। जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की सरकारे कर रहीं हैं। अर्थात स्थायी रूप से प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही हैं। सबसे आवश्यक सबके लिए शिक्षा। इस सरकार ने कुल बजट का 17 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया है जो दर्शाता है कि सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कितनी संवेदनशील है। प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 43 हजार 406 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरूस्त रखने के उद्देश्य से इस बजट में पुलिस विभाग को आवंटित होने वाली धनराशि में 2368 करोड़ की भारी वृद्धि की गयी है। जो इस प्रदेश को देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनायेगा। देश के सर्वाधिक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में ही हैं। बजट में धार्मिक स्थलों के विकास पर बल दिया गया है। काशी, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, मथुरा, गोरखपुर, चित्रकूट, बटेश्वर नाथ, गढ़मुक्तेश्वर, मां शाकुम्भरी धाम, सारनाथ सहित सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास और सौन्दर्यीकरण के लिए जो प्राविधान किये गये हैं, उसका हम सभी को हृदय से स्वागत करना चाहिए। मेरे क्षेत्र में गंगा जी के आधे से अधिक घाट और अनेक महत्वपूर्ण मन्दिर भी हैं। यह तीर्थ स्थल और मन्दिर केवल आस्था के केन्द्र नहीं होते। बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के भी बड़े केन्द्र होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद केवल पिछले वर्ष में साढ़े आठ करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन किया। इन श्रद्धालुओं ने काशी की अर्थ व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। नव्य और भव्य अयोध्या जी में भी प्रभु श्रीराम जी के दिव्य मन्दिर के उद्घाटन के बाद वहां भी यही स्थिति है। वहां के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रीन फील्ड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट स्कीम जलभराव और बाढ़ से मुक्ति के लिए योजना।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, नगरीय सेवाओं और अवस्थापना विकास की नई योजना और स्मार्ट सिटी योजना के प्राविधान से प्रदेश के शहरों की रिहाइशी सुविधाओं का विकास होगा। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने काशी में मेडिकल कालेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नॉलाजी के लिए इस बजट में धनराशि का आवंटन किया है। पूर्वान्चल के विकास के लिए 575 करोड़ रुपये की पूर्वान्चल विकास निधि का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मैं इस सरकार से निवेदन करता हूँ कि अस्सी घाट से लेकर संत रविदास घाट और संत रविदास घाट से लेकर सामने घाट तक मां गंगा के जल से हो रहे कटान को रोकने की व्यवस्था की जाये। सामने घाट में फ्लीपर गेट बना जिससे मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से मुक्त हो गया। मेरी मांग है कि वैसे ही अस्सी नदी घाट पर भी फ्लीपर गेट की व्यवस्था की जाये। मैं मांग करता हूँ कि नगर निगम की सीमा में मिलाये गये क्षेत्रों रामनगर, भगवानपुर, आदित्यनगर, भिखारीपुर, उत्तरी ककरमत्ता, मंडुवाडीह और लहरतारा में बुनियादी सुविधाओं के संयोजन के लिए मास्टर प्लान बनाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 वित्त मंत्री जी को एक विकास मूलक बजट देने के लिए मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

श्रीमती सलोना कुशवाहा-

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं अपनी तिलहर विधान सभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे जिताकर इस विधान सभा के पवित्र मन्दिर में भेजने का काम किया है। हमारे सम्मानित और ऊर्जावान माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पेश किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाये वह कम होगी। मोदी जी की गारण्टी और योगी जी की वारण्टी वाला वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट उत्तर प्रदेश के चहुँमुखी विकास की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट है जो प्रदेश के विकास को मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा। यह बजट देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की भाजपा सरकार की उत्कृष्ट नीतियों एवं उत्तर प्रदेश के उत्तम विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं, वंचितों, पिछड़ों तथा अन्नदाता किसान भाइयों का विशेष ध्यान रखा गया है। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाये जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। मान्यवर, मैं ऐसी डबल इंजन सरकार और इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह बजट राम राज्य की दिशा की ओर ले जाने वाला बजट है। आज पूरा देश राम राज्य मय है। इस बजट से अयोध्या पयर्टन केन्द्र के तौर पर स्थापित होगी। मान्यवर, आज 500 सौ साल बाद हमारे आदर्श प्रभु श्री रामलला अपनी जन्मभूमि अयोध्या में नव्य, भव्य और दिव्य मन्दिर में विराजमान हो गये हैं। पूरे विश्व ने इस अलौकिक दृश्य को देखा। हम अपनी आने

वाली पीढ़ियों को प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। आज हम सभी लोग आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। सुशासन हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को अपनाते हुए सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने सुशासन संकल्प के साथ प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई है।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने रामलला के लिए दो शब्द और बोलना चाहूंगी कि राम जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी गया राम जी के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी सुन्दरता और सरलता से पूरी विधान सभा को चलाने का जो आप काम कर रहे हैं, जब भी मैं विधान सभा में आती हूँ तो मुझे कुछ न कुछ नया मिलता है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक महिला विधायक हूँ, वैसे तो राम जी की कृपा क्षेत्र में बनी हुयी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अगर हो जायेंगी तो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण हो जाये तो हमारे क्षेत्र की जितनी बच्चियाँ हैं उसमें पढ़ने का काम करेंगी एक बहुत अच्छा संदेश जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक हमारी विधान सभा में कोई भी बस स्टाप नहीं है। बस को एक जगह रुकने के लिये कोई भी जगह नहीं है। महिलायें और बच्चियाँ कभी इधर, कभी उधर खड़ी होकर बस का इन्तजार करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा में एक बस स्टाप बन जाये। हमारे विधान सभा में एक और समस्या है 11 हजार की लाइन घनी आबादी में बहुत ही नीचे से होकर जा रही है जिसमें अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत सारे घर नीचे बन गये हैं ऊपर से 11 हजार की लाइन जा रही है जिसमें आये दिन चार-छः महीने में कोई न कोई दुर्घटना वहाँ पर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि यह 11 हजार की लाइन घनी आबादी के ऊपर से हटायी जाये। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र के युवा बच्चों की मांग है कि वहाँ पर कोई भी खेल का मैदान नहीं है, युवा बच्चों ने हमसे कई बार बोला है कि दीदी हमारे लिये एक खेल का मैदान बनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक खेल का मैदान बनवा दीजिएगा। धन्यवाद।

श्रीमती सलोना कुशवाहा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी का भी आभार करना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम, जोर से बोलो, जय-जय सियाराम।

श्रीमती ऊषा मौर्या-

मा0 अध्यक्ष जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। संविधान वह चीज है जिसकी वजह से मैं चुनकर आयी हूँ। यह संविधान की देन है जो मैं यहाँ पर हूँ। मा0 अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने आज बोलने का अवसर दिया। मुझे तो लगता था कि आज मेरा नाम ही कट जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज-242 में एक थाना सुल्तानपुर है वहाँ एक मुगल हाई-वे है, स्टेट हाई-वे है, उसमें तीन साल हो गये हैं वह रोड बन गयी है, लेकिन उसमें इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं।

मान्यवर, लेकिन इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं कि अभी 24 तारीख को ग्राम चौबेसी सराय में एक ऐसी घटना हो गयी जिसमें डम्पर पलटकर नाले के दूसरी तरफ चला गया और मौके पर ही एक बुजुर्ग की मौत भी हो गयी है। मैं चाहती हूँ कि हथगांव से लेकर कड़ा रोड को संज्ञान में लिया जाए। मैंने इससे पहले भी सदन में बोला है कि सातमील से लेकर डलमऊ हाई-वे जो मुराईबाग एवं रायबरेली को जोड़ता है। उसपर ओवरलोड गाड़ियां चलने के कारण बहुत ज्यादा गड्ढे हो गये हैं जिससे उस पर लोग पैदल तक नहीं चल पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसकी जांच एवं सर्वे होनी चाहिए कि साल भर में कितनी घटनाएं होती हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गौती ग्राम सभा से टांडा के लिए सड़क है जो कौशाम्बी को जोड़ती है। हमारे यहां पर अजुहा मण्डी है। वहां पर पचासों गांव पीड़ित हैं। किसान मण्डी नहीं जा पाते हैं क्योंकि उस सड़क पर बहुत बड़े-बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं और वह सड़क 6 किमी0 लम्बी सड़क है और वह सड़क 20 वर्ष पूर्व आर0ई0एस0 विभाग द्वारा बनाई गयी है। मैं चाहती हूँ कि इस सड़क का संज्ञान लेकर उसे जल्दी से बनवाया जाए। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, मै विकास ही गिना रही हूँ। एक संवत रोड है जिसकी लम्बाई कम-से-कम 7-8 किमी0 है, उसमें मिट्टी पड़ गयी है और ये लगा कि रोड पास हो गयी है। हरगांव से संवत ग्राम सभा है जो बहुत बड़ी ग्राम सभा है, लेकिन उसकी सड़क भी बहुत खराब है, उसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। मेरी पिछड़ी हुई विधान सभा क्षेत्र है जिसका संज्ञान लिया जाए। अब मैं बजट के सम्बन्ध में बोलना चाहूँगी और मैं एक मांग करती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र लगभग 50 किमी0 में फैली हुई है। हमारे यहां पर अन्त्येष्टि स्थल खराब पड़े हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम तीन अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाएं। मेरे यहां पर लोगों को अन्तिम संस्कार करने में बहुत कठिनाई आती है, कोई अन्तिम संस्कार के लिए खेत में ले जाता है या कहीं और ले जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास। मेरे जनपद फतेहपुर के लिए ऐसा कोई बजट नहीं आया है और मैं जानती हूँ कि एक चिकित्सालय बना हुआ है, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब लोग बीमार होते हैं तो उनको जिले के लिए रिफर किया जाता है तो जिला अस्पताल भी कानपुर के लिए रिफर कर देता है। मेरा कहना है कि अगर वह मेडिकल कालेज बना हुआ है तो उसमें इलाज क्यों नहीं होता है और मरीज को कानपुर के

लिए क्यों रिफर किया जाता है ? बजट में कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। मैं माननीय अध्यक्ष जी एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में ला रही हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मेरी एक मांग है कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सत्ता पक्ष के विधायकों को त्वरित विकास के लिए अलग से बहुत पैसा दिया जाता है, लेकिन विपक्ष के सम्मानित विधायकगण कहीं-न-कहीं से चुनकर आते हैं और वह भी सभी माननीय सदस्यों के बराबर होते हैं। मेरा कहना है कि वह पैसा विपक्ष के माननीय सदस्यों को क्षेत्र के विकास के लिए क्यों नहीं दिया जाता है ? मैं इसकी माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूँ। कहते है सबका साथ, सबका विकास और रामराज की बात करते हैं और कहते हैं कि रामराज में बहुत विकास हुआ है। मैं मानती हूँ कि रामराज है, लेकिन रामराज में सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर कोई प्रधान बनता है तो लोग कहते हैं कि आप इस ग्राम सभा के मुखिया हैं।

अगर एक विधायक बनता है वह चाहे जिस पार्टी का हो पूरी जनता का विधायक बनता है और यदि आज मुख्य मंत्री बने हैं सरकार में आप लोग हैं तो पूरे प्रदेश की जनता के लिए हैं, एक-एक जनता सरकार की है। तो सबको बराबर दिया जाये। सबका साथ दिया जाये। जय संविधान। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने महिलाओं को बोलने का मौका दिया। मैं कह रही हूँ कि हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है जिस तरह पहले सत्र में आपने महिलाओं के लिए एक दिन रखा था उसी तरह से आगे भी रखिए।

श्री अध्यक्ष-

अगले सत्र में रखेंगे।

(श्रीमती सलोना कुशवाहा जी के समाजवादी पार्टी के सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, रुकिए न। जब कोई महिला खड़ी होती है, तो आप लोग ऐसे ही विरोध करने लगते हो। एक मिनट उनको सुन लीजिए। क्या कह रही हैं आप ?

श्रीमती सलोना कुशवाहा-

मेरा कहने का मतलब है कि मा0 अध्यक्ष जी, जब भी सदन चले तो एक दिन महिलाओं के लिए निश्चित कर दिया जाये, जिस दिन सारी महिलाएं ही बोलें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, श्री समरपाल जी आप बोलिए। मनोज जी, आपने लिस्ट में महिलाओं का नाम भी बोलने के लिए लिस्ट में नहीं दिया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, एक दिन महिलाओं के लिए रख दीजिए, मैंने आपसे मिलकर भी कहा था।

***श्री समरपाल सिंह-**

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रामजी के ठेकेदारों से कहना चाहता हूं, जो लम्बरदार लम्बरदारी दिखा रहे हैं कि हम रामजी के ठेकेदार हैं, रामजी हर कण-कण में हैं, हर जगह राम जी है। (समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) जीव-जन्तुओं में रामजी हैं, बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे हैं राम जी के। राम जी का घर बना दिया है, राम जी तो सबका घर बनाते हैं एक कहावत मैं बताता हूँ उसे टाइम से अलग रखिएगा।

श्री अध्यक्ष-

क्या कह रहे हैं ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

ये एक कहावत कह रहे हैं इनके बोलने के टाइम में मत काटियेगा।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल, टाइम से काटेगा।

श्री समरपाल सिंह-

एक बनिये की गाय खो गयी, वह ढूंढता-ढूंढता मोहल्ले में गया तो आगे जाट खड़े थे, उससे पूछे क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। कहने लगा मेरी गाय खो गयी, वह भी उसके साथ ढूंढवाने लग गये। वह भी खर्चा-पानी करे, चाय पानी पिलाता हुआ, आगे हस्तिनापुर पहुंच गया। वहां मंदिर बहुत थे, पुराना जमाना था, कहने लगे देवी के मंदिर में बोल दो। उसने 250 रुपये का प्रसाद बोल दिया, आगे हनुमान जी का मंदिर मिला, उसमें भी 250 रुपये का प्रसाद बोल दिया, श्रीराम जी के मंदिर में भी 250 का प्रसाद बोल दिया, कृष्ण जी में 250 का प्रसाद बोल दिया। एक जाट बोला अरे [xxx] ये तो देख ले।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, ये शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री समरपाल सिंह-

सॉरी-सॉरी अध्यक्ष जी, गलती से निकल गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 समरपाल सिंह जी ये विधान सभा है, ये बिल्कुल एलाउड नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

मा0 अध्यक्ष जी इस तरह की भाषा विपक्ष के लोगों की ओर से ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह की भाषा एलाउड नहीं है।

श्री समरपाल सिंह-

गाय खरीदी पांच हजार की और प्रसाद हो गया साढ़े पांच हजार रुपये का। वह बोला गाय मिल जाये, प्रसाद कौन बांट रहा। ये भी वही लाला हैं, इन्हें राम जी से कोई हमदर्दी नहीं है। (हंसी) इन्हें तो सब सत्ता चाहिए। ये कहते हैं कि सबका साथ-सबका विकास, लेकिन सबका साथ-सबका विकास तो हो नहीं रहा। सबकी सड़क बन गयी, लेकिन हमारा तो खड़न्जा भी नहीं बना। (हंसी) शर्म करो यार।

श्री अध्यक्ष-

समरपाल जी मेरी तरफ बोलिए, सीधे बात मत करिए।

श्री समरपाल सिंह-

मैं अपनी पार्टी की ओर से मांग करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाये। (समाजवादी पार्टी के सदस्यों की ओर से मेजें थपथपाई गयीं) मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, चार-चार पांच-पांच किलो का राशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जिंदा रख रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ तुमने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर कैसे उठा दिया, जब 80 करोड़ लोगों को तुम राशन देकर जिंदा रख रहे हो।

सरकार जिन्दा रख रही है, 80 करोड़ को तो गरीबी के ऊपर कैसे हो सकते हैं 20 करोड़, यह तो बता दो और प्रदेश में बहुत अपराध बढ़ा है। लड़की, हमारी बच्ची, उठा ली वहाँ बनारस से प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और चलती कार में रेप किया। अब तक तो बुलडोजर चल जाता, अगर दूसरी पार्टी के होते। (सपा के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) बेसिक शिक्षकों को आपने बाबू बना दिया, इतना काम लेती है सरकार। मान्यवर, पढ़ाई का कोई काम नहीं हो रहा है। पटवारी का काम उनसे, झाड़ू-पोंछे का काम उनसे और जितना भी वोटर आदि का काम है, वह सब काम उनसे लिया जा रहा है। पढ़ाई बिल्कुल नगण्य हो गयी है। बेसिक शिक्षकों से पढ़ाई के अलावा और दूसरे काम उनसे न लिये जायें। आपने शिक्षक बनाया, वेतन मिला नहीं, मेरे पीछे सारी लड़कियाँ रो रहीं वहाँ पर और कह रहीं कि साहब हमारा वेतन दिला दो। अरे, शिक्षक बना दिया, वेतन का इन्तजाम नहीं ? (हँसी) इनको नियमित करो, वेतन का इन्तजाम करो। (हँसी) स्वास्थ्य सेवायें बहुत खराब हैं। हमारे यहाँ अमरोहा में गन्ने का मिल है, इतने दिन से बन्द पड़ा है, कहते हैं कि गन्ने के मिल सब चालू हो जायेंगे, कहाँ से चालू हो जायेंगे ? जितने नसेड़ी थे, सब मशीनें निकाल कर ले गये।

(हँसी) अध्यक्ष जी, जितना इनको मिला है, उतना हमें भी दिलाओ। यह आपको कराना ही पड़ेगा। (हँसी) मेरे क्षेत्र में स्टेडियम बनवाया जाय। हमारे क्षेत्र में डिग्री कालेज नहीं है, नौगाँव में एक डिग्री कालेज की व्यवस्था करायी जाय। तुगलकाबाद इण्टर कालेज है। मान्यवर, तुगलकाबाद में एक कन्या डिग्री कालेज है, उसमें स्टाफ नहीं है, एक चौकीदार है और एक टीचर है। वह सरकारी इण्टर कालेज है। मान्यवर, तुगलकाबाद, हसनगंज तहसील में पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे नौगाँव में कताई मिल बन्द पड़ा है बहुत दिनों से। वह सरकारी कताई मिल है, उसके लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिली। वह मिल चलवाया जाए और वहाँ काम करने वालों का बकाया दिलवाया जाय। यह बजट है, 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 31 लाख का, इससे किसानों का भला नहीं है। आप रोज कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, दूनी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद, इनका माइक बन्द करिए।

श्री समरपाल सिंह-

अध्यक्ष जी, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट भी नहीं। अब श्रीमती अर्चना पाण्डेय। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री आशीष पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय समरपाल सिंह जी बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन इन्होंने महिलाओं के प्रति समूह सखी का जो विषय है, उसके लिए अच्छे शब्द प्रयोग नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको भी अगर सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

अगर ऐसा कोई शब्द होगा, उसको दिखवा लूँगा और निकलवा दूँगा।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय जी हैं ? नहीं हैं।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, लोकेन्द्र जी बताइये।

***श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-**

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, आपको सादर धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, हम सब गौरवान्वित हैं कि आप जैसे योग्यतम नित नए आयामों को देने वाले अध्यक्ष हमें मिले हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्लीज, अब काफी हो गया। राकेश जी, प्लीज।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

प्लीज, डिस्टर्ब न करिए। मान्यवर, मैं आज बहुत आहत हूँ। मान्यवर, मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले आधा मिनट जरूर चाहूँगा। मन्दिरों में प्रसाद चढ़ाना हमारी आस्था का प्रश्न है और ऐसे मर्यादित मन्दिरों में प्रसाद चढ़ाने को ले करके टिप्पणी की जाय, उसकी मैं घोर निन्दा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ।

आपको इतना ही था तो गए होते राम मन्दिर की स्थापना में। 11 फरवरी को आप लोग चलिए राम मन्दिर किसने मना किया है, मा0 अध्यक्ष जी द्वारा आपको मन्दिर में आमंत्रित किया गया है। मा0 अध्यक्ष जी हम सब गौरवान्वित हैं आप जैसे योग्यतम नित नए आयाम स्थापित करने वाले गुरू श्रेष्ठ से संसदीय परम्पराएं सीखने का अवसर मिला। मैं आपको प्रणाम करता हूँ मा0 अध्यक्ष जी, यह चमक, दमक विधान सभा की महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मा0 अध्यक्ष जी, राम चरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा-'सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी' कहते हैं कि पूरे संसार में राम का निवास है, सब में श्री राम हैं, हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तुलसीदास जी की यह पंक्तियां आज पुनः फिर से चरितार्थ हुई हैं और पूरा देश आज राम मय हो गया है, यह कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज पूरा देश राम मय हो गया है। सन् 1935 में पीठाधीश्वर पूज्य महन्त दिग्गविजय नाथ ने आन्दोलन प्रारम्भ किया था, पूज्य महन्त अवैधनाथ जी ने उसकी कमान संभाली और उसके बाद तमाम संघर्षों के बाद वर्तमान काल खण्ड में उसी पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो आज मुख्य मंत्री हैं उन्होंने उसको मूर्त रूप प्रदान करने का काम किया है इसलिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बजट इसमें वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी, नो डॉउट वह बहुत ही योग्यतम व्यक्ति हैं और उनकी योग्यता हर बजट में परिलक्षित होती है, मैं उनको साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, इसमें प्रत्येक क्षेत्र को महत्वपूर्ण योजनाओं को लाभान्वित करने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया, उससे जहां रेवन्यू सरकार का बढ़ेगा उसके साथ-साथ पूरे देश में एक माहौल बना है। हमने बीते हुए समय को फिर से वापस लाने का काम किया है, चाहे अयोध्या में दीपोत्सव हो। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आपके काल खण्ड में सैफई में नाच होता था, हमारे काल खण्ड अयोध्या में 22 लाख दीपों को जला करके दीपोत्सव मनाया जाता है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, विश्वनाथ मन्दिर, विंध्याचल मन्दिर, नैमिष प्रत्येक विधान सभा में पौराणिक विधान सभा, पौराणिक स्थानों का विकास यह बहुत बड़ी बात है। मैं क्षमा चाहता हूँ इनके काल खण्ड में कांवड़िया निकलते थे तो हम लोग मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र मोहम्दी

विधान सभा की बात कर रहा हूं, हम लोग चाय-पानी पिला रहे थे कावड़ियों को तो हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया था, हमारे लोगों को उठा करके जेल में बन्द कर दिया गया था। मान्यवर, आज मन गौरवान्वित होता है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र से कांवड़िया निकल कर के जाते हैं, मन गौरवान्वित होता है, जब देखता हूँ कि कांवड़ियों में एक तरफ केसरिया ध्वज होता है और उससे पांच फुट ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है, एक तरफ वह भारत माता की जय कहते हैं और एक तरफ जय भोलेनाथ कहकर कांवड़िया ले जाते हैं। मान्यवर, मन गौरवान्वित होता है तब जब उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री हेलीकॉप्टर से उन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का काम करते हैं, यह मान्यवर हमारा काम है, अभी आप कह देते कि सबका साथ, सबका विकास एक छलावा है-उम्र जाया कर दी आपने साहब, हममे नुक्स निकालते-निकालते इतना खुद को तराशा होता तो आज यू0पी0 के चहेते बन जाते। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे नेतृत्व में सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः को ही मूल मंत्र माना हमेशा। यह सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत कार्ड की आप टिप्पणी करते हो, सबका साथ, सबका विकास उसी में परिलक्षित होता है। हम लोग जाते हैं आयुष्मान भारत कार्ड बांटने तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सौ कार्ड बांटते हैं तो 70 अपनी मुस्लिम बहनों को देकर आते हैं और 30 हिन्दू बहनों को देकर आते हैं, यह सबका साथ, सबका विकास है। आपके काल खण्ड वर्ष 2015 में मा0 मोदी जी के द्वारा दैवीय आपदा का पैसा भेजा गया था, हमारी विधान सभा क्षेत्र में भी आया, हमने तत्कालीन अधिकारी से कहा कि यह हमारे गांव में भी बंटवा दीजिए।

हमारी विधान सभा क्षेत्र में भी आया उन्होंने कहा क्षमा चाहता हूँ वकील साहब आपके यहाँ नहीं बंट सकता क्योंकि आपका गाँव तो जनसंघ का है। मैं प्रमाणिक बात कहता हूँ आप कहेंगे तो प्रमाण ला करके प्रस्तुत करूँगा, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बंका नाम का एक गाँव है। मान्यवर, मैं एक मिनट ज्यादा चाहूँगा समय समाप्त हो रहा है घड़ी भी देख रहा हूँ। चलिए मैं उदाहरण नहीं पेश करूँगा। अभी मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष पर अभी हमारे एक काबिल दोस्त ने टिप्पणी की थी। मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से इनके 10 वर्ष के काल खण्ड में 60 हजार लोगों को सहायता दी गई थी और हमारे 7 वर्ष के काल खण्ड में 1 लाख 62 हजार लोगों को दिया गया है जो कि अविस्मरणीय है, मान्यवर और उसमें धर्म, जाति, वर्ण के नाम पर बंटवारा नहीं किया गया। उसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई की जाति के नाम पर बंटवारा नहीं किया जो भी आया मैं खुद कहता हूँ कि मेरे यहाँ 25 परसेन्ट हमने मुस्लिम समाज को दिलवाया है तो यह-

'तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो साहब,
हम यहाँ नया कीर्तिमान बनाते रहेंगे।
तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा,
हम अपने पंखों से नई उड़ान भरते रहेंगे।'

मान्यवर, समय समाप्त हो रहा है मैं अपने को समापन की ओर ले जाता हूँ। मान्यवर अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में तहसील मोहम्मदी क्षेत्र लगभग ...

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट रुकें मा0 मंत्री जी आप बताइये।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी हमारे विपक्ष के एक साथी ने अपने उद्‌बोधन में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया और आपने कृपापूर्वक उसको निकलवा दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, यह विधान सभा एक ऐसी पवित्र जगह है और ऐसी जगह पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पर मुझे लगता है कि उन मा0 सदस्य को माफी भी माँगनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, उन्होंने खुद नहीं माँगी।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने तुरन्त कहा। ऐसा नहीं है उन्होंने तुरन्त कहा और कान पकड़ के माफी माँगी है। मैंने उसको निकलवा भी दिया और उन्होंने कान पकड़कर माफी माँगी है। मा0 सदस्य अमरेश कुमार जी, मेरा निवेदन है कि जो भी वक्ता बोलेंगे जैसे अभी लोकेन्द्र जी का सबसे जरूरी छूट गया था। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सबसे जरूरी है वह सबसे पहले बोलें।

श्री अमरेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका कोटि-कोटि अभिनन्दन करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े चहुमुखी, विकासोन्मुखी बजट पर बोलने का अवसर दिया। इस बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि यह बजट वर्ष 2024-25 का अन्त्योदय के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने वाला बजट है। यह पण्डित दीन दयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुषों के सपनों को साकार करने वाला यह बजट है उनके सपनों को साकार यदि किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उनके सपनों को साकार करने का काम किया जैसे कि अन्त्योदय अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति सबसे नीचे गरीबी रेखा में जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति को आवास दे करके और उनको भोजन हेतु राशन दे करके गैस सिलेण्डर और चूल्हा दे करके उनको बराबरी दिलाने का दर्जा उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह बजट रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट प्रदेश के मुखिया सिद्ध योगी जी के कुशल निर्देशन में माननीय सन्त स्वरूप वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट एक बुनियादी, ग्राम विकासोन्मुखी, आत्मनिर्भरता वाला बजट है। जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, पर्यावरण, नगरीकरण, विधि व्यवस्था पर निगरानी इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। यह बजट संसाधनों से समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय योगी जी की सरकार 2017 से 2022 तक प्रदेश का चहुमुखी विकास और प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना करने में कामयाब हुई है और माननीय महाराज जी के द्वारा जो प्रदेश में खुशहाली आयी है, उसके तहत् हमारे 176-मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता ने मुझे आजादी के बाद पहली बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी से चुन करके इस न्याय के मंदिर में भेजने का काम किया है। यह हमारी सरकार द्वारा किये गये कार्यों की वजह से हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल-कूद और पर्यावरण सहित भारत की आत्म सनातन संस्कृति की रक्षा एवं उसे बल प्रदान करने वाले संसाधनों के विकास हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था में की गयी है। यह बजट विकास के क्षेत्र में नई क्रांति लायेगा। इस बजट में ग्रामीण व शहरी विकास में सन्तुलन बनाने की पूरी व्यवस्था की गयी है। यह बजट देश के माननीय प्रधानमंत्री जी व प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश के गाँव, गरीब, किसानों, नौजवानों व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला बजट है। जिस तरीके से प्रदेश में सरकार की अच्छी नीति, ईमानदारी का कार्य और सबका साथ, सबका विश्वास और सबके सहयोग की तर्ज पर जिस तरीके का सरकार ने काम किया है, उसी पर आज हमारी प्रदेश की जनता का रूझान निरन्तर हमारी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में आम जन-मानस का रूझान है और जिस तरीके से राम राज्य आया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र जी के आगमन से, मैं तो समझता हूँ, जिस तरीके से हम लोगों की नजरों के सामने 500 वर्ष बाद भगवान श्री रामचन्द्र जी की प्राण-प्रतिष्ठा हुई और हम लोगों ने लाइव देखा और हम लोग 11 तारीख को जा करके भी दर्शन करेंगे। ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, मैं तो अपने आपको समझता हूँ कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे समय में कम से कम भगवान श्री रामचन्द्र जी अपने घर पहुँचे और प्राण-प्रतिष्ठा हुई और भव्य मंदिर बना। पूरे देश, सभी गाँव, गली-गली, घर-घर दीपोत्सव हुआ और रामराज्य का बखान हुआ और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल रहा, ऐसा पहली बार देखने को मिला। मैं आजादी के बाद पहली बार मोहनलालगंज विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। मैं अपने क्षेत्र की भी कुछ बातें रखना चाहता हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मोहनलालगंज में एक दीवानगंज गाँव पड़ता है। गाँव के बगल से नहर गई हुई है, किसान भाई अपने घरों से खेत को देखते हैं। लेकिन जब खेत जाने का अवसर होता है तो 8 किमी0 घूम करके उन्हें जाना पड़ता है, तब वह अपने खेत को पहुँचते हैं। हम यह चाहते हैं कि वहाँ कम से कम पुल का निर्माण हो जाये ताकि जैसे हमारे

किसान भाई छत पर बैठकर अपने खेत को देखते हैं तो वह कम समय में वहाँ जा भी सकें और हमारे किसान भाइयों को सहूलियत मिले। हमारा गोसाईगंज, जो सुल्तानपुर रोड से कानपुर रोड को जोड़ने वाला रास्ता है, जिसमें गोसाईगंज में क्रासिंग पड़ती है। वहाँ अक्सर गाड़ियों की लम्बी-लम्बी लाइन लगी रहती है। उस रेलवे क्रासिंग पर पुल का निर्माण अगर हो जाये तो वहाँ के लोगों को जाम से निजाद मिल जायेगी। पुल न होने के कारण लोग उस रास्ते में काफी परेशान रहते हैं। वहाँ एक-एक, दो-दो किमी0 का जाम लग जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज की नगर पंचायत अमेठी में नहर के माइनर के किनारे निःशुल्क योगा वेलनेस केन्द्र संचालित है। जिसमें पक्की पुलिया न होने के कारण व्यापक जनमानस को योगा वेलनेस केन्द्र आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा पक्की पुलिया बनाये जाने हेतु वर्षों की माँग पर मेरे द्वारा अपनी विधायक निधि से उक्त पक्की पुलिया का निर्माण कराये जाने हेतु सिंचाई विभाग को कई पत्र प्रेषित किये गये हैं। परन्तु अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। योग से जटिल गम्भीर रोग भी दूर हो रहे हैं। मैं उक्त स्थान पर पक्की पुलिया का निर्माण कराये जाने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, इसी तरीके से मोहनलालगंज में एक ओवरब्रिज की आवश्यकता है। जो कानपुर की तरफ जाने वाला रायबरेली रोड है, उस जगह भी बहुत जाम लगता है। वहां पर अक्सर जाम बना रहता है ताकि उस जाम से निजाद मिले तो हमारे क्षेत्र की जनता को कम से कम सहूलियत मिले। इसी क्रम में हमारे लखनऊ में जो बस जाती है वह मोहनलालगंज तो जाती है, लेकिन नगराम तक नहीं जाती है, पहले वह बस नगराम तक जाती थी। अगर वह बस नगराम तक जाने लगेगी तो वहां से आने-जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।

***श्री तेजपाल सिंह नागर-**

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस सभा में वर्ष 2024-25 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह बजट लोक कल्याण के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन बनाने के लिये एक और कदम बढ़ाया गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे साधुवादी, कर्मठ एवं विकासशील मुख्य मंत्री जी की सरकार का एक हिस्सा हूं, जिसकी चाह आज हमारे साथ जो विपक्ष में बैठे हैं, जिसकी चाह उनमें भी है। प्रदेश के यशस्वी वित्त मंत्री मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी ने भगवान राम को समर्पित राज्य के अब तक के सबसे बड़े बजट 07 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख पेश किया है, जिसमें यशस्वी एवं तपस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प स्पष्ट दिखाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देता है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी, वित्त राज्य मंत्री, मा0 मंत्रीगण और अनुभाग के सभी अधिकारीगण और कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने किसानों के उत्थान को ध्यान में रखकर विकसित उ0प्र0 की बुलन्द इमारत के लिये युवा और महिला सशक्तीकरण के जरिये भविष्य राज्य की मजबूत नींव रखी है, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। हम सब भाग्यशाली हैं कि जो स्वप्न हमारे पूर्वजों ने देखा था, हम सभी उस क्षण के प्रत्यक्ष रूप से भागी बन सके। लगभग 500 वर्षो के बाद हम सबको अपना गौरव प्राप्त हुआ है। यह विश्व के इतिहास की एक ऐसी घटना है जहाँ की बहुसंख्यक आबादी को अपने धार्मिक स्थान की पूजा करने के लिए लगभग 500 वर्षों का संघर्ष पूरा करना पड़ा है। यह भी अपने आप में विश्व में पहली बार हुआ है, जब इतने वर्षों के संघर्ष के बाद शांतिपूर्ण तरीके से किसी धार्मिक स्थान का मामला सुलझाया गया हो। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक अयोध्या में मन्दिर निर्माण हर सनातन धर्म का एक स्वप्न था। परन्तु 'होइहि सोई जो राम रचि राखा' इस स्वप्न को हकीकत में बदलने का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री मा0 योगी जी ने पूरा किया है। आज पूरा देश राममयी है, आज हर सनातनी गौरवान्वित है, आज हमारे लोगों का बलिदान साधु-सन्तों की तपस्या सफल हुयी है। हमें हमारे प्रभु राम मिले हैं और आज हमारे रामलला अपने जन्म स्थान पर निर्मित मन्दिर में विराजमान हुए हैं। यह केवल मा0 प्रधानमंत्री और मा0 मुख्य मंत्री जी के कारण ही मुमकिन हो पाया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सब मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे युगपुरुष को साक्षात देख, सुन रहे हैं और उनके द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आज हमारा देश फिर से विश्वगुरू के रूप में आ रहा है पूरा विश्व भारत की उन्नति का गवाह है। आज जहाँ विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है वहीं हमारी अर्थव्यवस्था निरन्तर नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। वर्षो से लम्बित गौतमबुद्धनगर में जेवर हवाई अड्डा योजना की दिशा और दशा देकर आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदलने का कार्य कर रहा है। यह हवाई अड्डा मात्र एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि विकास का एक इंजन होगा जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कि अर्थव्यवस्था को आगे ले जायेगा।

आज गौतमबुद्धनगर निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रथम पसन्द बन चुका है। जिससे न केवल इस क्षेत्र बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, जिन्होंने पूरे प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक की है, गौतमबुद्धनगर की कानून-व्यवस्था सब में उत्तम है इसके लिए मैं वहां के पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ। जो लोक बजट में है उसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करना चाहता हूँ। अयोध्या में महर्षि बाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम का विकास कराया गया, अयोध्या एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु डेढ़ सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद गौतमबुद्धनगर

के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य एवं भूमि कार्य हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुम्भ मेला, 2025 का आयोजन विश्व स्तरीय सुविधा के साथ किये जाने हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष-

अब धन्यवाद।

श्री तेजपाल सिंह नागर-

मान्यवर, चलो अच्छा लास्ट का बोल देता हूँ। इस विधान सभा को हमने पिछले कार्यकाल में देखा, अब भी हम देख रहे हैं आपने इसे हाईटेक बनाया है। आपने प्रत्येक विधायक चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, सभी को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। कुछ समस्या हमारी दादरी विधान सभा क्षेत्र की है उन्हें मैं बोल दूं। मान्यवर, पिछले कार्यकाल में जब आप माननीय उद्योग मंत्री थे और आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण तीनों की समस्याओं को देखते थे, एक गम्भीर समस्या थी। एक समस्या बिल्डर बायर्स के रजिस्ट्रियों की, वह समस्या हल हो गई है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। दूसरी समस्या किसानों की है, यह समस्या नोएडा एथॉरिटी में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी है और यमुना प्राधिकरण में भी है, मैं चाहता हूँ कि इसका शीघ्र निस्तारण हो। ग्रेटर नोएडा में शुद्ध गंगाजल जल्दी पहुंचे, दादरी एनटीपीसी रोड का चौड़ीकरण, शुद्धिकरण हो जाए, दादरी नगर में सीवर पड़ जाये। अन्त में मैं इस सभा को गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियां इस समय को याद रखेंगी युग पुरुष माननीय नरेन्द्र मोदी एवं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नमन करेंगी, सनातन की विजय को याद रखेंगी, मुख्य मंत्री जी के तप को याद रखेंगी, मुख्य मंत्री जी के सनातन के प्रति प्रण और उनकी भावना को याद रखेंगी।

श्री अध्यक्ष-

मास्टर साहब, अब समाप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह नागर-

इस प्रदेश की प्रगति के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को याद रखा जायेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, जय श्री राम।

श्री अध्यक्ष-

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बोला, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बोला, इनके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनमें से अगर कोई मा0 सदस्य बोलना चाहे तो बोल सकता है।

***श्री आर0 के0 पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल निर्देशन में माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी जी एवं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी के अतुलनीय सहयोग से बनी सरकार द्वारा 7 लाख 36 हजार करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया, जो कि अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट है। मेरी विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में बिजली की ओवरलोड की बहुत समस्या रहती है तो मईडीह में 132 किलोवाट के सब-स्टेशन की क्षमता को बढ़ा करके 220 किलोवाट कर दिया जाय तो मड़ियाहूँ नगर की समस्या का समाधान हो जायेगा। हमारी विधान सभा क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है लड़कियों की शिक्षा के लिए अगर एक राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हो जाय तो लड़कियों की उच्च शिक्षा में बहुत सहूलियत होगी। मड़ियाहूँ बाईपास पर हमेसा जाम लगा रहता है रेलवे लाइन पर, वहां एक आरओबी का निर्माण हो जाय और पॉली गुथवन मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर एक रेलेवे फाटक या अण्डरपास बन जाने से आवागमन में बहुत आसानी होगी। मड़ियाहूँ सी0एच0सी0 पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन की सुविधा नहीं है इसलिए बहुत दूर-दूर के मरीज परेशान होते हैं, अगर सी0एच0सी0 पर एक अल्ट्रसाउण्ड मशीन लग जाय तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा।

हमारी विधान सभा क्षेत्र में केले की खेती बहुत अधिक होती है। और हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक बरसाती नदी है जिसका नाम बसुई नदी है अगर उसपर दो-दो किमी0 पर चेकडेम बना दिया जाए तो हमारी विधान सभा क्षेत्र में किसानों की आय दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। हमारी विधान सभा क्षेत्र में रामपुर ब्लॉक, आकांक्षी ब्लॉक है यहां पर बिजली भदोही से आती है और जब भी इसमें कोई समस्या होती है तो बिजली काट दी जाती है, रामपुर ब्लॉक पर 132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन स्थापित हो जाए और एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हो जाए, तो रामपुर का भी विकास हो जाएगा। बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं, वह परिवार द्वारा प्रताड़ित होते हैं, तो उनकी प्रताड़ना को दूर करने के लिए महिला हेल्प डेस्क की तर्ज पर अगर तहसील स्तर पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए तो बुजुर्गों को अपने परिवार से जो उत्पीड़न होता है वह खत्म हो जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी यह जो बजट है, प्रगति का राम पथ है और यह नए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि देश में हम सर्वाधिक एयरपोर्ट के साथ 10 संचालित, 11 निर्माणाधीन उसमें 5 इण्टरनेशनल 4 संचालित, एक निर्माणाधीन देश में नम्बर वन पर हैं। सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे में अपना प्रदेश बन चुका है, इसमें 6 संचालित हैं और 7 निर्माणाधीन हैं। सबसे अधिक मेडिकल कालेज वाला अपना प्रदेश बन चुका है। इसमें से 65 संचालित हैं और 22 निर्माणाधीन हैं, सर्वाधिक मैट्रो वाला अपना प्रदेश बन गया है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं आगरा में हमारी मैट्रो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संचालित है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक लाभ यहां के लोगों को मिला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है। आयुष्मान भारत और मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 9 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हर घर नल योजना में 2 करोड़ से अधिक परिवारों को नल का कनेक्शन दे करके उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2.26 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर, उत्तर प्रदेश देश में पहले नम्बर पर है। पॉवर फॉर ऑल के उद्देश्य से 1.58 करोड़ घरों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देकर, अपना प्रदेश नम्बर वन है।

अपने प्रदेश में 24 हजार 461 अमृत सरोवर का चिन्हांकन किया गया है, उसमें से 15 हजार का निर्माण हो चुका है, यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। मेरठ से दिल्ली तक प्रथम रैपिड रेल सेवा पर काम चल रहा है। सबको निरोगी काया देने का संकल्प के साथ यह सरकार काम कर रही है। इसी के तहत 500 बेड का नया ट्रामा सेंटर के0जी0एम0यू0 में बना है और कैंसर संस्थान में पेट स्कैन मशीन लग गई है तथा प्रदेश का पहला एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर बन कर लोहिया संस्थान में बनकर तैयार है। रोजगार के सृजन के उद्देश्य से हरदोई में 1 हजार एकड़ में पार्क का सृजन हो रहा है, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 8 डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, इसमें 9 हजार मेगावाट का डेटा एकत्रित होगा और आई0टी0 सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और कम से कम 40 से लेकर 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा। लखनऊ में विश्व स्तरीय एयरो सिटी जोकि 1500 एकड़ में रुपये 600 करोड़ प्रस्तावित है, यह अपने प्रदेश की दशा को बदल कर रख देगा और हमारे अयोध्या में हमारे प्रभु राम जी विराजमान होने से और काशी में जो कॉरिडोर बन गया है, उससे जो पर्यटक आएंगे, उससे हमारी हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण के पर्यटक हिंदी सीखेंगे और हिंदी के विकास में ऐतिहासिक वृद्धि होगी और जो हमारी हिंदी भाषा का दक्षिण में प्रचार नहीं होता है, वह बैरियर टूटेगा। अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बालने का मौका दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।

[08:55] श्री अध्यक्ष द्वारा टैब पर लॉग-इन कर उपस्थिति दर्ज करने सम्बन्धी निर्देश

श्री अध्यक्ष-

हम सबके सामने जो यह डिवाइस है, उसमें एक उपस्थिति का भी बटन है, तो मैं अभी उसको देख रहा था कि कुछ मा0 सदस्य यहां पर उपस्थित थे आज दिन में, लेकिन उनकी प्रजेंट नहीं लगी, उनकी एबसेंट लगी है। उसका कारण यह है कि उन्होंने उसको लॉग-इन करके प्रजेंट नहीं लगाई। क्योंकि मैं उसको देख रहा था तो मुझे लगा कि यह सूचना होनी चाहिए। तो जो मा0 सदस्य यहां पर आते हैं, वह जरूर अपनी प्रजेंट लगा दिया करें। अब मैं रोज शाम को उपस्थिति बताउँगा कि कौन-कौन उपस्थित नहीं थे।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

अध्यक्ष जी, एक दिन पहले की भी नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

अब रह गयी, तो रह गयी वह आपकी गलती है। अगर आप वीडियो में उपस्थित होंगे तो लिखकर दे दीजिएगा। हमारे बहुत सारे सदस्य जो आज उपस्थित थे, वह लिखकर दे देंगे, तो उनकी उपस्थिति लग जायेगी।

श्री मनोज कुमार पारस-

अध्यक्ष जी, प्रमुख सचिव, विधान सभा को लिखकर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अयोध्या धाम दर्शनार्थ जाने हेतु सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य 11 फरवरी, 2024 को श्री अयोध्या धाम दर्शनार्थ जाना चाहते हैं और जो धर्मपत्नी के साथ जाना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कल पूरे दिन में कभी भी लिखकर पटल कार्यालय में अनुभाग अधिकारी को नोट करा दें, तो उस हिसाब से उचित व्यवस्था करने में थोड़ी सुविधा होगी।

बजट चर्चा पर मा0 सदस्यों हेतु पुनः समय का निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

अब हम अन्तिम दो वक्ताओं को बोलने के लिए बुलाएंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, तीन वक्ताओं को बुला दें, भले ही उनका समय कम कर दें।

श्री अध्यक्ष-

कितना समय कर दें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, दो वक्ताओं का 14 मिनट समय होता है। इस हिसाब से एक वक्ता को 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

14 मिनट में तीनों लोग बोल लें। डा0 हृदय नारायण सिंह आप 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

[08:57] वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों पर कटौती प्रस्ताव, जो हमारे मा0 सदस्य श्री ओम प्रकाश जी रखे हैं, उस प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपनी बात रखने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। इसके लिए आपको दिल से बहुत-बहुत आभार। मान्यवर, मैं मा0 उच्चतम न्यायालय को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन 22 जनवरी, 2024 के भव्य उद्घाटन के दौरान भारतीय मीडिया ने प्रभु श्री राम की तुलना में एक व्यक्ति विशेष को फोकस किया, जिस पर 05 फरवरी, 2024 को 'द न्यूयार्क टाइम्स' ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा है 'लाइव, कैमरा मोदी इट्स वन मैन शो इंडियन टेलीविजन'।

मान्यवर, सनातन के जो ध्वज वाहक हैं शंकराचार्य जी, इन लोगों के अनुसार ओरिजिनल रामलला की लगभग 5 से 6 इंच की मूर्ति है, उसके स्थान पर 51 इंच की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिससे शंकराचार्य लोग शायद व्यथित हैं और मैं उनके उद्गार कुछ पंक्तियों से कहना चाहूँगा।

'जो राम को लाये हैं, राम उन्हें ले जाएंगे,
इस देश में फिर से हम समरसता लाएंगे।
जो राम को लाये हैं, राम उन्हें ले जाएंगे।
22 जनवरी के अशुभ मुहूर्त में,
सनातनी चोला ओढ़, सनातन को ठेंगा दिखलाएंगे,
अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे,
इसीलिए जो राम को लाये हैं, राम उन्हें ले जाएंगे, राम उन्हें ले जाएंगे।'

मान्यवर, जनपद मऊ की घोषी चीनी मिल को सबसे अधिक गन्ने की सप्लाई हमारी सगड़ी विधान सभा क्षेत्र से होती है। घोषी चीनी मिल के गन्ना अनुपात का मानक 637 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि सगड़ी विधान सभा क्षेत्र के हरैया ब्लाक में गन्ना उत्पादक मानक 1150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चीनी मिल के अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते नैनीजोर करखिया, करखिया रूत्तम सराय, हैदराबाद, इस्माइलपुर, बेलहिया, रौनापुर, हाजीपुर, करमैनी, बातम, देवरिया, जाटपट्टी, बगही, बनहरा आदि तमाम गाँवों का अभी 60 प्रतिशत गन्ना खेतों में बचा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपके माध्यम से मा0 गन्ना मंत्री जी को आदेश दिया जाए कि घोसी चीनी मिल गन्ना को ले ले। हाजीपुर की चकबन्दी जल्द से जल्द करायी जाए। हाजीपुर से गोला सरयू नदी पर जो पुल बन रहा था, रुका हुआ है, उसको

भी चालू कराने की कृपा करें। हमारे साथी सामने बैठे हुए हैं, एक तरफ तो मा0 योगी जी मुख्य मंत्री हैं और एक तरफ मा0 नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच गोरखपुर-वाराणसी 4 लेन हाई-वे NH-24 बन रही है, वह 2014 में शुरू हुई थी और आज 2024 चल रहा है, पूर्ण नहीं हुई है। 210 किमी0 की रोड को अगर 3235 दिनों में पूर्ण नहीं किया गया तो जो बजट में लिखा हुआ है कि एक दिन में 12 किमी0 सड़कें बनती हैं, अगर उसको देखा जाए.....

(श्री अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य श्री हाकिल लाल बिन्द जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हाकिम लाल बिन्द-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट सत्र, 2024-25 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चन्द लाइनों के बाद अपनी विधान सभा क्षेत्र की बातें रखूंगा। सत्ता पक्ष के साथियों के लिए-

'अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे।

कलम के सिपाही अगर सो गये तो वतन के सिपाही वतन [xxx] देंगे।'

मान्यवर, हमारी विधान सभा क्षेत्र की बहुत गम्भीर समस्या है। हण्डिया विधान सभा क्षेत्र में बरोत बिठौली मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है। मैंने पिछली बार बजट सत्र में भी इस मामले को उठाया था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। यह 25 किमी0 की सड़क है, मात्र 10 फीट चौड़ी है और इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। भूसलपुर तिराहे से संसारीपुर बिन्द बस्ती तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। हमारी तहसील हण्डिया के अन्तर्गत नियुक्त तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं। सरकारी चकमार्गों को भी नापने में मोटी-मोटी रकम लेने का काम करती हैं। उनको हटाया जाना अति आवश्यक है। इसी के साथ नगर पंचायत हण्डिया में चैतन्य तिवारी नाम के अधिशासी अधिकारी हैं, वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चुनाव हुए लगभग 7 महीने हो गए हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन आज तक उनके भ्रष्टाचार की वजह से वहां पर कुछ विकास कार्य नहीं किया गया है। चकसारन से भूसलपुर, हिम्मतबहार तक सड़क का नवीनीकरण कार्य, ग्राम सभा कुराकाट के सामने रेलवे लाइन पर अण्डरपास का नव निर्माण कार्य, ग्राम सभा टेला में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य, नगर पंचायत हण्डिया में स्थित स्टेडियम का नवीनीकरण कार्य, ग्राम सभा कांगापुर से होलापुर तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। पिछले कार्यकाल में आदरणीय डिप्टी सी0एम0 महोदय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारी विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन करते हैं, लेकिन आज तक गंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए कोई डी0पी0आर0 तक

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नहीं बना है। हमारी विधान सभा क्षेत्र हण्डिया और मेजा विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है। हमारे यहां के लोगों को या तो मिर्जापुर से गंगा पार होना पड़ता है या इलाहाबाद होकर गंगा पार होना पड़ता है। लगभग 80 किमी0 का चक्कर काटकर हम उस पार जा पाते हैं। आए दिन नाव की दुर्घटनायें होती रहती हैं। आपसे निवेदन एवं आग्रह है तथा मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मा0 सदस्य ने अपने उद्‌बोधन के समय भारत के सिपाहियों के बारे में, भारत की सेना के बारे में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। मेरे ख्याल से आप उसको दिखवा लें और वह शब्द इस विधान सभा की कार्यवाही में मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं अभी दिखवा लूंगा।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, ऐसे शब्दों का इस विधान सभा में भारत की सेना भारत के सैनिकों के बारे में इस तरह के विचार व्यक्त करना मेरे ख्याल से यह कुंठित मानसिकता है। कुंठित मानसिकता है और जिसकी इतनी निन्दा की जाये उतनी ही कम है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठ जाइए। लास्ट में कौन बोलेगा, श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी लास्ट में कौन बोलेगा। कमाल भाई आप तो बोल चुके हैं आप तो सुबह बोले थे। डबल-डबल बोलेंगे।

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, पिछले 2022-2023 के श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण व बजट भाषण 2023-24 पर अशरफपुर में गोमती नदी पर सौ एक सौ पचीस मीटर का एक पुल बनना है यह इसौली विधान सभा क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जो अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या तीनो जिलों को जोड़ेगा। यह बहुत ही जरूरी है कि आम-जनमानस के साथ न्याय करते हुए वरीयता व प्राथमिकता के क्रम में धन आवंटित किया जाय। इसी कड़ी में पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे पर एक कट होना बहुत जरूरी है, मैंने पिछली बार कहा था श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर 2022-2023 में और बजट 2023-2024 में पूर्वान्चल औद्योगिक गलियारा बनाया जाये, ताकि साथ-साथ एक कट भी बन जाये। वहां पर बहुत जरूरी है। वह तहसील भी है और ब्लॉक भी है, ताकि सुल्तानपुर जिला व इसौली विधान सभा क्षेत्र को आर्थिक मजबूती प्रदान हो और उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो।

श्री अध्यक्ष-

ताहिर खान जी, क्या आप अपनी निर्धारित सीट से बोल रहे हैं ?

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, हां उसी से बोल रहे हैं। मैं अपनी ही सीट से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी ही सीट से बोल रहे हैं।

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, हां मैं अपनी ही सीट से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इस सीट को दिखवा लिया जाये डिस्प्ले में मा0 सदस्य का नाम नहीं आ रहा है।

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, यहां पर कट होना बहुत जरूरी है। पहले भी पिछले बजट में हमने इस मुद्दे को उठाया था। अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह बहुत गम्भीर मामला है। कट होना बहुत जरूरी है। एक ऐतिहासिक सड़क है नेशनल हाई-वे जो लखनऊ, वाराणसी मार्ग से अलीगंज से यह सड़क निकलती है। सीधे मिटने घाट होते हुए वल्लीपुर होकर प्रभातनगर अयोध्या को जोड़ती है। अगर यह सड़क बन जाये तो बीस-पचीस किलोमीटर की डिस्टेन्स बच जाये और यह इतना जरूरी है कि अगर अयोध्या में हमारे लोग जाना चाहते हैं तो बहुत घूम कर जाना पड़ता है। बजट है तो देना चाहिए। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम दो साल से लगातार मांग कर रहे हैं। यह बहुत जरूरी है, मैं आपके माध्यम से एम0डी0आर0 श्रेणी की सड़क है, आपका संज्ञान बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको संज्ञान में ले।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बोलने दीजिए। देखिये आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए यह विधान सभा है। कभी-कभी अच्छे अवसर आते हैं जिसमें अपनी बात कही जाती है। आप लोग कृपा करके उनको अपनी बात बोलने दीजिए।

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की तेइस करोड़ जनता आहत है कि डी0डी0ए0 और एन0डी0एम0सी0 दिल्ली में दिनांक 30-01-2024 को सुबह लगभग पांच बजे मेहरौली में कई ऐतिहासिक धरोहर को जो भारत की विरासत थी, उसको नष्ट करने का काम किया और भारत को विश्व पटल पर शर्मसार करने का काम किया। डी0डी0ए0 और एन0डी0एम0सी0 व दिल्ली

सरकार जो इन्वॉल्वमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि केन्द्र सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी और करना चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली सरकार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उस सरकार ने डी0डी0ए0 और एन0डी0एम0सी0 जो सबका साथ, सबका विश्वास अगर वाकई में आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति साफगोई है तो उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ कि डी0डी0ए0 और एन0डी0एम0सी0 के अधिकारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कराके दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है। भारत सरकार अग्रसर हो, साथ-साथ भारत का संविधान बचा रहे, हमारी एक सोच है। माननीय अध्यक्ष जी बस मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। दरिया बन के अपेक्षा करता हूँ कि किसी को डुबाने से बेहतर है कि भारत के हर नागरिक को सुरक्षा, भावना, आदर करते हुए, सागर बनकर समाहित करने का काम करें। सकारात्मक सोच रख कर मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए उनके द्वारा दोहराई गई कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहता हूँ कि-

'पैदा नजर-नजर में ऐसा मुकाम कर कि दुनिया सफर करे तेरे दामन को थाम कर।

मान्यवर, अभी आधा मिनट बचा है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता आहत है। इस पर ध्यान दिया जाये। यह बहुत सीरियस मामला है। एक और बहुत सीरियस मामला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के हालात बहुत खराब हैं। जिले में मेडिकल स्टाफ नहीं है। सी0एच0सी0 पर मेडिकल स्टाफ नहीं है, पी0एच0सी0 पर मेडिकल स्टाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, धन्यवाद।

श्री मो0 ताहिर खान-

मान्यवर, वहाँ पर ए ग्रेड की दवाइयाँ नहीं हैं। इन्स्ट्रूमेंट्स नहीं है, अल्ट्रासाउण्ड मशीन नहीं हैं, सी0टी0 स्कैन मशीन नहीं है। सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 के हालात बहुत खराब हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब आप समाप्त कीजिये। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मा0 सदस्य रह गये हैं तो अनुरोध है कि कृपया 03 मिनट का समय और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अब हम याचिकाएं लेते हैं।

[09:08] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

मैं उपस्थिति ले रहा हूँ, जो मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनकी याचिकाएं नहीं ली जायेंगी। जो मा0 सदस्य लिखकर दे गये हैं उनकी याचिकाएं ले ली जायेंगी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के बघरा से तिरपड़ी बुड़ीना खुर्द सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2.5 किमी0 तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनेष त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी से सम्बधित याचिका†

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी के किशनी चौराहे से वसैत हो कर रामशेरगंज मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज बाल्मीकि व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बधित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम खडित से फतेहपुर खोकरे मकीट मार्ग के मध्य ईशन नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जागेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम लड़ूपुर चकरपुर में बम्बा के ऊपर एक सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुमन गर्ग व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत बन्थरा नंगला मन्दिर से गुरूद्वारा होते हुए अमईपुर संडा सम्पर्क मार्ग तक

† छापी नहीं गई।

कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड बढ़पुर में स्थित ग्राम सभा रानीगंज के मजरा महमदपुर करसान से बघार नाले तक सड़क (लगभग 500 मी0) व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा विकास खण्ड परसपुर के सुसुण्डा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक राम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका सम्बधित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जमालपुर गोमा से लोहिया मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तालिब, निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू'', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कें फर्म मेसर्स कोहिनूर कन्सट्रक्शन द्वारा सिराइसमऊ से अलियामऊ सम्पर्क मार्ग व अन्य मार्गों में हुए गुणवत्ताहीन कार्यों की जाँच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर में भदौरा से हरकरनापुर-मगरखाई सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम तवड़ा से ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के

† छापी नहीं गई।

सम्बन्ध में श्री इसराइल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटान की समस्या के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा अंकुशपुर में जय गुरूदेव आश्रम से मुख्य मार्ग वाराणसी-कम्पोजिट विद्यालय घिटुआ तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारन के ग्राम पहासू से ग्राम चेड़ी तक कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रैना में कुंवरपाल राठी के घर तक लगभग 100 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिरोही व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद में कुम्हरई पुल से ग्राम अनगदा के सुरंजन सिंह की समाधी तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के मेरठ-करनाल हाई-वे से ग्राम बरलाजट तक 1.5 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत लहबरपुर मजरा गजाखेड़ा में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज के अन्तर्गत श्रेया हास्पिटल के सामने नहर की शाखा पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के अन्तर्गत नगर पालिका कुलपहाड़ में स्थित बस स्टैन्ड की बिल्डिंग का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा के अन्तर्गत ग्राम सुलतानपुर के उतरपारा से विश्वनाथगंज मार्ग व कतिपय अन्य मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विकास खण्ड गंगेश्वरी के ग्राम पथरा मुशकंद में गाँव के चौराहे से चीला ग्राम तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के ग्राम गोपालपुरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरू राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मथुरा के ब्लाक मथुरा में जुल्हेदी से कोन्हई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र सिंघल व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के ग्राम गढ़ीनौआबाद में रघुकुल कालेज में ग्राम गढ़ीनौआबाद तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भैया'', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भैया'', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के ब्लाक कटरा सादतगंज में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम बड़ौदा से आलियाबाद सम्पर्क मार्ग व फतेहपुर सम्पर्क मार्ग से चोला रेलवे स्टेशन तक काली सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किरनपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लॉक बहुआ के ग्राम गाजीपुर में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की शाखा खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर, गोमती नदी पर स्थित घोपाप धाम में अन्त्येष्टि स्थल, विश्राम गृह, रैन बसेरा, सामुदायिक शौचालय एवं विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में सीवर की समस्या के निराकरण हेतु सीवर लाइन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सरोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हंसवासुरवन वलीपुर चौराहा से मोहम्मदपुर (नहर की पटरी) जायस सम्पर्क मार्ग तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में आर0टी0ओ0 ऑफिस मार्ग से अन्दर रोड से अशोक गुप्ता के प्लाट होते हुए पकड़िया तक रोड व नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम खालसा में पक्की सड़क बुधिराम के घर से होते हुए महुली बार्डर महुली पक्की सड़क तक मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ब्लॉक खुर्जा के ग्राम सौंदाहबीबपुर में प्रेम के घर से बढ़ के वृक्ष (मेन चौक) तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम बागडपुर में मेन काली सड़क से लेकर पुलिस लाइन बछडौता तक (लगभग 1200 मी0) कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया, विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत परसुरामपुर ब्लाक के बेदीपुर जमुनहा मार्ग नहर पुल से रायपुर गांव तक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में श्री निखिल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा एवं विकास खण्ड मछलीशहर के ग्राम सभा कमालपुर से कटाहितखास तक पिच रोड मरम्मत के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम-नानई से ग्राम भैना तक लगभग 1.5 किमी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सबध मे श्री पंकज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमाँपुर विकास खण्ड-सिढपुरा के ग्राम मगथरा में मुख्य मार्ग से प्राथमिक विद्यालय तक मार्ग को सी0सी0 या इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-100, कासगंज सदर के अन्तर्गत ग्राम अमरपुरा भैसौरा बाईपास मार्ग से अनाज मण्डी के लिए सीधा रोड व काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बॉबी कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री ब्रजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर में ग्राम खानपुर से मझौला बिल्लौच तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डा0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी की तहसील सिराथू के कछुआ ब्लॉक में स्थित ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पटेल व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनपुर के ग्राम सभा खितौली में राकेश की चक्की से आगे स्थित नाले का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका†

डा0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील व विकास खण्ड सोहावल अन्तर्गत ग्राम पंचायत कलाफरपुर में सरयू नदी के किनारे कलाफरपुर घाट पर शवदाह केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में श्री उत्तम प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महराजगंज के अन्तर्गत भटहट-घोड़हवा मार्ग नटवा से बभनौली तक मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विभूति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर के अन्तर्गत नगर ललितपुर में शहर के मध्य होते हुए गोविन्द सागर डैम से निकली नहर में अण्डर पाइप लाइन डलवाते हुए निर्माण कार्य/संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डा0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र-121, नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम मिलक बमनपुरी से पीलीभीत-बरेली एन0एच0 तक सड़क पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शारदा नगर द्वितीय वार्ड में चरन भट्ठा रोड-पंचम खेड़ा हैवतमऊ रोड (निकट एसजीपीजीआई) पर स्थित इन्द्रपुरी कालोनी-तृतीय फेज में रमेश कुमार काकू, पूर्व पार्षद के मकान से उदयशंकर त्रिपाठी व डा0 अजय सिंह के मकान तक का मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकवेल पी0 सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत नगर पंचायत चितबड़ा गांव बाजार से माधव ब्रह्म बाबा स्थान होते हुए ग्राम सभा बीबीपुर में धरमापुर, नसीरपुर बन्धे तक सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत महासो मोड़ (निकट खुरहट बाजार) से महासो प्राइमरी पाठशाला

† छापी नहीं गई।

तक सड़क का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के बामौर ब्लाक के खड़ैनी, बामौर, गड़वई, ककरवई से गरौठा की ओर सड़क मार्ग की जर्जर/खराब सड़क पुनर्निर्माण/मरम्मत/गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के ब्लाक-मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम खिदौड़ा के गेट से पतला गेट तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजभूषण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कदौरा के कालपी मदारीपुर मुख्य मार्ग से हरचन्द्रपुर होते हुए ग्राम इकौना तक लगभग 7 किमी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अमोना पांडे से अजगरा तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहीर अहमद मलिक व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा जनपद बाँदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के ग्राम गुढाकला में विराजमान श्री हनुमान जी के मन्दिर तक सड़क की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाँदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम हस्तम, नाई, मकरी अजीतपारा आदि ग्रामों में फसलों की सिंचाई के निराकरण हेतु एक-एक राजकीय नलकूप की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विष्णु सिंह सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के नगर पालिका किरतपुर में ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 असलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड टाण्डा के अन्तर्गत नगर पंचायत इल्तिफातगंज सहजौरा श्मशान घाट का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इरफान अहमद व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के मझौवा लाल से कंचन चौराहा को जोड़ने वाले मार्ग (1 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड मझगवां में महराजगंज से महानन्दपुर गेगराव मटियारी सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाँदा के ब्लाक कमासिन में अन्दौरा सम्पर्क मार्ग नहर पुल से जमरेही नाथ तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र के शारदा नगर द्वितीय वार्ड में चरन भट्ठारोड पंचम खेड़ा पर हैवतमऊ रोड पर स्थित इन्द्रपुरी कालोनी-तृतीय फेज में रमेश कुमार काकू के मकान से उदय शंकर त्रिपाठी व डॉ0 अजय सिंह के मकान तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकवेल पी0 सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के सिधौली विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड कसमण्डा बहरीमऊ पानी टंकी के पास से जंगलेश्वर धाम तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकन्दरपुर-सम्मनपुर सम्पर्क मार्ग पर रामनाथ के खेत से ग्राम गंगिला के मुस्तफाबाद बब्बन के खेत तक जर्जर मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के बदलापुर में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदलापुर में अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स-रे मशीन लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के कस्बा आहार व उसके निकटवर्ती किसी स्थान पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल के ग्राम ईकड़ी काकेपुर मार्ग से सुरेश त्यागी के खेत तक कच्चे मार्ग (500 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिकेत भारद्वाज व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ग्यानपुर के ब्लाक ग्यानपुर में जिला पंचायत मार्ग भगवास से पलवारपुर मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कुशीनगर, ब्लाक पडरौना के अन्तर्गत ग्राम बहोरापुर मिल्की व जिगरा लगभग 04 किमी0 सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत नगर पंचायत मड़ियाहूँ में चण्डिका माता मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के वि0खं0 विलसण्डा अन्तर्गत ग्राम दियोरिया कला में राजकीय महाविद्यालय का निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के शाकुम्भरी हाई-वे से ग्राम बेलका, ग्राम अबाबाकरपुर नौगावां मार्ग पर से शाकुम्भरी बरसाती नदी गुजरती है, उक्त नदी के रास्ते पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री बिलाल व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर में निगोही तिलहर मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण बन्द रास्ते पर यातायात शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशांक गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279, आलापुर के विकास खण्ड जहाँगीरगंज के ग्राम-जमुनीपुर (राधानगर) में राजेसुल्तानपुर, महराजगंज मार्ग से दक्षिण उग्रसेन सिंह के घर तक (दूरी 1.5 किमी0) नव

† छापी नहीं गई।

निर्माण/पिच कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री कमलाकान्त राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री कमलाकान्त राजभर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज में कुशवां बाजार से लारपुर बक्सु मार्ग लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 मार्ग की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के निर्माण/मरम्मत शीघ्रातिशीघ्र कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम दुल्हारा से मठ तक की कच्ची सड़क को पक्का बनाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद संतकबीरनगर की विधान सभा क्षेत्र-314, धनघटा के पौली वि0ख0 के सुबखरी ग्राम पंचायत में विगत कई वर्षों से निर्माणाधीन चिकित्सालय बनाकर प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवंत व अन्य निवासीगण जनपद संतकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम पीरखेड़ा भट्टे से झिंझाना की ओर नाला की क्षतिग्रस्त पटरी (लम्बाई लगभग 1500 मी0) की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-236, सदर के वि0ख0 पहाड़ी के ग्राम पंचायत भदेदू के परगिया कुआं का पुरवा में गुडडू लोहार के घर से हनुमान केवट के घर तक सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 500 मी0 नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकिशोर यादव व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर में मेडिकल कालेज गोल चौराहा स्थित फल मण्डी के पीछे रेलवे लाइन एवं जी0टी0 रोड के बीच में करोड़ों रुपये की हजारों एकड़ सरकारी भूमि को तथाकथित भू-माफियाओं के कब्जे व मुनाफे में बेचे जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री जयमंगल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महराजगंज के बागापार मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका व्यपगत हुई।

डा0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डा0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के नवाबगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम शिवरई मठ मजरा रशीदाबाद वल्लभ से जहांनपुर लगभग 700 मीटर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री ठाकुर सुनील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के पीपरपुर से भुवालपुर तक जाने के लिए रेड़बीर में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेखर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड भीतरगांव की ग्राम पंचायत रार में मेन रोड दयाशंकर के खेत से सज्जन तिवारी के ट्यूबवेल होते हुये सिहूपुर सरहद तक मण्डी परिषद् से काले डामर रोड शून्य से लेपन तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार व अन्य निवासीगण जनपद घाटमपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की प्रदेश में वित्त विहीन कालेजों में कार्यरत शिक्षकों से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की प्रदेश में वित्त विहिन कालेजों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत पुरैना नहर पटरी ग्राम मुण्डेरवा सरहदी, जनपद गोण्डा बार्डर तक की सड़क पर 500 मी0 पक्की सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा ग्राम जाफरगंज मार्ग, मौहरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री लखन सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में अधिसूचित गांव की जमीनों के मानचित्र स्वीकृत एवं अकृषिक घोषित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड नूरपुर के ग्राम रामपुर फूना से ग्राम सरकथल तक डामर सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ियागंज में काली नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा, विकास खण्ड हिलौली अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर में राजकीय कृषि महाविद्यालय का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शंकर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के वि0खं0 पूरनपुर में धर्मापुर मुजफ्फरनगर मार्ग से शेखपुर मार्ग से नवदिया मुजफ्फरनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री नरेश पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मनीषा अनुरागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के ग्राम बंगरा में रामप्रसाद साहू के मकान से हरिया बसोर के मकान तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशु मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड-बलियाखेड़ी, थाना-नागल, ग्राम-उमाही में उमाही से कोटा तक लम्बाई लगभग 800 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरूल, निवासी जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मो0 ताहिर खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के उत्तरदहाँ रोड से डड़वा (रोहगौली) तक व भदहरा शिव मन्दिर से खरकपुर होते हुए शंकरगढ़ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष यादव, निवासी जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक रानी की सराय में पिच रोड से अनौरा, सोनवारा होते हुए लगभग 8 किमी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के ग्राम छीतरा में आई0टी0आई0 कालेज से राधा स्वामी सत्संग भवन तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-मंगरौरा के कान्धरपुर-पीथापुर सम्पर्क मार्ग से चन्द्रभानपुर होते हुए सराय शंकर मार्ग (2 किमी0) का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड-खड्डा के विद्युत उपकेन्द्र निबुआ नौरंगिया (कोटवा) एवं खड्डा में विद्युत क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत ग्राम वरना-गंघई जलालपुर भुतफर्का बाजार से चम्पापुर तिराहे तक मार्ग (3 किमी0) का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के ब्लाक सदरबढ़पुरा के ग्राम पोखरा से प्राचीन वनखण्डेश्वर महादेव मन्दिर तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के महुअर माइनर में हरधन जुड़ा ग्राम के पास आबादी भाग में नहर को पक्की करने के सम्बन्ध में श्री लालता यादव, निवासी जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई नगर के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के ग्राम में विकास भवन के बगल से राजू यादव के मकान से बम्बा तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू यादव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गोला के पिच रोड से सुरदापार राजा दलित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रिका प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत विकास खण्ड-इकौना में स्थित सीताद्वार मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर स्थित दोस्तपुर ब्लाक में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे सर्विस रोड 149 किमी0 तक ग्राम व्यासपुर में कूरेभार ड्रेन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र-131, विकास खण्ड-बनकटी के ग्राम चित्राखोर बाजार से पक्वा बाजार तक विशेष मरम्मत कार्य/नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत तहसील-महराजगंज, विकास खण्ड-शिवगढ़ में संचालित राजकीय विद्यालय हाई स्कूल ओसाह के भवन कक्षों की मरम्मत एवं टाइल्स शौचालय में लगवाये/निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत वीरपुर में अम्बेडकर पार्क के नाम से आरक्षित जमीन पर अम्बेडकर पार्क/सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमानन्द भारती व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरि प्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री हरि प्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र-132, जलालाबाद के विकास खण्ड-कलान में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड क्षेत्र करछना के शूलमई में अवैध खनन रोकने के सम्बन्ध में श्री मनीष निषाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद झाँसी महानगर के वार्ड संख्या-31, अयोध्यापुरी कालोनी में श्री संजय कुमार गुप्ता के मकान से श्री अनूप दुबे के मकान तक की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के हृदय रोग संस्थान में गरीबों के मुफ्त इलाज में आ रही प्रशासनिक विसंगतियों का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन बाबू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गई।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड-रसूलाबाद की नवलपुर रोड से राधेश्याम के दरवाजे तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना, कस्बा बीबी नगर में गुलावठी रोड से धारा सिंह की मड़िया तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश रुड़कीवाल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राकेश गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राकेश गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत रामा अमरापुर में वर्तमान स्थिति के अनुसार नाली अंकित कराने एवं अभिलेखीय नाली का विनियमन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-पल्हना की ग्राम सभा सिंहपुर सरैया (पिलौटा) बेसो नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

मा0 सदस्यों की उपस्थिति तथा नाम में सुधार विषयक श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री प्रदीप कुमार सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा नाम अभी तक सही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

इनका नाम अभी तक क्यों सही होकर नहीं आया है ? प्रदीप जी, इसका एक प्रॉसेस होता है, मैंने कल बोला था, फाईल चली है मेरे पास आएगी, तो मैं उसको देखूँगा उसके बाद ही नाम चेंज होगा। इस समय व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहा है।

आज दुर्गा यादव जी यहां पर उपस्थित थे, लेकिन उनकी प्रजेंट नहीं लगी। जिस समय मैं उपस्थिति देख रहा था, तो मैंने यह बात बोली थी कि कुछ सदस्य यहां पर थे, उन्होंने प्रजेंट नहीं लगायी है। मा0 दुर्गा जी थे, उन्होंने प्रजेंट नहीं लगायी।

---

† छापी नहीं गई।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं लगा दूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप न लगायें नहीं तो आप सबकी प्रजेंट लगा देंगे। उनको आप एक बार बता दें।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सत्र का आज तीसरा दिन है, क्योंकि सोमवार को तो बजट रखा गया था। आज तीसरा दिन है, तीन दिन तो आप लोगों को बैठना चाहिए। मैं भी तो बैठता हूँ।

[09:20] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाएं लेता हूँ।

आज दिनांक 08 फरवरी, 2024 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 83 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या की तहसील रुदौली के राजस्व ग्राम-फेलसण्डा में ईंट भट्ठे से हो रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकार को सीज करते हुये इनके द्वारा किये गये धन गबन की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री समर पाल सिंह की विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात जनपद अमरोहा में ग्राम बरखेड़ा से प्रेमपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मो0 हसन रूमी की जनपद कानपुर नगर के जलकल जोन-3 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र बाबूपुरवा में पेयजल की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की कालपी तहसील के अन्तर्गत कतिपय गांवों में ओलावृष्टि से हुई मटर की फसल में नुकसान के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के तहसील ऊन में ग्राम पंचायत भोगीमाजरा के कतिपय मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश की आयुर्वेद चिकित्सा विभाग में धनराशि प्रतिपूर्ति की व्यवस्था हेतु विभिन्न शासनादेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री बेचई सरोज की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के ग्राम सभा सिसेड़ी में मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना डा0 हृदय नरायण सिंह पटेल की गन्ना किसानों को अतिशीघ्र टोकन पर्ची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र-290, श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में मझौवा व ककरा घाट का पुल निर्माण कराये

जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली में ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री चन्दन चौहान की जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्गों का सी0सी0/इण्टरलॉकिंग एवं दोनों ओर नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मनोज कुमार प्रजापति की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम किशवाही में चन्द्रावल नदी में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जिला सहकारी बैंक बरेली के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को विधि सम्मत अनुमन्य ACP का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के धरमपुर रजवाहे में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पुल पतारी व उमरी मार्ग के बीच पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी की प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों के देयकों का भुगतान कराये जाने के के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत ग्राम बेलाडाडी करनपुर सेरहा की भूमि को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर जनपद का सीमांकन कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद सम्भल के तहसील चन्दौसी के अन्तर्गत रेलवे फाटक के ऊपर ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की विधान सभा क्षेत्र राठ के पनवाड़ी से राठ मार्ग निर्माण की TAC जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज फतेहपुर में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में ग्राम मल्लपुर से ग्राम मेहतरपुर करोड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के सरसावा नगर में बस स्टैण्ड का निर्माण कराने सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के धोपाप से कादीपुर राजमार्ग से होते हुये बाबा जनवारी नाथ धाम का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री लक्ष्मीराज सिंह की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में ग्राम बिलसूरी में रनिंग ट्रैक युक्त स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राजीव कुमार की गजरौला एमडीए स्थित पार्कों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की मेसर्स शकुन्तला फर्म के विरुद्ध स्टेट हाई-वे 126, फतेहगंज पूर्वी दातागंज मार्ग पर हुई दुर्घटनाओं में संलिप्तता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री राम अवतार सिंह की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम मेवा नवादा से अनीसा नगली तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के ग्राम पंचायत फतेहपुर कमासिन में सी0सी0 रोड का निर्माण रोके जाने के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री विजयपाल (आढ़ती), श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री पंकज गुप्ता, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राजेश्वर सिंह, श्री सौरभ सिंह, श्री बाबूलाल, श्री राम अचल राजभर, स्वामी ओउ्मवेश, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री मनीष रावत, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री सचिन यादव, श्री हाकिम लाल बिन्द, डॉ0 आर0 के0 पटेल, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री अरमान खान, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री कवीन्द्र चौधरी, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री लालजी वर्मा, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, श्री रामसिंह पटेल, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री राजकुमार सहयोगी, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री निर्मल वर्मा, श्री पल्टू राम, श्री नन्द किशोर गुर्जर, श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, श्री संजय कुमार शर्मा, श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री बम्बा लाल, श्री अतुल प्रधान, इंजी0 सरवन कुमार निषाद, डॉ0 असीम कुमार, श्री श्याम सुन्दर, श्री बृजभूषण राजपूत, श्रीमती सरोज सोनकर, श्रीमती मीनाक्षी सिंह, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्री अनिल कुमार, श्री संदीप सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'।

जिला अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग कटेहरी बाजार मछली मण्डी से पिलखावां मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

जिला अम्बेडकरनगर में बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग .....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[(राज्य मार्ग सं0-30) से कटेहरी बाजार से ग्राम पिलखावां की कुल लम्बाई 4.00 किमी0 है। जिसमें चैनेज-0.00 से 1.00 तक (कटेहरी बाजार से प्रतापपुर-चमुर्खा मार्ग लम्बाई 1.00 कि0मी0) पूर्व में गन्ना विभाग के स्वामित्व में था, इस भाग के पुनर्निर्माण हेतु लम्बाई 1.00 कि0मी0, लागत रु0 56.95 लाख की स्वीकृति शासनादेश सं0-29/2024/

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1/485902/2024/23-11099(099)/311/2023, पिबी 03-02-2024 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। चैनेज-1.00 से 4.00 तक (लम्बाई 3.00 कि0मी0) का मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है, जिसकी सतह सन्तोषजनक है।]

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, यहां लगाते हैं। यहां पर उत्तर देने के लिए निर्माण विभाग के माननीय मंत्री जी हैं नहीं। मान्यवर, हम क्या पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि जिन विभागों के वक्तव्य लगे हों क्योंकि विधान सभा में आज सुबह भी यह बात संज्ञान में आई कि कुछ माननीय मंत्री जी नहीं हैं। किसी के कुछ अपरिहार्य कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई भी न हो। इसके लिए मेरा निवेदन है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आप निवेदन कर लें कि वे यहां रहें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें तो एक किमी0 जो खराब है, वह 2 तारीख को स्वीकृत भी हो चुका है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, ये आश्वासन दे देंगे तो काम हो जायेगा। मान्यवर, मैं बता दूं कि पहले जो एक किमी0 इन्होंने स्वीकृत किया उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। मान्यवर, यह पूरी सड़क चार किमी0 है। मैं प्रायः प्रत्येक दिन जब वहां रहता हूँ, तो उस सड़क से गुजरता हूँ। इन्होंने कहा कि 3 किमी0 आने-जाने लायक है। लेकिन वह हैं नहीं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उसको फिर से दिखवा लें और अगर आने-जाने लायक नहीं है, टूटी है। अगर वह सड़क तीन किमी0 भी टूटी है, तो क्या उन तीन किमी0 की भी स्वीकृति जारी करने की कृपा करेंगे। बस इतना ही कहना है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

इसको हम फिर से दिखवा लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है मान्यवर, आश्वासन हो गया है।

जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना के दौराला में शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

जनपद मेरठ के सरधना स्थित शुगर मिल मेसर्स दौराला शुगर.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया]

[(शुगर इकाई), सरधना, जनपद मेरठ द्वारा कच्चे माल के रूप में 12,500 टन/दिन गन्ने की पेराई कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 2600 किली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाइयाँ यथा-ऑयल एण्ड ग्रीस स्कीमर, इक्वलाईजेशन टैंक, एनारोबिक फिल्टर, एयरेशन टैंक, सेकण्डरी क्लेरिफायर, एयरेशन टैंक सेकेण्ड, क्लेरिफायर सेकेण्ड स्लजड्राइंग बेड्स, मल्टीग्रेड फिल्टर एवं कार्बन फिल्टर हैं। सन्दर्भित उद्योग का वर्तमान क्रसिंग सीजन में निरीक्षण बोर्ड द्वारा दिनांक 28-12-2023 को किया गया एवं निरीक्षण के दौरान उक्त उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने को एकत्र कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मेरठ द्वारा विश्लेषित किया गया तथा प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार समस्त प्रचालक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा0का0नि0-35 (अ), दिनांक 14 जनवरी, 2016 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नियमित अनुश्रवण हेतु आनलाइन कॉन्टीन्यूअस एफ्लुएन्ट, मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है। उक्त मॉनिटरिंग सिस्टम बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण के समय संचालित पाया गया। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह के 15 दिन के भण्डारण क्षमता हेतु लैगून स्थापित है। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई हेतु कृषि भूमि पर प्रयोग में लाया जाता है। उद्योग को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत सशर्त सहमति जल तथा वायु दिनांक 31-12-2024 तक निर्गत है। तद्दिनांक को उद्योग के निरीक्षण में किसी स्रोत द्वारा भू-गर्भ में उत्प्रवाह डालने की पुष्टि नहीं हुई है।

2-दौराला एवं आस-पास के क्षेत्र में कैंसर, पेट सम्बन्धी रोगों के कारण लोगों की जान जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा पत्र संख्या-1284/जी/विधान सभा प्रश्न/2024, दिनांक 06-02-2024 को मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को पत्र प्रेषित करते

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सूचना/आख्या अविलम्ब प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है।

3-उद्योग द्वारा परिसर में अन्दर से किसी स्रोत द्वारा पानी धरातल में भेजने के सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा पत्र संख्या-1283/जी/विधान सभा प्रश्न/2024, दिनांक 06-02-2024 को सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भू-गर्भ जल विभाग, मेरठ को पत्र प्रेषित करते हुए सूचना/आख्या अविलम्ब प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है।]

***श्री अतुल प्रधान-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूर्व में भी माननीय सदन को इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरधना के दौराला कस्बे में यह मिल है और इसी के पास में शराब फैक्ट्री भी है। मैं पहले भी इसके फोटोग्राफ जमा कर चुका हूँ। अभी इन्होंने जो जवाब दिया तो अगर दौराला के आस-पास के गांवों की स्थिति देखें तो हजारों लोग कैंसर और पेट से सम्बन्धित गम्भीर बीमारी जैसे काला पीलिया, आँतें फटने का इन्फेक्शन इत्यादि से ग्रसित हो रहे हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं। विभाग ने जो उत्तर दिया है, उसमें कैंसर की बीमारी की स्थिति अपेक्षित रखी गई है और कहा गया है कि बाद में जानकारी मिलेगी। इसमें जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी है वह भी अपेक्षित रखी गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें एक कमेटी बना दी जाये। उस कमेटी में चाहे मुझे न रखा जाये कोई बात नहीं उसमें चाहे जिस भी प्रशासनिक अधिकारी को कर दीजिये, लेकिन कमेटी बनाकर जांच करा ली जाये। इसमें चाहे कलेक्टर की जांच कमेटी बना दी जाये या फिर चाहे कमिश्नर की जांच कमेटी बना दी जाये। मेरे रहने पर हो सकता है कि यह कहा जाये कि ये विपक्ष से हैं। इन्होंने उत्तर में कह दिया कि वहां पर वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट सुचारु रूप से चल रहा है, लेकिन वहां पर स्थिति यह है कि वह हमेशा बन्द पड़ा रहता है और जैसे ही वहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई जाता है, तो उसको चालू दिखा देते हैं। मैं नहीं कहना चाहता इस बात को, लेकिन वास्तव में वहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थिति बहुत खराब है, पूरे जनपद मेरठ में चाहे स्लाटर हाउस हो, चाहे बड़े हास्पिटल्स हों या फैक्ट्री हो। मेरा निवेदन है कि इसमें एक जांच कमेटी बना दी जाये जो वहां जाकर स्थिति का जायजा ले ले और इसमें कार्यवाही हो जाये।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण विभाग ने जो जांच की है उसके हिसाब से बाकी सब ठीक है, लेकिन उन्होंने चिकित्सा विभाग से यह कहा है कि आप यह देखें कि वहां पर पेट से सम्बन्धित या कैंसर से सम्बन्धित बीमारियाँ क्यों ज्यादा हो रही हैं। इत्तेफाक से यह विभाग मेरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास ही है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसे दिखवा लूँगा कि किस वजह से वहां बीमारी फैल रही है। मैं माननीय सदस्य को उससे अवगत भी करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कहा कि आप स्वयं इसको दिखवा लेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि चूंकि दोनों चीजें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं इसलिये इसमें जिलाधिकारी की एक कमेटी बनाइये जो दोनों चीजों को संयुक्त रूप से देखकर आपको रिपोर्ट दे दे।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, आपके निर्देशों का अनुपालन होगा।

सम्पूर्ण नगर पालिका परिषद्, इटावा क्षेत्र में जलभराव के निदान के सम्बन्ध में श्रीमती सरिता भदौरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, इटावा में जलभराव की समस्या के .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निस्तारण के लिए सी0 एण्ड डी0 एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा 13.6 किमी0 नाला निर्माण हेतु रु0 42.35 करोड़ के प्रस्ताव को तैयार किया गया है, जिसमें से नगर पालिका परिषद् इटावा के 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि द्वारा राहतपुरा से सरैया की ओर जाने वाले मार्ग, आगरा रोड से पुलिस लाइन जाने वाले मार्ग, पक्का बाग दुर्गा कालोनी मार्ग, महेरा चुंगी को जाने वाले मार्ग तथा अन्य आवश्यक जलभराव वाले क्षेत्रों में लगभग 4.500 किमी0 एवं लागत रु0 8.20 करोड़ नाला निर्माण के कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जलभराव वाले क्षेत्र पचावली मार्ग, विजयनगर मार्ग, अड्डा जालिम आदि में 3.800 किमी0 लम्बाई जिसकी लागत लगभग रु0 5.15 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं, उक्त स्वीकृत नालों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्रों में अवशेष नालों की लम्बाई 5.300 किमी0 एवं जिनकी लागत लगभग रु0 27.55 करोड़ की धनराशि का व्यय अनुमान आंकलित किया गया है, उक्त अवशेष नालों के निर्माण से सम्बन्धित धनराशि की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

***श्रीमती सरिता भदौरिया-**

माननीय अध्यक्ष जी, इटावा में जलभराव की समस्या बहुत पहले से है और पिछली सरकारों में भी रही है। जलभराव की समस्या से वहां पूरा शहर और वहां की गलियाँ ग्रसित रहती हैं। बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। हालांकि हमारी सरकार जबसे बनी है तबसे वहां पर काफी नालों का निर्माण हुआ है, लेकिन समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए काफी अधिक धन की जरूरत होगी। इसलिये मैं आपका सहयोग चाहती हूँ कि वहां पर नालों के लिए लगभग 27.55 करोड़ रुपये के प्रस्ताव बने हैं, तो आप माननीय मंत्री जी को आदेशित करें कि वह अतिरिक्त धनराशि दें, जिससे इटावा में जलभराव की समस्या जो थोड़ी बची है वह समाप्त हो जाये।

***श्री आशीष पटेल-**

माननीय अध्यक्ष जी, इटावा में कुल 13.6 किमी0 का नाला निर्माण होना था जिसके लिए 42.35 करोड़ रुपये का इस्टीमेट बना था, जिसमें से 4.5 किमी0 और लागत 8.20 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। लगभग 3.8 किमी0 और 5.15 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं। शेष सारी चीजें प्रक्रियागत हैं, तो वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर इसको दिखवा लिया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभा रवनियां में जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो चुकी सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेचई सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, लालगंज की ग्राम सभा रवनियां में श्री करिया यादव के घर से पिच रोड पारा तक कुल लम्बाई 01 किमी0 मार्ग का निर्माण कार्य ....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाइड लाइन से आच्छादित नहीं है। उपायुक्त (श्रम रोजगार), आजमगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 07-02-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्री करिया यादव के घर से श्री तिलकधारी यादव के घर तक लगभग 300 मीटर सी0सी0 रोड एवं श्री करिया यादव के ही घर से पिच रोड तक 800 मीटर खड़न्जा का निर्माण कार्य जिला पंचायत द्वारा कराया गया है। अतः उक्त कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा योजना से सम्बन्धित नहीं है। अतः प्रकरण में कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।]

***श्री बेचई सरोज-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा रवनियां में श्री करिया यादव के घर तक जाकर यह रोड समाप्त हो जाती है और फिर आगे के 700-800 मीटर की स्थिति बहुत खराब है। यह टूटा हुआ खड़न्जा है और इसमें जगह-जगह बहुत गड्ढे हैं। इसकी हालत इतनी खराब है जिसे हम कह नहीं सकते हैं, इसकी जांच करा ली जाये। 800 मीटर के बाद फिर पारा की एक सड़क मिलती है। लगभग 01 किमी0 का मार्ग काफी खराब है। पारा में एक डिग्री कालेज है, तो इस रास्ते से बहन, बेटियाँ और नौजवान छात्र आते-जाते हैं और आवागमन में बहुत कठिनाई होती है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मा0 अध्यक्ष जी मैंने पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से दो-दो बार कहा है। इसको करवा दें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

जवाब में लिखा है 800 मी0 खड़न्जा मार्ग है, जो क्षतिग्रस्त है और पंचायती राज विभाग से अनुरोध भी कर लिया गया है कि क्षतिग्रस्त खड़न्जे को ठीक कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नियोजन विभाग के अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग के उप निदेशक के पदों पर प्रोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06-02-2024 .....

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अर्थ एवं संख्याधिकारी की ज्येष्ठता सूची अन्तिम रूप से निर्धारित न होने के कारण अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति नहीं हो सकी। शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/409381/2023, दिनांक 17-10-2023 द्वारा अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त ज्येष्ठता सूची के प्रकाशन के क्रम में विषयगत कार्मिकों के पदोन्नति हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने में पाया गया कि अधिकांश कार्मिकों की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियां अपूर्ण हैं। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 06-05-2022 में निहित प्राविधानानुसार दिनांक 31-12-2023 के बाद पदोन्नति की कार्यवाही होने पर पदोन्नति हेतु पात्र कार्मिकों की वर्ष 2022-23 तक की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों की आवश्यकता है। वर्ष 2022-23 की गोपनीय प्रविष्टियां प्राप्त होने पर पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। पदोन्नति में विलम्ब प्रक्रियात्मक है, इसमें किसी कर्मचारी का दोष परिलक्षित नहीं होता है।]

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर मामला है। अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में जो प्रमोशन का मामला है मैं इस जवाब से सन्तुष्ट हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि जब मुख्य सचिव द्वारा अपने आदेश दिनांक 19 जुलाई को सभी विभागों में प्रमोशन की डेडलाइन 30 अगस्त दी गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

भाषण नहीं, इस इश्यू से सम्बन्धित हो तो पूछिये। नहीं, यह इससे सम्बन्धित नहीं है यह नहीं लिखा जायेगा। जब आप जवाब से सन्तुष्ट हैं, तो फिर पूछने का मतलब नहीं है।

चीनी मिल गेट एवं गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य द्वारा उपर्युक्तानुसार दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि .....

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रत्येक पेराई सत्र के प्रारम्भ में गन्ना खरीद एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु गन्ना एवं कृषक को अपने गन्ना भार में कोई कमी परिलक्षित होती है अथवा कोई संदेह होता है तो उसका प्रति-परीक्षण (Cross-Examination) मैनुअल कांटे पर तुलाकर कर सकते हैं।

इसी क्रम में पेराई सत्र, 2023-24 में प्रदेश में संचालित 120 चीनी मिलों द्वारा कुल 6,690 तौल कांटे संस्थापित कर चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के माध्यम से गन्ने की खरीद की जा रही है। दिनांक 06-02-2024 तक की प्राप्त सूचना के आधार पर चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के कुल 9,643 निरीक्षण विभिन्न मक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये हैं। कृत निरीक्षणों में चीनी मिल गेट पर 01 एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर 12 कुल 13 घटतौली (Incorrect Weightment) के प्रकरण संज्ञान में आये। जांच के दौरान क्रमशः चीनी मिल बिडवी (वेव समूह) के मिल गेट कांटे पर एवं चीनी मिल रोहानाकलां (आई0पी0एल0 समूह), करीमगंज (राणा समूह), बिसौली (यदु समूह), बरकातपुर (उत्तम समूह), चिलवरिया (सिम्भावली समूह), गुलरिया (बलरामपुर समूह), खम्भारखेड़ा (बजाज समूह), बुलन्दशहर (वेव समूह) एवं रामकोला (त्रिवेणी समूह) के वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली के प्रकरण संज्ञान में आये हैं।

तद्क्रम में चीनी मिल रामकोला (त्रिवेणी समूह) जिला-देवरिया एवं बरकातपुर (उत्तम समूह) जिला-बिजनौर में घटतौली के प्रकरण में संलिप्त चीनी मिल प्रबन्धन एवं मिल तौल लिपिक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी गयी है। इसी क्रम में अग्रेतर 13 मिल तौल लिपिकों के लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही के साथ 11 प्रकरणों में नियमानुसार सक्षम स्तर से सम्बन्धित चीनी मिल एवं मिल तौल लिपिकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये गये हैं।

गन्ना विकास विभाग कृषकों की समस्याओं के प्रति सजग एवं गम्भीर है।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

***श्री पंकज कुमार मलिक-**

मा0 अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने सदन में महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति वीर सिंह पुण्डीर जी की मूर्ति की स्थापना के लिए एक परमीशन की मांग की थी, जिसका आज आदेश चला गया है। विधान सभा को और सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैंने बड़ा महत्वपूर्ण मामला उठाया। आज किसान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। गन्ना किसान बहुत दुखी और परेशान है। मेरी जानकारी में आया है कि वेट इंडीकेटर के माध्यम से हर क्रय केन्द्र पर चाहे वह शुगर मिल में हों या वाह्य क्षेत्र में कय केन्द्र हों। जितने केन्द्र हैं वहाँ घटतौली की जाती है और घटतौली का तरीका इतना आसान है कि मिल मालिक या बड़ा अधिकारी अपने घर बैठकर एक बटन दबाकर घटतौल कर सकता है। इसके सन्दर्भ में एक टीम पूर्व गन्ना आयुक्त से मिली थी उन्होंने इसके सन्दर्भ में कई आदेश दिये, मैं पूरा मामला आपको दे भी दूंगा। मान्यवर, यह जो जवाब आया है यह ठीक नहीं है। पल पल, हर सेकेंड घटतौली की जा रही है। जिसके प्रमाण मैं आपको मा0 मंत्री जी के केबिन में अगर आप बुलायेंगे तो उपलब्ध करा दूंगा। आपसे अनुरोध है कि इस लुटते किसान को बचा लीजिए। वह बहुत मेहनत करके फसल उगाता है। उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, घटतौली की जा रही है। इसमें वरिष्ठ नेताओं या अधिकारियों की टीम लगाकर इसकी जांच करा लें। मैं पूरी जानकारी मा0 मंत्री जी आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, कोई स्पेसिफिक हो तो बता दीजिएगा तो उसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद चित्रकूट तथा बांदा में श्रम विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल प्रधान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

प्रकरण में श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान जाता है।

(श्रम मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[संख्या-15877/स्था0श्र0प्र0अ0-2024, दिनांक 05-02-2024 में अवगत कराया गया है कि जनपद चित्रकूट के श्रम प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर श्री दुष्यन्त कुमार, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सम्प्रति श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बबेरू, बांदा तथा श्री अरूण कुमार तिवारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, चित्रकूट के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय कानपुर में सम्बद्ध कर दिया गया। श्री दुष्यन्त कुमार के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या में दोषी पाये जाने पर श्री दुष्यन्त कुमार के विरुद्ध दण्डादेश पारित कर इनकी वर्ष 2024 की 01 वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से 02 वर्ष के लिये रोकने के दण्ड के साथ परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान करते हुये उनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। श्री अरुण कुमार तिवारी के विरुद्ध जाँच अधिकारी की जांच आख्या अप्राप्त होने के कारण श्री अरुण कुमार तिवारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अभी प्रचलित है।

3-प्रश्नगत विषय में ही जिलाधिकारी, चित्रकूट के पत्र संख्या-263/एस0टी0डी0एस0 /सीएम डैशबोर्ड/2023-24, दिनांक 23-09-2023 द्वारा सीएम डैशबोर्ड पर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना एवं कन्या विवाह सहायता योजना में जुलाई, 2023 के मूल्यांकन में चित्रकूट को डी श्रेणी प्राप्त होने के सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, चित्रकूट एवं उप श्रमायुक्त, चित्रकूट धाम क्षेत्र बांदा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का अनुरोध शासन से किया गया। उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1/424132/2023, दिनांक 08-11-2023 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रकरण में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्र संख्या-15100-01/ स्था0श्र0प्र0 अ0-2023, दिनांक 05-01-2024 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त को कारण बताओं नोटिस दिनांक 09-11-2023 को जारी की गयी, तत्पश्चात् श्री सुनील कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गई, श्री आर0 के0 गुप्ता, सहायक श्रमायुक्त, चित्रकूट को शिथिल

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर्यवेक्षण हेतु सचेत किया गया तथा श्री राजेश द्विवेदी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मानिकपुर, चित्रकूट को समस्त लम्बित प्रकरण का प्राथमिकता के आधार पर माह फरवरी, 2024 तक निस्तारित करने तथा श्री असित कुमार सिंह, उप श्रमायुक्त, चित्रकूट धाम, बांदा को अनुश्रवण हेतु निर्देशित किया गया है।

4-यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य, विधान सभा से प्राप्त शिकायतों एवं उनके पत्रांक-AA/2024/01, दिनांक 01-01-2024 द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वी0आई0पी0-02/36-02-2024, दिनांक 07-02-2024 द्वारा जिलाधिकारी, चित्रकूट की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। उक्तानुसार गठित समिति को प्रकरण का सम्यक् रूप से जाँच करके जाँच आख्या शासन को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।]

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, जो मा0 मंत्री जी का जवाब आया है मेरे द्वारा 2022 में जनपद चित्रकूट चूंकि एक आकांक्षी जिला है, आकांक्षी जिला होने के नाते समझा जा सकता है कि वहाँ तमाम समस्या होगी। हमारे जिले में श्रम विभाग की बहुत सी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। मैंने 2022 में शिकायत की थी और अपर श्रम आयुक्त जो आई0ए0एस0 अधिकारी थे, उन्होंने जांच किया था और वहां के श्रम अधिकारी को कानपुर में अटैच किया गया था। मान्यवर, मैंने जिनकी शिकायत किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसमें जवाब आया है कि डेढ़ साल से वह जांच चल रही है और जो बांदा के अधिकारी मेरे चुनाव के पहले तैनात थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गयी।

मान्यवर, इसमें जो जवाब आया है कि 5200 फाइलों में लगभग 5000 पत्रावलियां निरस्त की गयी हैं। मैंने पिछले सत्र में भी आपके समक्ष इस बात को उठाया था और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इस प्रकार कार्यवाही करेंगे। हमारे यहां के डी0एम0 एवं सी0डी0ओ0 आई0ए0एस0 हैं। मैंने शिकायत की थी तो उन्होंने जांच कराई थी। जांच में दिनांक 23 सितम्बर को प्रमुख सचिव, श्रम को पत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि मैं उनसे व्यक्तिगत मिला भी था, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब 6 तारीख को प्रश्न लगता है, आपका निर्देश मिलता है तो 7 तारीख को जिलाधिकारी कमेटी गठित करते हैं। मेरा कहना है कि आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा चुकी है। इसलिए मेरा कहना है कि उनके ऊपर कुछ-न-कुछ कार्रवाई की जाए और जो डेढ़ साल से जांच पेंडिंग है और मेरे सुनने में आया है कि उनको कहीं-न-कहीं जिला दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

उनको जिला दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा। इसको आप तय नहीं करेंगे। किसको कौन-सा जिला दिया जा रहा है यह आपको पता है ? आप अपनी बात बतायें।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जिसकी शिकायत की गयी है उसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने दिनांक 01-01-2024 को शिकायत की थी। शासन ने दिनांक 07-02-2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है और 15 दिन के अन्दर जांच आख्या मांगी गयी है। अब हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काफी समय पहले एक शिकायत की थी उसको भी इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा और जांच करा लीजिएगा।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, ठीक है।

विधान सभा क्षेत्र कालपी, जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम मगरौल, तहसील-कालपी में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र/तहसील कालपी जनपद जालौन के ग्राम मगरौल.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[चकबन्दी कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम मगरौल परगना कालपी, जनपद जालौन वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है। ग्राम मगरौल में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चकबन्दी निदेशालय द्वारा गांव सभा की ओर से प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद स्तर से ग्राम मगरौल में चकबन्दी कराने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर चकबन्दी निदेशालय द्वारा परीक्षणोपरान्त उक्त ग्राम को चकबन्दी हेतु उपयुक्त होने की दशा में प्रस्ताव शासन की अनुमति/स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तत्पश्चात् उक्त ग्राम में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लेकर चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष द्वारा अगले दिन गैर-सरकारी दिवस पर गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा कराये जाने विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष-

कल गैर-सरकारी दिवस भी होगा तो बहुत सारे माननीय सदस्यों ने मेरे से जानकारी चाही है कि आधा दिन लिखा हुआ है तो आधा दिन गैर-सरकारी दिवस है, ऐसा कार्य-सूची में लिखा जाता है और ऐसा ही होता है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आकर मेरे से जानकारी करनी चाही कि क्या कल आधा दिन ही सदन चलेगा। ऐसा नहीं है, पूरा समय सत्र चलेगा। मेरा एक निवेदन है कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्य सचेतक ने जो सूची दी थी, उसमें एक-दो लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोगों को बोलने के लिए बुला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्य सचेतक ने जो सूची दी है क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, श्री तेजपाल नागर तक बोलने के लिए बुलाया गया है। उसके बाद बहुत सारे माननीय सदस्य जो अभी भी बैठे हुए हैं जिनका आगे सूची में नाम है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन निर्णय आपको लेना है कि जहां पर छूटा है उसी हिसाब से क्योंकि रात को 09:00-09:30 बजे तक माननीय सदस्य बैठेंगे और कल फिर उनका नाम पीछे हो जायेगा तो इससे उनको थोड़ी सी कठिनाई हो जायेगी। जिस क्रम से सूची दी गयी है उसी क्रम से उसको आगे बढ़ायेंगे। यह मैं सारे माननीय सदस्यों के इन्ट्रेस्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्य बैठे थे कि हमारा नम्बर आयेगा और समयाभाव के कारण नम्बर नहीं आ सका तो उनको इस बात का प्रिविलेज मिलना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है, बाकी निर्णय जो आप सूची देंगे मैं उसी हिसाब से बोलने के लिए बुलाऊँगा। हम कल भी प्रयास करेंगे कि अधिक-से-अधिक माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकें और गैर-सरकारी दिवस की जो सूचनाएं हैं वह चाहे नियम-301 की हों या गैर-सरकारी संकल्प की हों। कल हम उसके ऊपर भी चर्चा करायेंगे। चाहे जितनी देर हो जाए। इसीलिए माननीय सदस्य थोड़ा समय निकालकर आएं। सभी लोगों को काम है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा काम है फिर भी मैं बैठता हूँ।

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 08 फरवरी, 2024 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(तारांकित प्रश्न संख्या-07 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-27-28 पर)

S.No.	Trades Name
1	Architectural Draughtsman
2	Carpenter
3	Catering & Hospitality Assistant
4	Computer Aided Embroidery And Designing
5	Computer Hardware & Network Maintenance
6	Computer Operator and Programming Assistant
7	Cosmetology
8	Cutting & Sewing (VI)
9	Dental Laboratory Equipment Technician
10	Desk Top Publishing Operator
11	Digital Photographer
12	Draughtsman (Civil)
13	Draughtsman (Mechanical)
14	Dress Making
15	Electrician
16	Electrician Power Distribution
17	Electronics Mechanic
18	Electroplater
19	Fashion Design & Technology
20	FINANCE EXECUTIVE
21	Fire Technology and Industrial Safety Management
22	Fitter
23	Food Beverage
24	Food Production (General)
25	Footwear maker
26	Foundryman
27	Health Safety & Environment
28	Health Sanitary Inspector
29	Hospital House Keeping
30	House Keeper
31	Industrial Painter
32	Information Communication Technology System Maintenance
33	Information Technology
34	Instrument Mechanic
35	Interior Decoration and Designing (P)
36	Interior Design & Decoration
37	Laboratory Assistant (Chemical Plant)
38	Leather Goods Maker
39	Lift and Escalator Mechanic
40	Litho- Offset Machine Minder
41	Machinist
42	Machinist (Grinder)
43	Marketing Executive
44	Mason (Building Constructor)
45	Mechanic (Motor Vehicle)
46	Mechanic (Tractor)

47	Mechanic Agriculture Machinery
48	Mechanic Auto Body Painting
49	Mechanic Auto Body Repair
50	Mechanic Auto Electrical and Electronics
51	Mechanic Consumer Electronics Appliances
52	Mechanic Diesel
53	Mechanic Machine Tool Maintenance
54	Mechanic Medical Electronics
55	Mechanic Two & Three Wheeler
56	Multimedia Animation & Special Effects
57	Painter General
58	Physiotherapy Technician
59	Plastic Processing Operator
60	Plumber
61	Pre/Preparatory School Management (Assistant)
62	Pump Operator-Cum-Mechanic
63	Radiology Technician
64	REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNICIAN
65	Secretarial Practice (English)
66	Sewing Technology
67	Sheet Metal Worker
68	Solar Technician (Electrical)
69	Stenographer & Secretarial Assistant (English)
70	Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi)
71	Surface Ornamentation Techniques (Embroidery)
72	Surveyor
73	Technician Power Electronics System
74	Textile Wet Processing Technician
75	Tool & Die Maker (Dies & Moulds)
76	Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures)
77	Tourist Guide
78	Trade Name
79	Travel & Tour Assistant
80	Turner
81	Weaving Technician
82	Welder
83	Welder (Fabrication & Fitting)
84	Wireman

नत्थी (ख)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-71 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-91-92 पर)

DDUGKY Candidate Data (From FY 2020-21 to 2022-23)

S.No.	District Name	Enrolled	Trained	Placed
1	Agra	2438	1462	518
2	Aligarh	1670	1094	383
3	Ambedkar Nagar	972	796	650
4	Amethi	1034	791	267
5	Amroha	172	141	144
6	Auraiya	1366	817	455
7	Ayodhya	1254	976	494
8	Azamgarh	539	393	108
9	Baghpat	1294	963	494
10	Bahraich	1706	1075	532
11	Ballia	584	352	89
12	Balrampur	1042	721	476
13	Banda	679	518	261
14	Bara Banki	2393	1709	805
15	Bareilly	1515	1274	643
16	Basti	1147	842	453
17	Bijnor	969	673	234
18	Budaun	1311	1067	671
19	Bulandshahr	1683	1355	434
20	Chandauli	1160	716	288
21	Chitrakoot	819	704	197
22	Deoria	1366	976	283
23	Etah	425	212	69
24	Etawah	1446	947	479
25	Farrukhabad	231	154	36
26	Fatehpur	1289	901	434
27	Firozabad	1451	990	491
28	Gautam Buddha Nagar	465	206	113
29	Ghaziabad	759	451	141
30	Ghazipur	530	350	178
31	Gonda	1414	1008	666
32	Gorakhpur	1957	1395	612
33	Hamirpur	981	745	486
34	Hapur	610	528	265
35	Hardoi	1845	1042	743
36	Hathras	1064	740	242
37	Jalaun	1776	1303	586
38	Jaunpur	1353	968	335
39	Jhansi	2180	1619	968
40	Kannauj	1249	810	341
41	Kanpur Dehat	2778	1923	971
42	Kanpur Nagar	1716	1166	480

DDUGKY Candidate Data (From FY 2020-21 to 2022-23)

S.No.	District Name	Enrolled	Trained	Placed
43	Kasganj	417	284	91
44	Kaushambi	1081	681	360
45	Kheri	1703	1073	575
46	Kushinagar	743	523	125
47	Lalitpur	1698	1225	638
48	Lucknow	2604	1946	993
49	Mahoba	805	498	236
50	Mahrajganj	953	592	287
51	Mainpuri	199	97	54
52	Mathura	2269	1630	606
53	Mau	472	258	68
54	Meerut	1079	798	787
55	Mirzapur	1395	779	464
56	Moradabad	1372	959	460
57	Muzaffarnagar	989	681	474
58	Pilibhit	1153	753	273
59	Pratapgarh	894	616	404
60	Prayagraj	2857	2207	1564
61	Rae Bareli	1398	961	337
62	Rampur	463	221	80
63	Saharanpur	1226	1008	851
64	Sambhal	635	364	150
65	Sant Kabir Nagar	442	392	195
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	612	514	302
67	Shahjahanpur	673	468	314
68	Shamli	466	364	319
69	Shrawasti	526	430	234
70	Siddharthnagar	620	389	175
71	Sitapur	2348	1571	800
72	Sonbhadra	1146	936	643
73	Sultanpur	1478	1112	727
74	Unnao	1874	1233	563
75	Varanasi	1848	1611	1132
	Total	91070	64047	32796

नत्थी (ग)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-84 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-99-100 पर)

NFBS District Wise Pendency Report

SNO	Districts	Old Data Without Aadhaar	Old Data -Aadhar Auth.,PFMS Accepted & Pending at DSWO	2023-24 New Application Pending at DSWO
1	2	3	4	5
1	AGRA	1795	456	500
2	ALIGARH	9686	164	442
3	ALLAHABAD	11545	233	508
4	AMBEDKAR NAGAR	3023	25	368
5	AMETHI	4349	488	127
6	AMROHA	8727	174	518
7	AURAIYA	5229	34	288
8	AZAMGARH	3185	202	41
9	BAGHPAT	1781	217	236
10	BAHRAICH	588	616	226
11	BALLIA	4849	246	230
12	BALRAMPUR	570	54	112
13	BANDA	1548	139	240
14	BARABANKI	3484	306	674
15	BAREILLY	9836	295	527
16	BASTI	873	104	0
17	BHADOHI	2522	45	139
18	BIJNOR	7885	1259	920
19	BUDAUN	1922	201	360
20	BULANDSHAHR	6340	381	281
21	CHANDAULI	3553	72	216
22	CHITRAKOOT	26	23	29
23	DEORIA	3090	241	303
24	ETAH	2393	100	265
25	ETAWAH	3130	256	214
26	FAIZABAD	5290	124	503
27	FARRUKHABAD	2859	617	329
28	FATEHPUR	3137	894	407
29	FIROZABAD	1470	394	584
30	GAUTAM BUDDHA NAGAR	2112	96	73
31	GHAZIABAD	1447	963	515
32	GHAZIPUR	4301	319	0
33	GONDA	4352	176	226
34	GORAKHPUR	11498	274	424
35	HAMIRPUR	77	77	126
36	HAPUR	3322	544	191
37	HARDOI	7938	2348	933
38	HATHRAS	3654	137	236
39	JALAUN	2575	546	246
40	JAUNPUR	6170	826	138
41	JHANSI	4384	256	211
42	KANNAUJ	4887	273	154
43	KANPUR DEHAT	1831	462	416
44	KANPUR NAGAR	6204	158	294
45	KASGANJ	3580	191	169
46	KAUSHAMBI	851	186	239
47	KHERI	3208	1723	1018

SNO	Districts	Old Data Without Aadhaar	Old Data -Aadhar Auth.,PFMS Accepted & Pending at DSWO	2023-24 New Application Pending at DSWO
48	KUSHI NAGAR	1354	321	263
49	LALITPUR	2216	58	18
50	LUCKNOW	13437	312	348
51	MAHARAJGANJ	5175	282	372
52	MAHOBA	0	98	81
53	MAINPURI	5726	969	372
54	MATHURA	3281	201	338
55	MAU	733	278	117
56	MEERUT	6738	262	459
57	MIRZAPUR	1250	232	66
58	MORADABAD	5636	715	555
59	MUZAFFARNAGAR	946	166	237
60	PILIBHIT	4096	204	368
61	PRATAPGARH	5120	633	241
62	RAE BARELI	8417	898	562
63	RAMPUR	5752	725	549
64	SAHARANPUR	2164	1695	1116
65	SAMBHAL	5881	1366	434
66	SANT KABEER NAGAR	1899	307	120
67	SHAHJAHANPUR	4741	450	252
68	SHAMLI	1931	237	110
69	SHRAVASTI	88	52	71
70	SIDDHARTH NAGAR	1978	88	22
71	SITAPUR	11477	588	601
72	SONBHADRA	1984	106	0
73	SULTANPUR	5034	306	368
74	UNNAO	3957	837	673
75	VARANASI	1635	460	246
	Grand Total	**299722**	**30761**	**24155**